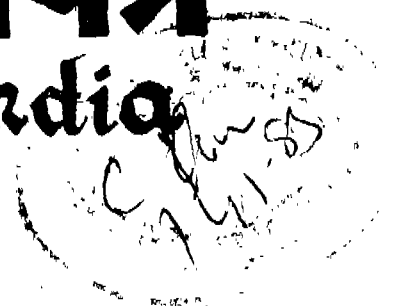




भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 49]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 8, 1984/अग्रहायण 17, 1906

No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 8, 1984/AGRAHAYANA 17, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II) PART II—Section 3—Sub-section (II)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएँ
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 1984

सूचनाएं

का.आ. 4210—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 क के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री एस. मानी, एडवोकेट, 105, 24वां क्रॉस 3 ब्लॉक ईस्ट, जयनगर, बंगलोर ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया जा रहा है कि उसे बंगलोर में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(75)/84-न्या.]

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 14th November, 1984

NOTICES

S.O. 4210.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by S. Maney, Advocate 105, 24th Cross, III Block East Jayanagar, Bangalore-560 011 for appointment as a Notary to practise in Bangalore.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(75)/84-Judl.]

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1984

का.आ. 4211—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 क के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री राज कृष्ण मलिक, एडवोकेट

बी-3, जंगपुरा-बी, प्रताप नगर बाजार के पीछे (राजदूत होटल के पास) नई दिल्ली-110014 ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया जा रहा है कि उसे केन्द्र शासित दिल्ली में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति को नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5 (34)/84-न्या.]

New Delhi, the 15th November, 1984

S.O. 4211.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Raj Krishan Malik Advocate, B-3, Jangpura-B, Behind Partap Market, (Near Hotel Rajdoot), New Delhi 110014 for appointment as a Notary to practise in Union Territory of Delhi.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(34)/84-Jud.]

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1984

का०आ० 4212.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री हरेन्द्र नाथ मुखर्जी 98, शाहजहान रोड, नई दिल्ली, ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिये दिया गया है कि उसे नई दिल्ली व्यवसाय करने के लिये नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाये।

[सं० 5(77)/84-न्या०]

New Delhi, the 19th November, 1984

S.O. 4212.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Harendranath Mukerjee, 98, Shah Jahan Road, New Delhi for appointment as a Notary to practise in New Delhi.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F-5(77)/84-Jud.]

का०आ० 4213.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री पी०के० सेन, (प्रणताप कुमार सेन), 9-बी, आनन्द पालित रोड, कलकत्ता-700014 ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया जाता है कि उसे कलकत्ता व 24-परगना व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं० 5(76)/84-न्या०]

S.O. 4213.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri P. K. Sen (Prantosh Kumar Sen) R/o. 9-B, Ananda Palit Road, Calcutta-700014 for appointment as a Notary to practise in Calcutta and 24-Parganas.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(76)/84-Jud.]

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1984

का०आ० 4214.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री देव कुमार सिन्हा, 18 रिचि रोड, कलकत्ता 700019 ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिये दिया जाता है कि उसे व्यवसाय करने के लिये नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाये।

2. उक्त व्यक्ति को नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाये।

[सं० 5(78)/84-न्या०]

New Delhi, the 20th November, 1984

S.O. 4214.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Deb Kumar Sinha, 18, Ritchie Road, Calcutta-700019 for appointment as a Notary to practise in Union of India.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F-5(78)/84-Jud.]

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1984

का०आ० 421.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री के०वि०

श्रीश्री, 1208, अशोकनगर, मण्ड्यासिटी, कर्नाटक, पिन-571401 ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अर्थात् एक आवेदन इस बात के लिये दिया जाता है कि उसे मण्ड्यासिटी, कर्नाटक व्यवसाय करने के लिये नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाये।

2. उक्त व्यक्ति को नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का अक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाये।

[सं० 5(79)/84-न्या०]

एस० गुप्ता, सज्जन प्राधिकारी

New Delhi, the 21st November, 1984

S.O. 4215.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri K. V. Sheshadri, Advocate, 1208, Ashoknagar, Mandya City Karnataka, Pin-571401 for appointment as a Notary to practise in Mandya City, Karnataka.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F-5(79)/84-Judl.]

S. GOOPTU, Competent Authority

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1984

क्र. आ. 4216.—केंद्रीय सरकार, आतंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1984 (1984 का 61) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को उनके नामों के सामने उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में, तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों में अपर लोक अभियोजक नियुक्त करती है।

अनुसूची

क्र.सं.	व्यक्तियों का नाम	विशेष न्यायालय का नाम
1	2	3
(1)	श्री जे. सी. कक्कर, सहायक जिला अटर्नी, भटिंडा	फिरोजपुर
(2)	श्री हरभगत सिंह सहायक जिला अटर्नी, रोपड़	पटियाला
(3)	श्री यशपाल शर्मा सहायक जिला अटर्नी, जलन्धर	जलन्धर
(4)	श्री पी. डी. शर्मा सहायक जिला अटर्नी, पटियाला	पटियाला

[सं. 3/5/84—विधिक सैल]

श्रीबल्लभ शरण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 4th December, 1984

S.O. 4216.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Terrorist Affected Areas (Special Courts) Act, 1984 (61 of 1984), the Central Government hereby appoints the persons named in column (2) of the Schedule annexed hereto to be Additional Public Prosecutors for the Special Courts specified against their names in the corresponding entry in column (3) thereof.

SCHEDULE

S. No.	Name of the Person	Name of the Special Court
(1)	(2)	(3)
1.	Shri J.C. Kakkar, Assistant District Attorney, Bhatinda.	Ferozepur
2.	Shri Harbhagat Singh, Assistant District Attorney, Ropar.	Patiala
3.	Shri Yashpal Sharma, Assistant District Attorney, Jalandhar.	Jalandhar
4.	Shri P.D. Sharma, Assistant District Attorney, Patiala.	Patiala

[No. 3/5/84—Leg. Coll.]

S.V. SHARAN, Jt. Secy.

(कानून और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1984

क्र.आ. 4217.—केंद्रीय सरकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री अंजन कुमार मुखर्जी, अधिवक्ता, कलकत्ता को नौ अपर विशेष न्यायाधीश, कलकत्ता के न्यायालय में श्री एम०पी० गुप्ता, एड्वेट, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, कलकत्ता और अन्य के विरुद्ध दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन, कलकत्ता नियमित मामला सं० 7/75 कलकत्ता में उपसंजात होने और अभियोजन का संचालन करने के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है।

[संख्या 225/20/84-ए०बी०डी०-II]

के०आर० गोपाल राव, अवर सचिव

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 20th November, 1984

S.O. 4217.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Anjan Kumar Mukherjee, Advocate, Calcutta, as a Special Public Prosecutor to appear and conduct prosecution of Delhi Special Police Establishment, Calcutta Regular Case No. 7/75-Calcutta against Shri S. P. Gupta, Agent, Central Bank of India, Calcutta and others in the court of 4th Additional Special Judge, Calcutta.

[No. 225/20/84-AVD. II]

K. R. GOPAL RAO, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1984

का० आ० 4218.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय सेवा-परीक्षा और सेवा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों के संबंध में नियंत्रक-महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) (द्वितीय संशोधन) नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 68 के उप नियम (1) में "पांच प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से ब्याज" शब्दों के स्थान पर "ऐसी दर पर ब्याज जो इस निमित्त सरकार द्वारा समय समय पर विहित की जाए" शब्द रखे जायेंगे।

[संख्या 7/3/84-पेंशन यूनिट]

एस०आर० अहीर, उप सचिव

टिप्पण: केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972, का० आ० 934 तारीख 1-4-1972 के रूप में प्रकाशित किये गये। नियमों का तृतीय संस्करण (दिसम्बर 1981 तक संशोधित), 1982 में मुद्रित किया गया तत्पश्चात् नियमों का डी०पी०एण्ड ए०आर० अधिसूचन सं० 32/4/83 पेंशन यूनिट, तारीख 26-8-1983 (का०आ० सं० 3477 तारीख 10-9-83) और अधिसूचना संख्या 29/4/83-पेंशन यूनिट तारीख 15-11-84 द्वारा संशोधित किया गया।

New Delhi, the 17th November, 1984

S.O. 4218.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Pension) (Second Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, in rule 68, in sub-rule (1), for the words "interest at the rate of five percent per annum", the words "interest at such rate as may be prescribed by the Government from time to time in this behalf" shall be substituted.

[No. 7/3/84-Pension Unit]

S. R. AHIR, Dy. Secy.

Note.—The Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 were published as S.O. 934 dated 1-4-1972. The Third Edition (corrected upto December 1981) of the rules was printed in 1982. The rules were subsequently amended vide DP&AR Notification No. 32/4/83-Pension Unit, dated 26-8-1983 (S.O. No. 3477 dated 10-9-83) and Notification No. 29/4/83-Pension Unit, dated 15-11-84.

गान्धी शांति प्रतिष्ठान तथा अन्य संगठन

कुबाल जांच आयोग

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1984

संशोधन

का०आ० 4219.—अधिसूचना संख्या 1/1/82 के०सी० आई० तारीख 26 जुलाई, 1982 के तहत जारी इस आयोग की क्रियाविधि को नियंत्रित करने वाले आदेश के पैरा 32 को निम्नलिखित अनुसार पढ़ा जाये:—

"प्रत्यायोजित आदेशिका पर हस्ताक्षर 32. आयोग के सचिव, निदेशक विधि अधिकारी, सहायक सचिव और

अनुभाग अधिकारी (विधायी) को नियम 4(2) और 4(6) के

अधीन आयोग के प्राधिकार से या द्वारा जारी किये गये सम्मनों तथा किसी अन्य प्रक्रिया पर हस्ताक्षर करने का प्राधिकार दिया गया है।

अर्थात् कि आयोग किसी विशेष मामले में, जिसमें यह ऐसा करना समायोजित या उचित समझे, आयोग के प्राधिकार से या द्वारा जारी किये गये सम्मनों अथवा किसी अन्य आदेशिका पर हस्ताक्षर करने का प्राधिकार, आयोग के अधीन कार्य कर रहे किसी अन्य अधिकारी को दे सकता है।"

[सं० 1/1/82 के०सी०आई०]

आयोग के आदेश से,

बी०एम०के० मट्टू, सचिव

KUDAL COMMISSION OF INQUIRY ON GANDHI PEACE FOUNDATION AND OTHER ORGANISATIONS

New Delhi, the 26th November, 1984

AMENDMENT

S.O.4219.—Para 32 of the Order regulating the procedure of this Commission issued vide Notification No. 1/1/82-KCI dated the 26th July, 1982 may be read as under:—

"Authority to Sign Process 32. The Secretary, Director, Law Officer, Assistant Secretary and Section Officer (Legal) in the Commission have been authorised under Rule 4(2)

and (6) to sign summons and any other process issued by or under the authority of the Commission:

Provided that the Commission may authorise any other Officer working under the Commission in a particular case to sign summons or any other process issued by or under the authority of the Commission here it deems fit and proper to do so."

[No. 1/1/82- KCI]

By Order of the Commission.
B.M.K. MATTOO, Secretary

योजना आयोग

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1984

का०आ० 4220.—योजना आयोग की दिनांक 30 जुलाई, 1984 को समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, डा० आई०एस० गुलाटी की अध्यक्षता में गठित भारत में निगमित कराधान से संबंधित अध्ययन दल को अवधि 30 नवम्बर, 1984 तक और बढ़ाई जाती है।

[सं० ए-12034/7/84-प्रशासन I]

के०सी० अग्रवाल, निदेशक (प्रशासन)

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 15th November, 1984

S.O. 4220.—In continuation of Planning Commissioner's notification of even number dated 30th July, 1984, the term of the Study Group on Corporate Taxation in India, constituted under the Chairmanship of Dr. I. S. Gulati, is further extended upto 30th November, 1984.

[No. A-12034/7/83-Admn. II]

K. C. AGARWAL, Director (Admn.)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सीमाशुल्क समाहर्ता का कार्यालय)

मदुरै, 15 अक्टूबर, 1984

अधिसूचना सं० 2/84

कां०आ० 4221.—सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 8(ए) संशुद्ध अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, निर्म्मांकित विवरणानुसार तूतिकोरिन पोर्ट के दक्षिणी बाँध के साथ-साथ एल०एस० 2183 मीटर में, अतिरिक्त बर्थ सं० 1 के अनुबद्ध, अवस्थित बर्थ सं० 2 को, माल या माल की किसी भी श्रेणी के लदान और उतारने के उचित स्थान के रूप में घोषित करता हूँ।

2. बर्थ सं० 2 का परिमाण निर्म्मांकित है।

लंबाई: 243 मीटर

चोड़ाई: 130 मीटर,

ठाँचा: 10.1 मीटर

सीमाएं:—

दक्षिण में: अतिरिक्त बर्थ सं० 1 तथा दक्षिणी बाँध—

रेलवे लाइन और सड़क सहित

उत्तर में: पोर्ट बेसिन

पूर्व में: पोर्ट बेसिन

पश्चिम में: वेओसी बार्क तथा अतिरिक्त बर्थ से लगा हुआ पाई बेसिन

[सी नं० VIII/40/4/83-कस्ट I]

के० शंकररामन, समाहर्ता

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Office of the Collector of Central Excise and Customs)

Madurai, the 15th October, 1984

NOTIFICATION 2/84

S.O. 4221.—In exercise of powers conferred by Section 8(a) of the Customs Act 1962 (52 of 1962) I declare Berth No. 2 located at L.S. 2183 metres along its South break water, Tuticorin Port in continuation of Additional Berth No. 1 as per details given below, as proper place for the loading and unloading of goods or for goods of any class.

2. The dimensional area in which the berth No. 2 located is as follows :—

Length : 242 metres

Breadth : 130 metres

Draught : 10.1 metres

BOUNDARIES :—

On the South : Additional Berth No. 1 and South break water with railway lines and road.

On the North : Port Basin

On the East : Port Basin

On the West : Port Basin enclosed between V.O.C. Wharf and additional berths

[C. No. VIII/40/4/83-Cus. II]

K. SANKARARAMAN, Collector

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1984

(आयकर)

का.आ.4222,—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अथवा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक तथा "कालेज" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है।

1. यह कि दक्षिण शिक्षण संस्था का फर्गुसन कालेज, पुणे, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक् लेखा रखेगा।
2. यह कि उक्त कालेज अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
3. यह कि उक्त कालेज अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक को एक-एक प्रति संबंधित आयुक्त को भेजेगा।

संस्था

"दक्षिण शिक्षण संस्था का फर्गुसन कालेज, पुणे"
यह अधिसूचना 7-9-1984 से 31-3-1986 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं० 6026 (फा०सं० 203/113/83-आ०क०नि०II)]

गिरीश दवे, अवर सचिव

New Delhi, the 7th November, 1984

(INCOME-TAX)

S.O. 4222.—It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Science and Technology, New Delhi, the Pres-

cribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "College" subject to the following conditions :—

- (i) That the Deccan Education Society's Fergusson College, Pune will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research
- (ii) That the said College will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April, each year.
- (iii) That the said College will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets and liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

"Deccan Education Society's Fergusson College, Pune".

This notification is effective for a period of from 7-9-1984 to 31-3-1986.

[No. 6026 (F. No. 203/113/83-ITA. II)]

GIRISH DAVE, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1984

क्र० आ० 4223.—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के धारा 21 क की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 21 की उपधारा 1 के खण्ड (ग) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से निम्नलिखित व्यक्तियों को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) की अधिमूचना संख्या एफ०-8/3/77-बी०ओ 1 (2) दिनांक 31 जनवरी, 1978 के अस्तंगत नामित सदस्यों के स्थान पर 26 नवम्बर, 1984 से भारतीय स्टेट बैंक के भोपाल स्थानीय मण्डल में सदस्य नामित करती है :—

1. श्री केदार नाथ शर्मा,
भोपाल स्थानीय मण्डल
कृषक 49, आदर्श नगर
शिवपुरी
(मध्य प्रदेश)
2. श्री नागेन्द्र सिंह,
धूप छांव,
सिविल लाईन्स,
रीया-486001
(मध्य प्रदेश)
3. श्री मधुकर मरमट,
309/5, नेहरू नगर,
इन्दौर-452003
(मध्य प्रदेश)
4. श्रीमती चन्द्र प्रभा पतेरिया,
कृषक,
807, राइट टाउन,
जबलपुर
(मध्य प्रदेश)

5. श्री यावर रशीद,
"शामला कोठी"
शामला हिल्स
भोपाल-462013
(मध्य प्रदेश)

[सं० एफ०-8/9/84-बी० ओ०-1]

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 16th November, 1984

S.O. 4223.—In pursuance of clause (c) of sub-section (1) of section 21, read with sub-section (1) of section 21A of the State Bank of India, Act, 1955 (23 of 1955), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby nominates the following persons to be members of the Bhopal Local Board of the State Bank of India with effect from November 26, 1984 in place of the members nominated under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) No. F. 8/3/77-BO. 1(2), dated 31st January, 1978, namely :—

BHOPAL LOCAL BOARD

1. Shri Kedar Nath Sharma,
Agriculturist,
49, Adarsh Nagar,
Shivpuri (Madhya Pradesh).
2. Shri Nagendra Singh,
Dhoop Chhaon,
Civil Lines,
Rewa-486001 (M.P.)
3. Shri Madhukar Marmat,
309/5, Nehru Nagar,
Indore-452003 (M.P.)
4. Smt. Chandra Prabha Pateria,
Agriculturist,
807, Wright Town,
Jabalpur (M.P.)
5. Shri Yawar Rashid,
'Shamla Kothi'
Shamla Hills,
Bhopal-462013 (M.P.)

[No. F-8/9/84-BO. I]

क्र०आ० 4224.—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के धारा 21क की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 21 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से निम्नलिखित व्यक्तियों को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) की अधिमूचना संख्या एफ०-8/3/77-बी०ओ०-1(2) दिनांक 31 जनवरी, 1978 के अस्तंगत नामित सदस्यों के स्थान पर 26 नवम्बर, 1984 से भारतीय स्टेट बैंक के खण्डीगढ़ स्थानीय मण्डल में सदस्य नामित करती है।

खण्डीगढ़ स्थानीय मण्डल

1. श्री परमपाल सिंह मान,
29, सैक्टर 9-ए,
खण्डीगढ़-160009
2. श्री माखन लाल दर,
वर सीड एण्ड फूट फार्म,
कर्ण नगर चौक, घमार्थ रोड, श्रीनगर-190010,
(जम्मू व कश्मीर)

3. कैप्टन ठाकुर घाम (मेकानिक्स),
कृषक,
घाम तथा ठाकुर वालकुम्हरी,
तहसील-नयमिहपुर
जिला कांगड़ा, बाया आलमपुर
हिमाचल प्रदेश
पिन-176082

4. श्री गुलाम हसन नायक,
एडवोकेट,
रुहू, अनंतनाग,
कश्मीर-192101
(जम्मू व कश्मीर)

[सं० एफ० 8/13/84-बी०ओ०-1]

S.O. 4224.—In pursuance of clause (c) of sub-section (1) of section 21, read with sub-section (1) of section 21A of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby nominates the following persons to be members of the Chandigarh Local Board of the State Bank of India with effect from November 26, 1984, in place of the members nominated under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) No. F. 8/3/77-BO. I(2), dated 31st January, 1978, namely :—

CHANDIGARH LOCAL BOARD

1. Shri Parmpal Singh Mann,
29, Sector 9-A,
Chandigarh-160009.
2. Shri Makhan Lal Dhar.
Dhar Seed and Fruit Farm,
Karan Nagar Chowk,
Dharmarth Road,
Srinagar-190010 (J & K)
3. Captain Thakur Dass (Retd.),
Agriculturist,
Village and P.O. Balakrupi,
Tehsil Jaisinghpur-176082,
Via Alampur,
Distt. Kangra (Himachal Pradesh)
4. Shri Ghulam Hassan Naik,
Advocate
Ruhu, Anantnag,
Kashmir-192101 (J & K)

[No. F. 8/13/84-BO. II]

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1984

का०आ० 4225.—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 21क की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 21 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से निम्नलिखित व्यक्तियों को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) की अधिसूचना संख्या एफ 8/3/77-बी०ओ०-1(2) दिनांक 31 जनवरी, 1978 के अंतर्गत नामित सदस्यों के स्थान पर

27 नवम्बर, 1984 से भारतीय स्टेट बैंक के गौहाटी स्थानीय मंडल में सदस्य नामित करती है।

गौहाटी स्थानीय मंडल

1. श्री ए०एन० अक़रम हुसैन,
सचिव, असम खादा और ग्रामोद्योग बोर्ड,
सर सादुल्ला रोड,
गौहाटी-781001 (असम)
2. श्री जॉन लालसंग जुआला
मिशन बाग
डाक घर ऐजल-796001
(मिज़ोरम)
3. श्री धरनी धर दास,
अध्यक्ष, कमेटी फार इकनामिक
रिकन्स्ट्रक्शन आफ असम,
हिदायतपुर, गौहट-781003
असम

[संख्या एफ० 8/6/84 बी०ओ०-1]

New Delhi, the 17th November, 1984

S.O. 4225.—In pursuance of clause (c) of sub-section (1) of section 21, read with sub-section (1) of section 21A of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby nominates the following persons to be members of the Gauhati Local Board of the State Bank of India with effect from November 27, 1984 in place of the members nominated under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) No. F. 8/3/77-BO. I(2), dated 31st January, 1978, namely :—

GAUHATI LOCAL BOARD

1. Shri A. N. Akram Hussain,
Secretary,
Assam Khadi & Village Industries Board,
Sir Sadulla Road,
Gauhati-781001 (Assam).
2. Shri John Lai Sangzuala,
Mission Veng,
P.O. Aizawl-796001. (Mizoram)
3. Shri Dharani Dhor Das,
Chairman,
Committee for Economic Re-construction of Assam,
Hedayatpur,
Gauhati-781003 (Assam).

[No. F. 8/6/84-BO. II]

का० आ० 4226 :—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम 1980 के खंड 9 के साथ पठित खंड 3 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श के पश्चात् और दिनांक 7 अप्रैल, 1982 के भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) की सं० एफ 9/44/81-बी०ओ० 1 की अधिसूचना को उस सीमा तक रद्द करते हुए जहाँ तक कि उसका संबंध श्री एन० के० कुषप्पा की नियुक्ति

से है, श्री नुवुला वेंकटरत्नम नायडू, गांव बन्वलुरु, तालुक रापुर, जिला नेल्दोर (आन्ध्र प्रदेश) को एतद्द्वारा 17 नवम्बर, 1984 से जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने के वास्ते उक्त खंड 3 के उपखंड (घ) के तहत कार्पोरेशन बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या एफ० 9/42/83-बी० ओ०-1]

च० बा० मीरचन्दानी, निदेशक

S.O. 4226.—In pursuance of clause 3, read with clause 9 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) No. F. 5/44/81-BO. I, dated the 7th April, 1982 in so far as it relates to the appointment of Shri N. K. Huchappa, hereby appoints Shri Nuvvula Venkata Rathnam Naidu, Vandluru Village, Via-Dachur, Rapur Taluk, Nellore District (A.P.) as a Director of the Corporation Bank with effect from November 17, 1984 to represent the interests of depositors under sub-clause (d) of the said clause 3.

[No. F. 9/42/83-BO. I]

C. W. MIRCHANDANI, Director

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1984

का०आ० 4227.—भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) की धारा 26 की उपधारा (2क) के साथ पठित धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (गक) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर ब्रांचें रोड शाखा, कलकत्ता के खजांची श्री तेजबहादुर राय को स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के कर्मचारियों में से, जो कर्मकार है, 20 नवम्बर, 1984 से 19 नवम्बर, 1987 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के निदेशक बोर्ड में निदेशक नियुक्त करती है।

[संख्या एफ० 15/6/81आई० आर०]

यशवंत राज, अवर सचिव

New Delhi, the 20th November, 1984

S.O. 4227.—In pursuance of clause (ca) of sub-section (1) of section 25 read with sub-section (2A) of section 26 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959), the Central Government hereby appoints Shri Tej Bahadur Rai, Cashier, State Bank of Bikaner and Jaipur, Brabourne Road Branch, Calcutta as a director on the Board of the State Bank of Bikaner and Jaipur from among the employees of the State Bank of Bikaner and Jaipur who are workmen for a period of three years commencing on 20th November, 1984 and ending with 19th November, 1987.

[No. F. 15/6/81-IR]

YASHWANT RAJ, Under Secy.

व्यापारिक मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 नवम्बर 1984

(इलायची नियंत्रण)

का०आ० 4228 :—केन्द्रीय सरकार, इलायची नियम, 1966 के नियम 5 के साथ पठित इलायची अधिनियम, 1965 (1965 का 42) की धारा

4 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अनुसरण में अधिसूचित करती है कि श्री लियोनार्ड सोलोमन सारिंग, सदस्य राज्य सभा को राज्य सभा द्वारा उक्त धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित इलायची बोर्ड के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है और विनिर्दिष्ट करती है कि श्री लियोनार्ड सोलोमन सारिंग इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा तब तक के लिए जब तक वह राज्य सभा के सदस्य बने रहते हैं, जो भी पहले हो, उक्त बोर्ड के सदस्य के रूप में पद धारण करेंगे।

[फा० सं० 36 (4)/84-प्लांट (बी)]

बी० एम० एस० नेगी, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 19th November, 1984

(CARDAMOM CONTROL)

S.O. 4228.—In pursuance of clause (c) of sub-section (3) of section 4 of the Cardamom Act, 1963 (42 of 1963), read with rule 5 of the Cardamom Rules, 1966, the Central Government hereby notifies that Shri Leonard Solomon Saring, Member, Rajya Sabha, has been elected by the Rajya Sabha to be member of the Cardamom Board, established under sub-section (1) of the said section 4, and specifies that Shri Leonard Solomon Saring shall hold office as a member of said Board with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette for a period of three years or until he ceases to be a member of the Rajya Sabha whichever is earlier.

[File No. 36(4)/84-Plant (B)]

B. M. S. NEGI, Under Secy.

(मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1984

का. आ. 4229.—मैसर्स "मोदी" कार्पोरेशन लि. द्वारा बचन "B" प्लाक कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001 को 1983-84 के दौरान पंजीगत मास के आयात के लिए 31,79,800 क्वाण केवल (202,346, पौण्ड) के मूल्य का आयात लाइसेंस नं. पी/सी/जी/2090288/डी/एक्स/एक्स/87/एच/82/टीजी/दिनांक 3-9-83 दिया गया था।

फर्म ने उपर्युक्त लाइसेंस को सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति/मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति, दोनों प्रतियों को अनुतिथि प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति/मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत करवाए बिना खो गई है और उनका बिल्कुल भी उपयोग नहीं हुआ है। फर्म यह स्वीकार करती है और बचन देती है कि मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति/मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति यदि बाद में मिल जाती है तो इस कार्यालय को वापिस कर दी जाएगी।

3. अपने तर्कों के समर्थन में फर्म ने आयात-निर्यात क्रियाविधि पुस्तक 1984-85 के अध्याय 15 के पैरा 353 द्वारा वांछित एक श्राव्य-पत्र दाखिल किया है। अद्योद्देशाक्षरी संतुष्ट है कि आयात लाइसेंस नं. पी/सी/जी/2090288 दिनांक 3-9-83 की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति/मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति खो गई है और निदेश देता है कि आवेदक को लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति/मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति की अनुतिथि प्रति जारी की जाए। लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति/मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति रद्द की गई है।

4. आयात लाइसेंस की सीमा-रुद्ध प्रयोजन/मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[मि. सं. 1395/82/23/सी.जे.]

प/न. बेंक, उपमुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात
कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 20th November, 1984

S.O. 4229.—M/s. Modi Carpets Ltd., Harsha Bhawan, 'E' Block, Connaught Circus, New Delhi-11000, were granted an Import Licence No. P/CG/2090288/D/XX/87/H/82/CG. I dated 3-9-1983 for Rs. 31,79,800 only (\$ 202,346) for the import of Capital Goods during the period 1983-84.

2. The firm have now requested for the issue of duplicate copy of Customs Purpose Copy/Exchange Control Copy/ both copies of the above Licence on the ground that the original Customs Purposes Copy/Exchange Control Copy have been lost without having been registered with any Customs Authority and utilised at all. The firm agrees and undertakes to return the original Customs Purposes Copy/Exchange Control Copy of the Licence if traced later, to this office for record.

3. In support of their contention the firm have filed an affidavit as required in Para 353 of Chapter XV of Hand-Book of Import Export Procedures 1984-85. The undersigned is satisfied that the original Customs Purposes Copy/E. C. Copy of Import Licence No. P/CG/2090288 dated 3-9-1983 has been lost and directs that duplicate copy of Customs Purposes Copy/E. C. Copy of the Licence may be issued to the applicant. The original Customs Purposes Copy/E. C. Copy of Licence has been cancelled.

4. The duplicate copy of Customs Purposes Copy/E. C. Copy of the Import Licence is being issued separately.

[F. No. 1395/82/23/CG. I]

PAUL BECK, Dy. Chief Controller of Imports & Exports
for Chief Controller of Imports & Exports.

(संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय)

(केंद्रीय लाइसेंस क्षेत्र)

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1984

निरस्त आदेश

का. आ. 4230.—सर्वश्री कुसुम कोचर, ए-329, नई सखी मण्डी, आज़ाद पुर देहली की एक आयात लाइसेंस सं. पी/जेड/0411713 दिनांक 15-3-84 वास्ते रु. 20000 ड्राई फ्रूट (काजू और खजूरों के अतिरिक्त) के आयात हेतु जारी किया गया था

आवेदक फर्म ने यह सूचित किया है कि उक्त लाइसेंस की दोनों कॉपियां बिना किसी कस्टम अधिकारी के पास पंजीकृत किये एवं बिना उपयोग किये ही कहीं खो गई है/अस्थानस्थ हो गई है।

आवेदक फर्म ने इस कथन के समर्थन में अब एक शपथ-पत्र आयात निर्यात की कार्य निधि पुस्तिका 1984-85 के पैरा 352 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

मैं संतुष्ट हूँ कि उक्त आयात लाइसेंस की मूल कस्टम एवं एक्सचेंज कापी खो गई है/अस्थानस्थ हो गई है।

1146 GI/84—2

अतः आयात-व्यापार नियंत्रण आदेश 1955 दिनांक 7-12-55 (यथा संशोधित) की धारा 9 (डी) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं उपरोक्त लाइसेंस सं. 0411713 दिनांक 15-3-84 की दोनों कापी को निरस्त करने का आदेश देता हूँ।

आवेदक की प्रार्थना पर अब आयात-निर्यात की कार्यनिधि-पुस्तिका 1984-85 के पैरा 352 के अनुसार उक्त लाइसेंस सं. 0411713 दिनांक 15-3-84 की कस्टम एवं एक्सचेंज कापी की अनुलिपि (डूब्लीकेट कापी) जारी करने पर विचार किया जायेगा।

[सं. ड्राई फ्रूट/2474/ए.एम. 84/ए.यू. III-(सी एल ए)]
डा. आर. के. धवन, उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

कृते, संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

(Office of the Joint Chief Controller of Imports & Exports)
(Central Licensing Area)

New Delhi, the 18th August, 1984

CANCELLATION ORDER

S.O. 4230.—M/s. Kusum Kochar, A-329, New Subzi Mandi Azadpur, Delhi was granted Import Licence No. P/Z/0411713 dated 15-3-84 for Rs. 20,000 for import of Dry Fruits (excluding Cashew Nuts and Dates). The firm have reported that both the copies of the same have been lost/misplaced without having been registered with any Customs Authority and unutilised at all.

The applicant firm has filed an affidavit in support of the above statement as required under para 352 of Hand Book of Import Export Procedure 1984-85. I am satisfied that the original Customs purpose and Exchange purpose copies of the said licence have been lost/misplaced.

In exercise of the powers conferred on me under section 9(D) of Import Trade Control order 1955 dated 7-12-1955 as amended, I order the cancellation of both copies of the said licence.

The applicant's case will now be considered for the issue of Duplicate Licence (Custom and Exchange Copies) in accordance with para 352 of Hand Book of Rules and procedure 1984-85.

[No. Dry Fruit/2474/AM-84/AU-III/CLA]

DR. R. K. DHAWAN, Dy. Chief Controller of Imports & Exports

For Jt. Chief Controller of Imports & Exports

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 1984

निरस्त आदेश

का. आ. 4231.—सर्वश्री सार्थो इन्टरनेशनल एक्सपोर्ट, सी-122, ईस्ट आज़ाद नगर की एक लाइसेंस सं. ए. पी. के/3023882 दिनांक 1983-84 वास्ते रु. 6200 अप्रैल मार्च 84 की आयात नीति के परिशिष्ट 17 में वर्णित हुए कालम वार के मदों हेतु शुप ओ-1 के अन्तर्गत जारी किया गया था।

आवेदक फर्म ने यह सूचित किया है कि लाइसेंस की दोनों कॉपियां बिना किसी कस्टम अधिकारी के पास पंजीकृत किये हुए एवं बिना उपयोग किये हुए आंशिक रूप से जल गई है। उन्होंने लाइसेंस की दोनों कॉपियां निरस्त करने हेतु समर्पित कर दी है।

अतः आयात व्यापार नियंत्रण अधिनियम, 1955 दिनांक 7-12-55 (यथा-संशोधित) की धारा 9 (डी) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं उपरोक्त लाइसेंस नं० 3023882 दिनांक 14-3-84 की मूल कस्टम एवं एक्सचेंज दोनों कापी को निरस्त करने का आदेश देता हूँ।

आवेदक प्रार्थना पर अब आयात-निर्यात की कार्यविधि-मुस्तका 1984-85 के पैरा 353 के अनुसार उक्त लाइसेंस नं० 3023882 दिनांक 14-3-84 की कस्टम एवं एक्सचेंज दोनों कापी को अनुलिपि (डुप्लीकेट कापी) जारी करने पर विचार किया जाएगा।

[सं० आर एच से/45/008631/ए जे-83/आर ई व्-2/
मं. एन ए-2013]

एस० एल० चौहान, डप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात
हुते संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

New Delhi, the 9th November, 1984

CANCELLATION ORDER

S.O. 4231.—M/s. Sanro International Export, C-122, East Azad Nagar, Licence No. P/K-3023882 dated 14-3-1984, for Rs. 6200 for items mentioned in Col. 4 against group 0.1 in Appendix 17 of AM-84 Import Policy. The firm have reported that both the copies of the same have been partly burnt out without having been registered with any Customs Authority and un-utilised at all. They have also surrendered both copies of the licence for cancellation.

In exercise of the powers conferred on me under section 9(d) of Import Trade Control Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended, I order the cancellation of both copies of the said licence.

The applicant's case will now be considered for the issue of Duplicate Licence(s) (Customs and Exchange Copies) in accordance with para 353 of Hand Book of Rules and Procedure 1984-85.

[RMC-65/008631/AJ-83/REP II/CLA-2013]

S. L. CHOHAN, Dy. Chief Controller of
Imports and Exports
for Jt. Chief Controller of Imports and Exports

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1984

का० आ० 4232:—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 28 की उप-धारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मै० इंजीनियरिंग कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय, लार्सन एण्ड टोबो हाउस, नरोत्तम मोरारजी मार्ग, बैलार्ड एस्टेट, बम्बई-400001, के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या 329/70 के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

[सं० 16/21/84एम-3]

वी० पी० गुप्त, निदेशक

MINISTRY OF INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS
(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 20th November, 1984

S.O. 4232.—In pursuance of sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969, (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M/s. Engineering Construction Corporation Limited, having its registered office at L&T House, Narottam Morarji Marg, Ballard Estate, Bombay-400001, under the said Act (Certificate of Registration No. 329/70).

[No. 16/21/84-M, III]
V. P. GUPTA, Director

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1984

का० आ० 4233:—राजनयिक एवं कोसली अधिकारी (गणप एवं शुल्क) अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (ख) के अनुपालन में केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा, पनामा स्थित भारतीय राजदूतावास में सहायक श्री जे० विजय कुमार को 29-10-84 में कोसली एजेंट का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[सं० टी० 4330/2/84]

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 16th November, 1984

S.O. 4233.—In pursuance of the clause (a) of Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorise Shri J. Vijaykumar, Assistant in the Embassy of India, Panama to perform the duties of Consular Agent with effect from 29th October, 1984.

[No. T-4330/2/84]

का० आ० 4234:—राजनयिक एवं कोसली अधिकारी (गणप एवं शुल्क) अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (क) के अनुपालन में केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा, पेरिस स्थित भारतीय राजदूतावास में सहायक श्री के० के० कुमार को 5 नवम्बर, 1984 से कोसली एजेंट का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[सं० टी० 4330/2/84]

बी० आर० घुलानी, उप-मन्त्रि

S.O. 4234.—In pursuance of the clause (a) of Section 2 of Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorise Shri K. K. Kumar, Assistant in the Embassy of India, Paris to perform the duties of Consular Agent with effect from 5th November, 1984.

[No. T-4330/2/84]

B. R. GHULIANI, Dy. Secy.

संस्कृति विभाग

(भारतीय पुरातत्व विभाग)

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1984

(पुरातत्व)

का० आ० 4235:—केन्द्रीय सरकार ने, भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 7 जनवरी, 1984 के पृष्ठ 19 पर प्रकाशित भारत सरकार के संस्कृति विभाग (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की अधिसूचना सं० का० आ० 27, तारीख 24 दिसम्बर 1983 द्वारा, इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने में अपने आशय की दो मास की सूचना दी थी, और उक्त अधिसूचना की एक प्रति प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षा अनुसार उक्त प्राचीन संस्मारक के समीप एक सहज-दृश्य स्थानी पर लगा दी गई थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ 9 जनवरी, 1984 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार का जनता से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः केन्द्रीय सरकार, अब उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपायुक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त प्राचीन संस्मारक का राष्ट्रीय महत्व का घोषित करती है।

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	परिच्छेद	संस्मारक का नाम	संरक्षण में लिया गया राजस्व मक्यांक	क्षेत्रफल	सं. माप	स्वामित्व	टिप्पण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कर्नाटक	बेल्लारी	सिरुगुप्पा ग्राम	उडेगोलान	प्लॉट संख्या 181, 187 और 189 में स्थित विष्णु सहस्रनाम भूमि के साथ दो अशोक चट्टान शिला-लेखा	सर्वेक्षण प्लॉट 181, 187 और 189	13.30 हेक्टर	उत्तर—सर्वेक्षण प्लॉट सं० 180, 188 और 191 पूर्व—सर्वेक्षण प्लॉट सं० 197 दक्षिण—सर्वेक्षण प्लॉट सं० 182, 183, 184 और 185 पश्चिम—सर्वेक्षण प्लॉट सं० 177 (नाला)	निजी	भूतन्त्र

[सं० 2/14/82-एम०]

DEPARTMENT OF CULTURE

(Archaeological Survey of India)

New Delhi, the 24th November, 1984

(ARCHAEOLOGY)

S.O. 4235.—Whereas by the notification of the Government of India, Department of Culture (Archaeological Survey of India), No. S.O. 77, dated the 24th December, 1983 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 7th January, 1984, at page 19, the Central Government gave two months' notice of its intention to declare the ancient monument specified in the Schedule annexed to that

notification to be of national importance, and a copy of the said notification was affixed in a conspicuous place near the said ancient monument, as required by sub-section (1) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 9th January, 1984; And whereas no objections have been received from the public by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby declares the said ancient monument specified in the Schedule annexed hereto to be of national importance.

SCHEDULE

State	District	Tehsil	Locality	Name of monument	Revenue plot numbers including under protection	Area	Boundaries	Ownership	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Karnataka	Bellary	Siruguppa	Udegolan Village	Two Ashokan Rock Edicts along with adjoining land comprised in survey plot Nos. 181, 187 and 189.	Survey plot Nos. 181, 187 and 189	13.30 Hectares	North:—Survey plot Nos. 180, 188, 190 and 191. East.—Survey plot No. 197. Suth.—Survey plot Nos. 182, 183, 184 and 185. West.—Survey plot No. 177 (Nala)	Private	Nil

[NO. 2/14/82—M]

का० आ० 4236:—केन्द्रीय सरकार ने भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 31 दिसम्बर, 1983 के पृष्ठ 5189 पर प्रकाशित, भारत सरकार के संस्कृति विभाग (भारतीय पुरात्व सर्वेक्षण) की अधिसूचना सं० का० आ० 4777 तारीख 13 दिसम्बर, द्वारा उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन संस्मारक की राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आशय की दो भाह की सूचना दी थी, और उक्त अधिसूचना की एक प्रति प्राचीन, संस्मारक तथा परातत्वीय स्थल अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 उपधारा (1) की अपेक्षा के अनुसार उक्त प्राचीन संस्मारक के समीप एक सहज दृश्य स्थान पर लगा दी गई थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 3 जनवरी, 1984 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार को जनता से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, अब उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त प्राचीन संस्मारक को जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, राष्ट्रीय महत्व का घोषित करती है।

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	परिक्षेत्र	संस्मारक का नाम	संरक्षण में लिया गया राजस्व प्लॉट संख्याक	क्षेत्रफल	परिसीमाएं	स्वामित्व	टिप्पण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उत्तर प्रदेश	चमोली	चमोली	मंडल	सर्वेक्षण सं० 89 में शिलालेख	रास्ते से पश्चिम में 30' X 30' माप का सर्वेक्षण प्लॉट सं० 89 का भाग	30' X 30' .008 हेक्टर	उत्तर—सर्वेक्षण प्लॉट सं० 89 का शेष भाग पूर्व—सर्वेक्षण प्लॉट संख्या 89 का शेष भाग दक्षिण—सर्वेक्षण प्लॉट सं० 89 का शेष अंश और रास्ता पश्चिम—सर्वेक्षण प्लॉट संख्या 89 का शेष भाग	वन विभाग उत्तर प्र०	ग्राम

[सं० 2/1/यू० प०/2/67-एम०]

एम० एस० मागराजा राब, महानिदेशक एवं पब्लिसिङ्ग सचिव

S.O. 4236.—Whereas by the notification of the Government of India, Department of Culture (Archaeological Survey of India), No. S.O. 4777, dated the 13th December, 1983 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 31st December, 1983 at page 5189, the Central Government gave two months' notice of its intention to declare the ancient monument specified in the Schedule annexed to that notification to be of national importance, and a copy of the said notification was affixed in a conspicuous place near the said ancient monument, as required by sub-section (1) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 3rd January, 1984;

And whereas no objections have been received from the public by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby declares the said ancient monument specified in the Schedule annexed hereto to be of national importance.

SCHEDULE

State	District	Tehsil	Locality	Name of monument	Revenue plot numbers included under protection	Area	Boundaries	Ownership	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Uttar Pradesh	Chamoli	Chamoli	Village Mandal	Rock Inscription in survey plot No. 89.	Part of survey plot No. 89 measuring 30' X 30' to the west of the pathway	30' X 30' .008 Hectares	North:—Remaining portion of survey plot No. 89 East:—Remaining portion of survey plot No. 89. South:—Remaining portion of survey	Forest Department Uttar Pradesh	Nil

plot No. 89
and pathway.
West:—Re-
maining portion
of survey plot
No. 89.

[No. 2/1/UP/2/67—M]

M. S. NAGARAJA RAO, Director General and Ex-Officio Joint Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

(संपदा निदेशालय)

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1984

का०भा० 4237.—राष्ट्रपति, मूल नियमों के नियम, 45 के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत सरकार के तत्कालीन निर्माण, आवास और पुनर्वास (निर्माण और आवास विभाग) की अधिसूचना सं०का०भा० 1533 तारीख 25 मई, 1963 का निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की मद सं० (2) में “कलकत्ता से, कलकत्ता नगर निगम की सीमाओं के भीतर आने वाला क्षेत्र अभिप्रेत है” शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात्:—

“कलकत्ता” से, कलकत्ता नगर निगम की सीमाओं के भीतर आने वाला ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसका विस्तार गार्डन रोच नगर पालिका और दक्षिणी अन्तर्गत नगरपालिका अर्थात्, बहाला, हावड़ा नगरपालिका (जिसके अन्तर्गत शिबपुर और बाली है) साल्ट लेक और बड़ानगर नगर पालिका, उत्तरी हमदम, हमदम और दक्षिणी हमदम नगरपालिकाएं जिसके अन्तर्गत लेकटाउन और बागुईहाटी के अधीन आने वाले क्षेत्र हैं” ।

[सं० डी-11029/44/82-रीजन्स]

बी०एस०रामन, उप निदेशक (संपदा)

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

(Directorate of Estates)

New Delhi, the 24th November, 1984

S.O. 4237.—In pursuance of the provisions of the rule 45 of the Fundamental Rules, the President hereby makes the following amendments to the notification of the Government of India in the late Ministry of Works, Housing and Rehabilitation (Department of Works and Housing) S.O. No. 1533 dated the 28th May, 1963, namely:—

In the said notification, in item No. (2) for the words “Calcutta means the areas included within the limits of the Municipal Corporation of Calcutta” the following words shall be substituted, namely:—

“Calcutta means the areas included within the limits of Municipal Corporation of Calcutta as extended upto Garden Reach Municipality and South Suburban Municipality—i.e. Behala, Howrah Municipality (including Shibpur and Bally) Salt Lake and the

areas falling under Baranagar Municipality, North Dum Dum, Dum Dum and South Dum Dum Municipalities including Lake Town and Baguihati.”

[F. No. D-11029/44/82-Regions]

V. S. RAMAN, Dy. Director of Estates

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, 26 सितंबर, 1984

आदेश

का. आ 4238.—केन्द्र सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1953 का 65) के साथ पठित विकास परिषद (कार्यविधि) नियम 1952 के नियम 3, 4 और 5 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस आदेश की तारीख से 2 वर्षों की अवधि के लिए एल्यूमिनियम उद्योग हेतु विकास परिषद स्थापित करती है और निम्न-लिखित व्यक्तियों को उक्त परिषद के सदस्य नियुक्त करती है:—

एल्यूमिनियम उद्योग हेतु विकास परिषद्

1. सचिव,

इस्पात एवं खान मंत्रालय,
(खान विभाग) शास्त्री भवन,
नई दिल्ली—अध्यक्ष ।

(क) एल्यूमिनियम के प्राथमिक उत्पादक

2. महानिदेशक,

मै. नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि.,
मुम्बई-2 ।

3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,

भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि.,
पूँज हाऊस, 18 नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली ।

4. प्रबंध निदेशक

इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लि.,
यूको बैंक बिल्डिंग, संजय मार्ग,
नई दिल्ली ।

5. अध्यक्ष,

हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कार्पोरेशन लि.,
यूको बैंक बिल्डिंग, संजय मार्ग,
नई दिल्ली ।

6. प्रबंध निदेशक,

मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लि.
98, मद्रास पीटर्स रोड,
मद्रास-600086

भागीदार एसोसिएशन

ख. एल्यूमिनियम के उपभोक्ता

7. अध्यक्ष,
इंडियन नाल-फेरस मेटल मेन्युफेक्चर्स एसोसिएशन,
द्वारा बम्बई चेम्बर्स ऑफ कामर्स और इंडस्ट्री,
मेकिनन मैकिनजी बिल्डिंग, बलार्ड एस्टेट,
बम्बई-400 038
8. अध्यक्ष,
केवल एंड कंडक्टर मेन्युफेक्चर्स एसोसिएशन आफ इंडिया,
308, मानसरोवर 90, नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली।
9. अध्यक्ष,
इंडियन इलेक्ट्रिकल मेन्युफेक्चर्स एसोसिएशन,
501, काकड चेम्बर्स, 132, डा. एनो वेस्ट रोड,
वरली, बम्बई-400 019।
10. महा सचिव,
नेशनल एलाइंस आफ यंग एंटरप्रायर्स,
301-302 सरस्वती भवन, 28 नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली-110 019
11. अध्यक्ष,
फेडरेशन आफ एसोसिएशन आफ म्यान इंडस्ट्रीज आफ इंडिया,
23 बी/2, नुन गोविन्दसिंह मार्ग,
नई दिल्ली-110005
12. अध्यक्ष,
आल इंडिया एल्यूमिनियम एक्वेटेशन मेन्युफेक्चर्स,
द्वारा मै. मद्रासीर एल्यूमिनियम लि.,
1603, निर्मल टावर, बाराबंसा रोड,
नई दिल्ली।
- ग. तकनीकी प्राधिकारी
13. महानिदेशक,
तकनीकी विकास उद्योग भवन,
नई दिल्ली।
14. अध्यक्ष,
औद्योगिक तागत एवं मूल्य बोर्ड,
आल नेशनल भवन, नई दिल्ली।
15. अध्यक्ष,
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, सेवा भवन, आर. के. पुरम,
नई दिल्ली।
16. विज्ञान आयुक्त,
नव उद्योग, निर्माण भवन,
नई दिल्ली।
- घ. आयातक एजेंसी
17. अध्यक्ष,
खनिज व धातु व्यापार निगम,
एकतरेस बिल्डिंग, बराडुर गार्ड जंक्शन मार्ग,
नई दिल्ली।
- ङ. सरकारी अधिकारी
18. सलाहकार (उद्योग एवं खनिज),
योजना आयोग, योजना भवन,
नई दिल्ली।
19. संयुक्त सचिव,
प्रभारी एल्यूमिनियम उद्योग
भवन विभाग, नई दिल्ली।

20. संयुक्त सचिव,
प्रभारी एल्यूमिनियम आयात,
वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली
21. संयुक्त सचिव,
विद्युत विभाग,
नई दिल्ली।
22. संयुक्त सचिव,
प्रभारी (विदेशी मूद्रा बजट),
आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।
23. आयुक्त,
कर गवेषण विभाग,
राजस्व विभाग, नई दिल्ली
24. निदेशक एवं नियंत्रक,
एल्यूमिनियम खान विभाग,
नई दिल्ली।

[संख्या 8/1/83-मेटल-5/मेटल-1]
विजय कुमार पापर, संयुक्त सचिव।

MINISTRY OF STEEL & MINES

(Department of Mines)

New Delhi, the 26th September, 1984

ORDER

S.O. 4238.—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) read with rules 3, 4 and 5 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby establishes a Development Council for Aluminium Industry for a period of two years with effect from the date of this Order and appoints the following persons to be members of the said Council, namely :—

DEVELOPMENT COUNCIL FOR ALUMINIUM INDUSTRY

1. Secretary,
Ministry of Steel and Mines,
(Department of Mines),
Shastri Bhavan, New Delhi—Chairman

A. PRIMARY PRODUCERS OF ALUMINIUM :

2. Managing Director,
M/s. National Aluminium Co. Ltd.,
Bhubaneswar.
3. Chairman-cum-Managing Director,
Bharat Aluminium Company Limited,
Punj House, 18, Nehru Place,
New Delhi.
4. Managing Director,
Indian Aluminium Company Limited,
UCO Bank Building,
Parliament Street,
New Delhi.
5. President,
Hindustan Aluminium Corporation Limited,
UCO Bank Building, Parliament Street,
New Delhi.
6. Managing Director,
Madras Aluminium Company Limited,
98, Peters Road,
Madras-600086.

ASSOCIATIONS REPRESENTING :

B. Consumers of Aluminium :

7. President,
Indian Non-Ferrous Metals Manufacturers' Assn.,
C/o Bombay Chamber of Commerce & Industry,
Mackinnon Mackenzie Building,
Ballard Estate,
Bombay-400038.
8. President,
Cable & Conductor Mfrs' Association of India,
308, Mansarovar 90, Nehru Place,
New Delhi.
9. President,
Indian Electrical Manufacturers' Association,
501, Kakad Chambers,
132, Dr. Annie Mesant Road, Worli,
Bombay-400019.
10. Secretary General,
National Alliance of Young Entrepreneurs,
301-302, Saraswati Bhavan,
28, Nehru Place,
New Delhi-110019.
11. President,
Federation of Association of Small Industries of
India,
23-B/2, Guru Gobind Singh Marg,
New Delhi-110005.
12. President,
All India Aluminium Extrusion Mfrs' Association,
C/o M/s. Mahavir Aluminium Limited,
1603, Nirmal Tower,
Borakhamba Road,
New Delhi.

C. Technical Authorities :

13. Director General, Technical Development, Udyog
Bhavan, New Delhi.
14. Chairman,
Bureau of Industrial Costs & Prices, Loknaya
Bhavan,
New Delhi.
15. Chairman,
Central Electricity Authority,
Sewa Bhawan, R. K. Puram,
New Delhi.
16. Development Commissioner,
Small Scale Industries, Nirman Bhavan,
New Delhi.

D. Importing Agency :

17. Chairman,
The Minerals and Metals Trading Corpn. of India,
Limited,
Express Building,
Bhadur Shah Zafar Marg,
New Delhi.

E. Government Officials :

18. Adviser (Industry & Minerals),
Planning Commission, Yojana Bhavan,
New Delhi.
19. Joint Secretary in charge of Aluminium Industry,
Department of Mines,
New Delhi.
20. Joint Secretary in charge of aluminium import,
Ministry of Commerce,
New Delhi.

21. Joint Secretary,
Department of Power,
New Delhi.

22. Joint Secretary,
in charge of Foreign Exchange Budget,
Department of Economic Affairs,
New Delhi.

23. Commissioner,
Tax Research,
Department of Revenue,
New Delhi.

24. Director and Controller of Aluminium, Department
of Mines,
New Delhi.

... Member Secy.

[No. 8/1/83-Met. V/Met. II]

V. K. THAPAR, Jt. Secy.

खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग

नागरिक पूर्ति विभाग

नई दिल्ली 17 जुलाई, 1984

का.आ. 4239.—अग्रिम संविदा (विनियमन) अधि-
नियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 3 की उपधारा
(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय
सरकार इसके द्वारा नागरिक, पूर्ति विभाग में आर्थिक सलाह-
कार डा.पी.एन. कौल को उनके मौजूदा कार्य के अलावा
वायदा बाजार आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियमित नियुक्ति
होने तक 5 जून, 1984 के पूर्वानु से उक्त आयोग के
सदस्य के रूप में नियुक्त करती है तथा साथ ही आयोग का
अध्यक्ष भी नामित करती है।

[संख्या ए-38011/1/84-प्रशा. II]

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

New Delhi, the 17th July, 1984

S.O. 4239.—In exercise of the powers conferred by sub-
section (2) of Section 3 of the Forward Contracts (Regula-
tion) Act, 1952 (74 of 1952), the Central Government here-
by appoints Dr. P. N. Kaul, Economic Adviser in the De-
partment of Civil Supplies, as a Member of the Forward
Markets Commission and also nominates him to be the
Chairman of that Commission with effect from the fore-
noon of 5th June, 1984, in addition to his present duties,
pending appointment of a regular officer for the post of
Chairman, Forward Markets Commission.

[File No. A-38011/1/84-Estt. II]

का.आ. 4240.—अग्रिम संविदा (विनियमन) अधि-
नियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 3 की उपधारा
(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय
सरकार वायदा बाजार आयोग, बम्बई के अध्यक्ष के रूप में
भारतीय आर्थिक सेवा के श्री बी. नन्जुनदेया की सेवाओं को
31 मई, 1984 को उनके सेवा निवर्तन की तारीख के
बाद से 4 दिनों की अवधि अर्थात् 1-6-1984 से 4-6-1984
तक बढ़ती है। श्री बी. नन्जुनदेया ने 5-6-1984 (पूर्वानु) से
वायदा बाजार आयोग बम्बई के अध्यक्ष तथा सदस्य का
कार्यभार छोड़ दिया है।

[संख्या ए-38011/1/84-प्रशा. II]

ओ. पी. मखीजा, अवर सचिव

S.O. 4240.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), the Central Government extends the service of Shri B. Nanjundaiya, IES, as Chairman, Forward Markets Commission, Bombay, beyond the date of his superannuation on 31st May, 1984 for a period of 4 days,

ie. from 1-6-1984 to 4-6-1984. Shri B. Nanjundaiya relinquished charge as Member and Chairman of the Forward Markets Commission, Bombay with effect from 5-6-1984 (FN).

[File No. A-38011/1/84-Estt. II]

O. P. MAKHIJA, Under Secy.

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 1984-10-30

क्र० प्रा० 4241.—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन वि०) विनियम, 1955 के विनियम 8 के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जिन 100 लाइसेंसों के विवरण नीचे अनुसूची में दिये गये हैं, वे लाइसेंसधारियों को मानक सम्बन्धी मुहर लगाने का अधिकार देते हुए, फरवरी 1981 में स्वीकृत किये गये हैं :

अनुसूची

क्रम सं० लाइसेंस संख्या (सी एम/एल)	वैधता की अवधि से तक	लाइसेंसधारी का नाम और पता	लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया और पदनाम		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सी एम/एल-9367 1981 02 03	81 02 16 82 02 15	मेस इलेक्ट्रिकल्स (प्रा०) लि०, ए-23/बी, लेन नं० 4, भानुव पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली	विद्युत विकिरक, 1000 वाट और 2000 वाट IS : 369-1965		
2. सी एम/एल-9386 1981 02 03	81 02 16 82 02 15	इंडियन डेयरी इन्क्विपमेंट क०, एच-23, बाली-नगर, नई दिल्ली-110005	मक्खन भापी, 10 प्रतिशत स्केन IS : 1223 (भाग 1) — 1970		
3. सी एम/एल-9389 1981 02 03	81 02 16 82 02 15	दयाल फटिलाइजर्स प्रा० लि०, 10वां कि० मी०, दिल्ली रोड, परतापुर रेलवे स्टेशन के सामने, परतापुर, मेरठ (उ० प्र०) (कार्यालय : 118, धापरनगर, मेरठ-250001)	जिक सफ्टेट कृषि ग्रेड IS : 8249-1976		
4. सी एम/एल-9390 1981 02 03	81 02 16 82 02 15	मोदी स्टील्स, (प्र० मोदी इंडस्ट्रीज लि०), मोदीनगर, जि० गाजियाबाद, (उ० प्र०)	बढ़ाई के लिए कार्बन इस्पात के बिलेट सभी श्रेणियाँ— IS : 1875—1978		
5. सी एम/एल-9391 1981 02 04	81 02 16 82 02 15	विश्राम निर्दिग मिल्स, 5 बी, एम. एन. बी. एस. ले-आउट, कांगूनगर मेन रोड, लिखपर-638602 (त. ना.)	सावा बुनी सूती बनिायों, टाइप : भार एन और भार एन एस साइज : 75 से 90 से. मी. नाप-24— IS : 4964 (भाग 2)—1975		
6. सी एम/एल-9392 1981 02 05	81 02 16 82 02 15	भारत स्टील इंडस्ट्रीज, ए-1 से ए-3 इंडस्ट्रियल इस्टेट, मौला घासी, हैदराबाद 500040 (कार्यालय 5-5-22, रानीगंज, मिक्तन्दाबाद-500003)	इस्पात जिड़की सेक्शन एफ 4 बी और टी 2— IS : 7452—1974		
7. सी एम/एल-9393 1984 02 05	81 02 16 82 02 15	विशेष एम्रो इंडस्ट्रीज, एफ-439, रोड नं० 12, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर-302013	संझास और पेगाबवानों के लिए क्लब टंकिया 10 लीटर और 12.5 लीटर समारि-वाली— IS : 774—1971		
8. सी एम/एल-9394 1981 02 06	81 02 16 82 02 15	अरुण इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज (प्रा०) लि०, शांतिनगर कोआप. इंडस्ट्रियल इस्टेट, बकोला, साप्ताकुज (ईस्ट), मम्बाई-400055	एक फेजी ए सी बिजली की छोटी मोटों, 0.75 किलो वोल्टी "ई" रोड वाली 1— IS 966—1964		
9. सी एम/एल-9395 1481 02 06	81 02 16 82 02 15	तोणीबा भालन्द बैटरीज लि०, एच. एम. टी. रोड, कालामासेरी, जिला एर्नाकुलम (केरल), (कार्यालय : 36/894 महात्मा रोड, एर्नाकुलम, कोचीन-682011)	भारी काम शुक्ल बैटरियां, पदनाम : भार 20— IS : 9128—1979		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10. सी एम/एल-9396 1981 02 06	81 02 16	82 02 15	बिकटरी बैटर्स, रेलवे स्टेशन के निकट, बला- कुडी-680307	बाय का पेटिबों के लिए प्लाईवुड की पट्टियां— IS 10 (भाग 3)—1974	
11. सी एम/एल-9397 1981 02 06	81 02 16	82 02 15	शाह स्टील इंडस्ट्रीज, बम्बई-अहमदाबाद एक्स- प्रेस हाईवे, ग्राम सावित्री, तानुक-बनीन, जिला धाना (कार्यालय: वेब प्रकाश, रोशन नगर रोड, बोरीवली (वेस्ट) बम्बई-400092)	टेलीग्राम और टेलीफोन प्रयोजनों के लिए अस्सीकृत इस्पात तार— IS: 279-1922	
12. सी एम/एल-9398 1981 02 09	81 02 16	82 02 15	पी. एन. एम. कम्पनी, पेरनदुराई मेन रोड, ऐरोड-638009 (त. ना.) (कार्यालय : 60 टी 5 एम. के. सी. रोड, ऐरोड- 638009)	हाइड्रोथोट पायबनीन धातु— IS: 3803—1975	
13. सी एम/डी-9399 1981 02 09	81 02 16	82 02 15	कनाटिक सोप एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स लि० (पू० पू०, गवर्नमेंट सोप फैक्टरी), डिस्ट्रिब्यूटर्स प्लांट, इंडस्ट्रियल सबर्ब, राजाजी नगर, बंगलोर- 560055 (कनाटिक)	घरेलू इस्तेमाल के लिए बुलाई के संश्लिष्ट पाउडर, केवल ग्रेड 1— IS: 4955—1978	
14. सी एम/एल-9400 1981 02 09	81 02 16	82 02 15	हर्षि केमिस्ट प्रा० लि०, 63/2 सरकारी, जय- नगर (दक्षिण) बंगलोर-560078 (कनाटिक)	बी एच सी (एच सी एच) जल परिलेपी पाउडर साम्र— IS: 562—1978	
15. सी एम/एल-9401 1981 02 09	81 02 16	82 02 15	एम. पी. गैस इन्विजमेंट प्रा० लि०, 1 ए/1, जी आई डी सी इंडस्ट्रियल इस्टर, पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 8, भद्रक (गुजरात) (कार्यालय : 53-57, लक्ष्मी इन्वोरेस बिल्डिंग, सर पी एम रोड, बम्बई- 400001)	5 मीटर से अधिक तमाई वाले नव निर्मित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस सिलिंडरों के लिए वाल्स फिटिंग— IS: 8737 (भाग 2)—1978	
16. सी एम/एल-9402 1981 02 09	81 02 16	82 02 15	एरोस्ट कास्टो सिलिंडर प्रा० लि०, ई-22, एम आई डी सी इंडस्ट्रियल एरिया, चिबल- बागा, धीरंगाबाद (महाराष्ट्र) (कार्यालय : 10, मैरीन चैम्बर्स, 42 न्यू मैरीन लाइम्स, बम्बई-400025)	सिंकर और उच्च दबाव द्रवणीय गैसों के लिए निम्नलिखित टाइप और तमाई की मैगनीज इस्पात के सीबन हीन सिलिंडर 3, 4, 10.2 और 14.0 मीटर पानी की तमाई वाले (आक्सीजन, कार्बन- डाइऑक्साइड, नाइट्रिक, प्रोक्साइड)— IS: 7285; 1974	
17. सी एम/एल-9403 1981 02 09	81 02 16	82 02 15	बी एल्सी एंड केमिकल्स कार्पोरेशन प्रा० इंडिया लि०, 10, जी. टी. रोड, डा० रिशरा जि० हुगली (पश्चिमी बंगाल) (कार्यालय : 34, चौरीजी रोड, कलकत्ता-700071)	बी एच सी (एच सी एच) जल परिलेपी पाउडर साम्र— IS 562; 1978	
18. सी एम/एल-9404 1981 02 09	81 02 16	82 02 15	एम. एम. इंडस्ट्रीज, 133, ग्रांड फोरलोर रोड, हावड़ा (प० ब०) (कार्यालय : 130, काटन स्ट्रीट, कलकत्ता-700007)	380 ग्राम/एम ² 68×39 (14 ओंस/45 इंच 8×15) तिरपाल के कपड़े से निर्मित पटसन के परतदार बीले— IS: 7406 (भाग 2)—1980	
19. सी एम/एल-9405 1981 02 09	81 02 16	82 02 15	स्वास्तिक लेमिनेटिंग इंडस्ट्रीज, 95/1/38, कोसीपुर रोड, कलकत्ता-700002 (प० ब०) (कार्यालय : 68, काटन स्ट्रीट, कलकत्ता-700007)	380 ग्राम/एम ² 68×39 (14 ओंस/45 इंच 8×10) तिरपाल के कपड़े से निर्मित पटसन के परतदार बीले— IS: 7406 (भाग 2)—1980	
20. सी एम/एल-9406 1981 02 09	81 02 16	82 02 15	डोमेस्टिक एप्लायेंसिज, 1522/328, बम्बुदयाल बाग, धीरंगा इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली- 110020	5 मीटर, 6 मीटर, 8.5 मीटर और 7.5 मीटर साइजों के घरेलू प्रेशर कुकर— IS: 2347—1974	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21. सी एम/एल-9407 1981 02 09	81 02 16	82 02 15	सूर्य केबल्स, गली नं० 9, समयपुर बादली, दिल्ली-110042	1100 बोल्ड तक की कार्यकारी बोल्डता के लिए पी वी सी रोहित केबल और नम्य रस्ते, बोलदार और बोलरहित, केबल तांबे के बालकों वाले (बहिरंग उपयोग और कम तापमान अवस्थाओं के केबलों को छोड़कर) IS : 694--1977	
22. सी एम/एल-9408 1981 02 09	81 02 16	82 02 15	गुप्ता केमिकल्स प्रा० लि०, बी-144, रोड नं० 9, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल इस्टेट, जयपुर- 302013 (राजस्थान) (कार्यालय : भुब- मरिया बिन्दिग सिपोलिया बाजार, जयपुर 302002)	9. कार्बेगिल शूलन पा डर-- IS : 7122--193	
23. सी एम/एल-9409 1981 02 09	81 02 16	82 02 15	श्री कस्तूरी निटर्स, 18 हाई रोड, तिरुपुर- 638602 (त. ना.)	मादा कुनी सूती बनियाने-टाइप : भार एन और भार एल एवं साइज : 75 से 90 सेमी, नाप : 24-- IS : 4964 (भाग 2)--1975	
24. सी एम/एल-9410 1981 02 10	81 02 16	82 02 15	कोसन मेटल प्राइवट्स प्रा० लि०, बम्बई फूड्स प्रीमाइजिज, कसारगाम, सुरत-395004 (गुजरात) (कार्यालय : 53-57, लक्ष्मी इंस्टोरेस बिन्दिग सर पो. एम. रोड, बम्बई-400001)	5 मीटर से अधिक समझी वाले तबनिमित द्रवीकृत पेट्रोसियम गैस मिलिन्डरो में इस्ते- माल के लिए बाल्व फिटिंग-- IS : 8737 (भाग 2)--1978	
25. सी एम/एल-9411 1981 02 10	81 02 16	82 02 15	मिल्क प्राइवट्स फेक्टरी, (ग्रामध्र प्रदेश डेयरी डवलपमेंट कारपोरेशन लि०, की यूनिट), बिसूर-517002	मंसाधित पनीर-- IS : 2785--1979	
26. सी एम/एल-9412 1981 02 10	81 02 16	82 02 15	मधुसूदन सिरेमिक्स, (प्रो० मधुसूदन बेजीटेबल प्राइवट्स कं० लि०, काडी-382715) जि० मेहसाणा (उ० प्र०)	1. लम्बे नमूने के बिठाव कुंड, साइज : 580 मिमी, 2. उड़ीसा नमूने के बिठाव कुंड साइज : 580 मिमी × 440 मिमी. 3. बाण बेसिन, जपटे प्लठ वाली और पीटिका साइज : 450 मिमी × 300 मिमी तथा 550 मिमी × 400 मिमी IS : 2556 (भाग 1)--1974 IS : 2556 (भाग 3)--1973 IS : 2556 (भाग 4)--1972	
27. सी एम/एल-9413 1981 02 10	81 02 16	82 02 15	सचदेवा इंडस्ट्रीज, 1/421, गली नं० 5 फेडस कालोनी इंडस्ट्रियल एरिया, जी०टी० रोड, शाहदरा, दिल्ली-110032 (कार्यालय : 7270-71, पुरानी रोहतक रोड, भाजपुर मार्किट चौक के निकट, दिल्ली- 110006)	1100 बोल्ड तक की कार्यकारी बोल्डता के लिए पी वी सी रोहित केबल, बोलदार और बोलरहित तांबे और एलुमिनियम के बालकों वाले, बहिरंग, उपयोग और कम तापमान के लिए केबलों सहित-- IS : 694--1977	
28. सी एम/एल-9414 1981 02 10	81 02 16	82 02 15	अशोक धायरन एंड स्टील फेब्रिकेटर्स, मावडी प्लांट, राजकोट-360004 (गुजरात)	18 मीटर के बर्गाकार टिन-- IS : 916--1975	
29. सी एम/एल-9415 1981 02 10	81 02 16	82 02 15	सेफेक्स फायर सब्सिज, 202-ए, धनराज इंडस्ट्रियल इस्टेट, सन मिस रोड, लोभर परेल (वेस्ट), बम्बई-400013	मुवाहू रासायनिक अग्निशामक, सोडा एसिड टाइप-- IS : 934--1976	
30. सी एम/एल-9416 1981 02 10	81 02 16	82 02 15	निगरानिया मेटल एंड स्टील इंडस्ट्रीज, नयी बम्बई-आगरा रोड, नासिक-422001	संरचना इस्पात (साधारण किस्म)-- IS : 1977--1975 (ग्रुप 2)	
31. सी एम/एल-9417 1981 02 10	81 02 16	82 02 15	जैन स्टील इंडस्ट्रीज, जी०टी० रोड, मंडी गोबिन्दगढ़-147301 (पंजाब)	संरचना इस्पात (मानक किस्म)-- IS : 226--1975 (ग्रुप 2)	
32. सी एम/एल-9418 1981 02 10	81 02 16	82 02 15		संरचना इस्पात (साधारण किस्म)-- IS : 1977--1975 (ग्रुप 2)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33. सी एम/एल-9419 1931 02 10	81 02 16	82 02 15	बारी इंडस्ट्रियल प्राइवेट्स, 34/6, एस एम प्राई एरिया, तीसरा बौराहा, पांचवा ब्लाक, राजाजी नगर, बंगलौर-560010	बिजली लगाने के लिए सब्सिडी प्राधिकार प्राप्तियां, 20 मिमी साइज— IS : 2509—1973	
34. सी एम/एल-9420 1981 02 10	81 02 16	82 05 15	हिन्दुस्तान रोलिंग्स एंड बायर्स प्रा० लि० 41/4, बहालगाव-सोनीपत रोड, सोनीपत (हरियाणा) (कार्यालय : 2-ई/22, महेवालान एक्सटेंशन, नयी दिल्ली-110055)	कंक्रीट प्रबलन के लिए सख्त बिचा इस्पात का तार, सभी साइज— IS : 432 (भाग 2)—1966	
35. सी एम/एल-9421 1981 02 11	81 03 01	82 02 28	किमान केमिकल वर्क्स, जूनी जिघाडी, तालुक करजान 391240 जिला बड़ोदरा (गुजरात)	मलायियाँ धूलन पाउडर— IS : 2568—1978	
36. सी एम/एल-9422 1981 02 11	81 03 01	82 02 28	वीन पेस्टिमाइड्स प्रा० लि०, ए 1/422, जी. आई. डी. सी. मकनेश्वर-393002 (गुजरात)	ऐरोसोल्फाय पायसनीय साइज— IS : 4323—1967	
37. सी एम/एल-9423 1981 02 12	81 03 01	82 02 28	मार्बल स्टील एन्टर प्राइसेज, (प्रो : मार्बल रोलिंग मिल्स प्रा० लि०) 242/1, जी.टी. रोड (उत्तर) डा० घुमुरी, हावड़ा (कार्यालय : 9, जगमोहन मलिक लेन, कलकत्ता- 700007)	कंक्रीट प्रबलन के लिए ठंडी बनी उच्च सामर्थ्य इस्पात की विकृत धरिया— IS : 1786—1979 (ग्रुप 2)	
38. सी एम/एल-9424 1981 02 12	81 03 01	82 01 28	पंजाब मेटल वर्क्स, तकोदर रोड, जालंधर- 144001	जल सेवा के लिए जोड़ चुड़ी टोटियां साइज— 15 मिमी— IS : 2692—1978	
39. सी एम/एल-9425 1981 02 12	81 03 01	82 02 28	मिल्क प्राइवेट्स फैक्टरी, (ग्राम प्रदेन डेयरी डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० की यूनिट), बिल्लूर-517002 (घा.प्र.)	पीप्टिक और सपरेटा दूध का पाउडर— IS : 1165—1975	
40. सी एम/एल-9426 1981 02 13	81 03 01	82 02 28	चामुंडी स्टील री रोलिंग मिल्स, 7वां मोल, होसूर रोड, बंगलौर-560068	संरचना इस्पात (मानक किस्म)— IS : 226—1975	
41. सी एम/एल-9427 1981 02 13	81 03 01	82 02 28	"	संरचना इस्पात (साधारण किस्म)— IS : 1977—1975	
42. सी एम/एल-9428 1981 02 13	81 03 01	82 02 28	बी.सी. मैनुफैक्चरर्स प्रा. लि., ए-8 यूनिट 5, धम्बासूर इंडस्ट्रियल इस्टेट, मद्रास-600058 (त.ना.)	हथि कार्यों के लिए साफ, ठंडे, राजा पानी के लिए निम्नलिखित साइजों के मोनोब्लैट पम्प, साइज : 50 मिमी × 35 मिमी गति : 2820 चक्कर प्रति मिनट टाइप/माइल : सी पी 50 × 35, मोटर : 2.2 किवा, बोमी "ई", ड्यूटी प्वाइंट : 25 एम कीर्ष पर दिल्बाच, × 5.9 एम पी एस और कुल दक्षता × 402— IS : 6595—1972	
43. सी एम/एल-9429 1981 02 16	81 03 01	82 02 28	बायोमैंगरपेट बीबीस कोआपरेटिव सोसाइटी लि., नं० आर—633, सामाकल रोड, बायो मैंगरपेट (डा०) जि० बिबी-621214 (म०ना०)	हथकरघा की सूती धोतिया, किस्म नं. 7 और 8— IS : 748—1974	
44. सी एम/एल-9430 1981 02 16	81 03 01	82 02 28	गोताजलि निटिंग मिल्स, 30 बी, कोणनगर, मैन रोड, तिरुपुर-638602 (म०ना०)	सावा बुनी सूती धनियानें टाइप : आर एम और आर एम एस साइज : 75 से 100 सेमी नाप : 24— IS : 4964 (भाग 2)—1975	
45. सी एम/एल-9431 1981 02 16	81 03 01	82 02 28	हेमा निटिंग कम्पनी, 5 बी, रामनगर, दूसरी स्ट्रीट, तिरुपुर-638602 (त.ना.)	सावा बुनी सूती धनियानें टाइप : धार एम और धार एम एस साइज : 80 से 90 सेमी नाप : 24— IS : 4964 (भाग 2)—1975	
46. सी एम/एल-9432 1983 03 16	81 03 01	82 02 28	श्री गोपालकृष्ण मिल्स प्रा. लि., पी. बडुगा- पलायम, पल्लाडाम, जि. कोयंबटूर (त.ना.) (कार्यालय : "शाखा पल्लाडाम" गणपति (डा.))	होत्ररी के लिए भूरे रंग के सूती धागेकाउन्ट : 39 एस, कम्बड— IS : 834—1975	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
47. सी एम/एल-9433 1981 02 16	81 03 01	82 02 28	कार्मस पेस्ट कंट्रोल (प्रा.) लि., पारेवरला, गुन्दूर नागार्जुनसागर रोड, जि. गुन्दूर (भा.प्र.)	डी डी टी जल परिलेपी पाउडर सामग्री— IS : 565—1975	
48. सी एम/एल-9434 1981 02 16	81 02 16	82 02 15	केन इलेक्ट्रिकल्स, पो.बा. नं. 56, रानी बाग रीबी-486001 (म.प्र.)	क्रिरोपरि प्रेषण कार्यों के लिए ए एसी और एसी एस घाट चालक— IS : 398 (भाग 1 और 2)—1976	
49. सी एम/एल-9435 1981 02 16	81 02 16	82 02 15	भार. के. इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज (इंडिया) ए-47, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, फेज 1, नयी दिल्ली।	1100 वोल्ट तक कार्यकारी वोल्टता के लिए पोलीएथाइलीन रोहित और पोमी थिलीन छोल वाले एलुमिनियम चालकों वाले केबल बहिरंग इस्तेमाल के लिए उपयुक्त, कम ताप- मान में काम आने वाले केबलों को छोड़कर— IS : 1596—1977	
50. सी एम/एल-9436 1981 02 16	81 03 01	81 02 28	न्यू लाइट इंडस्ट्रीज, एस-9 अजय एक्सेस मार्केट नयी दिल्ली-110018	बेरल चिटचनियां (प्रलोह धातु की)— IS : 204 (भाग 2)—1978	
51. सी एम/एल-9437 1981 02 16	81 03 01	82 02 28	क्राफ्टन प्रीम्स लि०, (मशीन डिपोजीट), डा. ई. मसिज रोड, चोरमी, बम्बई-400018 (महाराष्ट्र) (कार्यालय : 1, डा. बी.बी. गांधी मार्ग, बम्बई-400023)	कृषि कार्यों के लिए साफ, ठंडे, ताजापानी के लिए निम्नलिखित साइजों के मोनोसेट पम्प : साइज : 63 मि मी × 50 मि मी 76 मि मी × 63 मि मी गति : 1410 चक्कर प्रति मिनट 1440 चक्कर प्रति मिनट टाइप/माडल : एम बी एन-3 डी एम बी डी-5 डी इयूटी प्वाइंट : 11 मी. शीर्ष पर डिस्चार्ज 560 लीटर प्रति मिनट, और कुल दक्षता × 40% 14.5 मी. शीर्ष पर डिस्चार्ज 800 लीटर प्रति मिनट और कुल दक्षता 48 प्रतिशत मोटर : 2.2 किवा 3.7 किवा— IS : 6596—1972	
52. सी एम/एल-9438 1981 02 16	81 03 01	82 02 28	बायो कल्चर मैनुफैक्चरिंग लेबोरेटरीज, 259 फेज IV, पीनिया इंडस्ट्रियल एरिया, पीनिया बंगलौर-560058 (कर्नाटक)	एजेंटोबक्टर क्लॉकम इनोक्यूलेट— IS : 9138—1979	
53. सी एम/एल-9439 1981 02 16	81 03 01	82 02 28	विम्येक्स एजेंसीज, 84, घठारहवां चौराहा, छठी मेन रोड, मल्लेश्वरम्, बंगलौर (कर्नाटक) कार्यालय : 8, 17-ए, काम, बारहवीं मेन रोड, मल्लेश्वरम्, बंगलौर-560055)	निम्नांकित फसलों के लिए रिजोबियम के टीके : लोभिया, मुंगफली, हरा चना और कावा चना :— IS : 8268—1976	
54. सी एम/एल—9440 1981-02-16	81-03-01	82-03-28	माइन सेप्टी एप्लायर्स लि०, 9, सैयद अमीर अली एवेन्यू, सूट नं० 2, चतुर्थतल, कलकत्ता-700017 (पं०बं०) (कार्यालय : 6 ए, हालपगान रोड, ऐतली, कलकत्ता-700014)	खानों में गैस परीक्षण के लिए ज्वाला सुरक्षा सैम्प— IS : 7577—1975	
55. सी एम/एल—9441 1981-02-16	81-03-01	82-02-28	श्री अमृत बचन सा मिस्ट, छत्रपुरी रोड, यमुना नगर-135001	बाय की पेटियों के लिए प्लाईवुड के गले— IS : 10 (भाग 3)—1974	
56. सी एम/एल—9442 1981-02-26	81-03-01	82-02-28	सुपर सफिल प्रा० लि०, बी-45, मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया, नयी दिल्ली-110064	अल्ट्राहाइड्रोजनों के लिए पिस्टन छल्ले (आर- रिंग), साइज : 62 मिमी तक— IS : 8422 (भाग 1)—1977	
57. सी एम/एल—9443 1981-02-16	81-03-01	82-02-28	विल्ली पेपर प्राइवेट्स कं०, 19, गुडगांव रोड, कापसहेडा, नयी दिल्ली-110037	दूरमुद्रक कागज के पृष्ठ रोल— IS : 9031—1979	

1	2	3	4	5	6
58. सीएम/एल—9444 1981-02-16	81-03-01	82-02-28	बीधरी सेटल इंडस्ट्रीज प्रा० लि०, प्लाट नं० 71, सेक्टर 6, फरीदाबाद (हरियाणा)	1100 बोल्ड तक की कार्यकारी बोल्डता के लिए पोबीसी रोहित केबल और नम्य रस्से, खोलदार और खोल रहित, केबल तांबे के बालकों वाले, (कम तापमान में काम आने वाले केबलों को छोड़कर) IS : 684—1977	
59. सीएम/एल—9443 1981-02-16	81-03-01	82-02-28	बोंडेड पैकेजिंग प्रा० लि०, 177/354, जो० टों रोड, राबतपुर, शा० कानपुर विश्व-विद्यालय, कानपुर-208024 (उ०प्र०)	380 ग्राम/वर्ग मीटर, 68×39 (14 औंस/45 इंच 8×10) तिरपाल के कपड़े से निर्मित पटसन के परतदार जैसे— IS : 7406 (भाग 2)—1980	
60. सीएम/एल—9446 1981-02-16	81-03-01	82-02-28	रायल कोल्ड रो रोसिंग मिल, 123/431 फजलगंज, कानपुर (उ०प्र०)	संरचना इस्पात (मानक किस्म)— IS : 226—1975	
61. सीएम/एल—9447 1981-02-16	81-03-01	82-02-28	रायल कोल्ड रो रोसिंग मिल, 123/431, फजलगंज, कानपुर (उ०प्र०)	संरचना इस्पात (साधारण किस्म)— IS : 1977—1975	
62. सीएम/एल—9448 1981-02-16	81-03-01	82-02-28	हितेन एंड कं०, मरायबेला, शा० कस्तूरबा आश्रम, जि० धनबाद (बिहार) (कार्यालय : मरिया-828111, जि० धनबाद (बिहार))	1. तार के रस्सों के तन्तु, कोइ के लिए स्नेहक, बिटुमनी प्रकार, 2. तार की लड़ों और रस्सों के लिए स्नेहक बिटुमनी प्रकार, 3. काम में लाए जा रहे रस्से को संवारने के लिए स्नेहक, केबल ग्रेड 1— IS : 9182 (भाग 1, 2 और 3)—1979	
63. सीएम/एल—9449 1981-02-16	81-03-01	82-02-28	जी० रामस्वामी गूड कं०, गंगा टैक्सटाइल्स, 4/387, अजिनाशी रोड, कोयम्बरूर-641037 (त० ना०)	होजरी के लिए धूरे रंग के सूती धागे काउन्ट: 40 एस, कंधा सारे हुए— IS : 834—1975	
64. सीएम/एल—9450 1981-02-16	81-03-01	82-02-28	किंगडम लिटर्स, पेबीबी टोपूरमट्टी सीटरी स्ट्रीट, तिरुपुर—638601 (त० ना०)	सावा बनी सूती बनियामें—टाइप: 1 आरएम और आरएमएस साइज: 75 से 100 सेंमी माप: 24— IS : 4964 (भाग 2)—1975	
65. सीएम/एल—9451 1981-02-16	81-03-01	82-02-28	रामकृष्ण इंजीनियरिंग कं०, ए-10 और ए-11 सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट, अरुणकम मद्रास-600029 (त० ना०) (कार्यालय : 184, पुरसावल्लम् हाई रोड, मद्रास-600010)	दुग्ध संभारण के लिए स्टेमलेस इस्पात की निम्नलिखित क्षमता वाली तापरोधित टैंकियां, ऊर्ध्वज-2000 लिटर और क्षैतिज-5000 10000 तथा 15000 लिटर— IS : 2688—1964	
66. सीएम/एल—9452 1981-02-21	81-02-21	82-02-20	कासे बट्ट बसर्स प्रा० लिमिटेड, विनदोषी, विजयनगर एक्सप्रेस हाईवे के निकट, सिबा रिमचं सेक्टर के सामने गोडगाव (पूर्व) बम्बई-400063 (कार्यालय : महाराजजी मेशन, सर पी०एम० रोड, बंबई-400001)	गन्धकिया के लिए रबड़ के दस्ताने—साइज: केबल 6, 6-1/2, 7, 7-1/3, और 8— IS : 4148—1967	
67. सीएम/एल—9453 1981-02-21	81-03-01	82-02-28	भारत पल्कराइजिंग लिमिटेड, अंधेरी कुर्ली रोड, कवला, अंधेरी (महाराष्ट्र) (कार्यालय : "हेल्सामर हाउस", सयाजी रोड, बंबई-400025)	डीडीडी जन परिशेयो वाउडर माफ्ट— IS : 565—1975	
68. सीएम/एल—9454 1981-02-21	81-03-01	82-02-28	हिरोन स्माल स्केल इंडस्ट्रीज, 1/5 ए, मुर बा०रीतस्ता रोड, कलकत्ता-700010 (प० ब०)	बनिकों के लिए चमड़े के सुरक्षा बूट और जूते तथा भारी धातु उद्योगों के कामगारों के लिए चमड़े के सुरक्षा बूट और जूते— IS : 1989 (भाग 1 और 2)—1978	
69. सीएम/एल—9455 1981-02-21	81-03-01	82-02-28	जाबोइन हेंबरसन लिमिटेड, काशीपुर डिबिजन, 75ए, सूर्य सेन रोड, आमल बाजार, कलकत्ता-700035 (प० ब०)	380 ग्रा/वर्गमीटर, 68×39 (14 औंस/45 इंच, 8×10) तिरपाल के कपड़े से निर्मित पटसन के परतदार जैसे— IS : 7406 (भाग-2) 1980	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
70. सी.एम./एल.—9456 1981-02-21	81-03-01	82-02-28	हिमाचल स्टेट्स, डा० ए० ड० मशीनों, नलगढ़ (हिमाचल प्रदेश)	संरचना इस्पात (साधारण किस्म) — IS : 1977—1975	
71. सी.एम./एल.—9457 1981-02-21	81-03-01	82-02-28	श्री कन्नापिरान मिल्स लि०, साउरीपालाघम, कोयम्बतूर-641028 (त०ना०)	भूरे रंग के सूती धागे, ग्रेड-बी, काउन्ट : 80 एम, कड़ा मारे हुए— IS : 171—1973	
72. सी.एम./एल.—9458 1981-02-21	81-03-01	82-02-28	गिरि होजरी मिल्स, 81-बी, रमैया कालोनी, तिरुपुर—638602 (त०ना०)	सादा बुनी सूती बनिधाने-टाइप : आरएन और आरएनएम्, साइज : 75 से 100 सेंमी ताप : 24— IS : 4964 (भाग 2)—1975	
73. सी.एम./एल.—9459 1981-02-22	81-03-01	82-02-28	ईस्टर्न गैस एम्प्लॉयेस, 31 बां किमी पथर, निधु मिनेना के निकट, जे०टी० रोड, कुडली (हरियाणा) (कार्यालय : 340, नया सञ्जो मंडी, आजादपुर, दिल्ली-110033)	दुर्बी कृत पेट्रोलियम गैस के साथ प्रयुक्त थरेनू सूत्रे— IS : 4246—1978	
74. सी.एम./एल.—9460 1981-02-23	81-03-01	82-02-28	माउथ इंडिया सायर रोपर्स लि०, डा० एरायला-683561 अलवई (केरल)	शिरोपरि प्रेषण कार्यों के लिए एंक्रुमिनियम बालकों के प्रबलन के लिए जस्तीकृत इस्पात के तार— IS : 398 (भाग 2)—1976	
75. सी.एम./एल.—9461 1981-02-23	81-03-01	82-02-28	ऐलन इंडस्ट्रीज, एल्माईयाट्टम रोड, पलायेट, कोयम्बतूर-641004	हथि कार्यों के लिए अपकेम्प्री पम्पों के लिए तीन फेरी पिजरी प्रेरण मोटरें, साइज : 2 2 कि वा, श्रेणी "ए" रोशन वाली— IS : 7538—1975	
76. सी.एम./एल.—9462 1981-02-23	81-03-01	82-02-28	खंडेलवाल मिनरल एंड पेट्रोलियम, प्लाट न० ई-34, एम०आई०ई०सी० इंडस्ट्रियल एरिया, ह्रीगला रोड, नागपुर-440016 (महाराष्ट्र) (कार्यालय : "श्रैजी", 10ए, भगवाधर, नेआउट, घर्मपेट, नागपुर-440010)	ई०ई०टी धूलन पाउडर— IS : 564—1975	
77. सी.एम./एल.—9463 1981-02-23	81-03-01	82-02-28	यूनिवर्सल एंडो केमिकल इंडस्ट्रीज, डा० मिराकोल (उत्थो रोड), जि० 24 परगना (प०ब०) (कार्यालय 18, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कमरा न० 6, तामरा तल, कलकत्ता-700001)	एंक्रुमिनियम पायसनीय सान्द्र IS : 4323—1967	
78. सी.एम./एल.—9464 1981-02-23	81-03-01	82-02-28	कोस्टल पैकेजिंग प्रा० लि०, 95/1, कासीपुर रोड कलकत्ता-700002 (प०ब०) (कार्यालय 5/5, इलाहाबाद रोड, कलकत्ता-700002)	380 ग्राम/वर्गमीटर, 68×39 (14 औंस/45 इंच, 8×10) तिरपाल के कपड़े से निर्मित पटसन के परतदार थैले— IS : 7406 (भाग 2)—1980	
79. सी.एम./एल.—9465 1981-02-23	81-03-01	82-02-28	श्याम सिमिन्टर्स, 144/145- जे०एन० मुघर्जी रोड, धुमुगी हाथड़ा (प०ब०) (कार्यालय 10/2 बी, अमीपुर पार्क प्लेस, कलकत्ता-700062)	407 ग्राम/वर्गमीटर, 85×39 (15 औंस/45 इंच 8×10) तिरपाल के कपड़े से निर्मित पटसन के परतदार थैले— IS : 7403 (भाग I)—1974	
80. सी.एम./एल.—9466 1981-02-23	81-03-01	82-02-28	ट्रापिकल एंडो मिस्टर्स (प्रा० लि०) 530/2 बी, बनग्राम रोड, आषोपेट, मद्रास-600058	क्रिस्टलीय पायसनीय सान्द्र— IS : 8028—1976	
81. सी.एम./एल.—9467 1981-02-23	81-03-01	82-02-28	वैद्यनाथ आयरन एंड स्टील प्रा० लि०, वैद्यनाथपुर (डा०) वैद्यनाथ-देवदर	कंसीट प्रबलन के लिए 550 बी जो उच्च ताप पर इस्पात को बिहान मारना— IS : 1786—1966	
82. सी.एम./एल.—9468 1981-02-24	81-03-01	82-02-28	बी०के० इंडस्ट्रियल कारपोरेशन, 7 काली टेम्बर रोड, डा० नीमरा कलकत्ता-700049 (कार्यालय 18, नेताजी सुभाष रोड, पहला तल, कलकत्ता-700001)	हथि कार्यों के लिए साफ, ठंडे, ताजा पानी के वास्ते श्रेष्ठ प्रकार की पम्प— साइज 80 मिमी × 65 मिमी गति 1500 चक्र प्रति मिनट इंधन 15 एम सी० पर डिस्टेंस 3.30 मीटर प्रति मिनट, दबाव 60 प्रतिमिनट और पम्प निवेश 3.5 किवा— IS : 3595—1972	

1	2	3	4	5	6
83. सीएम/एल-9469 1981-02-24	81-03-01	82-02-28	कासिनान कुन्ती लाल एंड सन एन्ट्राप्रेनर प्रा० लि०, 3, जवाहर रोड, ऊनना-394210 जिला सूरत	एक फेज, 240 वोल्ट 50 साइकिंग, पानी का ड्र बाउण्डरी, 20 किवा तक रेटिंग का— IS : 368-1977	
84. सीएम/एल-9470 1981-02-25	81-03-01	82-02-28	एशो इंडस्ट्रियल केमिकल्स कं० 13ए, कल्याण ब्यू, रुद्रपुर-263153 जिला-नेनीताल (उ०प्र०)	एन्ड्रियल पायसमतीय सान्द्र— IS : 1307-1973	
85. सीएम/एल-9471 1981-02-25	81-03-01	82-02-28	गोल्डन केमिकल वर्क्स, 2, इंडस्ट्रियल इक्वलिपमेंट कालोनी, डा० रेवन मिन्क मिन्स अमृतसर-143104 (कार्यालय 8, अकाली मार्केट, अमृतसर)	सामान्य कार्यों के लिए अन्नरंग किंवदित्त के लिए तैयार मिश्रित रंगन, भारतीय मानक रंगों के अनुसूच IS : 3537-1966	
86. सीएम/एल-9472 1981-02-26	81-03-01	82-02-28	कानपुर प्लास्टिक प्रा० लि०, डी-19, पन्की इंडस्ट्रियल एरिया, डा० उद्योग नगर, कानपुर-208022 (उ०प्र०)	380 ग्राम/बर्मीटर, 68×39 (14 ओंम/45 इंच, 4×10) निराल के फाई से निर्मित पट्टमन के परादर धेरे— IS : 7406 (भाग 2)-1980	
87. सीएम/एल-9473 1981-02-27	81-03-01	82-02-28	बी०के० इंडस्ट्रियल कारपोरेशन, 7 काली मन्दिर रोड, डा० नोमना कनकता-700049 (प० ब०) (कार्यालय 18, नेताजी सुभाष रोड पट्टा पल, कलकत्ता-700001)	एक मिनिमम और चार स्ट्रुंग बाने, मिमना-किन् रेटिंग के जब मोलि उड्डे डोजन इन्जन निर्म 3.67 किवा (5 बीएचपी) गति 1500 चक्कर प्रति मिनिट गतिग कताम "बी" एचएफपी 269 ग्राम/किता बोट घंट (198 ग्राम/बीएचपीएच)— IS : 1601-1960	
88. सीएम/एल-9474 1981-02-27	81-03-16	82-03-15	इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वर्क्स, 16, सरदार प्रताप सिंह मार्ग, भांडुग, बम्बई-400073	संरचना इस्पात (मानक किस्म)— IS : 226-1975	
89. सीएम/एल-9475 1981-02-27	81-03-16	82-03-15	हिमालयन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल इस्टेट, अरुनचली नगर सैड नं० 23 व 23 अंगरकला, तिरुपुरा	पेय जल पूर्ति के लिए उच्च प्रत्यक्ष पानी इ-थाइलीन नल— साइज 90 मिमी, थ्रेणी 5 और 110 मिमी, थ्रेणी 4— IS : 4984-1978	
90. सीएम/एल-9476 1981-02-27	81-03-01	82-02-28	कोबा मर्चेंशन कं०, प्लाट नं० 15, सेक्टर 6, फरीदाबाद (हरियाणा)	मोटरगाड़ियों के निम्नस्तर के लिए पन्नी कमा-निंग, केत कसानी पोरों— IS : 1135-1973	
91. सीएम/एल-9477 1981-02-27	81-03-01	82-02-28	कविता केबल, 5 बी, सेक्टर 2, सोएडा, जिला गाजियाबाद (उ०प्र०)	1100 वोल्ट तक की कार्यकारी बोल्टना के लिए रीबीसी रोडिज केबल, बोल्टर और खोब रजिज, केबल एन्ड मिनिमम बालकों वाले (कम तापमान में काम आनेवाले केबलों को छाड़कर)— IS : 694--1977	
92. सीएम/एल-9478 1981-02-27	81-03-16	82-03-15	इंएनपीआई केमिकल वर्क्स, 135-बी, केवल बायरासांझा, बंगलौर-560006 (कर्नाटक)	टाइटेनियम डाइआक्साइड, बाय ग्रेड— IS : 8356-1977	
93. सीएम/एल-9479 1981-02-27	81-03-16	82-03-15	यूनियन पेन्टिस इंडस्ट्रीज, श्री रामनगर, विविजा (म०प्र०)	एंडोसल्फान पायसमतीय सान्द्र— IS : 4323-1967	
94. सीएम/एल-9480 1981-02-27	81-03-16	82-03-15	एल०कार एंड कं० प्रा० लि०, 4 डी, धर्मेन्द्र नारा रोड, कलकत्ता-700039 (प० ब०) (कार्यालय 49, ई, पूर्णदास रोड, कलकत्ता-700029)	केरोसीन डेजेट फाउन्डन पैर को स्याही (0.1 प्रतिगल लोहवृत्त)— IS : 220-1972	
95. सीएम/एल-9481 1981-02-27	81-03-16	82-03-15	गुरु रामदास आपरन एंड स्टील रोलिंग मिन्स, गुड की नगरी, मंडी गोविन्दगढ़ (पंजाब)	संरचना इस्पात (मानक किस्म)— IS : 226-1975	
96. सीएम/एल-9482 1981-03-27	81-03-16	82-03-15	विपनकुमार ओबेराम एंड कं०, बुजरी रोड, यमुना नगर-135001	बाय की पेटियां के लिए प्लाईवुड की पेटियां— IS : 10 (भाग 3)-1974	
97. सीएम/एल-9483 1981-02-27	81-03-01	82-02-28	मोमा प्लम्बिंग फिक्स्चर्स लि०, 64/6, साइट नं० 4 इंडस्ट्रियल एरिया साहिबाबाद-201003 जिला गाजियाबाद (उ०प्र०)	गोली वास्व (सेलिज प्लंजर टाइप का), साइज 15 मिमी— IS : 1703-1977	

98. सीएम/एल-9484 1981-02-27	81-03-01	82-02-28	विल्ली पेपर प्राइवट्स कं., 19, गुडगांव रोड, एक बार प्रयोजन कार्बन कागज, टाइप "E"— कापसहेडा, नयी दिल्ली-110037 (कार्यालय ई-34, कनटप्लेस, नई दिल्ली-110001)	IS : 9055-1979
99. सीएम/एल-9485 1981-02-27	81-03-01	82-02-28	इडेन केबिन्स, नेहरू रोड, पिथानी-125021	1100 बोर्ड तक की कार्बोसोरोसिटी के लिए पीवीसी रोहित केबल, बोलशर और बोलशर एडमिनिस्ट्रेशन बालकों वाले (कम तापमान में काम करने वाले केबलों को छोड़कर)— IS : 694-1977
100. सीएम/एल-9486 1981-02-27	81-03-16	82-03-15	इका केबलस प्रा. लि., 149, तारबारम् बेलारो रोड, सेम्बकम, मद्रास	1100 बोर्ड तक की कार्बोसोरोसिटी के लिए एक फाइल वाले पीवीसी रोहित और पीवीसी कवचित केबल, एडमिनिस्ट्रेशन बालकों वाले (बहिरंग प्रयोग और कम तापमान में काम करने वाले केबलों को छोड़कर)— IS : 694-1977

[सं. सी.एम.डी/13: 11]

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, 1984-10-30

S.O. 4241.—In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 8 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that hundred licences, particulars of which are given in the following Schedule, have been granted during the month of February 1981 authorizing the licensees to use the Standard Marks.

THE SCHEDULE

Sl. No.	Licence No. (CM/L-)	Period of Validity		Name & Address of the Licensee	Article/Process covered by the licences and the Relevant IS : Designation
		From	To		
1	2	3	4	5	6
1.	CM/L-9387 1981-02-03	81-02-16	82-02-15	Megs Electricals (P) Ltd., A-23/B, Lane No. 4, Anand Parbat Industrial Area, New Delhi.	Electric radiators 1000 W & 2000 W— IS : 369-1965
2.	CM/L-9388 1981-02-03	81-02-16	82-02-15	Indian Dairy Equipment Co., H-23, Bali Nagar, New Delhi-110015.	Milk butyrometers, 10 percent scale— IS : 1223 (Part I)—1970
3.	CM/L-9389 1981-02-03	81-02-16	82-02-15	Dayal Fertilizers Pvt. Ltd., 10th Kilometer, Delhi Road, Opposite Partapur railway Station, Partapur, Meerut (U.P.). (Office : 118 Thaparnagar, Meerut-250001).	Zinc sulphate, agricultural grade— IS : 8249-1976
4.	CM/L-9390 1981-02-03	81-02-16	82-02-15	Modi Steels, (Prop. Modi Industries Ltd.), Modinagar, Distt. Ghaziabad (U.P.)	Carbon Steel billets for forgings, all classes— IS : 1875-1978
5.	CM/L-9391 1981-02-04	81-02-16	82-02-15	Viswas Knitting Mills, 5B, S.N.V.S. Layout, Kangunagar Main Road, Tirupur-638602 (TN)	Plain knitted cotton vests Type : RN & RNS Size : 75 to 90 cms Gauge : 24 IS : 4964 (Part II)—1975
6.	CM/L-9392 1981-02-05	81-02-16	82-02-15	Bharat Steel Industries, A-1 to A-3 Industrial Estate, Moula Ali, Hyderabad-500040. (Office : 5-5-22, Ranigunj, Secunderabad-500003).	Steel window section F 4B and T2— IS : 7452-1974
7.	CM/L-9393 1981-02-05	81-02-16	82-02-15	Dinesh Agro Industries, F-439, Road No. 12, Vishwakarma Indl. Area, Jaipur-302013	Flushing cisterns for water closets and urinals capacity 10L and 12.5 L— IS : 774-1971
8.	CM/L-9394 1981-02-06	81-02-16	82-02-15	Arun Engg. Industries (P) Ltd., Shantinagar Co-op. Industrial Estate, Vakola, Santa-cruz (East), Bombay-400055.	Single-phase small AC electric motors, 0.75 KW, insulation class 'E' IS : 996-1964
9.	CM/L-9395 1981-02-06	81-02-16	82-02-15	Toshiba Anand Batteries Ltd., H.M.T. Road, Kalamaserry, Ernakulam Distt. Kerala State. (Office : XXXVI/694, Mahatma Road, Ernakulam, Cochin-682011)	Heavy duty dry batteries designation R 20— IS : 9128-1979

1	2	3	4	5	6
10. CM/L-9396 1981-02-06	81-02-16	82-02-15	Victory Battens, Near Railway Station, Chalakudy-680307	Plywood teachest battens— IS : 10 (Part III)—1974	
11. CM/L-9397 1981-02-06	81-02-16	82-02-15	Shah Steel Industries, Bombay Ahmedabad Express Highway, Village : Sativli, Tal : Bassein, Distt. Thana. (Office : D. o Prakash, Roshan Nagar Road, Borvli (West), Bombay-400092]	Galvanized steel wire for telegraphed telephone purposes— IS : 279-1972	
12. CM/L-9398 1981-02-09	81-02-16	82-02-15	P.N.M. Company, Perundurai Main Road, Erode-638009 (TN) (Office : 60 F 5 S.K.C. Road, Erode-638009)	Dimethoate EC— IS : 3903-1975	
13. CM/L-9399 1981-02-09	81-02-16	82-02-15	Karnataka Soaps and Detergents Ltd., (Formerly the Government Soap Factory) Detergent Plant, Industrial Suburb, Rajajinagar, Bangalore-560055 (Karnataka)	Synthetic detergent powders for household use, grade 1 only— IS : 4955—1978	
14. CM/L-9400 1981-02-09	81-02-16	82-02-15	Krishichemin Pvt. Ltd., 63/2, Sarakki, Jayanagar South, Bangalore-560078 (Karnataka).	BHC (HCH) WDPC— IS : 562—1978	
15. CM/L-9401 1981-02-09	81-02-16	82-02-15	L.P. Gas Equipment Pvt. Ltd., 1A/1, GIDC Industrial Estate, Old National Highway No. 8, Bharuch (Gujarat). (Office : 53—57, Laxmi Insurance Building, Sir P.M. Road, Bombay-400001)	Valve fittings for the use with newly manufactured liquefied petroleum gas cylinder of more than 5 litre capacity— IS : 8737 (Part II)—1978	
16. CM/L-9402 1981-02-09	81-02-16	82-02-15	Everest Kanto Cylinder Pvt. Ltd., E-22, MIDC Industrial Area, Chikalhana, Aurangabad (Maharashtra) (Office : 10 Marine Chambers, 43, New Marine Lines, Bombay-400020).	Seamless manganese steel cylinders for permanent and high pressure liquefiable gases of the following types and capacity : 3.4, 10.2 & 14.0 litre water capacity (oxygen, Co., N2O)— IS : 7285—1974	
17. CM/L-9403 1981-02-09	81-02-16	82-02-15	The Alkali & Chemical Corpn. of India Ltd. 10 G.T. Road, P.O. Rishra, Distt. Hooghly (West Bengal). (Office : 34 Chowringhee Road, Calcutta-700071).	BHC (HCH) WDEC— IS : 562—1978	
18. CM/L-9404 1981-02-09	81-02-16	82-02-15	M.M. Industries, 133, Grand Foreshore Road, Howrah (West Bengal). (Office : 130 Cotton Street, Calcutta-700007)	Laminated jute bags manufactured from 380g/m ² 68X39 (14 oz/45 in, 8X10) tarpaulin fabric— IS : 7406 (Part II)—1980	
19. CM/L-9405 1981-02-09	81-02-16	82-02-15	Swastik Laminating Industries, 95/1/38, Cossipore Road, Calcutta-700002 (W.B.) (Office : 68 Cotton Street, Calcutta-700007).	Laminated jute bags manufactured from 380g/m ² 68X39 (14 oz/45 in; 8X10), tarpaulin fabric— IS : 7406 (Part II)—1980	
20. CM/L-9406 1981-02-09	81-02-16	82-02-15	Domestic Appliances, 1522/328 Shambhu Dayal Bagh, Okhla Industrial Area, New Delhi-110020.	Domestic pressure cookers of 5 litres 6 litres, 6.5 litres and 7.5 litres sizes— IS : 2347—1974	
21. CM/L-9407 1981-02-09	81-02-16	82-02-15	Surya Cables, Gali No. 9, Samepur Badli, Delhi-110042.	PVC insulated cables and Flexible cords for working voltages upto and including 1100 V, sheathed and unsheathed with copper conductor only (excluding cables for out door use and low temperature conditions)— IS : 694—1977	
22. CM/L-9408 1981-02-09	81-02-16	82-02-15	Gupta Chemicals Pvt. Ltd., B-144, Road No. 9, Vishwakarma Indl., Estate, Jaipur-302013 (Rajasthan). (Office : Bhukhmariya Bldg., Tripolia Bazar, Jaipur-302002).	Carbaryl DP— IS : 7122—1973	
23. CM/L-9409 1981-02-09	81-02-16	82-02-15	Sri Kasturi Knitters, 18, Harvey Road, Tirupur-638602 (TN)	Plain Knitted cotton vests : Type : RN & RNS Size : 75 to 90 cms Gauge : 24— IS : 4964 (Part II)—1975	
24. CM/L-9410 1981-02-10	81-02-16	82-02-15	Kosan Metal Products Pvt. Ltd., Bombay Food Premises, Katargam, Surat-395004 (Gujarat). (Office : 53—57, Laxmi Insurance Bldg., Sir P.M. Road, Bombay-400001).	Valve fitting for the use with newly manufactured liquefied petroleum gas cylinder of more than 5 litre capacity— IS : 8737 (Part II)—1978	
25. CM/L-9411 1981-02-10	81-02-16	82-02-15	Milk Products Factory (A Unit of A.P. Dairy Development Corpn. Ltd.,) Chittoor-517002..	Processed Cheese— IS : 2785—1979	

1	2	3	4	5	6
26. CM/L-9412 1981-02-10	81-02-16	82-02-15	Madhusudan Ceramics, (Props : Madhusudan Vegetable Products Co. Ltd.,) Kadi-382715 Distt. Mehsana (N.G.)	(i) Long pattern squatting pan size 580mm (ii) Orissa pattern squatting pan size 580mmX440mm (iii) Wash basin flat black & pedestal sizes 450mmX300mm & 550mmX400mm IS : 2556 (Part I)—1974 IS : 2556 (Part III)—1973 IS : 2556 (Part IV)—1972	
27. CM/L-9413 1981-02-10	81-02-16	82-02-15	Sachdeva Industries, 1/421, Gali No. 5, Friends Colony Indl. Area, G.T. Road, Shahdara, Delhi-110032. (Office : 7270-71, Old Rohtak Road, Near Azad Market Chowk, Delhi-110006).	PVC insulated cables for working voltage upto and including 1100 V, sheathed and unsheathed with copper and aluminium conductors including cables for outdoor use/low temperature conditions— IS : 694—1977	
28. CM/L-9414 1981-02-10	81-02-16	82-02-15	Ashok Iron & Steel Fabricators, Mavdi Plot, Rajkot-360004 (Gujarat).	18 litre square tins— IS : 916—1975	
29. CM/L-9415 1981-02-10	81-02-16	82-02-15	Safex Fire Services, 202-A, Dhanraj Industrial Estate, Sun Mill Road, Lower Parel (West), Bombay-400013.	Portable Chemical fire extinguisher soda acid type— IS : 934—1976	
30. CM/L-9416 1981-02-10	81-02-16	82-02-15	Tingrania Metal & Steel Industries, New Bombay Agra Road, Nasik-422001.	Structural steel (ordinary quality)— IS : 1977—1975 (Group II).	
31. CM/L-9417 1981-02-10	81-02-16	82-02-15	Jain Steel Industries, G.T. Road, Mandi Gobindgarh-147301 (Punjab).	Structural Steel (standard quality)— IS : 226—1975 (Group II)	
32. CM/L-9418 1981-02-10	81-02-16	82-02-15	-do-	Structural steel (ordinary quality)— IS : 1977—1975	
33. CM/L-9419 1981-02-10	81-02-16	82-02-15	Wahl Industrial Products, 34/6, SSI Area, 3rd Cross, 5th Block, Rajajinagar, Bangalore-560010.	Rigid non-metallic conduits for electrical installations 20 mm size— IS : 2509—1973	
34. CM/L-9420 1981-02-10	81-02-16	82-02-15	Hindustan Rollings & Wires Pvt. Ltd., 41/4, Bahalgarh Sonapat Road, Sonapat (Haryana). (Office : 2-E/22, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055).	Hard drawn steel wire for concrete reinforcement all sizes— IS : 432 (Part II)—1966	
35. CM/L-9421 1981-02-11	81-03-01	82-02-28	Kisan Chemical Works, Juni Jithardi, Taluk Karjan—391240 Distt. Vadodara (Gujarat).	Malathion DP— IS : 2568—1978	
36. CM/L-9422 1981-02-11	81-03-01	82-02-28	Keen Pesticides (P) Ltd., A1/422, G.I.D.C. Ankleshwar-393002 (Gujarat).	Endosulfan EC— IS : 4323—1967	
37. CM/L-9423 1981-02-12	81-03-01	82-02-28	Modern Steel Enterprises, (Prop. Modern Rolling Mills P. Ltd.), 242/1, G.T. Road (North), P.O. Ghosuri, Howrah. (Office : 9 Jagmohan Mullick Lane, Calcutta-700007).	Cold-worked steel high strength deformed bars for concrete reinforcement— IS : 1786—1979 (Group II)	
38. CM/L-9424 1981-02-12	81-03-01	82-02-28	Punjab Metal Works, Nakodar Road, Jullundur-144001.	Ferrule cocks for water service size 15mm— IS : 2692—1978	
39. CM/L-9425 1981-02-12	81-03-01	82-02-28	Milk Products Factory, Chittoor (A Unit of Andhra Pradesh Dairy Development Corpn. Ltd.) Chittoor-517002 (A.P.)	Whole & Skim milk powder— IS : 1165—1975	
40. CM/L-9426 1981-02-13	81-03-01	82-02-28	Chamundi Steel Re-rolling Mills, 7th Mile, Hosur Road, Bangalore-560068.	Structural steel (standard quality)— IS : 226—1975	
41. CM/L-9427 1981-02-13	81-03-01	82-02-28	-do-	Structural steel (ordinary quality)— IS : 1977—1975	
42. CM/L-9428 1981-02-13	81-03-01	82-02-28	Beama Manufacturers Pvt. Ltd., A-8 Unit, Ambattur Industrial Estate, Madras-600058 (Tamil Nadu).	Monoset pumps for clear, cold, fresh water for agricultural purposes of the following sizes : size— 50mmX35mm Speed—2820 RPM Type/model—CP 50X35 Motor—2.2 kw, class 'E' Duty point—at 25m head, discharge 5.9 lps and overall efficiency 40%— IS : 6595—1972	
43. CM/L-9429 1981-02-16	81-03-01	82-02-28	Thathiengarpet Weavers' Co-operative Society Ltd., No. R-633, Namakal Road, Thathiengarpet P.O. Trichy Distt.-621214 (Tamil Nadu).	Handloom cotton dhotis variety No. 7 & 8— IS : 748—1974	

1	2	3	4	5	6
44. CM/L-9430 1981-02-16	81-03-01	82-02-28	Geetanjali Knitting Mills, 30B, Kongu Nagar, Main Road, Tirupur-638602 (Tamil Nadu)	Plain knitted cotton vests Type : RN & RNS Size : 75 to 100 cms Gauge : 24— IS : 4964 (Part II)-1975	
45. CM/L-9431 1981-02-16	81-03-01	82-02-28	Hema Knitting Co., 5-B Ramnagar, II Street, Tirupur-638602(TN)	Plain knitted cotton vests : Type : RN & RNS Size : 80 to 90 cms Gauge : 24 IS : 4964 (Part II)-1975	
46. CM/L-9432 1981-02-16	81-03-01	82-02-28	Sri Gopalkrishna Mills Pvt./Ltd., P. Vadugapalayam, Palladam, Coimbatore Dist. (TN) (Office : Branch : 'Palladam' Ganapathy Post.)	Cotton yarn, grey, for hosiery count : 39s combed— IS : 834-1975	
47. CM/L-9433 1981-02-16	81-03-01	82-02-28	Farmers Pest Control (P) Ltd., Parecherla, Guntur-Nagarjuna Sagar Road, Distt. Guntur(A.P.)	DDT WDPC— IS : 565-1975	
48. CM/L-9434 1981-02-16	81-02-16	82-02-15	Ken Electricals, Post Box No. 56, Rani Bang, Rewa-486001(M.P.)	AAC & ACSR conductors for overhead transmission purposes— IS : 398(Part I&II)-1976	
49. CM/L-9435 1981-02-16	81-02-16	82-02-15	R.K. Electrical Industries (India), A-47, Naraina Industrial Area, Phase I, New Delhi.	Polyethylene insulated and polyethylene sheathed cables for working voltages upto and including 1100 V with aluminium conductor suitable for outdoors use excluding cables for low temperature conditions— IS : 1596-1977	
50. CM/L-9436 1981-02-16	81-03-01	82-02-28	Nu-Lite Industries, S-9 Ajay Enclave Market, New Delhi-110018	Tower bolts (non ferrous metal)— IS : 204 (Part II)-1978	
51. CM/L-9437 1981-02-16	81-03-01	82-02-28	Crompton Greaves Ltd., (Machine Division) Dr. E. Moses Road, Worli, Bombay-400018 (Maharashtra) (Office : 1 Dr.V.B. Gandhi Marg, Bombay-400023)	Monoset pumps for clear, cold, fresh water for agricultural purposes of the following sizes : Size-63mm x 50 mm 76mm x 63 mm Speed-1410 RPM 1440 RPM Type/Model-MBN-3D MBD-5D duty point— At 11 m head, discharge 560 lpm and overall efficiency 40% At 14.5m head, discharge 800 lpm and overall efficiency 48 % motor-2.2 kw 3.7kw IS : 6595-1972	
52. CM/L-9438 1981-02-16	81-03-01	82-02-28	Bio-culture Manufacturing Laboratories, 259, Phase IV, Peenya Industrial Area, Peenya, Bangalore-560058 (Karnataka)	Azotobacter chroococcum inoculants— IS : 9138-1979	
53. CM/L-9439 1981-02-16)	81-03-01	82-02-28	Vimpex Agencies, 84, 18th Cross, 6th Main Road, Malleswaram, Bangalore (Karnataka) (Office : 8, 17A, Cross, 12th Main Road, Malleswaram, Bangalore-560055)	Rhizobium inoculants for the following crops : cowpea, groundnut, greengram and blackgram— IS : 8268-1976	
54. CM/L-9440 1981-02-16	81-03-01	82-02-28	Mine Safety Appliances Ltd., 9 Syed Amir Ali Avenue, Suit No. 2, Fourth Floor, Calcutta-700017(W.B.) (Office : 6 A, Hatipagan Road, Entally, Calcutta-700014)	Gas testing flame safety lamps for mines— IS : 7577-1975	
55. CM/L-9441 1981-02-16	81-03-01	82-02-28	Shree Amrit Bachan Saw Mills, Khajuri Rd., Yamunanagar-135001	Plywood teachest battens— IS : 10(Part III)-1974	
56. CM/L-9442 1981-02-16	81-03-01	82-02-28	Super Circle Pvt Ltd., B-45, Mayapuri Indl. Area, New Delhi 110064.	Piston rings (R-ring) for internal combustion engines, size upto & including 62 mm— IS : 8422(Part I)-1977	
57. CM/L-9443 1981-02-16	81-03-01	82-02-28	Delhi Paper Products Co., 19, Gurgaon Road, Kapasheda, New Delhi-110037	Teleprinter paper page rollers— IS : 9031-1979	
58. CM/L-9444 1981-02-16	81-03-01	82-02-28	Choudhary Metal Industries (P) Ltd., Plot No. 71, Sector 6, Faridabad(Haryana)	PVC insulated cables and flexible cords for working voltages upto and including 1100V sheathed and unsheathed with copper conductor only (excluding cables for low temperature conditions)— IS : 694-1977	
59. CM/L-9445 1981-02-16	81-03-01	82-02-28	Bonded Packaging (P) Ltd., 117/354, G.T. Road, Rawatpur, P.O. Kanpur University, Kanpur-208024 (U.P)	Laminated jute bags manufactured from 380g/m ² ; 68x39 (140 Z/45 in; 8x10) tarpaulin fabric— IS : 7406 (Part II)-1980	

1	2	3	4	5	6
60. CM/L-9446 1981-02-16	81-03-01	82-02-28	Royal Cold Re-rolling Mill, 123/431, Fazalganj, Kanpur(UP)	Structural steel (standard quality)– IS : 226-1975	
61. CM/L-9447 1981-02-16	81-03-01	82-02-28	Royal Cold Re-rolling Mill, 123/431, Fazalganj, Kanpur(UP)	Structural steel (ordinary quality) IS : 1977-1975	
62. CM/L-9448 1981-02-16	81-03-01	82-02-28	Hiten & Co., Saraidhela, P.O. Kasturba Ashram, Dist, Dhanbad (Bihar). (Office : P.O. Jharria-828111 Distt. Dhanbad, Bihar)	(i) Lubricants for fibre core of wire ropes bituminous type (ii) Lubricants for wire strands and rope bituminous type (iii) Lubricants for rope dressing in service grade 1 only– IS : 9182 (Part I, II & III)–1979	
63. CM/L-9449 1981-02-16	81-03-01	82-02-28	G. Ramaswamy & Co., Ganga Textiles, 4/387, Avanashi Road, Coimbatore-641037(TN)	Cotton yarn, grey for hosiery count: 40 s combed– IS : 834-1975	
64. CM/L-9450 1981-02-16	81-03-01	82-02-28	Kingdom Knitters, Pethichettyapuram, 3rd street, Tirupur-638601(TN)	Plain knitted cotton vests : Type : RN & RNS Size : 75 to 100 cms gauge : 24– IS : 4964 (Part II)–1975	
65. CM/L-9451 1981-02-16	81-03-01	82-02-28	Ramakrishna Engg. Co., A-10 & A-11, SIDCO Indl. Estate, Arumabkkam, Madras-600029(TN). (Office : 184 Purasawalkam High Road, Madras-600010)	Insulated stainless steel milk storage tank of the following rated capacity : vertical-2000 litres horizontal-5000, 10000, 15000 litres– IS : 2688-1964	
66. CM/L-9452 1981-02-21	81-03-01	82-02-28	Kale Rubber Works Pvt. Ltd., Dindoshi, Near Vijayanagar Express Highway, Opposite CIBA Research Centre, Goregaon(East) Bombay-400063 (Office : Behramji Mansion, Sir P.M. Road, Bombay-400001.	Surgical rubber gloves, sizes 6, 6-1/2, 7, 7-1/2 and 8 only– IS : 4148-1967	
67. CM/L-9453 1981-02-21	81-03-01	82-02-28	Bharat Pulverising Mills Pvt. Ltd., Andheri Kurla Road, Chakala, Andheri (Maharashtra) (Off : "Hexamar House", Sayani Road, Bombay-400025).	DDT WDPC– IS : 565-1975	
68. CM/L-9454 1981-02-16	81-03-01	82-02-28	Hiron Small Scale Industries, 1/5A, Burwaritala Road, Calcutta-700010(W.B.)	Leather safety boots and shoes for miners; and leather safety boots and shoes for workers in heavy metal industries– IS : 1989 (Part I&II)–1978	
69. CM/L-9455 1981-2-21	81-03-01	82-02-28	Jardine Henderson Ltd., Kossipur Division 75A, Suryo Sen Road, Alambazar, Calcutta-700035(W.B.)	Laminated* jute bags manufactured from 380 g/m; 68x39 (14 oz/45 in; 8 x 10) tarpaulin fabric– IS : 7406(Part II)–1980	
70. CM/L-9456 1981-02-21	81-03-01	82-02-28	Himachal Steels, V.P.O. Majholi, Nalagarh (H.P.)	Structural steel (ordinary quality)– IS : 1977-1975	
71. CM/L-9457 1981-02-21	81-03-01	82-02-28	Sri Kannapiran Mills Ltd., Sowripalayam, Coimbatore-641028(TN)	Grey cotton yarn, grade B count 80 s combed IS : 171-1973	
72. CM/L-9458 1981-02-21	81-03-01	82-02-28	Giri Hosiery Mills, 81-B, Ramaiah Colony, Tirupur-638602(TN)	Plain knitted cotton vests: Type : RN & RNS size : 75 to 100 cms gauge : 24– IS : 4964 (Part II)–1975	
73. CM/L-9459 1981-02-22	81-03-01	82-02-28	Easten Gas Appliances, 31 KM Stone, Near Nidhu Cinema, G.T. Road, Kundli (Haryana) (Office : 340, New Subzi Mandi, Azadpur, Delhi-110033.	Domestic gas stoves for use with LPG – IS : 4246-1978	
74. CM/L-9460 1981-02-23	81-03-01	82-02-28	South India Wire Ropes Ltd., Edathala Post-683561 Alwaye (Kerala State)	Galvanized steel wire for reinforcement aluminium conductors for overhead transmission purposes– IS : 398 (Part II) –1976	
75. CM/L-9461 1981-02-23	81-03-01	82-02-28	Ellen Industries, Ellaithottam Road, Peelamedu, Coimbatore-641004.	Three phase squirrel cage induction motors for centrifugal pumps for agricultural application size 2.2 kw with class 'A' insulation– IS : 7538-1975	
76. CM/L-9462 1981-02-23	81-03-01	82-02-28	Khandelwal Mineral & Pesticides, Plot No. E-34, M.I.D.C. Industrial Area, Hingna Road, Nagpur-440016 (Maharashtra) (Office : 'Shriji', 10A, Bhagawaghar, Layout, Dharampeth, Nagpur-440010).	DDT DP– IS : 564-1975	

1	2	3	4	5	6
77.	CM/L-9463 1981-02-23	81-03-01	82-02-28	Universal Agro Chemical Industries, P.O. Sirakole (Usthi Road), Dist. 24 Parganas (W.B.) (Office : 16, India Exchange Place, Room No. 6, 3rd Floor, Calcutta-700001)	Endosulfan EC- IS : 4323-1967
78.	CM/L-9464 1981-02-23	81-03-01	82-02-28	Coastal Packers P. Ltd., 95/1, Cossipore Road, Calcutta-700002 (West Bengal) (Office : 5/5, Clive Row, Calcutta-700001)	Laminated jute bags manufactured from 380 g/m ² , 68x39 (14 oz/45 in; 8x10) tarpaulin fabric. IS : 7406 (Part II)-1980
79.	CM/L-9465 1981-02-23	81-03-01	82-02-28	Shyam Laminators, 144/145, J.N. Mukherjee Road, Ghusuri, Howrah (West Bengal) (Office : 10/12 B, Alipur Park Place, Calcutta-700002)	Laminated jute bags manufactured from 407 g/m ² ; 85x39 (15 oz/45 in; 10x10) tarpaulin fabric. IS : 7406 (Part I)-1974
80.	CM/L-9466 1981-02-23	81-02-01	82-02-28	Tropical Agro Systems (P) Ltd., 530/2B, Vanagaram Road, Athipet; Madras- 600058	Quinalphos EC- IS : 8028-1976
81.	CM/L-9467 1981-02-23	81-03-01	82-02-28	Baidyanath Iron & Steel (P) Ltd. Baijnath- pur P.O. Baidyanath-Deoghar	Cold-worked steel high strength deformed bars for concrete reinforcement— IS : 1786-1966
82.	CM/L-9468 1981-02-24	81-03-01	82-02-28	B.K. Industrial Corpn., 7, Kali Temple Road., P.O. Nimta, Calcutta-700049 (Office : 180 Netaji Subhas Road, First Floor, Calcutta-700001)	Horizontal centrifugal pumps for clear, cold, fresh water for agricultural pur- poses, size-80mm x 65mm 7 speed-1500 RPM duty point-at 15m head, discharge 8.30 lpm efficiency 60% and pump input 3.5 kw— IS : 6595-1972
83.	CM/L-9469 1981-02-24	81-03-01	82-02-28	Kantilal Chunilal & Sons Appliances Pvt. Ltd., 3, Jawahar Road, Udhna-394210 Dist. Surat.	Single phase, 240 V, 50 cycles, immersion water heater upto 20 kw rating— IS : 368-1977
84.	CM/L-9470 1981-02-25	81-03-01	82-02-28	Agro Industrial Chemicals Co., 13 A, Kalyani View, Rudrapur-263153 Distt. Nainital (U.P.)	Aldrin EC— IS : 1307-1973
85.	CM/L-9471 1981-02-25	81-03-01	82-02-28	Golden Chemical Works, 2, Industrial De- velopment Colony, P.O. Rayon Silk Mills, Amritsar-143104 (Office : 8 Akali Market, Amritsar)	Ready mixed paint, finishing interior for general purposes, to Indian standard colours— IS : 3537-1966
86.	CM/L-9472 1981-02-26	81-03-01	82-02-28	Kanpur Plastipack Pvt. Ltd., D-19, Panki Industrial Area, P.O. Udyog Nagar, Kanpur-208022 (UP)	Laminated jute bags manufactured from 380 g/m ² ; 68x39 (14 oz/45 in; 4x10) tarpaulin fabric— IS : 7406 (Part II)-1980
87.	CM/L-9473 1981-02-27	81-03-01	82-02-28	B.K. Industrial Corpn; 7, Kali Temple Road, P.O. Nimta, Calcutta-700049 (W.B.) (Office : 18, Netaji Subhas Road, 1st Floor, Calcutta-700001)	Verticle single cylinders four strokes water cooled, diesel, engine of the following ratings: out-put : 3.67 kw (bhp) speed 1500 RPM governing-class 'B' SFC : 269g/kwh (198g/bhph)— IS : 1601-1960
88.	CM/L-9474 1981-02-27	81-03-16	82-03-15	Industrial Engg. Works, 16, Sardar Pratap Singh Marg, Bhandup, Bombay-400078.	Structural steel (standard quality)— IS : 226-1975
89.	CM/L-9475 1981-02-27	81-03-16	82-03-15	Himalayan Industries, Industrial Estate, Arundhuri Nagar, Shed No 22 & 23, Agartala, Tripura.	High density polyethylene pipes for potable water pipes sizes 90mm class 5 and 110mm class 4— IS : 4984-1978
90.	CM/L-9476 1981-02-27	81-03-01	82-02-28	Koba Suspension Co., Plot No. 15, Sector 6, Faridabad (Haryana)	Leaf springs for automobile suspension spring leaves only— IS : 1135-1973
91.	CM/L-9477 1981-02-27	81-03-01	82-02-28	Kavisa Cables, 5 B, Sector II, NOIDA, Distt. Ghaziabad (U.P.)	PVC insulated cables for working voltages upto and including 1100V sheathed and unsheathed with aluminum conductor only excluding cables for low tempera- ture conditions— IS : 694-1977
92.	CM/L-9478 1981-02-27	81-03-16	82-03-15	ENPI Chemical Works, 135-B, Kval Byra- sandra, Bangalore-560006 (Karnataka)	Titanium dioxide, food grade— IS : 8356-1977

1	2	3	4	5	6
93.	CM/L-9479 1981-02-27	81-03-16	82-03-15	Union Pesticides, Shri Ram Nagar, Vidisha (M.P.)	Endosulfan EC— IS : 4323—1967
94.	CM/L-9480 1981-02-27	81-03-16	82-03-15	S. Karr & Co.(P) Ltd., 4 D, Dharmatolla Road, Calcutta-700039 (W.B.) (Office : 49 E Purna Dass Road, Calcutta-700029)	Ferro-gallo tannate fountain pen ink (0.1 percent iron content)— IS : 220—1972
95.	CM/L-9481 1981-02-27	81-03-16	82-03-15	Guru Ram Dass Iron & Steel Rolling Mills, Guru Ki Nagari, Mandi Gobindgarh (Punjab)	Structural steel (standard quality)— IS : 226—1975
96.	CM/L-9482 1981-02-27	81-03-16	82-03-15	Vipon Kumar Oberoi & Co., Khujuri Road, Yamunanagar-135001	Plywood teachests battens— IS : 10 (Part III)—1974
97.	CM/L-9483 1981-02-27	81-03-01	82-02-28	Soma Plumbing Fixtures Ltd., 64/6, Site No. 4 Industrial Area, Sahibabad-201005 Ghaziabad (U.P.)	Ball valves (horizontal 'plunger type) size 15 mm— IS : 1703—1977
98.	CM/L-9484 1981-02-27	81-03-01	82-02-28	Delhi Paper Products Co., 19, Gurgaon Road, Kapasheda, New Delhi-110037 (Office : E-34, Connaught Place, New Delhi-110001)	One time carbon paper, type A— IS : 9055—1979
99.	CM/L-9485 1981-02-27	81-03-01	82-02-28	Indane Cables, Nehru Road, Bhiwani-125021	PVC insulated sheathed and unsheathed with cables with aluminium conductors for working voltages upto and including 1100 volts (excluding cables for low temperature conditions)— IS : 694—1977
100.	CM/L-9486 1981-02-27	81-03-16	82-03-15	Inca Cables Pvt Ltd., 149, Tambaram Vela-cherry Road, Sembakkam, Madras.	Single core PVC insulated and PVC sheathed cables with aluminium conductors for working voltages upto and including 1100 volts, excluding cables for outdoor use and low temperature applications— IS : 694—1977

[No. CMD/13 : 11]

क्र० आ० 4242.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन मुहर) विधम और विनियम, 1955 के नियम 3 के उपनियम (2) और विनियम 3 के उपनियम (2) और (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे अनुसूची में जिन भारतीय मानकों के विवरण दिए गए हैं, वे 1981-04-30 को निर्धारित किए गए हैं :

अनुसूची

क्रम सं०	निर्धारित भारतीय मानक की पद संख्या और शीर्षक	नए भारतीय मानक द्वारा रद्द किए गए भारतीय मानक, यदि कोई हो की पद संख्या और शीर्षक	टिप्पणी यदि कोई हो तो
(1),	(2)	(3)	(4)
1.	IS : 500—1980 पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइट फोटोग्राफी की विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण)	IS : 500—1972 पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइट फोटोग्राफी ग्रेड की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	—
2.	IS : 955—1980 दमकल प्रयोग के लिए शुल्क पाउडर टैंकर की कार्यकारिता संबंधी अपेक्षाएं (पहला पुनरीक्षण)	IS : 955—1974 दमकल प्रयोग के लिए शुल्क पाउडर टैंकर	—
3.	IS : 1667—1981 टाकियों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	IS : 1667—1971 टाकियों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	—
4.	IS : 1748—1981 ट्रेफाइट चड़ियों का आकार (पहला पुनरीक्षण)	IS : 1748—1961 ट्रेफाइट चड़ियों का आकार	—
5.	IS : 2191 (भाग 2)—1980 लकड़ी के सपाट किबाड़ों (कोशिकीय और खोखले ट्रेड टा प) की विशिष्टि भाग 2 पार्टीकल बोर्ड और हार्ड बोर्ड के बिल्ले वाले (दूसरा पुनरीक्षण)	IS : 2191 (भाग 2)—1966 लकड़ी के सपाट किबाड़ों (कोशिकीय और खोखले फोड टाइप) की विशिष्टि भाग 2 पार्टीकल बोर्ड के बिल्ले वाले (पहला पुनरीक्षण)	—

(1)	(2)	(3)	(4)
6. IS : 2202 (भाग 2)—1980 लकड़ी के सपाट किबाड़ों (डोस कोड टाइपर) की विशिष्टि : भाग 2 पार्टीकल बोर्ड प्रोर हार्ड बोर्ड के बिस्ले वाले (दूसरा पुनरीक्षण)	IS : 2202 (भाग 2)—1966 लकड़ी के सपाट किबाड़ों (डोस कोड टाइप) की विशिष्टि : भाग 2 पार्टीकल बोर्ड के बिस्ले वाले (पहला पुनरीक्षण)	—	
7. IS : 3013—1980 केरोबोरान की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	IS : 3013—1972 केरोबोरान की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	—	
8. IS : 3028—1980 सड़क पर चलने वाहनों के शोर मापन (पहला पुनरीक्षण)	IS : 3028—1965 मोटर वाहनों के शोर मापन पद्धति	—	
9. IS : 3040—1980 भारतीय सेमल की रुई की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 3040—1965 गद्दा भारी के लिए भारतीय सेमल की रुई की विशिष्टि	—	
10. IS : 3189—1981 पटसन उद्योग के लिए तीव्र गति वाले अटेरनों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 3189—1965 पटसन के लिए तीव्र गति वाले अटेरनों की विशिष्टि	—	
11. IS : 3488—1980 गढ़ाई के लिए उपयुक्त पीतल के सरियों वंशों प्रोर सेक्शनों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 3488—1966 गढ़ाई के लिए उपयुक्त पीतल के सरियों वंशों प्रोर सेक्शनों की विशिष्टि	—	
12. *IS : 4449—1980 विहृस्क्रियों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	IS : 4449—1976 विहृस्क्रियों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	—	*भा०मा०सं० प्रमाणन चिह्न योजना के उद्देश्यों के लिए IS : 4445—1980 1981-07-31 से लागू
13. IS : 4681—1981 क्रीज मिटाने के कोण नाप द्वारा चुन हटने पर बड़े हुए कपड़े की मात्रा ज्ञात करने की पद्धति (पहला पुनरीक्षण)	IS : 4681—1968 सिक्कुडन हटने पर बड़े हुए कपड़े की मात्रा ज्ञात करने की पद्धति (क्रीज मिटाने के कोण-नाप द्वारा)	—	
14. IS : 4757—1980 संवेष्टित बुसों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 4757—1968 संवेष्टित बुसों प्रोर प्रणोद बाशरों के माप	—	
15. IS : 4985—1981 पेय जल पूर्ति के लिए अनम्यकृत पीबीसी पाइपों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 4985—1968 पेय जल पूर्ति के लिए अनम्यकृत पीबीसी पाइपों की विशिष्टि	1981-07-31	
16. IS : 5054—1980 3 मेगा हटेंज से अधिक के रेडियों प्रावृत्ति संयोजकों की सामान्य प्रपेक्षाओं प्रोर परीक्षण पद्धतियों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 5054 (भाग 1)—1969 रेडियों प्रावृत्ति संयोजकों की विशिष्टि : भाग 1 सामान्य प्रपेक्षाएं प्रोर परीक्षण पद्धतियां	—	
17. IS : 5154—1980 लेड ऐसिड कर्षण बैटरियों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 5154—1969 लेड ऐसिड कर्षण बैटरियों की विशिष्टि	—	
18. IS : 5226—1980 ग्रांज की कार्निया-स्वेत पटल डिस्क ईलियट नमूने की चिमटियों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 6226—1969 ग्रांज की कार्निया-स्वेत पटल डिस्क ईलियट नमूने की चिमटियों की विशिष्टि	—	
19. IS : 6250—1981 छत डालने में प्रयुक्त स्लेट टाइलों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 6250—1971 छत डालने में प्रयुक्त स्लेट टाइलों की विशिष्टि	—	
20. IS : 7148—1980 बेल्डन उद्योग के लिए लोह मिश्र धातुओं की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 7148—1973 बेल्डन उद्योग के लिए लोह मिश्र धातुओं की विशिष्टि	—	
21. IS : 7687—1980 दूरसंचार के लिए प्रेरकों प्रोर ट्रांसफार्मरों के क्रोडों की मापन पद्धतियां (पहला पुनरीक्षण)	IS : 7687—1974 दूरसंचार के लिए प्रेरकों प्रोर ट्रांसफार्मरों के क्रोडों की मापन पद्धतियां	—	
22. IS : 7703 (भाग 4)—1981 सतत फिलामेंट पालियस्टर प्रोर पालिमाइड के फ्लेट भागे की परीक्षण पद्धतियां भाग 4 नमूने लेना	—	—	
23. IS : 7784 (भाग 2) (खंड 2)—1980 कास जल निकास तंत्र के डिजाइन की रीति संहिता : भाग 2 विशिष्ट प्रपेक्षाएं खंड 2 ऊपर वाली नलियां	—	—	
24. IS : 7784 (भाग 2/खंड 5)—1980 कास जल निकास तंत्र के डिजाइन की रीति संहिता : भाग 2 विशिष्ट प्रपेक्षाएं खंड 5 साइफननुमा जल नलियां	—	—	
25. IS : 8190 (भाग 2)—1980 फसल कीटनाशियों की पैकिंग संबंधी प्रपेक्षाएं : भाग 2 तरल फसल कीटनाशी (पहला पुनरीक्षण)	—	—	
26. IS : 8198 (भाग 9)—1980 संपीड़न गैसों के लिए इस्पात सिलिंडरों की रीति संहिता : भाग 9 सल्फरडाई गैस	—	—	

(1)	(2)	(3)	(4)
27. IS : 9001 (भाग 7)—1980 पर्यावरणीय परीक्षण की मार्गदर्शिका : भाग 7 सम्पर्क और संबंधन के लिए सल्फर डाइऑक्साइड परीक्षण		—	—
28. IS : 9080 (भाग 2/खंड 4)—1981 विद्युत ताप संस्थापनाओं में सुरक्षा प्रपेक्षाएं : भाग 2 प्रतिरोध तापन उपकरणों की विशेष प्रपेक्षाएं खंड 4 वांतिश और ऐसे ही अन्य उद्देश्यों को सुझाने में प्रयुक्त संस्थापनाओं में सुरक्षा		—	—
29. IS : 9080 (भाग 4)—1981 विद्युत ताप संस्थापनाओं में सुरक्षा प्रपेक्षाएं : भाग 4 ब्रॉक अट्टी संस्थापनाओं की विशेष प्रपेक्षाएं		—	—
30. IS : 9302 (भाग 9/खंड 1)—1980 ध्वनि तंत्र उपकरण के लक्षण और मापन पद्धतियां : भाग 9 प्रोग्राम लेबल मापी खंड 1 सामान्य		—	—
31. IS : 9302 (भाग 9/खंड 2)—1980 ध्वनि तंत्र उपकरण के लक्षण और मापन पद्धतियां भाग 9 प्रोग्राम लेबल मापी : खंड 2 शीर्ष प्रोग्राम मापी, टाइप		—	—
32. IS : 9302 (भाग 9/खंड 3)—1981 ध्वनि तंत्र उपकरण के लक्षण और मापन पद्धतियां : भाग 9 प्रोग्राम लेबल मापी खंड 3 शीर्ष प्रोग्राम मापी, टाइप 2		—	—
33. IS : 9645—1980 सूक्ष्मवार प्लगों की विशिष्टि		—	—
34. IS : 9666—1980 ब्लेक ग्रेन्यूल की विशिष्टि		—	—
35. IS : 9667—1980 ट्राइडेमार्क तकनीकी की विशिष्टि		—	—
36. IS : 9671—1980 वायुयान जनित ध्वनि मापन के लिए प्रावृत्ति चारॉकन (डी-चारांकन) की विशिष्टि		—	—
37. IS : 9675—1980 बुने हुए सूती कौतों, हल्के, मध्यम और भारी गुणता वाले की विशिष्टि		—	—
38. IS : 9678—1980 विद्युत उपकरणों की तापक वृद्धि मापने पद्धतियां		—	—
39. IS : 9682—1980 डलवां तावां डूवीयों के निरीक्षण की अभिस्तावित प्रक्रिया		—	—
40. IS : 9686—1980 लचीले कौते की विशिष्टि		—	—
41. IS : 9690—1980 डीकर हॉक उपकरण द्वारा बामु मेद्यता पद्धति से क्रीसोटोइल एसबेस्टोस रेशो का रेशायन ज्ञात करने की परीक्षण पद्धति		—	—
42. IS : 9691—1980 बावर मेकनेट वर्गीकारक द्वारा क्रीसोटोइल एसबेस्टोस रेशो की लम्बाई के वर्गीकरण (रेशा लम्बाई का आद्र पद्धति द्वारा वर्गीकरण) की परीक्षण पद्धति		—	—
43. IS : 9699—1981 रौतों की लम्बी टांकी की विशिष्टि		—	—
44. IS : 9700—1981 सक्रियित एलुमिना की विशिष्टि		—	—
45. IS : 9705 (भाग 1)—1980 निर्वीत पाहप लाहनों के लिए दूत-मोचन युग्मक की विशिष्टि : भाग 1 पेंचदार युग्मक टाइप की		—	—
46. IS : 9707—1981 वायुचालित पेंचकसों और नट रनरों की विशिष्टि		—	—
47. IS : 9709—1980 एक क्रिस्टल वाले संश्लिष्ट स्फटिक की विशिष्टि		—	—
48. IS : 9711—1980 समक्रमिक स्पन्ध जनित की विशिष्टि		—	—
49. IS : 9712—1981 केक की विशिष्टि		—	—
50. IS : 9714—1981 मोपेड के नियंत्रणों, सूचकों और स्थित सूचकों के चिह्न		—	—

*भा मा सं० प्रमाणन चिह्न योजना के उद्देश्यों के लिए IS : 9671—1980 1981-07-15 से लागू होगा ।

1	2	3	4
51.	IS : 9715—1981 इस्पात की दृश्य सूचीकरण प्रणाली वाली अलमारियों की विशिष्टि	—	—
52.	IS : 9717—1980 दस्त्य ग्रंथन टू की विशिष्टि	—	—
53.	IS : 9723—1981 मशीन औजारों के निर्माण के लिए माड्यूलिय इकाईयों के माप-बहु-नकू शीर्ष-केसन और निवेश भाग दंड के माप	—	—
54.	IS : 9724 (भाग 1)—1981 तेल चालित युग्मकों के लिए टी आकार के ग्रावदुम मेल स्टड (स्टड भाग) की विशिष्टि भाग 1 गड़ी वस्तुओं से बने	—	—
55.	IS : 9724 (भाग 2)—1981 तेल चालित युग्मकों के लिए टी आकार के ग्रावदुम मेल स्टड (स्टड भाग) की विशिष्टि भाग 2 बार स्टड के बने	—	—
56.	IS : 9725 (भाग 1)—1981 तेल चालित युग्मकों के लिए टी आकार के मेल स्टड (स्टड भाग) की विशिष्टि भाग 1 गड़ी वस्तुओं से बने	—	—
57.	IS : 9726—1981 मोपेड के भार वर्ग और परिभाषाएं	—	—
58.	IS : 9742—1981 ऊष्मा रोधन के लिए फुहार की गई खनिज लई की विशिष्टि	—	—

इन भारतीय मानकों की प्रतियां ब्रिटी के लिए भारतीय मानक संस्था, मानक भवन, 9 ब्रह्मपुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 और ग्रहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, बम्बई, कलकत्ता, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मद्रास, पटना और त्रिवेन्द्रम स्थित शाखा कार्यालयों में उपलब्ध है।

[संख्या सी.एम.बी./13 : 2]

ए०एस०बीमा, अपर महानिदेशक

S.O. 4242—In pursuance of sub-rule (2) of Rule 3 sub-regulations (2) and (3) of regulation 3 of Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules and Regulations, 1955, the Indian Standards Institution hereby notifies that the Indian Standard(s), particulars of which are given in the Schedule hereto annexed, have been established on 1981-04-30 :

SCHEDULE

Sl. No.	No. and Title of the Indian Standards Established	No. and Title of the Indian Standard or Standards, if any, superseded by the new Indian Standard	Remarks if any
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS : 500—1980 Specification for potassium metabisulphite, photographic grade (third revision)	IS : 500—1972 Specification for potassium metabisulphite photographic grade. (second revision)	—
2.	IS : 955—1980 Functional requirement for dry powder tender for fire brigade use (first revision)	IS : 955—1964 Dry powder tender for fire brigade use	—
3.	IS : 1667—1981 Specification for toffees (second revision)	IS : 1667—1971 Specification for toffees (first revision)	—
4.	IS : 1748—1981 Sizes of graphite crucibles (first revision)	IS : 1748—1961 Size of graphite crucibles	—
5.	IS : 2191 (Part II)—1980 Specification for wooden flush door shutters (cellular and hollow core type) : Part II Particle board and hardboard face panels (second revision)	IS : 2191 (Part II)—1966 Specification for wooden flush door shutters (cellular and hollow core type) : Part II Particle board face panels (first revision)	—
6.	IS : 2202 (Part II)—1980 Specification for wooden flush door shutters (solid type) : Part II Particle board and hardboard face panels (second revision)	IS : 2202 (Part II)—1966 Specification for wooden flush door shutters (solid core type) : Part II Particle board face panels (first revision)	—
7.	IS : 3013—1980 Specification for ferroboron (second revision)	IS : 3013—1972 Specification for ferroboron (first revision)	—

(1)	(2)	(3)	(4)
8. IS : 3028—1980 Measurement of noise emitted by moving road vehicles (first revision)	IS : 3028—1965 Method of measurement of noise emitted by motor vehicles	—	
9. IS : 3040—1980 Specification for Indian kapok (first revision)	IS : 3040—1965 Specification for Indian kapok for stuffing purposes	—	
10. IS : 3189—1981 Specification for high-speed bobbins for jute industry (first revision)	IS : 3189—1965 Specification for high speed jute bobbins	—	
11. IS : 3488—1980 Specification for brass bars, rods and sections suitable for forging (first revision)	IS : 3488—1966 Specification for brass bars, rods and sections suitable for forging	—	
12.* IS : 4449—1980 Specification for whiskies (second revision)	IS : 4449—1976 Specification for whiskies (first revision)	*For purposes of ISI Certification Marks Scheme; IS : 4449—1980 shall come into force with effect from 1981-07-31	
13. IS : 4681—1981 Method for determination of recovery from creasing of textile fabrics by measuring the angle of recovery (first revision)	IS : 4681—1968 Method for determination of wrinkle recovery of fabrics (by measuring crease recovery angle)	—	
14. IS : 4757—1980 Specification for wrapped bushes (first revision)	IS : 4757—1968 Dimensions for wrapped bushes and thrust washers	—	
15. IS : 4985—1981 Specification for unplasticized PVC pipes for potable water supplies (first revision)	IS : 4985—1968 Specification for unplasticized PVC pipes for potable water supplies	—	1981-07-31
16. IS : 5054—1980 Specification for general requirements and methods of tests for radio frequency connector above 3 MHz (first revision)	IS : 5054 (Part I)—1969 Specification for radio frequency connectors : Part I General requirements and tests	—	
17. IS : 5154—1980 Specification for lead-acid traction batteries (first revision)	IS : 5154—1969 Specification for lead-acid traction batteries	—	
18. IS : 5226—1980 Specification for forceps, eye, corneo cleral disc, Elliot's pattern (first revision)	IS : 5226—1969 Specification for forceps, eye, corneo cleral disc (Elliot's pattern)	—	
19. IS : 6250—1981 Specification for roofing slate tiles (first revision)	IS : 6250—1971 Specification for roofing slate tiles	—	
20. IS : 7148—1980 Specification for ferro-alloys for welding industry (first revision)	IS : 7148—1973 Specification for ferro-alloys for welding industry	—	
21. IS : 7687—1980 Methods of measurement for cores for inductors and transformers for telecommunications (first revision)	IS : 7687—1974 Methods of measurement for cores for inductors and transformers for telecommunications	—	
22. IS : 7703 (Part IV)—1981 Methods for test for continuous filament polyester and polyamide flat yarn : Part IV Sampling	—	—	
23. IS : 7784 (Part II/Sec 2)—1980 Code of practice for design of cross drainage works; Part II Specific requirements: Section 2 Superpassages	—	—	
24. IS : 7784 (Part II/Sec 5)—1980 Code of practice for design of cross drainage works : Part II Specific requirements : Section 5 Syphon aque-ducts	—	—	
25. IS : 8190 (Part II)—1980 Requirements or packing of pesticides : Part II Liquid pesticides (first revision)	IS : 8190 (Part II)—1976 Requirements for packing of pesticides : Part II Liquid pesticides	—	

1	2	3	4
26.	IS : 8198 (Part IX)—1980 Code of practice for steel cylinders for compressed gases : Part IX Sulphur dioxide gas	—	—
27.	IS : 9001 (Part VII)—1980 Guidance for environmental testing : Part VII Sulphur dioxide test for contacts and connections	—	—
28.	IS : 9080 (Part II/Sec 4)—1981 Safety requirements in electro-heat installations : Part II Particular requirements for resistance heating equipment : Section 4 Protection in installations used for drying varnishes and other similar products	—	—
29.	IS : 9080 (Part IV)—1981 Safety requirements in electro-heat installations : Part IV Particular requirements for arc furnace installations	—	—
30.	IS : 9302 (Part IX/Sec 1)—1980 Characteristics and methods of measurement for sound system equipment : Part IX Programme level meters : Section 1 General	—	—
31.	IS : 9302 (Part IX/Sec 2)—1980 Characteristics and methods of measurement for sound system equipment : Part IX Programme level meters : Section 2 Peak programme meters, type I	—	—
32.	IS : 9302 (Part IX/Sec 3)—1981 Characteristics and methods of measurements for sound system equipment : Part IX Programme level meters : Section 3 Peak programme meters type II	—	—
33.	IS : 9645—1980 Specification for threaded plugs	—	—
34.	IS : 9666—1980 Specification for blank granules	—	—
35.	IS : 9667—1980 Specification for tridemorph, technical	—	—
36.*	IS : 9671—1980 Specification for frequency weighting for the measurement of aircraft noise (D-weighting)	—	—
37.	IS : 9675—1980 Specification for woven cotton tapes, light medium and heavy qualities	—	—
38.	IS : 9678—1980 Methods of measuring temperature-rise of electrical equipment	—	—
39.	IS : 9682—1980 Recommended procedure for inspection of cast copper tuyeres	—	—
40.	IS : 9686—1980 Specification for elastic tape	—	—
41.	IS : 9690—1980 Methods of test for determination of openness or fiberization of chrysotile asbestos fibre by air permeability methods using dyckerhoff apparatus	—	—
42.	IS : 9691—1980 Method of test for length distribution (wet classification of fibre length) of chrysotile asbestos fibre using bauer-McNett classifier	—	—
43.	IS : 9699—1981 Specification for chisel, dental, large	—	—
44.	IS : 9700—1981 Specification for activated alumina	—	—

*For purposes of ISI Certification marks Scheme;
IS : 9671—1980 shall come into force with effect from 1981-07-15

(1)	(2)	(3)	(4)
45.	IS : 9705 (Part I)—1980 Specification for quick release coupling for vacuum pipe lines : Part I Screwed couplings type B	—	—
46.	IS : 9707—1981 Specification for pneumatic screw drivers and nut runners	—	—
47.	IS : 9709—1980 Specification for synthetic quartz single crystal	—	—
48.	IS : 9711—1980 Specification for synchronizing pulse generator	—	—
49.	IS : 9712—1981 Specification for cakes	—	—
50.	IS : 9714—1981 Symbols for controls, indicators and tell-tales for mopeds	—	—
51.	IS : 9715—1981 Specification for steel visible indexing system cabinets	—	—
52.	IS : 9717—1980 Specification for trays, impression, dental	—	—
53.	IS : 9723—1981 Dimensions for modular units for machine tool construction—multi-spindle heads-casing and input drive shaft dimensions	—	—
54.	IS : 9724 (Part I)—1981 Specification for taper male stud tee body (stud branch) for oil-hydraulic couplings : Part I Made from forgings	—	—
55.	IS : 9724 (Part II)—1981 Specification for taper male stud tee body (stud branch) for oil-hydraulic couplings : Part II Made from bar stock	—	—
56.	IS : 9725 (Part I)—1981 Specification for male stud tee body (stud branch) for oil-hydraulic couplings : Part I Made from forgings	—	—
57.	IS : 9726—1981 Denominations and definitions of weights of mopeds	—	—
58.	IS : 9742—1981 Specification for sprayed mineral wool thermal insulation	—	—

Copies of these Indian Standards are available for sale with the Indian Standards Institution, Manak Bhavan, 9 Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110002 and also from its branch offices at Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhuvaneshwar, Bombay, Calcutta, Chandigarh, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Madras, Patna and Trivandrum.

[No. CMD/13 : 2].

A S CHEEMA, Addl. Director General

ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1984

का. आ. 4243.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकीहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजौरा-बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाठ्य अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाईन (भूमि में उप-

योग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आक्षेप एतद्द्वारा घोषित किया है।

बतर्क कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजिरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य—गुजरात

जिला—भरुच ता०—अकलेश्वर

गाँव	ब्लॉक नं०	हेक्टेयर	एकड़	सेन्टीयर
1	2	3	4	
डडास	9	0	32	77
	10	0	15	15
	11	0	10	20
	21	0	19	20
	23	0	35	48
	25	0	25	62
	26	0	21	41
	27	0	01	89
	28	0	12	89
	29	0	02	68
	51	0	28	97
	52	0	14	58
	132	0	39	60
	133/ग. + बी	0	19	50
	134	0	06	60
	144	0	12	25
	145	0	31	05
	146	0	04	46
काटे ट्रेक		0	03	00
154	0	10	58	
155	0	16	42	
	0	40	00	
156	0	24	80	
161	0	04	05	
162	0	32	45	
163	0	21	40	
164	0	24	25	
168	0	11	55	
Kotar	0	29	30	

[सं० 14016/110/84/जी० पी०]

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 20th November, 1984

S.O. 4243.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareilly-Jagdishpur in Gujarat State Pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Scheduled annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodra (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE
PIPELINE FROM HAJIRA TO BAREILLY TO
JAGDISHPUR

State : Gujarat

District : Bharuch

Taluka : Ankleshwar

Village	Block No.	Hec- tare	Are	Con- tinue
1	2	3	4	5
Dadhal	9	0	32	77
	10	0	15	15
	11	0	10	20
	21	0	19	20
	23	0	35	48
	25	0	25	62
	26	0	21	41
	27	0	01	89
	28	0	12	89
	29	0	02	68
	51	0	28	97
	52	0	14	58
	132	0	39	60
	133/A + B	0	19	50
	134	0	06	60
	144	0	12	25
	145	0	31	05
	146	0	04	46
	Cart track	0	03	60
	154	0	10	58
	155	0	16	42
	Cart track	0	40	00
	156	0	24	80
	161	0	04	05
	162	0	32	45
	163	0	21	40
	164	0	24	25
	168	0	11	55
	Kotar	0	29	30

[No. 'O-14016/110/84/GP]

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1984

का० अ० 4243:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) की अधीन भारत सरकार के उर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का० अ० सं० 2389 तारीख 7-7-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइन को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया है।

और यतः गृहम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार का रिपोर्ट दे दी है।

और, आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, जतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया गया है।

और, आगे, उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियाँ में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली में अगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य—गुजरात	जिला—वडोदरा	तालुका—करजण		
गांव	सर्वे न०	हेक्टर आर	सेन्टीयर	
1	2	3	4	5
छछवा	73	0	31	52
	78	0	00	16
	74	0	36	44
	75	0	19	04
	72	0	17	18
	69/3	0	37	66
	89	0	00	24
	89/1	0	13	92
	90	0	32	80
	88/2	0	02	08
	111/2	0	53	12
	112/1	0	05	28
	111/1	0	26	22
	109	0	28	00
	106/1	0	04	80
	106	0	00	48
	110	0	11	52
	103/2	0	20	48
	103/3	0	25	60
	103/1	0	23	52
	103/4	0	26	40
	104	0	02	56
	140	0	17	28
	141	0	14	88
	143/2	0	01	60
	143	0	34	40
	166/2	0	00	48
	16/1	0	21	12
	165	0	13	16
	164	0	18	08
	177	0	45	60
	174	0	00	16
	176	0	18	80
	182/2	0	08	16
	182/1	0	34	24
	184	0	11	68
	181/1/A	0	00	20
	185	0	10	88
	186	0	13	12
	187	0	00	10
	187/1	0	32	16
	188	0	16	40
	199/2	0	01	60
	306	0	20	16
	226	0	00	16

New Delhi, the 21st November, 1984

S.O. 4244.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 2389 dated 7-7-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule, appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline,

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances

SCHEDULE

PIPELINE FROM HAJIRA TO BAREILLY TO

JAGDISHPUR

State : Gujarat	District : Vadodara	Taluka : Karjan		
Village	Survey No.	Hec-tare	Ac-re	Centiare
1	2	3	4	5
Chanchava	73	0	31	52
	78	0	00	16
	74	0	36	44
	75	0	19	04
	72	0	17	18
	69/3	0	37	66
	89	0	00	24
	89/1	0	13	92
	90	0	32	80
	88/2	0	02	08
	111/2	0	53	12
	112/1	0	05	28
	111/1	0	26	22
	109	0	28	00
	106/1	0	04	80
	106	0	00	48
	110	0	11	52
	103/2	0	20	48
	103/3	0	25	60
	103/1	0	23	52
	103/4	0	26	40
	104	0	02	56
	140	0	17	28
	141	0	14	88
	143/2	0	01	60
	143	0	34	40
	166/2	0	00	48
	166/1	0	21	12
	165	0	13	16
	164	0	18	08
	177	0	45	60
	174	0	00	16
	176	0	18	80

1	2	3	4	5
	182/2	0	08	16
	182/1	0	34	24
	184	0	11	68
	181/1/A	0	00	20
	185	0	10	88
	186	0	13	12
	187	0	00	10
	187/1	0	32	16
	188	0	16	40
	199/2	0	01	60
	306	0	20	16
	226	0	00	16

[No. O-12016/59/84-ONG-D-4/GP]

का० आ० 4245 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के उर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का० आ० सं० 1647 तारीख 2-5-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना घोषित कर दिया था।

और यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रबत शक्ति का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रबत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजटय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप से घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजौरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य—गुजरात	जिला—बडोदरा	तालुका—वाघाडीया		
गांव	सर्वे न०	हेक्टर	आर	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
गुताल	605	0	26	24
	604	0	41	92
	620	0	50	72
	621/2	0	49	76
	602/2	0	02	88
	626/2	0	16	64
	593	0	87	04
	589	0	22	88
	588	0	25	44
	587	0	22	08

1	2	3	4	5
	765	0	32	96
	766	0	31	84
	768/2	0	05	28
	767/1	0	21	60
	767/2	0	22	72
	784	0	20	32
	785/7	0	05	44
	785/8	0	10	40
	783/2	0	21	76
	783/3	0	08	64
	782	0	12	96
	793/4	0	21	44
	793/2	0	09	12
	793/3	0	19	36
	794	0	06	88
	802/3	0	13	76
	802/2	0	02	88
	802/1	0	00	48
	801/1	0	15	52
	801/3	0	18	88
	800/1	0	24	00
	819	0	14	08
	818/2	0	14	72
	820	0	00	28
	827	0	15	36
	824	0	15	36
	825	0	21	28
	826	0	10	40
	836	0	13	28
	837	0	22	40
	838	0	01	76
	839/1	0	31	36
	839/2	0	16	00
	381	1	76	80
	869	0	18	40
	870/1	0	00	32
	346	0	44	00
	347	0	10	56
	345	0	00	16
	348	0	56	32
	349	0	76	04
	350	0	22	24
	352	0	49	12
	353	0	02	40
	354	0	40	16
	289	0	43	84
	288	0	27	76

[सं० O/12016/28/84 प्रोड/जी० पी०]

S.O. 4245.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 1647 dated 2-5-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 5 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule, appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly-Jagdishpur

State : Gujarat District : Vadodra Taluka : Vaghodiya

Village	Survey No.	Hec acre	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Gut:1	605	0	26	24
	604	0	41	92
	620	0	50	72
	621/2	0	49	76
	602/2	0	02	88
	626/2	0	16	64
	593	0	87	04
	589	0	22	88
	588	0	25	44
	587	0	22	08
	765	0	32	96
	766	0	31	84
	768/2	0	05	28
	767/1	0	21	60
	767/2	0	22	72
	784	0	20	32
	785/7	0	05	44
	785/8	0	10	40
	883/2	0	21	76
	783/3	0	08	64
	782	0	12	96
	793/4	0	21	44
	793/2	0	09	12
	793/3	0	19	36
	794	0	06	88
	802/3	0	13	76
	802/2	0	02	88
	802/1	0	00	48
	801/1	0	15	52
	801/3	0	18	88
	800/1	0	24	00
	819	0	14	08
	818/2	0	14	72
	820	0	00	28
	827	0	15	36
	824	0	15	36
	825	0	21	28
	826	0	10	40
	836	0	13	28
	837	0	22	40
	838	0	01	76

1	2	3	4	5
	839/1	0	31	36
	839/2	0	16	00
	381	1	76	80
	869	0	18	40
	870/1	0	00	32
	346	0	44	00
	347	0	10	56
	345	0	00	16
	348	0	56	32
	349	0	76	04
	350	0	22	24
	352	0	49	12
	353	0	02	40
	354	0	40	16
	289	0	43	84
	288	0	27	76

[No. O-12016/28/84-Prod./GP]

कां०आ० 4246,---यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का.आ.सं. 2523 तारीख 19-7-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आणव्य घोषित कर दिया।

और यतः, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया गया है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजिरा से धरेली से जयदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला—वडोदरा तालुका—डमोई

गांव	खस/क.नं०	हेक्टर	आर	सेंटीयर
बीगवार	159	0	16	48
	158	0	01	92
	157	0	12	48
	काटं ट्रेक	0	00	48
	156	0	22	56
	156	0	19	04
	155	0	17	28
	154	0	15	66
	153	0	00	16
	152	0	01	28

[सं० O-12016/60/84/प्रो.एन०जी.-बी-4/जी०पी०]

S.O. 4246.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 2523 dated 19-7-84 under sub-section (1) Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule, appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declarations in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira to Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Dabhoi

Village	Block No.	Hec- tare	Are Cent-	Cent-
Borbar	159	0	16	48
	158	0	01	92
	157	0	12	48
	Cart track	0	00	48
	156	0	22	56
	156	0	19	04
	155	0	17	28
	154	0	15	66
	153	0	00	16
	152	0	01	28

[No. O-12016/60/84/ONG-D-4/GP]

कां० प्रा० 4247.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना कां० प्रा० सं० 2533 तारीख 20-7-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है की इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया गया है।

1146 GI/84-6

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात	जिला—वडोदरा	तालुका—डभोई		
गांव	सब न०	हेक्टेयर एमार्स	सेंटीयर	
काड़ाधारपुरा	बेकार भूमि	0	02	40
	57	0	01	12
	56	0	14	56
	55	0	30	88
	54	0	03	36
	51	0	23	68
	49	0	12	96
	50	0	13	12
	63/1	0	18	94
	63/2	0	04	08
	61	0	31	44
	60/पी	0	35	52
	32	0	01	92
	31	0	40	16
	28	0	55	04
	27	0	06	40
	बेकार भूमि	0	07	99

[सं० O-12016/62/84-ओ एनजी-डी-4/जी पी]

S.O. 4247.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 2533 dated 20-7-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule, appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declarations in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Barelilly-Jagdishpur

State : Gujarat	District : Vadodara	Taluka : Dabhoi		
Village	Survey No.	Hec- tare	Are	Centi- tare
Kadadharpura	Waste land	0	02	40
	57	0	01	12
	56	0	14	56
	55	0	30	88
	54	0	03	36
	51	0	23	68
	49	0	12	96
	50	0	13	12
	63/1	0	18	94
	63/2	0	04	08
	61	0	31	44
	60/P	0	35	52
	32	0	01	9
	31	0	40	162
	28	0	55	04
	27	0	06	40
	Waste land	0	07	99

[N.O. O-12016/62/84/ONG-D-4-GP]

का०धा० 4248.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का०धा० सं० 2532 तारीख 20-7-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए प्रजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और प्राये, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करते के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार प्रजित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है की इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा प्रजित किया गया है।

और प्राये उम धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्वेश वेसी है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए
राज्य:—गुजरात तालुका—बडोदरा तालुका—डमोई

गांव	ब्लाक नं०	हेक्टेयर	घार	सेंटीघर
1	2	3	4	5
छत्राल	बाउन्डी	0	10	00
	442	0	01	44
	441	0	01	60
	437	0	58	40

1	2	3	4	5
	386	0	26	08
	389	0	38	72
	390	0	11	52
	391	0	29	20
	393	0	18	64
	काटे टुक	0	08	00
	394	0	09	76
	337	0	22	88
	338	0	00	16
	383	0	37	68
	382	0	24	64
	378	0	64	16
	379	0	12	96
	369	0	27	20
	370	0	39	52
	371	0	17	12
	363	0	07	52
	356	0	16	00
	354	0	03	52
	345	0	27	00
	343	0	08	32
	344	0	20	04
	333	0	24	96
	334	0	04	32
	244	0	00	16
	246	0	26	08
	247	0	12	16
	254	0	01	76

[सं० O-12016/63/84/घो.पू.मं.जी.-डी-4/जी०पी०]

S.O. 4248.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 2532 dated 20-7-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule, appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM HAJIRA-BAREILLY-JAGDISHPUR

State : Gujarat District : V. d. d. Taluka : D. bhoi

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Centi-are
1	2	3	4	5
Chhatra I	Boundary	0	10	00
	442	0	01	44
	441	0	01	60
	437	0	58	40
	386	0	26	08
	389	0	38	72
	390	0	11	52
	391	0	29	20
	393	0	18	64
	Cart track	0	08	00
	394	0	09	76
	337	0	22	88
	338	0	00	16
	383	0	37	68
	382	0	24	64
	378	0	64	16
	379	0	12	96
	369	0	27	20
	370	0	39	52
	371	0	17	12
	363	0	07	52
	355	0	16	00
	354	0	03	52
	345	0	28	00
	343	0	08	32
	344	0	20	04
	333	0	24	96
	334	0	04	32
	244	0	00	16
	246	0	26	08
	247	0	12	16
	254	0	01	76

[No. O-12016/63/84-ONG-D-4/GP]

कां.प्र. 4249.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना कां.प्र.सं. 2384 तारीख 7-7-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया गया है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और

प्राकृतिक गैस प्रायोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा,

अनुसूची

हजिरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए राज्य—गुजरात जिला—बड़ोदरा तालुका—बभोद

गांव	ब्लॉक नं०	हेक्टेयर	घर	सेंटीघर
1	2	3	4	5
गिकरीया	77	0	28	32
	64	0	04	32
	74	0	04	48
	65	0	20	80
	66	0	17	76
	67	0	19	20
	58	0	02	40
	57	0	17	76
	56	0	41	62
	56/पी	0	24	96
	51	0	00	16
	110	0	21	44
	50	0	36	00
	111	0	11	36
	112	0	24	32
	166	0	22	24
	165	0	21	22
	164	0	26	72
	171	0	28	96

[सं. O-12016/65/84/प्र एम जी-बी-4/जी पी]

S.O. 4249.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 2384 dated 7-7-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule, appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM HAJIRA-BAREILLY-JAGDISHPUR

State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Dabhoi

Village	Block No.	Hec- tare	Are	Centi- tiare
Thikariya	77	0	28	32
	64	0	04	32
	74	0	04	48
	65	0	20	80
	66	0	17	76
	67	0	19	20
	58	0	02	40
	57	0	17	76
	56	0	41	62
	56/P	0	24	96
	51	0	00	16
	110	0	21	44
	50	0	36	00
	111	0	11	36
	112	0	24	32
	166	0	22	24
	165	0	21	22
	164	0	26	72
	171	0	28	96

[No. O-12016/65/84-ONG-D-4/GP]

कां० प्रा० 4250.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना कां० प्रा० सं० 2396 तारीख 12-7-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और ध्याते, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है की इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया गया है।

और ध्याते उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्वेण वेतो है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए
राज्य—गुजरात जिला—वडोदरा तालुका—डभोई

गांव	ब्लॉक नं०	हेक्टेयर एप्रार्ड	सेंटीयर
1	2	3	4
पारिखा	54	0	08
	38	0	07
	53	0	32
	56	0	33

1	2	3	4	5
	57	0	00	16
	67	0	29	28
	68	0	17	60
	69	0	21	60
	70	0	17	60
	73	0	07	20
	74	0	00	16
	72	0	20	00
	71	0	04	48
	काटे टैक	0	06	40
	306	0	02	56
	308	0	16	00
	305	0	31	20
	304	0	00	80
	188	0	05	76
	189	0	33	82
	190	0	13	60
	191	0	00	80
	205	0	00	32
	204	0	16	32
	203	0	13	60
	202	0	13	12
	201	0	06	08
	215	0	08	80
	216	0	05	44
	217	0	02	56
	218	0	33	12
	277	0	13	12
	232	0	11	84
	233	0	17	60
	274	0	09	60
	236	0	22	56
	235	0	11	20
	237	0	08	00
	152	0	04	00
	वाजन्की	0	06	00

[सं. O-12016/66/84 ओ एन जी-डी-4/जी पी]

S.O. 4250.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 2396 dated 12-7-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule, appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM HAJIRA-BAREILLY-JAGDISHPUR

State : Gujarat District : Vadodra Taluka : Dabhoi

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Parikha	54	0	08	16
	38	0	07	68
	53	0	32	00
	56	0	33	12
	57	0	00	16
	67	0	29	28
	68	0	17	60
	69	0	21	60
	70	0	17	60
	73	0	07	20
	74	0	00	16
	72	0	20	00
	71	0	04	48
Cart track		0	06	40
	326	0	02	56
	308	0	16	00
	305	0	31	20
	304	0	00	80
	188	0	05	76
	189	0	33	82
	190	0	13	60
	191	0	00	80
	205	0	00	32
	204	0	16	32
	203	0	13	60
	202	0	13	12
	201	0	06	08
	215	0	08	80
	216	0	05	44
	217	0	02	56
	218	0	33	12
	277	0	13	12
	232	0	11	84
	233	0	17	60
	274	0	09	60
	236	0	22	56
	235	0	11	20
	237	0	08	00
	152	0	04	00
Boundary		0	06	00

[No. O-12016/66/84-ONG-D-4/GP]

कां.प्रा.० 4251.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना कां.प्रा.सं० 2397 तारीख 12-7-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और चाहे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अतः, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया गया है।

और चाहे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए
राज्य—गुजरात जिला—वडोदरा तालुका—डबोई

गांव	ब्लॉक नं०	हेक्टेयर	एअरई	सेंटीयर
1	2	3	4	5
अमवलपुरा	119/ए	0	37	12
	119/बी	0	02	32
	116	0	28	00
	87	0	02	88
	112	0	08	96
	111	0	08	64
	107	0	05	52
	109	0	00	32
	108	0	06	40
	106	0	14	88
	103	0	09	76
	37	0	29	12
	39	0	11	52
खराब भूमि		0	03	68
	42	0	29	44
	43	0	25	88
	44	0	02	88
	48	0	43	36
	57	0	26	72
	66	0	39	20
	60	0	00	26
	63	0	01	12
	49	0	11	68
	64	0	35	68
	62	0	12	80
खराब भूमि		0	02	32

[सं० O-12016/67/84/ओ एन जी-डी-4/जी पी]

S.O. 4251.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 2397 dated 12-7-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962); the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule, appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline.

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests, on this date of the publication of his declarations in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM HAJIRA-BAREILLY-JAGDISHPUR

State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Dabhoi

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Abdalpura	119/A	0	37	12
	119/B	0	02	32
	116	0	28	00
	87	0	02	88
	112	0	08	96
	111	0	08	64
	107	0	05	52
	109	0	00	32
	108	0	06	40
	106	0	14	88
	103	0	09	76
	37	0	29	12
	39	0	41	52
	Waste land	0	03	68
	42	0	29	44
	43	0	25	88
	44	0	02	88
	48	0	43	36
	57	0	26	72
	66	?	39	20
	60	0	00	26
	63	0	01	12
	49	0	11	68
	64	0	35	68
	62	0	12	80
	Waste land	0	02	32

[No. O-12016/67/84-ONG-D-4/GP]

कां० प्रा० 4252.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना कां० प्रा० सं० 2388 तारीख 7-7-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना प्राणय घोषित कर दिया।

और यतः मध्यम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया गया है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तब और प्राकृतिक गैस प्रायोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली, से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए
राज्य—गुजरात जिला—वडोदरा तालुका—डभोई

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	एअरई	सेटीयर
1	2	3	4	5
बणादरा	965	0	60	00
	964	0	06	08
	952	1	59	16
काटे ट्रैक		0	04	32
	1150	0	03	12
	1152	0	61	12
	1180	0	12	48
	941	0	42	88
	938	0	46	88
	937	0	09	60
	936	0	37	44
	935	0	06	08
	934	0	00	40
	930/1	0	30	56
	931	0	06	56
	932	0	00	72
	909	0	40	72
	829	0	00	56
	910	0	36	80
	911	0	06	72
	914	0	52	16
काटे ट्रैक		0	05	76
	879	0	06	56
	878	0	32	32
	872	0	38	08
	873	0	19	52
		0	04	80
	788	0	20	32
	787	0	00	48
	786/1	0	31	04
	786	0	21	44
काटे ट्रैक		0	04	76
	760/1	0	44	32
	761	0	04	80
	760/3	0	50	76
	762	0	03	46
	763	0	51	84
	763/1	0	05	76
	756	0	21	76

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	676, 677,	0	50	03		934	0	00	40
	678, 679					930/1	0	30	56
	672	0	17	94		931	0	06	56
	671	0	20	16		832	0	00	72
	662	0	16	00		909	0	40	72
	660	0	03	04		829	0	00	56
	661	0	20	16		910	0	36	80
	659	0	24	80		911	0	06	72
	658	0	06	40		914	0	52	16
	657	0	18	24		Cart track	0	05	76
	कार्ट ट्रैक	0	03	30		879	0	06	56
	645	0	26	26		878	0	32	32
	646	0	01	76		872	0	38	08
	644	0	31	36		873	0	19	52
	643	0	27	04		Cart track	0	04	80
						788	0	20	32
						787	0	00	48
						786/1	0	31	04
						786	0	21	44
						Cart track	0	04	76
						760/1	0	44	32
						761	0	04	80
						760/3	0	50	76
						762	0	03	46
						763	0	51	84
						763/1	0	05	76
						756	0	21	76
						676, 677, 678, 679	0	50	03
						672	0	47	94
						671	0	20	16
						662	0	16	00
						660	0	03	04
						661	0	20	16
						659	0	24	80
						658	0	06	40
						657	0	18	24
						Cart track	0	03	30
						645	0	26	26
						646	0	01	76
						644	0	31	36
						643	0	27	04

[सं० 0-12016/68/84/ओ एन जी-डी-4/ जी पी]

S.O. 4252.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 2388 dated 7-7-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule, appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM HAJIRA-BAREILLY-JAGDISHPUR

State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Dabhoi

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Vanadara	965	0	60	00
	964	0	06	08
	952	1	59	16
	Cart track	0	04	32
	1150	0	05	12
	1152	0	61	12
	1180	0	12	48
	941	0	42	88
	938	0	46	88
	937	0	09	60
	936	0	37	44
	935	0	06	80

[No. O-12016/68/84/ONG-D-4/GP]

कां० 4253.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना कां० सं० 2387 तारीख 7-7-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाईपलाईन को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अर्जित किया गया है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाईप लाईन बिछाने के लिये।

राज्य—गुजरात जिला—वडोदरा तालुका—डेभोई

गांव	ब्लॉक नं०	हेक्टर	एकर	सेंटीयर
बनेया	24	0	34	88
	25	0	32	96
	26	0	36	96
	35	0	11	52
	36	0	33	82
	34	0	06	40
	100	0	43	74

[सं० ओ-12016/72/84/ओ एन जी डी-4(जी पी)]

S.O. 4253.—Whereby notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 2387 dated 7-7-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule, appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM HAJIRA-BAREILLY-JAGDISHPUR

State : Gujarat	District : Vadodara	Taluka : Dabhoi		
Village	Block No.	Hec- tare	Are	Cent- tiare
Banajya	24	0	34	88
	25	0	32	96
	26	0	36	96
	35	0	11	52
	36	0	33	82
	34	0	06	40
	100	0	43	74

[No. O-12016/72/84-ONG-D-4/GP

कां० 4254.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना कां० 2530 तारीख 20-7-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाईपलाईन को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाईप लाईन बिछाने के लिये।

राज्य : गुजरात जिला—वडोदरा तालुका—बागोडीया

गांव	ब्लॉक नं०	हेक्टेयर	आर	सेंटीयर
वेजलपुर	108	0	02	72
	175	0	32	80
	176	0	18	52
	177/1 + 2	0	49	52

[सं० ओ-12016/73/84/ओ एन जी डी-4]

S.O. 4254.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 2530 dated 20-7-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM HAJIRA TO BAREILLY TO
JAGDISHPUR

State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Vaghodia

Village	Survey No.	Hec- tare	Acre	Cen- tiare
Vejalpur	108	0	02	72
	175	0	32	80
	176	0	18	52
	177/1+2	0	49	52

[No. O-12016/73/84-ONG-D-4]

कां० प्रा० 4255—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना कां० प्रा० सं० 2520 तारीख 16-7-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाईपलाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और ध्याते, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईपलाइनों बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया गया है।

और ध्याते उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार ने होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजिरा से नरेशी से जगदीशपुर तक पाईप लाइन बिछाने के लिये।

राज्य : गुजरात जिला—वडोदरा तालुका—डभोई

गांव	प्लॉक नं०	हेक्टेयर	एकड़	सेंटियर
1	2	3	4	5
सेजपुरा	192	0	11	36
	193	0	22	56
	191	0	44	00
	196	0	00	48
	203	0	21	92
	187	0	26	40
	186	0	49	12
	173	0	09	76
	185	0	04	04
	205	0	30	56
	कार्ट ट्रैक	0	03	36
	206/मी	0	05	76
	209	0	10	48

1	2	3	4	5
	208	0	04	96
	210	0	09	93
	212	0	09	92
	218	0	03	84
	217	0	03	32
	216	0	23	04
	221	0	01	44
	222/मी	0	66	96
	239	0	36	96
	243/मी	0	21	28
	244	0	14	72
	कार्ट ट्रैक	0	05	60
	कोटर	0	03	68

[सं० ओ-12016/74/84-ओ एन जी डी-4/जी पी]

S.O. 4255.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 2520 dated 16-7-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira to Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Dabhoi

Village	Block No.	Hec- tare	Acre	Cen- tiare
1	2	3	4	5
Sejpara	192	0	11	36
	193	0	22	56
	191	0	44	00
	196	0	00	48
	203	0	21	92
	187	0	26	40
	186	0	49	12
	172	0	09	76

1	2	3	4	5
	185	0	04	04
	205	0	30	56
	Cart track	0	03	36
	206/P	0	05	76
	209	0	10	48
	208	0	04	96
	210	0	09	92
	212	0	09	92
	218	0	03	84
	217	0	03	32
	216	0	23	04
	221	0	01	44
	222/P	0	66	96
	239	0	36	96
	243/P	0	21	28
	244	0	14	72
	Cart track	0	05	60
	Kotar	0	03	68

[No. O-12016/74/84/ONG- D4/GP]

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1984

का०प्रा० सं० 4256—यतः भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहाँ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में व्ययन स्थल सं० एस०डी०आई० से जी०जी०एस०-1 तक पेट्रोलियम परिवहन के लिये भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित किये गये हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के खण्ड-7 के उपखण्ड (1) की धारा (1) में विनिर्दिष्ट कार्य दिनांक 8-6-82 से समाप्त कर दिया है।

अतः अब पेट्रोलियम पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियम, 1963 के नियम-4 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते हैं।

अनुसूची

एस०डी०आई० से जी०जी०एस०-1 तक पाईप लाइन कार्य समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का०प्रा० सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग	मोटवान	4512	17-12-83	8-6-82

[सं० ओ-12016/13/82-प्रोड-II]

New Delhi, the 22nd November, 1984

S.O. No. 4256—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. SDJ to GGS I in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub section (1) of section 7 of the said Act on 8-6-82.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

COMPETENT AUTHORITY UNDER THE ACT FOR GUJARAT

SCHEDULE

TERMINATION OF PIPELINE FROM D.S. SDJ to GGS I

Name of Ministry	Village	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Energy, Deptt. of Petroleum, Motwan		45-12	17-12-83	8-6-82

[No. O-12016/13/82-Prod. II]
M.S. SRINIVAS Dy. Secy.

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1984

का०प्रा० सं० 4257—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का प्रा सं 2390 तारीख 7-7-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाईपलाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया गया है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेदन देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाईप लाइन बिछाने के लिये।

राज्य—गुजरात जिला—बड़ोदरा तालुका—बेमोई

गांव	प्लॉट नं०	हेक्टेयर ए	प्रार ई सेंटीयर
राजली	311	0	05 46
	313	0	27 68
	318	0	12 16
	316	0	17 28

1	2	3	4	5
	315	0	17	12
	331	0	41	62
	332	0	26	56
	333	0	17	04
	334	0	22	88
	335	0	03	44

[सं. मो-12016/57/84-ओ एन जी-डी-4(जी पी)]

S.O. 4257.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 2390 dated 7-7-84, under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline,

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from H jira—Boreilly—Jagdishpur

St to : Gujarat District : Vadodra Taluka : D bhoi

Village	Block No.	He- ctare	Are	Cent- ner e
Rajali	311	0	05	46
	313	0	27	68
	318	0	12	16
	316	0	17	28
	315	0	17	12
	331	0	41	62
	332	0	26	56
	333	0	17	04
	334	0	22	88
	335	0	03	44

[N. O-12015/57/85/ONG-D-4/ (GP)]

कां.मो.सं. 4258-यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना सं. कां.मो. 2529 तारीख 20-7-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाईपलाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया।

और यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिर्णय किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अर्जित किया गया है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की योजना तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

ओ.एन.जी.सी. मेहसाना कानॉन की गैस देने के लिये।

राज्य—गुजरात जिला और तालुका—मेहसाना

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	एकड़	घंटीयार
हेदुवा हणमंत	148/2	0	13	68
	148/1	0	07	68
	444	0	11	05
	152	0	14	75
	151	0	06	00
	156/3	0	05	28
	156/2	0	09	24
	156/1	0	09	12
	157	0	17	16
	159	0	17	28
काटे ट्रेक		0	00	96
	169	0	03	60
	176	0	24	72

[सं. मो-12016/77/84-ओ एनजी-डी-4(जी पी)]

S.O. 4258.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 2529 dated 20-7-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline for Gas supply to ONGC Mahanadi Colony				
State : Gujarat District & Taluka : Mahanadi				
Village	Survey No.	Hec- tare	Aro	Chak- tara
Heduva Hanumant	148/2	0	13	68
	148/1	0	07	68
	144	0	11	05
	152	0	14	75
	151	0	06	00
	156/3	0	05	28
	156/2	0	09	24
	156/1	0	09	12
	157	0	17	16
	159	0	17	28
	Cart track	0	00	96
	169	0	03	60
	176	0	24	72

[No. O-12016/77/84- ONG-D-4 (GP)]

कां.प्रा. 4259-यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना कां.प्रा.सं. 2339 तारीख 6-7-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार की पाइपलाईनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अथ, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाईन बिछाने के लिये।

राज्य—गुजरात जिला—वडोदरा तालुका—डेसई

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर आर	सेंटीयर	
1	2	3	4	5
बाणोद	कोटार	0	09	44
	फाटें ट्रेक	0	05	12
	169/1/पी	0	22	83
	169/1/पी	0	20	48
	169/1/ए/पी	0	17	12
	216	0	09	88

1	2	3	4	5
	214/1	0	32	00
	214/2	0	20	80
	214/1/पी	0	03	04
	212	0	34	08
	209	0	04	16
	210	0	19	68
	211	0	06	08
	198	0	16	00
	197	0	00	80
	194	0	28	80
	199	0	00	32
	191	0	00	64
	192	0	07	52
	193	0	15	68
	397	0	21	92
	177	0	17	60
	176	0	04	96
	178/1	0	04	96
	178/2	0	14	08
	178/3	0	11	68
	178/4	0	01	84
	173/1	0	00	20
	406	0	16	96
	403	0	15	84
	404/1	0	03	52
	404/2	0	19	68
	126	0	30	24
	129	0	01	92
	128/1	0	13	28
	128	0	00	24
	126/2	0	07	52
	127	0	16	16
	केन्स	0	07	20

[No. O-12016/56/84-प्रा एन जी-जी 4(जी पी)]

S.O. 4259.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 2339 dated 6-7-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hujira to Barolli to Jagdishpur

State : Gujarat District : Vadodra Taluka : Dabhoi

Village	Survey No.	Hec- tare	Are	Con- tains
1	2	3	4	5
Banod	Kotar	0	09	44
	Cart track	0	05	12
	169/1/P	0	22	88
	169/1/P	0	20	48
	169/1/A/P	0	17	12
	216	0	00	88
	214/1	0	32	00
	214/2	0	20	80
	214/1/P	0	03	04
	212	0	34	08
	209	0	04	16
	210	0	19	68
	211	0	06	08
	198	0	16	00
	197	0	00	80
	194	0	28	80
	199	0	09	32
	191	0	00	64
	192	0	07	52
	193	0	15	68
	397	0	21	92
	177	0	17	60
	176	0	04	96
	178/1	0	04	96
	178/2	0	14	08
	178/3	0	11	68
	178/4	0	01	84
	173/1	0	00	20
	406	0	16	96
	403	0	15	84
	404/1	0	03	52
	404/2	0	19	68
	126	0	30	24
	129	0	01	92
	128/1	0	13	28
	128	0	00	24
	126/2	0	07	52
	127	0	16	16
	Kabus	0	07	20

[No. O-12016/56/84 - ONG-D-4/(GP)]

का.प्र. 4260.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का.प्र.सं. 2385 तारीख 7-7-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से सम्बन्धित भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और धार्य यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से सम्बन्धित भूमियों में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिर्देश किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा में बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : वडोडरा तालुका : डभोई

गांव	प्लॉक नं.	हेक्टेयर	एकर	सेन्टीयर
मुलतानपुरा	11	0	06	56
	27	0	38	04
	28	0	05	28
	26/B	0	10	88
	25	0	11	52
	24	0	05	60
	23	0	00	32
	41	0	16	32
	42	0	03	20
	43	0	15	52
	40	0	03	04
	46	0	65	00
	45	0	00	48
	47	0	38	88
	48	0	02	40
	49	0	08	64
		0	03	76

[सं. 0-12016/55/84/आ एनजी-डी-4/(जी पी)]

S.O. 4260.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 2385 dated 7-7-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline,

And whereas, the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline,

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from H jira—Boreilly—Jagdishpur

State : Gujarat District : Vadodra Taluka : Dabhoi

Village	Block No.	He- tare	Are	Con- ti re
Sultanpura	11	0	06	56
	27	0	38	04
	28	0	05	28
	26/B	0	10	88
	25	0	11	52
	24	0	05	60
	23	0	00	32
	41	0	16	32
	42	0	03	20
	43	0	15	52
	40	0	03	04
	46	0	65	00
	45	0	00	48
	47	0	38	88
	48	0	02	40
	49	0	08	64
	Cart Track	0	03	76

[No. O-12016/55/84.. ONG - D-4 (GP)]

का.भा. 4261 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का.भा.सं. 2425 तारीख 19-7-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइन बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया गया है।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की उक्त तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : धडोदा तालुका : करजण

गांव	सर्वे नं.	हेक्टर	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
हजिपुरा टीबी	10	0	00	16
	9/3	0	08	80
	9/2	0	12	96

1	2	3	4	5
	9/1	0	03	20
	9/4	0	20	96
	8/9	0	04	64
	काटे ट्रैक	0	03	20
	12	0	00	32
	13	0	12	32
	14/1	0	10	20
	14/2	0	11	20
	14/3	0	07	84
	15	0	20	32
	16	0	02	24
	23	0	23	16
	22/1	0	08	80
	22/2	0	18	56
	काटे ट्रैक	0	07	04
	36/1	0	18	32
	36/2	0	00	16
	37/7	0	02	56
	37/8	0	02	60
	37/9	0	20	96
	38	0	34	56
	90/1	0	09	60
	90/3	0	47	20
	96/2	0	16	32
	96/2	0	16	00
	90/P	0	11	68
	86	0	18	88
	काटे ट्रैक	0	14	08
	98	0	17	12
	99	0	05	44
	99/1	0	16	96
	100/1	0	06	88
	100/2	0	02	88
	119	0	14	88
	117/2	0	07	04
	116	0	22	72
	114	0	40	64
	114	0	12	16
	113	0	06	72

[सं. O-12016/49/84/प्रोजेक्ट-डी-4 (जीपी)]

S.O. 4261.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 2524 dated 19-7-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of the right of user in the said lands shall instead of vesting in Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hujira—Boreilly—Jagdishpur

State : Gujarat District : Broda Taluka : Karjan

Village	Survey No.	Hec- tare	Acre	Con- tinue
1	2	3	4	5
Katipura Timbi	10	0	00	16
	9/3	0	08	80
	9/2	0	12	96
	9/1	0	03	20
	9/4	0	20	96
	8/9	0	04	64
Cart track		0	03	20
	12	0	00	32
	13	0	12	32
	14/1	0	10	20
	14/2	0	11	20
	14/3	0	70	84
	15	0	20	32
	16	0	02	24
	23	0	23	16
	22/1	0	08	80
	22/2	0	18	56
Cart track		0	07	04
	36/1	0	18	32
	36/2	0	00	16
	37/7	0	02	56
	37/8	0	01	60
	37/9	0	20	96
	38	0	34	56
	90/1	0	09	60
	90/3	0	47	20
	96/2	0	16	32
	96/1	0	16	00
	96/P	0	11	68
	86	0	18	88
Cart track		0	14	08
	98	0	17	12
	99	0	05	44
	99/1	0	16	96
	100/1	0	06	88
	100/2	0	02	88
	119	0	14	88
	117/2	0	07	04
	116	0	22	72
	114/P	0	40	64
	114	0	12	16
	113	0	06	72

[No. O-12016/49/84/ONG-D-4 / (GP)]

का.प्रा.सं. 4262:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का.प्रा.सं. 2115 तारीख 15-6-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना प्राण्य घोषित कर दिया।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधिन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिर्णय किया गया है।

अतः, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस प्रायोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात

जिला : बड़ोदा

तालुका : वागोडीया

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	एअरई	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
माखोघर	255/2	0	21	60
	257/1	0	16	00
	247	0	09	60
	248	0	24	00
	253	0	03	04
	249	0	12	00
	242/1	0	24	00
	242	0	00	16
	241	0	29	60
	240	0	03	20
	239	0	00	32
	कार्ट ट्रैक	0	06	40
	168	0	13	96
	169	0	24	00
	कार्ट ट्रैक	0	07	20
	170	0	07	36
	167	0	25	92
	166/1	0	00	32
	173	0	07	52
	174	0	14	72
	172	0	05	76
	175	0	03	84
	201	0	29	12
	205	0	14	40
	कार्ट ट्रैक	0	00	48
	200	0	08	80
	202/1	0	02	56
	198/1	0	12	80
	199	0	14	40
	183/1	0	00	16
	184	0	09	44
	185	0	16	32
	186	0	06	40
	188/A	0	20	00
	कार्ट ट्रैक	0	08	00
	104	0	04	64

1	2	3	4	5
	189	0	10	56
	6	0	27	20
	7	0	00	48
	14/1/P	0	26	29
	14/1/P	0	01	76
	26	0	19	36
	24	0	23	00
	23	0	06	40
	28/1	0	05	12
	32	0	36	00
	34	0	20	00
	35	0	01	12
	37/2	0	28	00
	37/1	0	12	48
	37	0	20	00
	39	0	08	62
	40	0	11	20
	900	0	04	80
	901	0	14	08
	22	0	00	48
	740	0	02	40
	741	0	04	48
	742	0	26	00
	743/1	0	14	24
	743/2	0	00	16
	745/1	0	14	40
	746/1	0	08	00
	746/2	0	02	08
	749/1	9	16	32
	749/2/P	0	01	65
	749/2/P	0	04	32
	649	0	02	40
	744	0	24	80
	748	0	00	16
	750	0	10	40
	804	0	13	60
	751	0	16	00
	752	0	20	32
	753	0	36	00
	754/2	0	14	40
	755	0	05	60
	892/1	0	00	80
	892/2	0	40	00
	891	0	48	80
	890	0	08	48
	889/6	0	02	40
	889/7	0	05	80
	889/5	0	00	48
	889/4	0	00	16

[सं. O-12016/45/84/ओएनजी-डी-4/(जी पी)]

S.O. 4262.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 2115 dated 5-6-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central

Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act -submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira—Boreilly—Jagdishpur

St-to : Gujarat District : Baroda Taluka : Vaghodia

Village	Survey No.	Hec- tare	Acre	Centi- tiere
Madodhar	255/2	0	21	60
	254	0	16	00
	247	0	09	60
	248	0	24	00
	253	0	03	04
	249	0	12	00
	242/1	0	24	00
	242	0	00	16
	241	0	29	60
	240	0	03	20
	239	0	00	32
	Cart track	0	06	40
	168	0	13	96
	169	0	24	00
	Cart track	0	07	20
	170	0	07	36
	167	0	25	92
	166/1	0	00	32
	173	0	07	52
	174	0	14	72
	172	0	05	76
	175	0	03	84
	201	0	29	12
	205	0	14	40
	Cart track	0	00	48
	200	0	08	80
	202/1	0	02	56
	198/1	0	12	80
	199	0	14	40
	183/1	0	00	16
	184	0	09	44
	185	0	16	32
	186	0	06	40
	188/A	0	20	00
	Cart track	0	08	00
	104	0	04	64
	189	0	10	56
	6	0	27	20
	7	0	00	48
	14/1/P	0	26	29

2	3	4	5
14/1/P	0	01	76
26	0	19	36
24	0	23	00
23	0	06	40
28/1	0	05	12
32	0	36	00
34	0	20	00
35	0	01	12
37/2	0	28	00
37/1	0	12	48
37	0	20	00
39	0	08	62
40	0	11	20
900	0	04	80
901	0	14	08
22	0	00	48
740	0	02	40
741	0	04	48
742	0	26	00
743/1	0	14	24
743/2	0	00	16
745/1	0	14	40
746/1	0	08	00
746/2	0	02	08
749/1	0	16	32
749/2/P	0	01	65
749/2/P	0	04	32
649	0	02	40
744	0	24	80
748	0	00	16
750	0	10	40
804	0	13	60
751	0	16	00
752	0	20	32
753	0	36	00
754/2	0	14	40
755	0	05	60
892/1	0	00	80
892/2	0	40	00
891	0	48	80
890	0	08	48
889/6	0	02	40
889/7	0	05	80
889/5	0	00	48
889/4	0	00	16

[No. O-12016/45/84/ONG - D-4(GP)]

का.आ. 4263 :—यत् पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का.आ.सं. 2114 तारीख 15-6-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया।

और यत् सभ्य प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत् केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा सशक्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में

उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया गया है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेदित है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में खोजना के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात

जिला : बड़ोदा

तालुका : करजण

गांव	कस्तक नं.	हेक्टर	आर	किमी.मीटर
1	2	3	4	5
बाळीयापुरा	20	0	15	68
	21	0	21	44
	22	0	07	36
	19	0	01	60
	23	0	04	48
	24	0	27	04
	18	0	39	20
	17	0	00	96
काटे ट्रेक		0	05	92
480		0	23	04
481		0	01	12
482		0	33	60
484		0	31	68
485		0	31	68
493/P		0	06	24
471		0	08	96
काटे ट्रेक		0	05	40
494		0	34	72
464		0	34	88
463/P		0	57	40
461		0	00	32
काटे ट्रेक		0	04	48
462		0	17	60
454		0	27	68
452		0	15	20
453		0	35	20
446		0	53	60
काटे ट्रेक		0	07	68
348		0	04	96
418		0	69	60
408		0	35	36
409		0	30	88
410		0	07	68
402		0	40	48
401		0	36	32
398		0	17	12
396		0	05	96
393		0	14	64
394		0	31	20
380		0	52	40
381		0	03	20
379		0	24	32

1	2	3	4	5
	375	0	21	60
	376	0	14	08

[सं. O-12016/44/84-ओएनजी-डी-4 (जी पी)]

S.O. 4263.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 2114 dated 15-6-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira - Bareilly - Jagdishpur

State : Gujarat District : Baroda Taluka : Karjan

Village	Block No.	He- tare	Are	Con- tinue
1	2	3	4	
Pachhiyapura	20	0	15	68
	21	0	21	44
	22	0	07	36
	19	0	01	60
	23	0	04	48
	24	0	27	04
	18 1	0	39	20
	17	0	00	96
	Cart track	0	05	92
	480	0	23	04
	481	0	01	12
	482	0	33	60
	484	0	31	68
	485	0	31	68
	493/P	0	06	24
	471	0	08	96
	Cart track	0	05	40
	494	0	34	72
	464	0	34	88
	463/P	0	57	40
	461	0	00	32
	Cart track	0	04	48
	462	0	17	60
	454	0	27	68
	452	0	15	20
	453	0	35	20
	446	0	53	60

1	2	3	4	5
	Cart track	0	07	68
	348	0	04	96
	418	0	69	60
	408	0	35	36
	409	0	30	88
	410	0	07	68
	402	0	40	48
	401	0	36	32
	398	0	17	12
	396	0	05	96
	393	0	14	64
	394	0	31	20
	380	0	52	40
	381	0	03	20
	379	0	24	32
	375	0	21	50
	376	0	14	08

[No. O-12016/44/84—ONG : D-4 / (GP)]

का.जा. 4264 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का.जा.सं. 2110 तारीख 15-6-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आग्रह घोषित कर दिया।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अधिस्त करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्वहण करती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात	जिला : बड़ोदा	तालुका : करजन		
गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	एम्पारई	सेन्टीमीटर-
1	2	3	4	5
करन	कार्ट ट्रैक	0	03	36
	41	0	05	76
	43	0	32	00
	44	0	15	40
	49	0	27	36
	47	0	30	88

1	2	3	4	5
	46	0	17	44
	74	0	74	56
	73	0	24	80
	काटे ट्रैक	0	05	18
	82	0	32	80
	83	0	15	68
	85	0	05	08
	81	0	28	64
	58	0	04	32
	42	0	37	60

[सं०-0-12016/41/84-ओएनजी-डी-4/(जीपी)]

S.O. 4264.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 2110 dated 15-6-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat District : Baroda Taluka : Karjan

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Karan	Cart track	0	03	36
	41	0	05	76
	43	0	32	00
	44	0	15	40
	49	0	27	36
	47	0	30	88
	46	0	17	44
	74	0	74	56
	73	0	24	80
	Cart track	0	05	18
	82	0	32	80
	83	0	15	68
	85	0	05	08
	81	0	28	64
	58	0	04	32
	42	0	37	60

[No. O-12016/41/84/ONG-D-4/(GP)]

कां० प्रा० 4265.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का प्रा सं 2109 तारीख 15-6-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न भूनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया।

और यतः सक्षम प्राधिकारियों ने उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न भूनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न भूनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया गया है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप से, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

भूनुसूची

हजीरा — बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए
राज्य : गुजरात जिला : बड़ौदा तालुका : करजन

गांव	सर्वे नं	हेक्टेयर एम्भारई	सेन्टीयर
कला	काटे ट्रैक	0	02 32
	240/2	0	19 84
	239/2	0	22 72
	30/6/पी	0	11 36
	29	0	17 12
	28/1	0	17 28
	28/2	0	08 96
	31/3	0	05 12
	40/1	0	00 24
	40	0	05 12
	41	0	00 24
	42	0	08 80
	43	0	01 60
	44	0	06 69
	45	0	00 48
	46	0	18 40
	काटे ट्रैक	0	04 32
	24	0	43 58
	23	0	04 32
	22	0	32 82
	21	0	00 32
	19	0	00 80
	18	0	09 24
	काटे ट्रैक	0	02 80

[सं० O-12016/40/84 ओएनजी-डी-4/(जीपी)]

S.O. 4265.—Whereas, by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 2109 dated 15-6-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly—Jagdishpur

State:Gujarat District : Baroda Taluka : Karjan

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Centiare
Kala	Cart track	0	02	32
	240/3	0	19	84
	239/2	0	22	72
	30/6/P	0	11	36
	29	0	17	12
	28/1	0	17	28
	28/2	0	08	96
	31/3	0	05	12
	40/1	0	00	24
	40	0	05	12
	41	0	00	24
	42	0	08	80
	43	0	01	60
	44	0	06	69
	45	0	00	48
	46	0	18	40
	Cart track	0	04	32
	24	0	43	58
	23	0	04	32
	22	0	32	82
	21	0	00	32
	19	0	00	80
	18	0	09	24
	Cart track	0	02	80

[No. O-12016/40/84/ONG-D-4/(GP)]

का. प्रो. 4266.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का.प्रो.सं. 1928 तारीख 1-6-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न भूमि में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइन को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और प्रागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न भूमि में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिर्देश किया है।

अतः, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न भूमि में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया गया है।

और प्रागे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

भूमि सूची

हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : बड़ोदा तालुका : करजन

गांव	म्होक नं	हेक्टेयर	घार	सेन्टीयर
गामपुरा	199	0	03	52
	176	0	11	52
	408	0	09	76
	408	0	35	36
	405	0	16	32
	404	0	26	40
	403	0	02	24
	399	0	28	80
	396	0	00	64
	400	0	16	64
	394	0	17	12
	392	0	12	68
	392	0	18	56
	391	0	01	92

[सं. O-12016/37/84/प्रोएनजी-डी-4/(जीपी)]

S.O. 4266.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 1928 dated 1-6-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly-Jagdishpur				
State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Karjan				
Village	Block No.	Hec- tare	Acre	Cen- tiare
Shanapura	199	0	03	52
	176	0	11	52
	409	0	09	76
	408	0	35	36
	405	0	16	32
	404	0	26	40
	403	0	02	24
	399	0	29	60
	396	0	00	64
	400	0	16	64
	394	0	17	12
	393	0	12	68
	392	0	18	56
	391	0	01	92

[No. O-12016/37/84/ONG-D-4/(GP)]

कां०भा० 4267.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना कां०भा० सं० 1822 तारीख 22-5-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना प्रायश्चित्त कर दिया था।

और यतः समक्ष प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगी।

अनुसूची

हजिरा-बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात	जिला : वडोदरा	तालुका : बायोडीया		
गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	घार	सेंटियर
बायोडीया	574	0	20	30
	625/1	0	02	72
	648/1	0	36	63
	कांटेरेक	0	03	78

1	2	3	4	5
	670	0	01	12
	671/1	0	03	12
	673	0	25	12
	624	0	08	27
	679/2	0	02	40
	679/1	0	39	34
	682	0	15	20
	914	0	13	60
	918	0	03	84
	920/3	0	16	12
	921	0	17	44
	943	0	14	56
	942	0	16	16
	941	0	04	00
	940	0	21	12
	963	0	15	52
	964	0	06	72
	966	0	39	38
	967	0	09	78
	937/1	0	10	32
	968/1	0	00	80
	969	0	21	12
	970	0	10	80
	973/1	0	22	58
	973/2	0	26	56
	974	0	33	12
	975/2	0	07	36
	972	0	06	40
	1015	0	00	08
	1023	0	03	36
	1024	0	33	44
	1022	0	16	80
	1020	0	13	44
	1019	0	21	92
	1030	0	20	32
	882/1/ए	1	13	12

[सं० O-12016/29/84/ओएनजी-डी-4/(जीपी)]

S.O. 4267.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 1822 dated 22-5-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that

the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira—Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Vadhodiya

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
1	2	3	4	5
Vaghodiya	574	0	20	30
	625/1	0	02	72
	648/1	0	36	68
	Cart track	0	03	76
	670	0	01	12
	671/1	0	03	12
	673	0	25	12
	624	0	09	27
	679/2	0	02	40
	679/1	0	39	36
	682	0	15	20
	914	0	13	60
	918	0	03	84
	920/3	0	16	12
	921	0	17	44
	943	0	14	56
	942	0	16	16
	941	0	04	00
	940	0	21	12
	963	0	15	52
	964	0	06	72
	966	0	39	36
	967	0	09	78
	937/1	0	10	32
	968/1	0	00	80
	969	0	21	12
	970	0	10	80
	973/1	0	22	56
	973/2	0	26	56
	974	0	33	12
	975/2	0	07	36
	972	0	06	40
	1015	0	00	08
	1023	0	03	36
	1024	0	33	44
	1022	0	16	80
	1020	0	13	44
	1019	0	21	92
	1030	0	20	32
	882/1/A	1	13	12

[No. O-12016/29/84/ONG-D-4(G.P.)]

अधिसूचना

का० भा० 4268.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का०भा०सं० 2528 तारीख 20-7-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है:

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 8 को उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया गया है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्वेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तैज और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एन०के०ई०के०से सी०टी०एफ० नार्थ कडी तक पाइपलाइन बिछाने के लिये
राज्य—गुजरात जिला—मेहसाना तालुका—कडी

गांव	सं०	हेक्टेयर	एआरई	सेंटोअर
चालासन	93	0	37	20
	काटेडूक	0	01	20
	71	0	08	00

[सं० O-12016/78/84/ओएनजी-डी-4/(जीपी)]

S.O. 4268.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 2528 dated 20-7-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline,

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from N.K.E.K. to CTF N. Kadi

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hec-tare	Area	Cen-tiare
Chalasan	93	0	37	20
	Cart track	0	01	20
	71	0	08	00

[No. O-12016/78/84/ONG-D-4/(G.P.)]

कां.आ.सं. 4269.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना कां.आ.सं. 2521 तारीख 18-7-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया गया है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एन.के.पी.सी. से एन.के.पी. 82 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य—गुजरात जिला—अहमदाबाद तालुका—विरमगम

गांव	सं.नं०	हेक्टेयर	एआरई सेंटीयर
बालसासन	77/1	0 04	32
	79/2	0 02	28
	83/2	0 15	24
	83/1	0 01	80
	83/3	0 06	24
	84/1	0 08	88

[सं. ओ-12016/82/84-ओएनजीसी-4(जीपी)]

S.O. 4269.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 2521 dated 16-7-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SC HEU 11

Pipeline from N.K.E.C. to NK-82

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Viramgam

Village	Survey No.	Hec-tare	Area	Centiare
Balsasan	77/1	0 04	32	
	79/2	0 02	28	
	83/2	0 15	24	
	83/1	0 01	80	
	83/3	0 06	24	
	84/1	0 08	88	

[No. O-12016/82/84-ONG-D-4 (G.P.)]

कां.आ. 4270.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना कां.आ.सं. 2721 तारीख 8-8-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया गया है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एन.के.पी. 29 (एन.के.पी.) से एन.के.पी. 82

राज्य—गुजरात जिला—अहमदाबाद तालुका—विरमगम

गांव	सं.नं०	हेक्टेयर	एआरई सेंटीयर
बालसासन	157/1	0 01	44
	158/1	0 09	84
	154/3	0 02	64
	154/2	0 03	72
	154/1/2	0 04	44
	154/1/1	0 04	44
	153/2	0 05	64
	152	0 00	72

[सं. ओ-12016/83/84-ओएनजीसी-4(जीपी)]

S.O. 4270.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 2721 dated 8-8-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from NK-29 (NKP) to NKDZ

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Viramgam

Village	Survey No.	Hec-tare	Area	Centi-are
Balsasan	157/1	0	01	44
	158/1	0	09	84
	154/3	0	02	64
	154/2	0	03	72
	154/1/2	0	04	44
	154/1/1	0	04	44
	153/2	0	05	64
	152	0	00	72

[No. O-12016/83/84-ONG-D-4/(G.P.)]

कांआं 4271—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 57) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना कांआं सं 1646 तारीख 2-5-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना अधिकार घोषित कर दिया था।

आर प्रतः सक्षम प्राधिकरण न उक्त आधानयम का धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे रही है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त आधानयम का धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित किया गया है।

और आगे इस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की वजह से और प्राकृतिक गैस प्रयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होना।

अनुसूची

हजिरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला—वाडोदरा तालुका—करजण

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	आर	सेंटोहर
कंधारिया	192	0	25	68
	185	0	33	60
	186	0	18	08
	183	0	05	28
	165	0	00	32
	166	0	40	16
	167	0	26	08
	178/1	0	00	32
	178	0	41	60
	177	0	41	60
	176	0	22	95
	174/1	0	41	60
	174/2	0	16	32
	173	0	02	08

[सं. बी-12016/27/84-प्रोड/जीपी]

S.O. 4271.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 1646 dated 2-5-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline,

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira Bareilly Jagdishpur

State : Gujarat District : Vadodara Taluka - Karjan

Village	Survey No.	Hec-tare	Area	Centi-are
Kanthariya	192	0	25	68
	185	0	33	60
	186	0	18	08
	183	0	05	28
	165	0	00	32
	166	0	40	16
	167	0	26	08
	178/1	0	00	32
	178	0	41	60
	177	0	41	60
	176	0	22	95
	174/1	0	41	60
	174/2	0	16	32
	173	0	02	08

[No. O-12016/27/84-Prod/G.P.]

का.आ. 4272.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश राज्य में हाजिरा-बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) विनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, बी. 58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सूनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की माफ़त।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने हेतु

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	अर्जित रकबा एकड़ में	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
झाँसी	झाँसी	झाँसी	परवाई	162	1-70	
				163	0-46	
				172	0-01	
				173	1-58	
				191	0-08	
				192	0-52	
				193	0-18	
				195	0-40	
				196	1-03	
				199	0-66	
				208	0-80	
				209	0-40	
				210	0-85	
				340	1-65	
				353	0-69	
				354	0-14	
				355	0-05	
				356	0-35	
				357	0-02	
				449	0-32	
				358	0-79	
				359	0-35	
				360	0-06	
				361	0-01	
				368	0-07	
				390	0-23	
				392	0-38	
				393	1-25	

1	2	3	4	5	6	7
				418	0-03	
				419	0-05	
				420	0-05	
				421	0-01	
				422	0-02	
				417	0-45	
				415	0-06	
				435	0-16	
				414	0-35	

[सं. ओ-14016/358/84-जीपी]

S.O. 4272,—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira to Bareilly to Jagdishpur Pipeline Project in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission H. B. J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj, Lucknow (226020) U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Gas Pipe line from HAJIRA-BAREILLY-JAGDISPUR Project

Dist	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acers.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Jhansi	Jhansi	Pasvai	162	1-70	
				163	0-46	
				172	0-01	
				173	1-58	
				191	0-08	
				192	0-52	
				193	0-18	
				195	0-40	
				196	1-03	
				199	0-66	
				208	0-80	
				209	0-40	
				210	0-85	
				340	1-65	
				353	0-69	
				354	0-14	
				355	0-05	
				356	0-35	
				357	0-02	
				449	0-32	
				358	0-79	
				359	0-35	

1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Jhansi	Jhansi	Parvai	360	0-06	
				361	0-01	
				368	0-07	
				390	0-23	
				392	0-38	
				393	1-25	
				418	0-03	
				419	0-05	
				420	0-05	
				421	0-01	
				422	0-02	
				417	0-45	
				415	0-06	
				435	0-16	
				414	0-35	

[No. O-14016/358/84/GP]

का. आ. 4273.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजिरा-बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वाक्य अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

उतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में रहित कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच. बी. जे. पाइपलाइन, 83, सुभाष नगर, सावेर रोड, उज्जैन (म. प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेंगे।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सूनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी निधि व्यवसायी की मार्फत।

एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम—बाजपुरा तहसील—राजगढ़ जिला—राजगढ़ राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु.क्र०	खसरा नं०	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (है. फुट से में)
1	2	3
1.	110	0.080
2.	100	0.036
3.	109	0.033
4.	102	0.025
5.	105	0.132
6.	106	1.200
7.	107	0.600

1	2	3
8.	115	0.102
9.	117	0.084
10.	118	0.0180
11.	119	0.360
12.	41	0.392
13.	120	0.032
14.	40	0.066
15.	38	0.468
16.	37	0.264
17.	101	0.018
18.	104	0.030
19.	39	0.010
कुल योग क्षेत्रफल		4.112

[सं. आ-14016/359/84-जीपी]

S.O. 4273.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Scheduled annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Gas Pipeline 83, Subash Nagar, Sanver Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village	Gujpura	Tehsil Rajgarh	Distt. Rajgarh
SCHEDULE			
S.No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectare	
1.	110	0.080	
2.	100	0.036	
3.	109	0.033	
4.	102	0.025	
5.	105	0.132	
6.	106	1.200	
7.	107	0.600	
8.	115	0.012	
9.	117	0.084	
10.	118	0.0180	
11.	119	0.360	
12.	41	0.392	
13.	120	0.032	
14.	40	0.066	
15.	38	0.468	
16.	37	0.264	
17.	101	0.018	
18.	104	0.030	
19.	39	0.010	
TOTAL AREA		4.112	

[No. O-14016/359/84-GP]

कां० आ० 4274.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजोरा से बरेली से जगदीशपुर पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये ;

और, यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है ;

अर्थात् कि उक्त भूमि में हितवन् कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग एच० बी० जे० पाईप लाइन 83 सुभाष नगर सावर रोड, उज्जैन म० प्र० 456001 इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

एच० बी० जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम : चुनाखेड़ी तहसील : तराना जिला : उज्जैन राज्य (मध्य प्रदेश)

अनु० क्र०	खसरा नं०	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)
1	2	3
1.	1	0.243
2.	2/1/2	0.243
3.	9	0.425
4.	10	—
5.	11	0.352
6.	12/1	0.607
7.	12/2	—
8.	15/1	0.025
9.	36	0.085
10.	15/2	0.015
योग—कुल क्षेत्रफल :		1.995

[सं० ऑ०-14016/360/84-जीपी]

S.O. 4274.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Bareilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission ;

And, whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority Oil and Natural Gas Commission, H.B.J. Gas pipeline 83, Subash Nagar, Saver Road, Ujjain (M.P.):

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village: Chunakhedi Tehsil : Tarana Distt: Ujjain. (M.P.)

S.No.	Survey No.	Area to be Acquire in R.O.U. Hectare.
1.	1	0.243
2.	2/1/2	0.243
3.	9	0.425
4.	10	—
5.	11	0.352
6.	12/1	0.607
7.	12/2	—
8.	15/1	0.025
9.	36	0.085
10.	15/2	0.015

TOTAL AREA

1.995

[No. O-14016/360/84-GP]

का० आ० 4275.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजोरा से बरेली से जगदीशपुर पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है :

अर्थात् कि उक्त भूमि में हितवन् कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच० बी० जे० पाईप लाइन 83 सुभाष नगर सावर रोड उज्जैन म० प्र० 45600 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

एच० बी० जे० गैस पाईप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम : हजराबदा तहसील : बड़नगर जिला : उज्जैन राज्य (मध्य-प्रदेश)

अनु० क्र०	खसरा नं०	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)
1.	2	3
1.	76/4	0.052
2.	83	0.397
3.	10	0.167
4.	79	0.648
5.	78	0.366
6.	72	0.010
7.	71	0.449
8.	69	0.124
9.	70	0.564
10.	53	0.032
11.	22	0.689
12.	19	0.836

1	2	3
13.	18	0.136
14.	17/1/2	0.166
15.	17/1/3	0.115
16.	17/1/4	0.251
17.	139	0.073
18.	17/3/2	0.240
19.	17/3/1	0.083
20.	27/2	0.198
21.	124	0.031
22.	35	0.314
23.	34/1	0.341
24.	29/2	0.125
25.	34/2	0.251
26.	30	0.585
27.	136	0.793
28.	137	0.408
29.	138	0.427
30.	14	0.020

कुल योग :—क्षेत्रफल 8.871

[स. O-14016/361/84 (जी.पी.)]

S.O. 4275.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Barilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And, whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed thereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. gas pipeline, 83, Subash Nagar, Sanver Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

BHJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Harnavada : Tehsil Badnagar Distt. : Ujjain

S.No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1.	76/4	0.052
2.	83	0.397
3.	10	0.167
4.	79	0.648
5.	78	0.366
6.	72	0.010
7.	71	0.449
8.	69	0.124
9.	70	0.564

1	2	3
10.	53	0.032
11.	22	0.669
12.	19	0.836
13.	18	0.136
14.	17/1/2	0.166
15.	17/1/3	0.115
16.	17/1/4	0.251
17.	139	0.073
18.	17/3/2	0.240
19.	17/3/1	0.083
20.	27/2	0.198
21.	124	0.031
22.	35	0.314
23.	34/1	0.341
24.	29/2	0.125
25.	34/2	0.251
26.	30	0.585
27.	136	0.793
28.	137	0.408
29.	138	0.427
30.	14	0.020

TOTAL AREA

8.871

[No. O-14016/361/84 (GP)]

का० प्रा० सं० 4276.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजिरा से बरेली से जगदीशपुर पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और, यतः, प्रतीत होता है कि ऐसी बाधों को बिछाने की प्रयोजन के लिए एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः, अब, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है ;

बशर्ते कि उस भूमि में हितवन्त कोई व्यक्ति उस भूमि के मीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग, एच. बी. जे. पाइप लाइन 83 सुभाष नगर सांवर रोड, उज्जैन (म. प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

एच. बी. जे. प्रोजेक्ट, जिला-उज्जैन, (म. प्र.)

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम : मोलपुरा तहसील : बड़नगर जिला उज्जैन राज्य : (मध्य-प्रदेश)

अनु क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)
1	2	3
1.	235	0.052
2.	237/3	0.366
3.	237/1	0.166
4.	239/1/1	0.518
5.	240	0.021
6.	239/1/2/4	0.146

1	2	3
7.	239/1/2/3	0.146
8.	239/1/2/2	0.146
9.	239/1/2/1	0.179
10.	239/2	0.166
11.	239/3	0.314
12.	239/4	0.157
13.	239/5	0.209
14.	190	0.397
15.	189	0.314
16.	188	0.314
17.	239/9	0.031
18.	239/10	0.021
19.	236	0.031
20.	229	0.052
21.	23722	0.010
कुल योग :—क्षेत्रफल		3.756

[सं. O-14016/362/84/(जी.पी.)]

S.O. 4276.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Barilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And, whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority Oil and Natural Gas Commission, HBJ gas pipe line 83, Subash Nagar, Sanver Road Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Malpura Tehsil : Badnagar Distt. : Ujjain

SCHEDULE

S.No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
1.	235	0.052
2.	237/3	0.366
3.	237/1	0.166
4.	239/1/1	0.518
5.	240	0.021
6.	239/1/2/4	0.146
7.	239/1/2/3	0.146
8.	239/1/2/2	0.146
9.	239/1/2/1	0.179
10.	239/2	0.166
11.	239/3	0.314
12.	239/4	0.157
13.	239/5	0.209

1	2	3
14.	190	0.397
15.	189	0.314
16.	188	0.314
17.	239/9	0.031
18.	239/10	0.021
19.	236	0.031
20.	229	0.052
21.	237/2	0.010
TOTAL AREA		3.756

[No. O. 14016/362/84-(GP)]

कां० प्रा० 4277.—यत्, केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में (हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तैल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये;

और, यत्, यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः, अब, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है ;

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितवन् कोई व्यक्ति उस भूमि के मोक्षे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तैल एवं प्राकृतिक गैस प्रायोग एच० पी० जे० पाईप लाईन 83 सुबाष नगर सावेर रोड उज्जैन (म० प्र०) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितया यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्ययसायी की मार्फत।

अनुसूची

एच. पी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम : झरखेड़ी बाजार तहसील : महिबपुर जिला : उज्जैन

अनु क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)
1	2	3
1.	81	0.648
2.	88	0.518
3.	153	0.073
4.	87	0.057
5.	152	0.063
6.	67/1	0.129
7.	67/2	0.081
8.	154/1	0.227
9.	154/2	—
10.	155	0.057
11.	159	0.028
12.	336/1	0.049
13.	336/2	0.291
14.	60	0.502
15.	66	0.032
16.	82	0.526

1	2	3
17.	338	0.263
18.	65/1	0.356
19.	144	0.089
20.	146	0.291
21.	147	0.129
22.	133/2	0.299
23.	156	0.121
24.	157	0.004
25.	64	0.057
26.	65/2	0.061
27.	63	0.040
28.	59/1	0.040
29.	57	0.004
30.	59/3	0.299
31.	61	0.032
32.	308	0.170
33.	315	0.134
34.	337	0.344
35.	142	0.093
36.	196	0.129
37.	170/1	0.081
38.	170/2	0.105
39.	312	0.162
40.	335/2	0.081
41.	311/2	0.182
42.	313/4	0.057
43.	311/1	0.174
44.	309	0.316
45.	85	0.016
46.	86	0.045
47.	141	0.073
48.	143	0.024
49.	160/1	0.049
50.	340/1/1/2	0.036
51.	160/2	0.081
52.	140/2	0.008

कुल क्षेत्रफल योग :— 7.728

[सं. O-14016/363/84 (जी.पी.)]

S.O. 4277.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Barilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And, whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, HBJ gas pipe line, 83 Subash Nagar, Sanver Road, Ujjain (M.P.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Burkhedi Bajar Tehsil : Mahidpur Distt. : Ujjain

S.No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectare
1.	81	0.648
2.	88	0.518
3.	153	0.073
4.	87	0.057
5.	152	0.065
6.	67/1	0.129
7.	67/2	0.081
8.	154/1	0.227
9.	154/2	—
10.	155	0.057
11.	159	0.028
12.	336/1	0.049
13.	336/2	0.291
14.	60	0.502
15.	66	0.032
16.	82	0.526
17.	338	0.263
18.	65/1	0.356
19.	144	0.089
20.	146	0.291
21.	147	0.129
22.	133/2	0.299
23.	156	0.121
24.	157	0.004
25.	64	0.057
26.	65/2	0.061
27.	63	0.040
28.	59/1	0.040
29.	57	0.004
30.	59/3	0.299
31.	61	0.032
32.	308	0.170
33.	315	0.134
34.	337	0.344
35.	142	0.093
36.	196	0.129
37.	170/1	0.081
38.	170/2	0.105
39.	312	0.162
40.	335/2	0.081
41.	311/2	0.182
42.	313/4	0.057
43.	311/1	0.174
44.	309	0.316
45.	85	0.016
46.	86	0.045
47.	141	0.073
48.	143	0.024
49.	160/1	0.049
50.	340/1/1/2	0.036
51.	160/2	0.081
52.	140/2	0.008
53.		

TOTAL AREA

7.728

[No. O. 14016/363/84/(GP)]

का.आ. 4278.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजिरा-बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के एच. बी. जे. पाइप लाइन 83 सुभाष नगर, सावर रोड, उज्जैन (म. प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम : हीरण खेड़ी तहसील : राजगढ़ जिला : राजगढ़ राज्य : मध्य-प्रदेश
अनुसूची

अनु. क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)
1	2	3
1.	659/1	1.985
2.	659/2	0.025
3.	621	0.005
4.	622	0.480
5.	623	0.253
6.	626	0.038
7.	629	0.038
8.	630	0.063
9.	631	0.013
10.	635	0.379
11.	636	0.114
12.	568	0.430
13.	542	0.026
14.	529	0.278
15.	539	0.015
16.	537	0.101
17.	538	0.228
18.	518	0.350
19.	521	0.038
20.	516/1	0.759
21.	515	0.063
22.	500	0.076
23.	499	0.076
24.	455	0.400

1	2	3
25.	497	0.101
26.	488	0.063
27.	487	0.013
28.	470	0.126
29.	469	0.253
30.	467	0.051
31.	468/1	0.126
32.	563	0.525
33.	569	0.228
34.	456	0.025
35.	457	0.005
36.	458	0.568
37.	462	0.013
38.	498	0.005
39.	640	0.010

कुल : क्षेत्रफल योग 7.845

[मं. O-14016/364/84/(जी पी)]

S.O. 4278.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareilly-Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Scheduled annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, HBI Gas Pipeline, 83, Subhash Nagar, Sanver Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPELINE 'PROJECT

Village : Hiran Khedi Tehsil: Rajgarh Distt. : Rajgarh
SCHEDULE

S.No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
1.	659/1	1.985
2.	659/2	0.025
3.	621	0.005
4.	622	0.480
5.	623	0.253
6.	626	0.038
7.	629	0.038
8.	630	0.063
9.	631	0.013
10.	635	0.379
11.	636	0.114
12.	568	0.430
13.	542	0.026

1	2	3
14.	529	0.278
15.	539	0.015
16.	537	0.101
17.	538	0.228
18.	518	0.350
19.	521	0.038
20.	516/1	0.759
21.	515	1063
22.	500	0.076
23.	499	0.076
24.	455	0.400
25.	497	0.101
26.	488	0.063
27.	487	0.013
28.	470	0.126
29.	469	0.253
30.	467	0.051
31.	468/1	0.126
32.	563	0.025
33.	569	0.228
34.	456	0.025
35.	457	0.005
36.	458	0.568
37.	462	0.013
38.	498	0.005
39.	640	0.010
TOTAL AREA		7.845

[No. O-14016/364/84/(GP)]

का.आ. 4279.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजिरा-बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाय अमसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1982 (1982 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है ;

वशातः कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच. बी. जे. पाइप लाइन, 83 सुभाषनगर, सांघेर रोड, उज्जैन (म. प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम : कढ़ाई तहसील : तराना जिला : उज्जैन, राज्य (मध्य-प्रदेश)

अमसूची

अनु. क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)
1	2	3
1.	164/1	0.328
2.	165	0.102
3.	179	0.172
4.	551	0.164
5.	164/2	0.230
6.	178	0.234
7.	181	0.377
8.	186	0.133
9.	187	0.005
10.	183	0.318
11.	589/1/1	0.286
12.	550/1	0.076
13.	552	0.196
14.	559/2	0.545
15.	559/3	—
16.	560	0.364
17.	568	0.576
18.	569	0.315
19.	599	0.113
20.	600	0.321
21.	577/2	0.005
22.	570	0.041
23.	577/3	0.091
24.	574	0.163
25.	575	0.146
26.	532/2	0.364
27.	573	0.018
28.	532/1	0.114
29.	591/1	0.040
30.	593	0.005
31.	592/2/1	—
32.	592/2/2	0.661
33.	601/1	0.200
34.	631	0.247
35.	630	0.424
36.	629	—
37.	628	0.424
38.	636/1	0.606
39.	637	0.230
40.	638	0.026
41.	182/1	0.025
42.	592/1	0.144

योग कुल :—क्षेत्रफल 8.829

[सं. O-14016/365/84/(जी. पी.)]

S.O. 4279.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareilly-Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1952 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Gas Pipeline, 83, Subash Nagar, Sanver Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Kadhaj Tehsil : Tarana Distt. : Ujjain

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1.	164/1	0.328
2.	165	0.102
3.	179	0.172
4.	551	0.164
5.	164/2	0.230
6.	178	0.234
7.	181	0.377
8.	186	1.133
9.	187	0.005
10.	183	0.318
11.	589/1/1	0.280
12.	550/1	0.076
13.	552	0.196
14.	559/2	0.545
15.	559/3	—
16.	560	0.364
17.	568	0.576
18.	569	0.315
19.	599	1.113
20.	600	0.321
21.	577/2	0.005
22.	570	0.041
23.	577/3	0.091
24.	574	0.163
25.	575	0.146
26.	532/2	0.364
27.	573	0.018
28.	532/1	0.114
29.	591/1	0.040
30.	593	0.005
31.	592/2/1	0.661
32.	592/2/2	—
33.	601/1	0.200
34.	631	0.247
35.	630	0.424
36.	629	—
37.	628	0.424
38.	636/1	0.606
39.	637	0.230
40.	638	0.026
41.	182/1	0.025
42.	592/1	0.144
Total Area		8.829

[No. O-14016/365/84-(GP)]

का.का. 4280.—यसः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजौरा-बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाय अस्सूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है ;

वस्तुतः कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच. बी. जे. पाइप लाइन, 83, सुभाष नगर, सावर रोड, उज्जैन (म.प्र.) 458001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की माफ़त ।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्रामः काठा तहसीलः राजगढ़ जिला : राजगढ़ राज्य (मध्य-प्रदेश)

अनुसूची		
अनु. क्र.	खगण. नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)
1	2	3
1.	83	0.005
2.	145	0.005
3.	148	0.005
4.	166	0.080
5.	165	0.234
6.	80	0.171
7.	164	0.234
8.	163	0.132
9.	81	0.258
10.	84	0.234
11.	85	0.144
12.	86	0.025
13.	88	0.300
14.	89	0.010
15.	152/1	0.030
16.	152/2	0.015
17.	139	0.010
18.	167	0.025
19.	149	0.010
20.	140	0.032
21.	141	0.032
22.	142	0.032
23.	143	0.064
24.	144	0.100
25.	150	0.030
26.	151	0.234

1	2	3
27.	196	0.332
28.	197	0.312
29.	217	0.776
30.	222	0.013
31.	218	0.276
32.	219	0.696
33.	242/3	0.372
34.	243	0.048
कुल योग — क्षेत्रफल		5.076

[सं. अ-14016/366/84(डी. पी.)]

S.O. 4280.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Barsily to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Gas Pipeline, 83, Subash Nagar Sanver Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Lale-Talai, Tehsil : Rajgarh, Dist : Rajgarh (M.P.)

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
1.	83	0.005
2.	145	0.005
3.	148	0.005
4.	166	0.080
5.	165	0.234
6.	80	0.171
7.	164	0.234
8.	163	0.132
9.	81	0.258
10.	84	0.234
11.	85	1.144
12.	86	0.025
13.	88	0.300
14.	89	0.010
15.	152/1	0.030
16.	152/2	0.015
17.	139	0.010
18.	167	0.025
19.	149	0.010
20.	140	0.032

1	2	3
21.	141	0.032
22.	142	0.032
23.	143	0.004
24.	144	0.100
25.	150	0.030
26.	151	0.234
27.	196	0.132
28.	197	0.312
29.	217	0.776
30.	222	0.013
31.	218	0.276
32.	219	0.696
33.	242/3	0.372
34.	243	0.048

Total Area

5.076

[No. O-14016/366/84-(G.P.)]

का.अ. 4281.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजिरा-बरेली से बागदीहपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन लेन तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एक्टुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एक्टु द्वारा घोषित किया है।

इसमें कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि को नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सशक्त प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच. बी. जे. पाइप लाइन, 83, सुभाषनगर, सावर रोड, उज्जैन (म. प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम—शजडावा तहसील—बड़नगर जिला—उज्जैन राज्य—(मध्य प्रदेश)

अनुसूची

शत. क्र. खसरा नं. उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)

1	2	3
1	535/1	0.299
2	564	0.071
3	645	0.105
4	776	0.031
5	817	0.330
6	558	0.010
7	552	0.200
8	553	0.314
9	554	0.114

1	2	3
10.	560/1	0.627
11.	560/2	0.627
12.	561	0.134
13.	555	0.073
14.	563/2	0.418
15.	638/2	0.167
16.	565	0.389
17.	635/1	0.688
18.	643/2	0.500
19.	647	0.392
20.	654	0.293
21.	639	0.293
22.	655	0.314
23.	656	0.500
24.	781	0.041
25.	816	0.585
26.	819	0.052
27.	820	0.375
कुल योग :—क्षेत्रफल		7.887

[N. O-14016/367/84-(जी.पी.)]

S.O. 4231.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule appended hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Gas Pipeline 83, Subash Nagar, Sanver Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

OIL & NATURAL GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Ajravada : Tehsil : Bandnagar Distt. : Ujjain

SCHEDULE

S.No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
1.	535/1	0.209
2.	564	0.071
3.	645	0.105
4.	776	0.031
5.	817	0.330
6.	558	0.010
7.	552	0.20
8.	553	0.314
9.	554	0.114
10.	560/1	0.627
11.	560/2	0.627
12.	561	0.188

1	2	3
13.	555	0.73
14.	563/2	0.418
15.	638/2	0.167
16.	565	0.389
17.	638/1	0.688
18.	643/2	0.500
19.	647	0.392
20.	654	0.293
21.	639	0.293
22.	655	0.314
23.	656	0.500
24.	781	0.041
25.	816	0.566
26.	819	0.052
27.	820	0.375
TOTAL AREA		7.887

[No. O-14016/367/84-(GP)]

का.आ. 4282.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजिरा से बरेली से जमदीशपुर पेट्रोलियम की परिवहन के लिए पाइप लाइन तैल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा दिखाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाठ्य अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

वशतः कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि को नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तैल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के एच. बी. जे. पाइप लाइन 83 सुभाष नगर सावर रोड, उज्जैन (म. प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

एच. बी. जे. गैस पार्प लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम-विभागीय क्षेत्री तहसील-मुता जिला-मुता राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु.क्र.	समस्या नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर्स में)
1	2	3
1.	59	0.261
2.	59	0.272
3.	62	1.076
4.	64	1.045
5.	65/2	0.362
6.	61	0.917
7.	65/1/1	0.261
8.	164/1	0.167
9.	164/2	0.041
10.	165/1	0.157
11.	165/2	0.021
12.	61/183	0.952

1	2	3
13.	65/192	1.066
14.	141/185	0.157
15.	66	0.099
16.	166	0.031
17.	40/2	0.013
18.	40/1	0.499
19.	39	0.303
20.	29	0.115
21.	28	0.209
22.	27/1	0.183
23.	27/2	0.183
24.	27/196	0.021
25.	26	0.063
26.	11	0.031
27.	25	0.163
28.	19	0.272
29.	20/1	0.418
30.	21/1	0.073
31.	64/182	0.272
32.	61/184	0.010
कुल योग :- क्षेत्रफल		8.813

[सं. अ-14016/368/84-(जो. पो.)]

S.O. 4282.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira Barcilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State Pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, H.B.J. Gas Pipeline 83, Subash Nagar, Sanver Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Vinayak Khedi Tehsil : Guna Distt. : Guna
SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
1.	59	0.261
2.	52	0.272
3.	62	1.076

1	2	3
4.	64	1.045
5.	65/2	0.362
6.	61	0.917
7.	65/1/1	0.261
8.	164/1	0.167
9.	164/2	0.041
10.	165/1	0.157
11.	165/2	0.021
12.	61/183	0.052
13.	65/192	1.066
14.	141/185	0.157
15.	66	0.099
16.	166	0.031
17.	40/2	0.013
18.	40/1	0.499
19.	39	0.303
20.	29	0.115
21.	28	0.209
22.	27/1	0.183
23.	27/2	0.183
24.	27/196	0.021
25.	26	0.063
26.	11	0.031
27.	25	0.163
28.	19	0.272
29.	20/1	0.418
30.	21/1	0.073
31.	64/182	0.272
32.	61/184	0.010
TOTAL AREA		8.813

[No. C-14016/368/84-(GP)]

रई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1984

का.अ. 4283 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप-लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का दर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना कां.अ.अं. 1503 तारीख 21-4-83 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का प्रयत्न अग्रिम घोषित कर दिया।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार का रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अतः, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार

एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और साथ ही उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेज और प्रकृतिक गैस आयात में, सभी बाधों से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगी।

अनुसूची

वायर वेड और ऐनोड वेड बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात	जिला : सुरा	तालुका : यार्सी		
गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	अर्ब	सेन्टीयर
वरीयाव	275/1	0	06	65
	274	0	02	84

[सं. जी-12016/15/84 आएनजी-डी-4]

New Delhi, the 26th November, 1984

S.O. 4283.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 1583 dated 17-4-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declares its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline,

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission file from encumbrances.

State : Gujarat	District : Surat	Taluka : Cheriya		
Village	Block No.	Hectare	Area	Centiare
Variav	275/1	0	06	65
	274	0	02	84

[No. O 12016/15/84/ONG-D-4]

का.आ. 4284—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप-लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम के विभाग की अधिसूचना का.आ.सं. 1475 तारीख 17-4-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप-लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया।

और साथ ही उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेज और प्रकृतिक गैस आयात में, सभी बाधों से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगी।

और साथ ही उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेज और प्रकृतिक गैस आयात में, सभी बाधों से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगी।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और साथ ही उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेज और प्रकृतिक गैस आयात में, सभी बाधों से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगी।

अनुसूची

वायर वेड और ऐनोड वेड बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात	जिला : मेहसाणा	तालुका : कडी		
गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	अर्ब	सेन्टीयर
मर्वाडी	139/1	0	01	98

[सं. आ-12016/14/84/आएनजी-डी-4]

S.O. 4284.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 1475 dated 17-4-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declares its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by subsection (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline.

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pineloc from VJD 'F' to GGS' Vhaj

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hectare	Area	Culture
Nand Kot	128/1	0	01	98

INQ. 0-12016/14/21/CN3.0-3

का.सं. 4285.-यस: पेट्रोलियम और खादों का इस्तेमाल (जिन में खादों के अधिकार का कर्ज) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन खाद संचयन के अर्जा संवत् 1962, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का.सं. 2393 जारी 1-8-62 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट धूम्रपान के उपयोग के अधिकार का पाइलान्सों को विद्युत के लिए अर्जित करने का अनायास अधिकार दे दिया है।

और यह सक्षम प्रधिकारी ने उक्त आवेदन की धारा ७ को उल्लंघन (१) के अधीन सरकारी कार्य में देर दे दी है।

कौरव ज्ञाने वरत, कौरवों पराक्रम ने जवा, रिचर्ड पराक्रम कर
 करने के लक्ष्यका इतने अधस्तुता से संताप अनुभूति में जवा-
 रिचर्ड ज्ञानों से जवाका यह अधस्तुता अजित ज्ञानों का
 विशिष्टता विता है।

(1) द्वारा प्रदत्त जानकारी का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एवं दूसरे व्यक्तियों करती है कि वह अधिभूतता में संलग्न अनुत्पत्ती में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उतारा या भरा या पार्श्वगत विभाग के पत्ता के लक्ष्य प्रकट या अन्य प्रकार से जाना है।

और आगे उस प्रश्न की उत्पत्ति (१) द्वारा प्रस्तुत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट देती है कि उक्त सूक्तियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार से निहित रहने की प्रणति तथा एवं प्रत्यक्ष भी आयोक्त में सभी बलाओं से मुक्त रूप में अधिपति के प्राप्ति की इतनी शक्ति को निहित रहना।

अनुवर्तते

ज.ल.ब. (ज. 17) स.व.र.फ. (अ.-३७) तह दिहा
साह: पछन के साह ।

राज्य : गुजरात	प्रति : महत्त्व	वस्तुतः : वस्तु
मात्र	सर्व नं.	वस्तुतः : वस्तु
मरका	266/2	0 02 00
	268	0 07 95
	269	0 09 00
	271/1	0 03 00
	271/2	0 10 05
	280	0 10 74
	281	0 06 00
	249	0 09 45

[सं. जा- 12016/55/84/प्र(एनजा)-डा-4]

S.O. 4263.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 2393 dated 1-7-74 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (30 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule a, pending to this notification :

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 5 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From JLD (3.17) to JRF (4.36)

State : Gujarat District : Mehsana Tahsil : Kadi

Village	Survey No.	Hectares	Area	Centiares
M. 10	1510	0	01	00
	269	0	07	95
	263	0	09	00
	271/1	0	03	00
	271/2	0	10	05
	270	0	10	74
	255	0	06	00
	249	0	01	48

[REF. G-12016;53/84;ONG-L 4]

वा.आ. 4236--प्रश्न: केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लार्डिंग से यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एच.वां.एल.वि. के जालबाजी की जाय। एक पेशेवरों के परिवार के लिए पाठ्यालय तथा आर प्रकृति और अवकाश इस प्रकार की जाती पाठ्यालय ।

और इस पर प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस लाइन (भूमि में उपयोग के अधिनियम का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना अथवा एतद्वारा घोषित किया है।

वगत कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सहन प्रतिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस वायुमय, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा राड, वडोदरा-9 का इस अधिनियम की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

निर ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसका सुनवाई व्यक्तिगत हों या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एच.ए.ए.सी. से आभारता जी.जी. एस. 1 तल पाइप लाइन बिछाने के लिये।

राज्य :	गुजरात	जिला व तालुका :	मेहसाणा
गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर एकरई	सेंटीयर
कुका	318	0	09 24

[तं. ओ-12016/117/84/आएजी-डी-4]

S.O. 4286.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SBAC to Sob GGS I in Gujarat a pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission:

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpur Road, Vadodra (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

State : Gujarat District & Tehsil : Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Area Centiare
Kuka	318	0	09 24

[No. O-12016/117/84/ONG-D-4]

नदे दिल्ली, 21 नवम्बर, 1984

आ.ओ. 4287—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि तेल तथा हित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जौटाणा जी.जी.एस. से सोभासण सो.टी.एस. तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस वायुमय द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस लाइन (भूमि में उपयोग के अधिनियम का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

वगत कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सहन प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस वायुमय, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा राड, वडोदरा-9 का इस अधिनियम की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसका सुनवाई व्यक्तिगत हों या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

जौटाणा जी.जी.एस. से सोभासण सो.टी.एस. तक पाइप लाइन बिछाने के लिये।

राज्य—गुजरात : जिला एवं तालुका—मेहसाणा

गाँव	ब्लाक नं०	हेक्टेयर	एआरई है	सेटीयर
1	2	3	4	5
	1529	—	31	20
	1522	0	01	25
	2523	0	06	15
	1524	0	13	40
	1525	0	51	80
अंगारण	काट ट्रेक	0	04	00
	1611	0	72	30
	1392	0	11	20
	1391	0	09	00
	1390	0	16	20
	1386	0	03	20
	1387	0	15	60
	1384	0	02	00
	1388	0	00	20
	1376	0	27	60
	1377	0	06	80
	काट ट्रेक	0	00	80

1	2	3	4	5
	1345	0	14	89
	1344	0	05	60
	काटे ट्रैक	0	01	00
	1326	0	02	00
	1327	0	11	60
	1328	0	00	20
	1333	0	00	25
	1329	0	10	00
	1331	0	14	00
	1332	0	09	60
	1336	0	21	40
	1290	0	00	25
	1291	0	22	35
	1296	0	00	15
	काटे ट्रैक	0	01	40
	1115	0	09	00
	1114	0	00	60
	1116	0	20	80
	1117	0	03	20
	1118	0	08	00
	1120	0	13	45
	1119	0	00	20
	1081	0	19	60
	1080	0	08	00
	1079	0	00	60
	काटे ट्रैक	0	01	20
	1147	0	11	60
	काटे ट्रैक	0	01	60
	1077	0	07	00
	1076	0	05	60
	1063	0	16	40
	1064	0	12	80
	1065	0	04	40
	1055	0	12	60
	1056	0	04	00
	1052	0	07	80
	1051	0	09	00
	1044	0	13	00
	1047	0	18	00
	998	0	16	00
	999	0	11	20
	1000	0	05	00
	1001	0	05	00
	काटे ट्रैक	0	01	40
	832	0	05	00
	834	0	17	75
	833	0	05	00
	831	0	17	00

1	2	3	4	5
	829	0	01	40
	830	0	00	90
	799	0	22	00
	800	0	17	20
	काटे ट्रैक	0	09	50
	798	0	00	50
	608	0	28	20
	609	0	00	15
	607	0	28	00
	610	0	00	50
	काटे ट्रैक	0	00	20
	605	0	05	40
	606	0	00	15
	604	0	02	10
	601	0	05	00
	600	0	03	15
	593	0	00	85
	597	0	08	20
	काटे ट्रैक	0	00	60
	481	0	03	60
	482	0	04	50
	498	0	00	15
	497	0	02	50
	496	0	03	30
	494	0	02	20
	493	0	02	95
	491	0	06	25
	489	0	02	60

[सं. ओ-12016/118/84/ओ एन जी-डी-4]

प्रा.सं. राजगोपालन, डेस्क अधिकारी

S.O. 4287.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Jotana GGS to Soobhasan CTF in Gujarat State Pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Scheduled annexed hereto;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Jotana GGS to Sobhasan CTF.

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Area	Centiare
1	2	3	4	5
Ambasan	1529	0	31	20
	1522	0	01	25
	1523	0	06	15
	1524	0	13	40
	1525	0	51	80
	Cart track	0	04	00
	1611	0	72	80
	1392	0	11	20
	1391	0	09	00
	1390	0	16	20
	1386	0	03	20
	1387	0	15	60
	1384	0	02	00
	1388	0	00	20
	1376	0	27	60
	1377	0	06	80
	Cart track	0	00	80
	1345	0	14	80
	1344	0	05	60
	Cart track	0	01	00
	1326	0	02	00
	1327	0	11	60
	1328	9	00	20
	1333	0	00	25
	1329	0	10	00
	1331	0	14	00
	1332	0	09	60
	1336	0	21	40
	1290	0	00	25
	1291	0	22	35
	1296	0	00	15
	Cart track	0	01	40
	1115	0	09	00
	1114	0	00	60
	1116	0	20	80
	1117	0	08	20
	1118	0	08	00
	1120		13	45
	1119	0	00	20
	1081	0	19	60
	1080	0	08	00
	1079	0	00	60
	Cart track	0	01	20
	1147	0	11	60
	Cart track	0	01	60
	1077	0	07	00
	1076	0	05	60
	1063	0	16	40
	1064	0	12	80
	1065	0	04	40
	1055	0	12	60
	1056	0	04	00
	1052	0	07	80
	1051	0	09	00
	1044	0	18	00
	1047	0	18	00
	998	0	16	00
	999	0	11	00
	1001	0	05	00
	Cart track	0	01	40

#	1	2	3	4	5
		832	0	05	00
		834	0	17	75
		833	0	05	00
		831	0	17	00
		829	0	04	40
		830	0	00	90
		799	0	22	00
		800	0	17	20
		Cart track	0	09	50
		798	0	00	50
		608	0	28	20
		609	0	00	15
		607	0	28	00
		610	0	00	50
		Cart track	0	00	20
		605	0	05	40
		606	0	00	15
		604	0	02	10
		601	0	05	00
		600	0	03	15
		593	0	00	85
		597	0	08	20
		Cart track	0	00	60
		481	0	03	60
		482	0	04	50
		498	0	00	15
		497	0	02	50
		496	0	03	30
		494	0	02	20
		493	0	02	95
		491	0	06	25
		489	0	02	60

[No. O-12016/118/84/ONG-D-4]

P.K. RAJAGOPALAN, Desk Officer

(Department of Coal)

ERRATUM

New Delhi, the 22nd November, 1984

S.O. 4288.—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Energy, (Department of Coal) No. S.O. 1155 dated the 23rd March, 1984, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 7th April, 1984.

at page 1028

in line 34 :—

for “(Department of Coal) No. S.O. 3661”

read “(Department of Coal) No. S.O. 3631”;

in line 40 :—

For “measuring 1472.00 acres (approximately)”

or 595.60 hectares (approximately)”

read “measuring 1472.00 acres (approximately)”

or 595.69 hectares (approximately)”;

at page 1029 :—

in line 20 :—

for “93 (Part), 95 (Part), 95 to 105”

read “93 (Part), 94 (Part), 95 to 105”;

in line 40 :—

for “plot numbers acquired in village Lachhamapur

1 to 34, 35 (Part), 46, 38, 39, 40 (Part),”

read “plot numbers acquired in village Lachhamapur

1 to 34, 35 (Part), 36, 37, 39, 40 (Part)”.

[No. 19/10/83-CL/CA]

SAMAY SINGH, Under Secy.

श्रीमद् बीर पुनर्वास मंत्रालय

(श्रीमद् विभाग)

नई दिल्ली, 31 मई, 1984

का.भा. 4289—केन्द्रीय सरकार अधकृषि खान श्रीमद् कल्याण निधि अधिनियम, 1946 (1946 का 22) की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसरण में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान अधकृषि खान श्रीमद् कल्याण निधि से वित्त पोषित कार्यकलापों की तथा उस वर्ष के लेखी और वर्ष 1984-85 के लिए उक्त निधि की प्राप्तियों और व्ययों के प्राकल्पनों संबंधी निम्नलिखित रिपोर्ट प्रकाशित करती है।

भाग-I

1. सामान्य:

अधकृषि खान श्रीमद् कल्याण निधि का गठन खान श्रीमद् कल्याण अधिनियम, 1946 (1946 का 22) के अधीन अधकृषि खान उद्योग में नियोजित श्रमिकों की सार्व से संबंधित स्कीमों के पोषण के लिए किया गया है।

2. इस अधिनियम में निर्धारित किए गए सारे अधकृषि पर मूल्यानुसार साढ़े छः प्रतिशत की अधिकतम दर पर सीमाशुल्क के उद्ग्रहण के लिए व्यवस्था है। परकर की दर, जो पहले मूल्यानुसार 2-1/2 प्रतिशत थी, को 15 जुलाई, 1974 से बढ़कर 3-1/2 प्रतिशत कर दिया गया है। इस संगठन का प्राथमिक विभिन्न अधकृषि उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में उनके औसत उत्पादन के अनुपात में कल्याणकारी उपायों से संबंधित व्यय के लिए किया जाता है।

भाग-II

चिकित्सा:

अधकृषि खान श्रीमद् कल्याण संगठन द्वारा अधकृषि श्रमिकों और उनके भागिदारों के लिए भिन्न किस्मों की चिकित्सा सुविधाओं की निशुल्क व्यवस्था की जाती है। इन सुविधाओं में अस्पतालों, प्रसूति एवं शिशु कल्याण केन्द्रों का प्रावधान व उनके रखरखाव गृह उपचार सहित अयरोग के उपचार की सुविधाएं, प्राथमिक औषधालयों सहित औषधालयों सुविधाएं और ग्राम्य सुविधाएं शामिल हैं। रिपोर्टींग वर्ष के दौरान अधकृषि श्रमिकों और उनके भागिदारों के उपचार के लिए कल्याण संगठन द्वारा निम्नलिखित केन्द्रीय और क्षेत्रीय अस्पताल चलाए जाते रहे:—

क्रमांक	अस्पताल का नाम	पलंगों की संख्या
1.	केन्द्रीय अस्पताल, कर्मा (बिहार)	100
2.	केन्द्रीय अस्पताल, गंगापुर (राजस्थान)	30
3.	केन्द्रीय अस्पताल कालीचंद (भारत प्रदेश)	30
4.	केन्द्रीय अस्पताल, तिसरी (बिहार)	30
5.	क्षेत्रीय अस्पताल, तालपुर (भारत प्रदेश)	10
6.	केन्द्रीय अस्पताल कालीचंद (भारत प्रदेश) के साथ सम्बद्ध क्षय रोग बार्ड	20
7.	क्षय रोग अस्पताल, कर्मा (बिहार)	50
8.	क्षेत्रीय अस्पताल, सैयबपुरम (भारत प्रदेश)	10

इसके अतिरिक्त तीन अधकृषि का उत्पादन करने वाले राज्यों में निम्नलिखितों ग्राम्य प्रकार के चिकित्सा संस्थान भी लगातार कार्य करते रहे।

चिकित्सा संस्थान	भारत प्रदेश	बिहार	राजस्थान	कुल
एलोपैथिक औषधालय	—	5	3	3
प्राथमिक औषधालय	2	8	4	14
प्रसूति शिशु कल्याण केन्द्र	3	—	3	6
होम्योपैथिक क्लिनिक	1	—	—	1
खलते फिरते चिकित्सालय एकक	1	3	2	6
लघु सामुदायिक केन्द्र	—	4	3	7

कल्याण संगठन क्षय रोग से पीड़ित श्रमिकों के इलाज के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करता रहता है। क्षय रोग अस्पतालों और चिकित्सालयों की स्थापना करने के अलावा क्षयरोग/सिलिकोसिस से पीड़ित अधकृषि श्रमिकों के लिए विशेष उपचार की व्यवस्था करने हेतु क्षयरोग सैनिटोरियम, सत्रास में चार पलंग प्रारंभित रखे गए। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय अस्पताल गंगापुर में इस प्रयोजन के लिए 10 पलंगों वाली एक अलग बार्ड भी है। गवर्नमेंट बेलफेयर एंड टी. बी. एंड चेस्ट डिजिज अस्पताल, नेल्डोर में केवल अधकृषि श्रमिकों और उनके परिवारों के उपयोग के लिए चार पलंगों का प्रारंभण जारी रहा। क्षय रोग के रोगी को 9 माह तक की अवधि के लिए 100/- रुपये प्रति माह का निर्वहण भत्ता दिया जाता है, यदि परिवार के लिए कमाने वाली केवल बही सदस्य हो। रिपोर्टींग वर्ष के दौरान बिहार में रोगियों को 850/- रुपये का निर्वहण भत्ता मंजूर किया गया। भारत प्रदेश में एक रोगी को निर्वहण भत्ते के अंतर्गत 148.35 रु. का भुगतान किया गया। राजस्थान में 10 अधकृषि श्रमिकों को निर्वहण भत्ता दिया गया। केन्द्रीय अस्पताल गंगापुर में भाषों के इलाज के लिए एक निविद भगाया गया जिसमें 97 प्रापरेशन किए जाने थे।

विभिन्न चिकित्सा सुविधाएं

भातक दुर्घटना और लाभ योजना के अंतर्गत निधि ने श्रमिक की पत्नी को 250 रुपये की (जिसे अब बढ़ा कर 500 रु. कर दिया गया है) एकमुश्त अवायगी और पांच वर्ष की अवधि के लिए 25/- रुपये प्रतिमास के भत्ते की अवायगी और प्रत्येक स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए उसके 15 वर्ष के होने

तक या बिबाह करने तक, जो भी पहले हो, 16 रुपए मासिक छात्रवृत्ति की व्यवस्था के रूप में वित्तीय सहायता देना जारी रखा गया। रिपोर्टीय अवधि के दौरान इस योजना के अधीन ग्रामपंच प्रदेश के एक मामले में 6875/- रुपये, कर्म, बिहार में मृतक के दो आश्रितों को 600/- और भीलवाड़ा, राजस्थान के एक मामले में 500/- रु. का भुगतान किया गया।

तेलुगुभाषी कोड़ प्रस्पताल में कोड़ से पीड़ित बिहार के भ्रष्टक खनिकों के उपचार की व्यवस्था जारी रही। केन्सर से पीड़ित भ्रष्टक खनिकों के उपचार के लिए केन्द्रीय प्रस्पताल कल्ला (आसनसोल) और रांची में कान्के में स्थित मानसिक रोगों के प्रस्पताल में मानसिक रोगों से पीड़ित भ्रष्टक खनिकों के उपचार की व्यवस्था जारी रही। केन्सर से पीड़ित भ्रष्टक के उपचार की योजना के अन्तर्गत 77 रोगियों को प्रस्पताल में दाखिल किया गया है, जिसमें सामान्यतः 9 मास से अत्यधिक अवधि के लिए मुक्त उपचार की व्यवस्था की गई और कुछ प्रवादा वाले मामलों में यह अवधि 9 मास से अधिक हो सकती है, यदि उपचार कर रहे चिकित्सा प्राधिकारी ऐसा चाहें।

भ्रष्टक खान श्रम कल्याण संगठन द्वारा चलाए जा रहे प्रस्पतालों में ऐसे रोगियों का भी उपचार किया जाता है, जिन्हें यह हक प्राप्त नहीं है। उनके उपचार के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निधि संगठनों को सहायता अनुदान दिया जाता है। भ्रष्टक खान श्रमिकों को 50/- रु. प्रति जोड़ा से अत्यधिक लागत पर ऐनों की सप्लाई की जाती है। इस लागत में फ्रेम तथा लेन्स की कीमत भी शामिल है। यदि लेन्सों को बदलने की आवश्यकता होती है तो उन्हें 20/- रु. से अत्यधिक लागत पर एक वर्ष में बदला जाएगा।

ख. शिक्षा और मनोरंजन सुविधाएं

भ्रष्टक श्रमिकों और उनके आश्रितों के लिए शिक्षा और मनोरंजन सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु कल्याण संगठनों द्वारा बहुदेशीय संस्थान चलाए जाते हैं। प्रत्येक संस्थान में एक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र और एक महिला कल्याण केन्द्र भी शामिल है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का विस्तार करने हेतु कल्याण संगठन ने सहायक और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र भी खोले हैं। मनोरंजन के प्रयोजनार्थ खनन क्षेत्रों में रेडियो सेट स्थापित किए गए हैं और भ्रष्टक श्रम कल्याण संगठन के अन्तर्गत मनोरंजन क्लब, पुस्तकालय और रीडिंग कक्ष कार्य करते रहे हैं। मिडिल स्कूल/हाई स्कूल चलाए जा रहे हैं। इन सुविधाओं की व्यवस्था करने वाले संस्थानों की संख्या इस प्रकार है:—

क्रमांक	संस्थाओं का व्योरा	ग्रामपंच प्रदेश	बिहार	राजस्थान	कुल
1.	बहुदेशीय संस्थान (प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र और महिला कल्याण केन्द्र सहित)	—	9	3	12
2.	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	—	6	6	6
3.	प्राथमरी/प्रारम्भिक स्कूल	4	—	—	4
4.	मिडिल स्कूल	—	1	—	1
5.	हाई स्कूल	2	1	—	3
6.	सहायक केन्द्र	—	1	—	1
7.	खनिकों के बच्चों के लिए छात्रावास/होस्टल	2	1	1	4
8.	चलते फिरते सिनेमा एकक	1	3	1	5
9.	विभागीय रेडियो सेट	22	16	7	45
10.	मनोरंजन क्लब	14	—	8	22
11.	भजन मंडली	9	9	—	18
12.	पुस्तकालय और वाचनालय	—	15	7	22

चलते फिरते सिनेमा एकक के माध्यम से शैक्षिक एवं धार्मिक महत्व की फिल्में दिखाई जाती हैं।

स्कूलों और कालेजों में भ्रष्टक खनिकों के पढ़ रहे पुत्रों/पुत्रियों के अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। वित्तीय वर्ष 1983-84 के दौरान 283 छात्रों के लिए 89,590 रु. की राशि मंजूर की गई।

मनोरंजन : वर्ष 1983-84 के दौरान तीन क्षेत्रों अर्थात् राजस्थान, हैदराबाद और कर्मा में भ्रष्टक खनिकों के लिए क्षेत्रीय वार्षिक क्रीड़ा/खेलों और कर्मा में केन्द्रीय क्रीड़ा आयोजित करने के लिए 37,000 रुपए मंजूर किए गए।

(ग) पेय जल की सुविधाएं :

भ्रष्टक खनन क्षेत्रों में पेय जल की कमी एक चिरकालिक समस्या है। इस समस्या को हल करने के लिए कुछ खोदने की एक योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत अनुमानित लागत का 75 प्रतिशत या वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत जो कम हो, खान मालिकों को कुछ खोदने के लिए दिया जाता है। ग्रामपंच प्रदेश में कालीबेहू गांव में एक स्थायी जल प्रदाय योजना अर्थात् तेलुपुर और सैयवपुरम चल रही है। अभी तक ग्रामपंच प्रदेश में 29 कुओं और राजस्थान क्षेत्र में 16 नए कुओं को खोदा गया है। राजस्थान क्षेत्र में 47 कुओं की मरम्मत की गई है।

(घ) आवास :

दो आवास योजनाएं अर्थात् अपना मकान बनाओ योजना और टाइप-I आवास योजना चल रही है।

अपना मकान बनाओ योजना के अन्तर्गत भ्रष्टक खनिकों को प्रत्येक मकान के लिए 1500 रु. की वित्तीय सहायता का भुगतान देय है। (600 रु. वार्षिक सहायता के रूप में और मासिक किराओं में बिना ब्याज के रूप में 900 रु.) इस राशि को पहली अप्रैल, 1983 से बढ़ा कर क्रमशः 1000 रु. और 4000 रु. कर दिया गया है। यह ऋण तीन वर्षों से अत्यधिक अवधि में मासिक किराओं में वसूल किया जाएगा। उपरोक्त योजना के अन्तर्गत ग्रामपंच प्रदेश क्षेत्र में 374 मकान और राजस्थान क्षेत्र में 344 मकान बनाए जा चुके हैं।

टाइप-I भावास योजना के अन्तर्गत साधारण क्षेत्रों में मानक अनुमानित लागत का 75 प्रतिशत है, जो 8,825 रु. है और कपास पैदा करने वाली काली या उमरी भूमि वाले क्षेत्रों में 7,925 रु. या मकानों के निर्माण की वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत इनमें जो भी कम हो, आर्थिक सहायता दी है। आर्थिक सहायता की राशि को पहली अप्रैल, 1983 से बढ़ा कर 10,000 रुपये का 75 प्रतिशत या निर्माण की वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत जो भी कम हो, कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त साधारण क्षेत्रों के लिए 2000/- रुपये का 50 प्रतिशत और कपास पैदा करने वाली काली या उमरी हुई भूमि वाले क्षेत्रों में 2000/- रु. या वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत इनमें जो भी कम हो, विकास व्यय भी देय है। आन्ध्र प्रदेश में अब तक 80 मकान पूरे हो चुके हैं। विभागीय कालोनी योजना के अन्तर्गत 120 मकान पूरे किए गए हैं और छः मकानों को इसबासी मकान योजना के अन्तर्गत पूरा किया गया है। बाद की ये दो योजनाएं अब चल नहीं रही हैं।

भाग-3

वर्ष 1983-84 की प्राप्तियां और व्यय इस प्रकार हैं :--

प्राप्तियां

पहली अप्रैल, 1983 को अग्रशील	2,32,65,328.30 रु.
वर्ष 1983-84 के दौरान प्राप्तियां	52,60,008.71 रु.
वर्ष 1983-84 के दौरान व्यय	1,09,35,749.62 रु.
31 मार्च, 1984 के अन्त शेष	1,75,89,587.39 रु.

भाग-4

वर्ष 1984-85 के लिए अनुमानित प्राप्तियां और व्यय

बजट अनुमान	1,50,00,000 रुपये
व्यय	1,22,95,000 रुपये

[सं. एच-12015/5/84-अस्यू-II]

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

New Delhi, the 31st October, 1984

S.O. 4289.—In pursuance of Sub-section (4) of Section 3 of the Mica Mines Labour Welfare Fund Act, 1946 (XXII of 1946) the Central Government hereby publish the following report of the activities financed from the Mica Mines Labour Welfare Fund during the year ending 31st March, 1984 together with a statement of accounts for that year and an estimates of receipts and expenditure of the said fund for the year 1984-1985.

PART—I

1. GENERAL

The Mica Mines Labour Welfare Fund has been constituted under the Mica Mines Labour Welfare Fund Act, 1946 (22 of 1946) for financing schemes relating to the welfare of labour employed in the mica mining industry.

2. The Act provides for the levy of a duty of customs on all mica exported upto a maximum rate of 6½ % advalorem. The rate of cess, which was 2½ per cent advalorem previously, has been increased to 3½ per cent with effect from the 15th July, 1974. The collection are allocated for expenditure on welfare measures among the various mica producing areas in proportion to their average production.

PART—II

A. Medical

Various types of medical facilities for mica workers and their dependents are provided free of cost by the Mica Mines Labour Welfare Organisations. These include provision and maintenance of hospitals, maternity and child welfare centres, facilities for treatment of T.B. including domiciliary treatment dispensary service including Ayurvedic dispensaries and other facilities etc. The following central and Regional hospitals continued to be maintained by the Welfare Organisations for the treatment of mica miners and their dependents during the year under report:—

Sl. No.	Name of the hospitals	Bed strength
1.	Central Hospital, Karma (Bihar)	100
2.	Central Hospital, Gangapur (Rajasthan)	30
3.	Central Hospital, Kalichedu (Andhra Pradesh)	30
4.	Regional Hospital Tisri (Bihar)	30
5.	Regional Hospital Talupur (Andhra Pradesh)	10
6.	T.B. Ward attached to Central Hospital Kalichedu (Andhra Pradesh)	20
7.	T.B. Hospital, Karma (Bihar)	50
8.	Regional Hospital, Sydapuram (A.P.)	10

In addition the following other medical institutions also continued to function in the three mica producing states.

Medical Institutions	Andhra Pradesh	Bihar	Rajasthan	Total
Allopathic Dispensaries	5	8
Ayurvedic Dispensaries	2	..	8	14
Maternity & Child Welfare Centres	3	..	3	6
Homoeopathic Clinic	1	1
Mobile Medical Unit	1	3	2	6
Small Community Centres	..	4	3	7

The Welfare Organisations have been endeavouring to provide adequate facilities for treatment of the miners suffering from T.B. Apart from setting up of T.B. Hospitals and clinics, four beds remained reserved in Mador (Ajmer), for providing specialised treatment to mica miners suffering from T.B. Silicosis. Besides there is a 10 bedded segregated ward in the Central Hospital, Gargapur for the purpose. Four beds in the Govt. Welfare Fund T.B. and Chest Disease Hospital Nellore, continued to be reserved for exclusive use mica miners and their families. A subsistence Allowance of Rs. 100/- P.M. is granted to T.B. patient for a period upto 9 months where happens to be the only earning member of the family. During the period under report patients in Bihar were sanctioned subsistence allowance amounting to Rs. 850/- One patient in Andhra Pradesh was paid Rs. 148.35 under the T.B. Subsistence Allowance. And 10 mica miners were paid subsistence allowance in Rajasthan. An Eye Camp was arranged at Central Hospital, Gangapur and 97 operations were carried out.

MISCELLANEOUS MEDICAL FACILITIES

Under the Fatal Accident and Benefit Scheme, the Fund continued to provide financial assistance to the spouse of a minor in form of a lumpsum payment of Rs. 250/- (since revised to Rs. 500/-) and monthly allowance of Rs. 25/- payable for a period of five year and a monthly scholarship of Rs. 15/- payable in respect of each school going child till the age of 15 or is married whichever is earlier. During the period under report an amount of Rs. 5675 to one case in Andhra Pradesh, Rs. 600/- to two dependent of the deceased in Karma, Bihar and Rs. 500/- to one case in Bhilwara, Rajasthan was paid under this scheme.

Arrangements continued for the treatment of mica miners of Bihar suffering from leprosy at the Tetulmari Leprosy Hospital. For the treatment of mica miners suffering from Cancer, arrangements continued at the Central Hospital Kalla (Asansol), and for mental disease at the Mental Hospital Kanke, Ranchi. Under the for the treatment of mica miners suffering from cancer patients are admitted in above hospital which provide free treatment generally for a period not exceeding 9 months and in exceptional cases this period can be more than 2 months if the treating medical authority so desires.

The non-entitled patients also get treatment from the Hospitals run by the Mica Mines Labour Welfare Organisations. For their treatment grants-in-aid is paid by the concerned state Govts. to the Fund Organisations. Spectacles are supplied to the Mica Mine Workers at a cost not exceeding Rs. 50/- which includes cost of frame and lenses. If the power of lenses needs a change the same will be replaced at a cost not exceeding Rs. 20/- for lenses after one year.

(B) EDUCATIONAL AND RECREATIONAL FACILITIES

For providing educational and recreational facilities to mica workers and their dependents, various multipurpose Institutes, each comprising of an Adult Education Centre and Womens Welfare centre, are run by the Welfare Organisations. In order to expend the Adult Education activities, Feeder and Adult Education Centres have also been opened by the Welfare Organisations. For Recreation purposes Radio Sets have been installed in the mica mining areas and recreation clubs as well as library and reading rooms have been functioning under the Mica Mines Labour Welfare Organisations. In order to provide educational facilities, primary Schools, Middle Schools/High Schools are run by the Welfare Organisations. The number of Institutions providing the above facilities are as under:—

Sl.No.	Particulars of Institutions	A.P.	Bihar	Raj.	Total
1.	Multipurpose Institution with Adult Education Centre & Women's Welfare Centre	..	9	3	12
2.	Adult Education Centre	6	6
3.	Primary Elementary Schools	4	4
4.	Middle Schools	..	1	..	1
5.	High Schools	2	1	..	3
6.	Feeder Centres	..	1	..	1
7.	Boarding houses/Hostel for miners children	2	1	1	4
8.	Mobile Cinema Units	1	3	1	5
9.	Departmental Radio Sets	22	16	7	45
10.	Recreation Clubs	14	..	8	22
11.	Bhajan Mandalies	9	9	..	18
12.	Library & Reading Rooms	..	15	7	22

Films of educational and religious value are exhibited through a mobile cinema Units.

Scholarships are awarded to the sons/daughters of mica miners studying in schools and colleges for their studies. During the financial year 1983-84 Rs. 89,590 were sanctioned to 283 students.

Recreation:

During the year 1983-1984 an amount of Rs. 37,000 was sanctioned for holding regional Annual sports/games meets for Mica miners at the three Regions namely Rajasthan, Hyderabad and Karma as also for holding central sports event at Karma.

(C) Drinking Water Facilities

Scarcity of drinking water is a chronic problem in mica mining areas with a view to resolve this problem, scheme for sinking of wells has been introduced. Under this scheme 75% of the estimated cost or 75 per cent of the actual cost, whichever is less is paid to mine owners for sinking wells. In Kalichedu Village in Andhra Pradesh a permanent Water Supply Scheme i.e. Talupur and Sydapuram are also under consideration. Twenty nine wells in Andhra Pradesh region and 16 new wells in Rajasthan region have been sunk so far. Forty seven wells in Rajasthan region have also been renovated.

(D) Housing

Two schemes viz. Build Your own House Scheme and Type I Housing Scheme are in vogue.

Under Build Your Own House Scheme financial assistance to the tune of Rs. 1500/- per tenement (Rs. 600/- in the form of subsidy and Rs. 900/- in the form of interest free loan) were payable to the mica miners. This amount has since been increased to Rs. 1000/- and Rs. 4000/- respectively with effect from 1st April 1983. The loan is recoverable in monthly instalments spread over a period of not exceeding 9 years. 374 houses in A.P. region and 344 houses in Rajasthan Region have been completed under the aforesaid scheme.

Under Type I Housing Scheme Subsidy were payable at the rate of 75% of the estimated cost of Rs. 6,825/- for ordinary areas and Rs. 7,925/- for black cotton and swelly soil areas or 75% of general cost of construction, whichever is less. The amount of subsidy has been increased with effect from 1st April, 1983 to 75% of Rs. 10,000/- or 75% of actual cost of construction whichever is less. In addition to it the development charges are also payable @50% percent of Rs. 2000/- for ordinary areas and 75% of Rs. 2000/- for black cotton and swelly soil areas or the actual cost whichever is lower. 80 houses so far have been completed under the Departmental Colony Scheme and another six months houses have been completed under subsidised housing scheme. The latter two scheme are now no more in vogue.

PART—III

The receipts and expenditure for the year 1983-1984 are as under:—

RECEIPTS

Opening balance as on 1st April, 1983	Rs. 2,32,65,328.30
Receipts during 1983-1984	Rs. 52,60,008.71
Expenditure during 1983-1984	Rs. 1,09,35,749.62
Closing balance as on 31st March, 1983.	Rs. 1,75,89,587.39

PART—IV

Estimated receipts and expenditure for the year 1984-1985 are as follows:—

Budget Estimates	Rs. 1,50,00,000
Expenditure	Rs. 1,22,95,000

[No.H-12015(5)84—WII

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1984

का०प्रा० 4290.—लोह अयस्क भगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि नियम, 1978 के नियम 3 के साथ पठित लोह अयस्क खान और भगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1976 (1976 का 61) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश राज्य के लिये एक सलाहकार समिति गठित करती है जिसके सदस्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

- | | |
|---|---------------------|
| 1. अम मंत्री,
मध्य प्रदेश, भोपाल | अध्यक्ष |
| 2. कल्याण आयुक्त
लोह अयस्क भगनीज अयस्क
क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण
संगठन 122, नेपियर चाउन,
जबलपुर (मध्य प्रदेश) | उपाध्यक्ष
(पदेन) |
| 3. क्षेत्रीय अमायुक्त (केन्द्रीय
203, नार्थ सिविल लाईन्स,
जबलपुर (मध्य प्रदेश) | सदस्य
(पदेन) |

4. श्री प्यारेलाल बेलचन्दन
विधान सभा सदस्य,
शिवपारा, जिला दुर्ग (मध्य प्रदेश)

5. महाप्रबंधक,
मैसर्स नेशनल मिनरल डेवलपमेंट
कारपोरेशन, बेलाडिला आयरन
और प्रोजेक्ट डिपोजिट संख्या 14,
करान्दुल, (जिला बस्तर, मध्य प्रदेश)
6. महाप्रबंधक,
मैसर्स स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया,
लिमिटेड, भिलाई स्टील प्लांट,
भिलाई, (जिला-दुर्ग, मध्य प्रदेश)

नियोजकों
के
प्रतिनिधि

7. जनरल सैक्रेटरी,
मैटल माइन्स वर्कर्स यूनियन,
डाकघर राजहारा,
राजहारा (जिला-दुर्ग, मध्य प्रदेश)
8. जनरल सैक्रेटरी,
मैटल माइन्स वर्कर्स यूनियन,
डिपोजिट संख्या-14,
बेलाडिला आयरन और प्रोजेक्ट,
डाकघर किरन्डुल, (जिला-किरन्डुल,
बस्तर, मध्य प्रदेश)

कर्मचारियों
के
प्रतिनिधि

9. श्रीमती जयबहन,
विधान सभा सदस्य,
भमतारी, रायपुर (मध्य प्रदेश)

महिला
प्रतिनिधि

10. कल्याण प्रशासक,
रायपुर

सचिव

2. उक्त नियमों के नियम 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, उक्त समिति का मुख्यालय जबलपुर में निर्धारित करती है।

[यू० 19012/4/84-इल्यू-II]

New Delhi, the 20th November, 1984

S.O. 4290—In exercise of the powers conferred by the section 5 of the Iron Ore Mines and Managanese Ore Mines and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund Act, 1976 (61 of 1976) read with rule 3 of the Iron Ore Mines Managanese Ore and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund Rules, 1978, the Central Government hereby constitutes an Advisory Committee for the State of Madhya Pradesh consisting of the following members, namely :—

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Minister for Labour
Madhya Pradesh, Bhopal. | Chairman |
| 2. Welfare Commissioner,
Iron Ore/Manganese Ore/Chrome Ore
Mines Labour Welfare Organisation,
122, Nappier Town, Jabalpur (M.P.) | Vice-Chairman
(Ex-officio) |
| 3. Regional Labour Commissioner (C),
203, North Civil Lines, Jablpur (M.P.) | Member
(Ex-officio) |
| 4. Shri Pyarelal Belchandun, M.L.A.,
Shivpara (Distt. Durg) (M.P.) | Member |
| 5. General Manager,
M/s. National Mineral Development
Corporation,
Bailadila Iron Ore Project Deposit No.14
Karnadul (Distt. Bastar, M.P.) | Employers'
Representatives |
| 6. General Manager,
M/s. Steel Authority of India Ltd.
Bhilai Steel Plant,
Bhilai (Distt. Durg, M.P.) | |
| 7. General Secretary,
Metal Mines Workers Union,
P.O. Rajhara,
(Rajhara Distt. Durg, M.P.) | Employees'
Representatives |
| 8. General Secretary,
Metal Mines Workers Union,
Dpt. No.14, Bailadila Iron Ore Project,
P.O. Kirandul, (Distt. Kirandul,
Bastar, M.P.) | Employees'
Representatives |
| 9. Smt. Jayaben, M.L.A.,
Dhamtari, Distt.
Raipur (M.P.) | Women
Representatives |
| 10. Welfare Administrator,
Raipur. | Secretary |

2. The Central Government in exercise of the powers conferred by rule 16 of the said rules, hereby fixes Jabalpur as the headquarter of the said Committee.

[No. U-19012/4/84-W.II]

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1984

का. प्रा. 4291.—लोह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि नियम, 1978 के नियम 3 के उप नियम (2) के साथ पठित, लोह अयस्क/मैंगनीज अयस्क और क्रोम खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1976 (1976 का 61) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार दिनांक 2 अप्रैल, 1983 को भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में पृष्ठ 1764 पर प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की तारीख 16 मार्च, 1983 की अधिसूचना संख्या का. प्रा. 1765 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में प्रविष्ट 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा अर्थात् :—

6. श्री टी. वी. चौधरी,
बी. ई. (खनन) प्रबंध निदेशक,
आन्ध्र प्रदेश माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड,
11-5-460, रेड हिल्स,
हैदराबाद-500004।

[संख्या यू. 23017/4/80-एम. I इल्यू. II]

कंवर राजिन्दर सिंह,
अवर सचिव

New Delhi, the 28th November, 1984

S.O. 4291.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Iron Ore/Manganese Ore/Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund Act, 1976 (61 of 1976), read with sub-rule (2) of Rule 3 of the Iron Ore/Manganese Ore/Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund Rules, 1978, the Central Government makes the following amendment to the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O.No. 1765 dated the 16th March, 1983 published at pages 1764 of the Gazette of India, part II, Section 3, sub-section (ii) dated the 2nd April, 1983 namely:—

In the said notification for entry against Serial No. 6, the following shall be substituted, namely:—

6. Shri T. V. Chowdary,
B.E. (Mining),
Managing Director,
Andhra Pradesh Mining Corporation Ltd.,
11-5-460, Red Hills,
Hyderabad-500004.

[No. U-23017/4/80M-IV/W-II]
KANWAR RAJINDER SINGH, Under Secy.

पुनर्वास विभाग

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 1984

का. प्रा 4292 निष्कांत सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) में संयुक्त सचिव, श्री एस के वसु को उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके अधीन महाभिरक्षक को सौंपे गये कार्यों का विष्ठावन करने के लिये 18 अक्टूबर, 1984 से महाभिरक्षक, निष्कांत सम्पत्ति नियुक्त करती है।

2. इससे 30 जून, 1983 की अधिसूचना संख्या 1(14) वि से / 83-एस एस -II (ब) का अधिक्रमण किया जाता है।

[संख्या 1(21) / वि से / 84-एस एस-II(ब)]

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 9th November, 1984

S.O. 4292.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950, (31 of 1950), the Central Government hereby appoints Shri S. K. Basu, Joint Secretary in the Ministry of Labour & Rehabilitation (Department of Rehabilitation) as the Custodian General of Evacuee Property for the purpose of performing functions assigned to such Custodian General by or under the said Act with effect from 18th October, 1984.

2. This supersedes Notification No. 1(14)/Spl. Cell/83-SS. II, (B), dated the 30th June, 1983.

[No. 1(21)/Spl. Cell/84-SS. II. (B)]

कां० प्र० 4293 —विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा पुनर्वास विभाग में संयुक्त सचिव श्री एस के बसु को उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके अधीन मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त को सौंपे गये कार्यों का निष्पादन करने के लिये 18 अक्टूबर, 1984 से मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त नियुक्त करती है।

2. इससे 30 जून, 1983 की अधिसूचना संख्या-1(14)/वि से./83-एस एस -II का अधिकरण किया जाता है।

[संख्या-1(21)/वि से /84-एस एस -II(क)]

डी डी इंगटी, प्रवर सचिव

S.O. 4293.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints Shri S. K. Basu, Joint Secretary in the Department of Rehabilitation as Chief Settlement Commissioner for the purpose of performing the functions assigned to such Chief Settlement Commissioner by or under the said Act with effect from 18th October, 1984.

2. This supersedes Notification No. 1(14)/Spl. Cell/84-SS.II (A), dated the 30th June, 1983.

[No. 1(21)/Spl. Cell/84-SS. II. (A)]

D. D. INGTY, Under Secy.

S.O. 4294.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2 Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Benedih Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 14th November, 1984.

A. V. S. SARMA, Desk Officer
[No. L-20012(87)/82-D.III(A)]

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) DHANBAD

PRESENT :

Shri I. N. Singha,

Presiding Officer.

Reference No. 93 of 1982

In the matter of an industrial dispute under S. 10(1)-(d) of the I. D. Act, 1947.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Benedih colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., Post Office : Nowagarh, Dist. Dhanbad.

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers.—Shri B. Joshi, Advocate.

On behalf of the workmen.—Shri S. Bose, Secretary,

Rastriya Colliery Mazdoor Sangh.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, the 9th November, 1984

AWARD

This is an industrial dispute under S. 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947. The Central Government vide its order No. L-20012(87)/82-D. III(A) dated 29-7-82 has referred this dispute to this Tribunal for adjudication on the following terms :—

SCHEDULE

“Whether the demand of the workmen of Benedih colliery of Messrs Bharat Coking Coal Ltd., Post Office : Nowagarh, District Dhanbad for regularisation of the piece-rated workers listed in the Annexure below into time-rated, with retrospective effect from 1980, is justified ? If so, to what relief are the workmen concerned entitled ?”

ANNEXURE

S/Shri/Smt.

1. Manager Singh, Drillman.
2. Kishori Paswan Drillman.
3. Jaiaram Gope Drillman.
4. Rati Rai, Drillman.
5. Laljee Yadav Drillman.
6. Sidheshwar Sao, Drillman.
7. Kartik Mahato, Drillman.
8. Kuldip Dusad, Exp. Carrier.
9. Tarachand Mahato, Carrier.
10. Bhola Mahato, Carrier.
11. Bajinath Mahato, Carrier.
12. Rookan Bhuin, Carrier.
13. Munshi Singh, Fireman.
14. Chhotan Mahato, Genl Mazdoor.
15. Bhanu Mahato, Pump Khalasi.
16. Mohan Dusad, Prop Mazdoor.
17. Surajdeo Beldar, Prop. Mazdoor.
18. Ramdas Ravidas, Prop. Mazdoor.
19. Karmu Nunjia, Prop. Mazdoor.
20. Sahdeo Bhula, Prop. Mazdoor.
21. Kasurwa Bhuia, Prop. Mazdoor.
22. Sito Bhuia, Prop. Maz.
23. Dhani Bhuia, Prop. Mazdoor.
24. Lal Behari Das, Prop. Mazdoor.
25. Chaita Mahato, Prop. Mazdoor.
26. Ram Pd. Nunia, Prop. Mazdoor.
27. Chanarik Beldar, Exp. Carrier.
28. Somrit Beldar, Exp. Carrier.
29. Kewal Beldar, Prop. Mazdoor.
30. Chandradeo Belder, Prop. Mazdoor.
31. Chandradip Beldar, Prop. Maz.
32. Surajdeo Nunia, Truck Khalasi.
33. Dasrath Beldar, Truck Khalasi.
34. Ramsarup Beldar, Truck Khalasi.
35. Surajdeo Beldar, Truck Khalasi.
36. Nagina Kamin No. 1, Coal Suppl.
37. Ramratia Kamin, No. 1, Coal Suppl.
38. Rajranla Dusadin, Coal Supplier.
39. Rasmani Kamin, Coal Supplier.
40. Keso Kamin, Trammer.
41. Sanichar Rai, Drillman.
42. Dhangl Kamin, Coal Supplier.
43. Ram Sahai Majhi, Drillman.

2. Soon after the receipt of the reference, notices were sent to the parties for filing written statement. While the employers filed their written statement in time, the union prayed for the filing the same. After several adjournments, the parties ultimately filed memorandum of settlement on 27-10-84 in terms of which all the concerned workmen have been regularised w.e.f. 1-1-84 in time-rated jobs without any difference of wages or any other benefit as a result of their above absorption in time rated jobs. Since the settlement is beneficial to both the parties, I accept the same and my award accordingly. The settlement will form part of the award.

Dated : 9-11-84.

I. N. SINHA, Presiding Officer,

BEFORE THE PRESIDING OFFICER

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL,
NO. II AT DHANBAD

Reference No. 93 of 1982

Employers in relation to the Management of Benedih Colliery.

AND

Their workmen

Petition of compromise

The humble petition on behalf the Parties aforesaid most respectfully sheweth :—

1. That without prejudice to the respective contentions of the parties, it is submitted that the dispute referred to this Hon'ble Tribunal for adjudication by notification No. L-20012(87)/82/D. III (A) dated 29th July '82 has been settled on the following terms :—

Terms of settlement

1. That Shri Kishori Paswan, Pump Operator, Cat. II (Sl. No. 2) Shri Mangar Singh, Drillman (Sl. 1), Cat. IV, Shri Jairam Gope, Drillman, Cat. IV (Sl. No. 3), Shri Rati Rai, Drillman (Sl. No. 4), Shri Lafjee Yadav, Drillman, Cat. IV (Sl. No. 5), Shri Sudeshwar Sao, Drillman, Cat. IV (Sl. No. 6), Shri Kartik Mahato, Drillman, Cat. IV (Sl. No. 7), Shri Sanichar Roy, Drillman, Cat. IV (Sl. No. 41), Shri Ram Sahai Manjhi, Drillman, Cat. IV (Sl. No. 43) will be regularised with effect from 1-1-84 plus three increments.

2. That Shri Kuldip Dusadh, Explosive Carrier, Cat. II (Sl. No. 8) Shri Tara Mahato, Line Mazdoor, Cat. II (Sl. No. 9), Shri Bhola Mahato, Line-Mazdoor Cat. II (Sl. No. 10), Shri Baijnath Mahato, Line Mazdoor, Cat. II (Sl. No. 11), Pokhan Bhuiya, Line Mazdoor, Cat. II (Sl. No. 12), Chanarik—Beldar, Line Mazdoor, Cat. II (Sl. No. 27) will be regularised with effect from 1-1-84 plus three increments.

3. That Shri Mohan Dusadh, Pump Operator, Cat. II (Sl. No. 16), Surajdeo-Beldar, Prop Mazdoor, Cat. II (Sl. No. 17), Ramdas Rabidas, Prop Mazdoor, Cat. II (Sl. No. 18), Karmu Nonia, Prop Mazdoor Cat. II (Sl. No. 19) Sahadeo Bhuiya, Prop Mazdoor, Cat. II (Sl. No. 20), Kasurwa Bhuiya, Prop Mazdoor, Cat. II (Sl. No. 21), Sita Bhuiya, Prop Mazdoor, Cat. II (Sl. No. 22), Dhanl Bhuiya, Prop Mazdoor, Cat. II (Sl. No. 23), Lal Bihari Das, Prop Mazdoor, Cat. II (Sl. No. 24), Chaita Mahato, Prop. Mazdoor, Cat. II (Sl. No. 25), Ram Prasad Nonia, Prop Mazdoor, Cat. II (Sl. No. 26), Kewal Beldar, Pump Operator, Cat. II (Sl. No. 29), and Chandradip Beldar, Pump Operator, Cat. II (Sl. No. 31) will be regularised with effect from 1-1-1984 plus three increments.

4. That Shri Chandradeo Beldar (Sl. No. 30) will be regularised as Surface Trammer in Cat. III with effect from 1-1-1984 and he will be fixed with the initial starting of Cat. III plus three increments.

5. That Shri Munshi Singh will be regularised as Tyndel in Cat. IV with effect from 1-1-1984 and he will be fixed with the initial starting of Cat. IV plus three increments.

6. That Shri Chhotan Mahato (Sl. No. 14) will be regularised as Trammer with effect from 1-1-1984 and he will be fixed with the initial starting in Cat. III plus three increments.

7. That Shri Bhanu Mahato (Sl. No. 15) will be regularised as Line Mazdoor in Cat. II with effect from 1-1-1984 and he will be fixed with the initial starting in Cat. II plus three increments.

8. That Shri Dasarath Beldar (Sl. No. 33) and Ramsarup Beldar (Sl. No. 34) will be regularised as Truck Khalasi in Cat. II with effect from 1-1-84 and they will be fixed with the initial starting in Cat. II plus three increments.

9. That Shrimati Nagia Kamin, Coal Supplier, Cat. I (Sl. No. 36), Smt. Ramratia Kamin, Coal Supplier, Cat. I (Sl. No. 37), Smt. Rajrania Dusadhin, Coal Supplier, Cat. I (Sl. No. 38), Smt. Rasmani Kamin, Mason Kamin, Cat. I (Sl. No. 39), Dhangi Kamin, Coal Supplier, Cat. I, (Sl. No.) will be regularised with effect from 1-1-1984 plus three increments.

10. That Shri Kesho Bhuiya, will be regularised as Trammer in Cat. III with effect from 1-1-1984 and he will be fixed with the initial starting of Cat. III plus three increments.

11. That neither the concerned workmen nor the union on their behalf will claim any difference of wages or any other benefit relating to their absorption in time rate job from piece rated job on regular basis on the change over of job and regularisation has been done on the basis of their own demands made by their own volition for their own benefit.

That in view of the settlement, there remains nothing to be adjudicated.

Under the facts and circumstances stated above, the Hon'able Tribunal will be graciously pleased to accept the terms of settlement as fair and proper and will be pleased to pass the Award in terms of the settlement.
For the workmen.

B. N. Yadav.

(Bajinath Yadav)

Br. Secy. R. C. M. S.

(S. Bose).

Secy., R.C.M.S.

For the Employers.

S. S. THAKUR, Superintendent

Benedih Colliery

M. B. Jha, Dy. Personnel Manager

Block-II Area

I. N. SINHA, Presiding Officer

[No. L-20012(87)/82-D-III. (A)]

S.O. 4295.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Damoda Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., and their workmen, which was received by the Central Government the 14th November, 1984.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL (NO. 2) DHANBAD

PRESENT :

Shri I. N. Sinha,

Presiding Officer.

Reference No. 62 of 1982.

In the matter of an industrial dispute under S. 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Damoda Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Ltd.

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers.—Shri B. Joshi, Advocate.

On behalf of the workmen.—Shri S. Bose, Secretary, Rastriya Colliery Mazdoor Sangh, Dhanbad.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, the 7th November, 1984

AWARD

This is an industrial dispute under S. 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947. The Central Government in the Ministry of Labour vide its order No. L-20012(55)/82-D. III(A) dated 24th June, 1982 has referred this industrial dispute to this Tribunal for adjudication with the following schedule :

SCHEDULE

"Whether the demand of the workmen of Damoda colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office : Nawagarh, District Dhanbad for regularisation of the workmen listed in the Annexure below as Night Guards is justified ? If so, to what relief are the workmen concerned entitled ?"

ANNEXURE

1. Shri Jagdish Mochi, Wagon Mazdoor.
2. Shri Jugal Chamar, Trammer.
3. Shri Ram Khelawan Pandey, Trammer.
4. Shri Guma Chamar, Genl. Mazdoor.
5. Shri Ghanarik Beldar, Khanak.
6. Shri Sadafal Bhuiya, Trammer.
7. Shri Lakhan Nonia, Khanak.
8. Shri Raghubir Nonia, Khanak.
9. Shri Briksha Bhuiya, Khanak.
10. Shri Chota Kharhar Chamar, Khanak.

2. Soon after the receipt of the reference notices were sent to the parties for filing written statement. Accordingly the parties filed their written statements. Thereafter the case was fixed for filing the other papers by the parties. Ultimately, on 30-10-84 the parties filed a memorandum of settlement in terms of which all the concerned workmen shall be regularised as Night Guard and the concerned workmen will not get any difference of wages. Since the settlement is beneficial to both the parties. I accept the settlement and pass my award in terms of the settlement. The settlement will form part of the award.

Dated : 7-11-84.

I. N. SINHA, Presiding Officer

PETITION OF COMPROMISE IN REF. NO. 68/82.

The humble petition on behalf of the parties to the above reference most respectfully sheweth :—

1. That without prejudice to the respective contentions of the parties contained in the written statement, they have agreed to settle the dispute on the following terms.

TERMS OF SETTLEMENT

1. That the concerned workmen S/Sri Jagdish Mochi, Bailing Mazdoor, Jugal Chamar, Trammer, Khelawan Pandey, Trammer, Guma Chamar, General Mazdoor, Chamarik Beldar, M/Loader, Sadafal Bhuiya, Trammer, Lakhan Nonia, M/Loader Raghubir Nonia, M/Loader, Briksha Bhuiya, M/Loader & Ch. Kharhar Chamar, M/Loader shall be regularised as Night Guard and shall be placed in grade 'G'.
2. That S/Sri Chamarik Beldar, M/Loader, Lakhan Nonia, M/Loader, Raghubir Nonia, M/Loader,

Briksha Bhuiya, M/Loader and Ch. Kharhar Chamar, M/Loader shall be regularised as Night Guard and be placed in grade 'G' with effect from 1-12-1983 and S/Sri Jagdish Mochi, Bailing Mazdoor, Jugal Chamar, Trammer, Khelawan Pandey, Trammer, Guma Chamar, General Mazdoor and Sadafal Bhuiya, Trammer shall be regularised with immediate effect and their notional seniority will be maintained with effect from 1-12-83.

3. That the concerned workmen shall be placed in grade 'G' with starting initial basic.

4. That the concerned workmen shall not claim any back wages or difference of wages.

2. That in view of the settlement there remains nothing to be adjudicated.

It is, therefore, humbly prayed that the settlement may kindly be accepted and award may be passed in terms of the settlement.

Signature of Representative of the Management.

Signature of Representative of the workmen/union.

1. Sri V. R. Joshi,
Personnel Manager,
Barora Area.

1. Sri. Shankar Bose,
Secretary, R.C.M.S.

2. Sri A. N. Yadava,
Manager,
Damoda Colliery.

2. Sri Parshuram Sharma,
Area Secretary,
R.C.M.S.,
Barora Area.

3. Sri M. K. Singh,
Sr. Personnel Officer,
Barora Area.

3. Sri Mohan Sharma,
Vice President,
R.C.M.S.,
Damoda Colliery.

I. N. SINHA, Presiding Officer

[No. L-20012(55)/82-D-III. (A)]

New Delhi, the 17th November, 1984

S.O. 4296.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Jankunder Open Cast Project of Messrs Bharat Coking Coal Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 12th November, 1984.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (No. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri I. N. Sinha,

Presiding Officer.

Reference No. 23 of 1982.

In the matter of Industrial Disputes under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947.

The employers in relation to the management of Junkunder Open Cast Project of Messrs. Bharat Coking Coal Ltd., Chanch Victoria Area No. XII, Begunia, Post Barakar, Distt. Burdwan and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers.—Shri G. Prasad, Advocate.
On behalf of the workmen.—Shri S. Bose, Secretary, R.C.M.S., Dhanbad.

STATE : West Bengal.

INDUSTRY : Coal.

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-20012(371)/84-D. III(A) dated the 27th February, 1982.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Junkunder Open Cast Project of Messrs. Bharat Coking Coal Ltd., Chanch Victoria Area No. XII, Begunia, Post Office Barakar, District Burdwan, in dismissing Sarvasiri Kam Deep Roy, Ram Bahadur Thapa and Sher Bahadur Singh, Night Guards from service with effect from the 12th January, 1981 is justified? If not, to what relief are the said workmen entitled?

The case of the management is that the concerned workmen were on duty from 10 P.M. to 6 A.M. on 2-8-79 at the quarry of I.O.C.P. During that period a theft was committed at the quarry from where field switch 3/62, Russian Drill Cable (2) Russian Electric Shovel (5-7)(4) Russian Electric Shovel (2-6) worth Rs. 31,250.00 were stolen. The concerned workmen along with another were chargesheeted on 4-8-79 under the Model Standing Orders for Coal Mining Industry applicable to and adopted by the management for neglect of duty causing wilful damage to property of the management. The concerned workmen received the chargesheet and submitted their respective replies on different dates admitting that theft was in fact committed. The said reply was found to be unsatisfactory and thereafter a common joint departmental enquiry was made in presence of the concerned workmen in accordance with the principles of natural justice. The workmen concerned were given full chance and opportunity to cross-examine the management's witnesses and also to examine themselves and their witnesses. The enquiry officer found them guilty of the charges and submitted his detailed report giving reasons therefor. The concerned workmen were not able to establish their defence. The concerned workmen were dismissed with effect from 12-1-81 by a letter issued by the Agent, I.O.C.P. after the approval of the competent authority was obtained. The action of the management in dismissing the concerned workmen were fully justified and the concerned workmen are not entitled to any relief. It was further stated on behalf of the management that since the workmen concerned were dismissed after due fair and proper departmental enquiry conducted in accordance with the principles of natural justice, it was essential that a preliminary order be passed as to whether the departmental enquiry made by the management is fair and proper and in case the domestic enquiry is found not fair and proper, an opportunity may be given to the management to lead evidence to justify the action taken by them.

The case of the concerned workmen is that they are permanent employees in the capacity of Night Guard in I.O.C.P. of M/s. B.C.C. Ltd. Their Area Immediate Officer is the Area Security Officer and their controlling officer is the Chief Security Officer BCCL. The higher officials of the Security Department and the Project took up the matter of theft with the appropriate authorities including Police and directed the concerned workmen to make a statement before the Welfare Officer of the Project who recorded their statement in writing. The Security Department of BCCL and the local police Station Officer also investigated the case and had prepared their respective records but to the best of the knowledge of the concerned workmen the report did not state anything against them. After about a week the concerned workmen were served with chargesheet under the signature of the Superintendent Junkunder with a back date. The said chargesheet is invalid and without jurisdiction as the chargesheet did not contain copy of reports of enquiry made by Security department and copy of the

statement recorded by the Welfare Officer of the Project. The further objection of the concerned workmen is that the Superintendent Junkunder Colliery was not the controlling authority of the concerned workmen who were Night Guards. The concerned workmen had stated in detail that they were not at fault and had not committed any misconduct. The Superintendent of the Colliery illegally and without jurisdiction conducted a show of enquiry which was just a formality and with pre-determined motive got a report prepared against them by the enquiry Officer of his choice who was neither impartial nor fair and was not appointed by a competent authority. Thereafter the General Manager of Area No. XII by his letter dated 4/12-81 dismissed the concerned workmen from their service.

On the preliminary point, whether the departmental enquiry was fair and proper, the management examined two witnesses and the concerned workmen examined four witnesses. Besides that, both the parties exhibited document in support of their respective cases.

In nutshell the main objection regarding the departmental enquiry raised on behalf of the concerned workmen is that the authority which framed the charge against them had no authority to take disciplinary action and frame charge against them and as such there was no legal charge against them which could be enquired in a domestic enquiry.

It has been contended by Shri S. Bose, Secretary, R.C.M.S. representing the workmen, that the Superintendent of Junkunder Colliery who had issued the chargesheet dated 4-8-79 was not the competent authority to frame charge against them and as such the entire domestic proceeding being without authority was a nullity. It is submitted that the concerned workmen being Night Guards in Junkunder Open Cast Project were under the control of the Chief Security Officer and the said Chief Security Officer was their controlling authority and their Area Immediate Officer was the Area Security Officer. MW-1 who had enquired into the charges against the concerned workmen in the domestic enquiry has stated that the Superintendent of Junkunder Open Cast Project had appointed him as Enquiry Officer. It would further appear from Ext. M-1 to M-1/3 that the chargesheets were issued under the signature of the Superintendent of Junkunder Open Cast Project. MW-1 has further stated that Shri Mahanti was the Superintendent who had appointed him as the Enquiry Officer. Ext. M-3 dated 21-8-79 is the Order appointing MW-1 Shri U. K. Sinha as Enquiry Officer and this order was issued by the Superintendent, Junkunder Open Cast Project. MW-2 who is a Dy. Personnel Manager has stated that there is Board of Directors in BCCL which has delegated powers for Security Personnel. Ext. W-1 is the delegation of powers which has been marked Ext. On the evidence of MW-2. MW-2 has further stated that Shri R. N. Singh was the DIG/Chief Security Officer of BCCL in 1975 and he has proved a dismissal letter dated 3-12-75 marked as Ext. W-2, which has been issued under the signature of Shri R. N. Singh, DIG/Chief Security Officer. It will appear from it that one Shri Rajendra Singh, Night Guard was dismissed from service for serious misconduct by the order of Shri R. N. Singh, DIG/Chief Security. MW-2 has further stated that the DIG/Chief Security used to issue Officer Order from time to time in the same area and the order issued by the DIG/Chief Security dated 18-10-73 is marked Ext. W-3. This Ext. W-3 is an Office Order of transfer of Night Guards from Lodna Colliery to the Security Headquarters Jhargora. Ext. W-4 is the letter dated 6-5-75 issued under the signature of the Assistant Security Officer showing that he had passed an Order of warning against one Shri Ramdip Roy, Night Guard. These exhibits have been filed to show that it was the security department which was dealing with transfer, dismissal, appointment of Night Guard of the Security department of BCCL. MW-2 has clearly stated that the Security department had not issued the chargesheet against the concerned workmen. MW-2 has tried to show in his evidence that there was consultation before issuance of chargesheets between the Superintendent, I.O.C.P. and DIG/Chief Security and that he was present at the time of the said consultation. There is absolutely no paper to show that the Superintendent, I.O.C.P. had any consultation with the DIG/Chief Security before issuance of chargesheets against the concerned workmen. MW-2 does

not remember if any note sheet of the discussion had been prepared. Had there been really any consultation as stated by MW-2, there must have atleast been a note of discussion regarding the fact that the DIG/Chief Security after consultation had agreed that the chargesheet be issued by the Superintendent, J.O.C.P. All these evidence in the statement of MW-2 has been introduced to show that the chargesheet was actually issued with the consultation of the DIG/Chief Security. The management was probably aware by the time of hearing of this preliminary point that there was no material to show that the Chief of Security Officer had issued the chargesheet against the concerned workmen and as such the chargesheet was without any authority and therefore in the evidence of MW-2, the theory of consultation between the Superintendent and the Chief Security has been introduced which cannot be accepted in view of the fact that there is no paper in support of the said fact.

It has been submitted on behalf of the concerned workmen that there has been a delegation of powers in favour of the DIG/Chief Security and under the said delegated powers the DIG/Chief Security had the full powers for removal from service and dismissal from service in respect of all the security personnel under his charge. In accordance with the rules and that the Area General Manager/Sub-Area Manager or the Colliery Manager had no powers to take disciplinary action against the Security Personnel. Ext. W-1 is the schedule of powers for Security Personnel to that effect. On reference to Circular dated 25-3-69 at page 26 of the Compendium of Important circulars of Vol. I issued by the department of Administration, M/s. BCCL (which has been filed before me after calling for the same from the Hon'ble Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad) by which it will appear that the Managing Director has sub-delegated to the Director (Administration) all the powers delegated to him under the revised schedule of powers approved by the board of directors at their meeting held on 5-9-62 in respect of all the matters concerning establishment, administration, personnel, revenue, security and vigilance etc. The Office Order dated 4-5-73 at page 183 of the Compendium shows that the director (Administration) placed the services of all Colliery Guards, Night Guards, Watchman, Chaprasi and other Office Peon at the disposal of Chief of Security for all the BCCL and CMA mines with effect from 1-5-73 and in order to have smooth administration, the Chief Security was made responsible for transfer, posting promotion and disciplinary action of all ranks below the Officers level and under the schedule enclosed to the said order and further delegated to him full powers of removal and dismissal from services in respect of Officers and the staff under his charge in accordance with the rules. The evidence of WW-1 also shows that the DIG/Chief Security of BCCL was his head of the department and that the appointment, transfer, posting and promotions are all done by the Chief of Security. He has further stated that he was not chargesheeted by the Security department and that no enquiry was conducted into the charges by the Security Department. It will thus appear from the circulars, orders and the evidence referred to above, that the DIG/Chief Security had delegated powers to take disciplinary action and issue order of dismissal against the Night Guard.

There is no evidence to the effect that the Superintendent of Junkunder Open Cast Project had any authority to take any disciplinary action against the Security Personnel. There is also no evidence that the Superintendent was holding any higher post than the DIG/Chief Security.

From all the materials discussed above, it will appear that the concerned workmen were under the Chief Security and the concerned workmen were under the Chief Security and the charges had not been framed against the concerned workmen by the Chief Security and that the Superintendent of J.O.C.P. who had framed the charges against the concerned workmen and had appointed the Enquiry Officer had neither any authority to frame charge against the concerned workmen nor had any authority to order for disciplinary action against them. This being the position it is clear, that the person who had issued the chargesheet against the concerned workmen had no authority to issue the chargesheet and the chargesheet issued was without any authority and

was complete nullity. Any enquiry made on the basis of an illegal chargesheet was, therefore, inoperative and cannot be acted upon. I hold, therefore, that the chargesheet framed against the concerned workmen being without authority was not at all a chargesheet and the same was a nullity.

It was submitted on behalf of the management that if the Tribunal holds that the domestic enquiry was not fair and proper the management should be given an opportunity to adduce further evidence in order to prove the charge against the concerned workmen. Ordinarily, the management would have been given an opportunity to adduce evidence before this Tribunal if the domestic enquiry was held to be improper. The difficulty in the present case is that in view of my findings made above the chargesheet was issued without any authority and as such in the eye of law, there was no charge against the concerned workmen and this being a nullity there was no valid charge before this Tribunal to which the management could be called upon to adduce evidence to prove the charge. The evidence could have been led by the management only if there was a valid charge existing on the record before me but as there is no valid charge against the concerned workmen, I hold that the management cannot be allowed to adduce any evidence in proof of the illegal charge which is a nullity. It has therefore to be held that the management cannot be allowed to adduce evidence in this case. The reference is finally disposed off on the above decision on the preliminary point alone.

In view of the above, I hold that the action of the management of Junkunder Open Cast Project of M/s. B.C.C. Ltd., in dismissing the concerned workmen from service with effect from 12-1-81 is not justified and as such the concerned workmen are reinstated on their jobs with all back wages and consequential benefits.

This is my Award.

Dated : 31-10-84.

I. N. SINHA, Presiding Officer
[No. L-20012(371)/81-D-III (A)]

S.O. 4297.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bhowra (North) Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 12th November, 1984.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri I. N. Sinha, Presiding Officer.

Reference No. 86 of 1982

In the matter of Industrial Disputes under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947

PARTIES :

Employers in relation to the management of Bhowra (North) Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Bhowra, District Dhanbad and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers—Shri B. Joshi, Advocate.

On behalf of the workmen—Shri J. D. Lall, Advocate.

STATE : Bihar

INDUSTRY : Coal

Dhanbad, the 30th October, 1984

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947, has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-20012(104)/82-D-III (A), dated, the 9th August, 1982.

SCHEDULE

"Whether the demand of the underground piece-rated Trammers of 7/10 Incline of Bhowra (North) Colliery, Bhowra Area of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Bhowra, District Dhanbad for upward revision in the rates of their wages is justified? If so, to what relief are the said workmen entitled?"

The case of the concerned workmen is that S/Shri Satya Dusaich and 23 others as annexed in the annexure attached to their W.S. were working as piece rated trammers underground in seam No. 7/10 incline of Bhowra (N) Colliery. Prior to February 1981 three trammers were working on the surface and four trammers were working underground in each shift in 7/10 incline of Bhowra (N) Colliery. The strength of trammers per shift on the surface and underground are pre-fixed in every mine pit or incline by way bipartite settlement and the work load per head per shift along with basic tramping rate per tub is also fixed as per formula prescribed as per National Coal Wage Agreement No. 1 and II. Prior to the implementation of NCWA-II, the basic tramping rate per tub as fixed under NCWA-I was Rs. 2.02 P. in respect of underground trammers of 7/10 incline which raised to Rs. 2.22 per tub under NCWA-II which came into effect from 1-1-1979. The strength of the underground trammers of 7/10 incline was raised from 4 trammers per shift to 8 trammers per shift and the strength of surface trammers were raised from three to four w.e.f. 1-2-1981. As a result of the said unilateral increase in the underground trammers of incline No. 7/10 from 4 to 8 per shift the earning of the underground trammers was reduced as the basic wages which was shared by four trammers were now shared by eight trammers reducing their earning to almost half of what they were earning prior to 1-2-81. The Coal Wage Board Recommendation, and NCWA-I and II provide specifically for (1) Periodic appraisal for tramping rate and for refixation of tramping rate whenever there was change in the mining condition from time to time. In February, 1981 there was change in the mining condition which necessitated the increase in the number of trammers per shift and as such as per provision of NCWA-II there was need for upward revision or tramping rate of the concerned workman w.e.f. 1-2-1981 but the same was refused by the management giving rise to the present dispute. The strength of underground trammers was fixed in a bipartite settlement to four per shift vide settlement dated 1-3-1979 and the management violated the said settlement by increasing the strength of trammers from four to eight w.e.f. 1-2-1981. The management of Bhowra Colliery did not fix the basic tramping rate as per the formula and procedure laid down in NCWA-II which came into effect from 1-1-79. The basic tramping rate should have been fixed at about Rs. 3 per tub instead of Rs. 2.22 P. per tub which was fixed by the management w.e.f. 1-1-79. The concerned workman are entitled to basic tramping rate of Rs. 3 per tub with effect from 1-1-79 and Rs. 6 per tub with effect from 1-1-81.

It is further stated in the rejoinder of the concerned workman that prior to 1981 there was one working panel in 7/10 incline and the same was quite near to the haulage and the road was straight and as such four trammers were able to handle the tramping of the tube effectively. In the beginning of the year 1981 the old panel was closed and another panel was started having circuitous feeder road which increased distance considerably and four underground trammers per shift was added to the four trammers already working from before. From November, 1982 the management, however, revised the tramping rates upwards and as such no claim has been made after November, 1982. On the above facts it has been submitted on behalf of the workmen four upward revision in their basic tramping rate @ Rs. 3 per tub with effect from 1-1-79 and to Rs. 6 per tub with effect from 1-2-81.

It will appear from the facts of the case stated above that the demand of the concerned workmen were two fold. Their first demand was that their tramping rate was not fixed according to the prescribed formula of NCWA-II with effect from 1-1-79 and that their basic tramping rate should have been Rs. 3 per tub with effect from 1-1-79. Their second demand is that from first of February, 1981 the management increased the number of underground trammers from four to eight in each shift and as such the rate should have been fixed at Rs. 6 per tub in as much as their earning

was reduced almost to half from 1-2-81 after the four more trammers were employed by the management in each shift. During the hearing of the argument Shri J. L. Lall, Advocate, representing the concerned workmen gave up their first claim that the basic tramping rate with effect from 1-1-79 should be fixed @ Rs. 3 per tub as such there is no dispute regarding upward revision of the basic tramping rate or the concerned workmen with effect from 1-1-79 and the present dispute is confined only to the upward revision of the basic tramping rate with effect from 1-2-81 @ Rs. 6 per tub.

The question for determination, therefore is whether the demand of the workmen for upward revision in the rates of their basic wages from 1-2-81 to 31-10-82 @ Rs. 6 per tub is justified.

The workmen and the management each have examined one witness in support of their respective cases. Besides that two documents have been exhibited on behalf of the workmen.

In para 75 vol. I of Wage Board Recommendation the matter relating to the trammers have been dealt with. In para 59 it is stated that as there is no fixed workload for piece rated trammers their piece rate vary not only from colliery to colliery but also from section to section depending mainly upon distance gradient and turnover of tubs. The formula for fixing the tramping rate per tub in respect of piece rated trammers has been given in the Wage Board Recommendation. Additionally from 1-1-79 NCWA-I came in operation. In para 5.7 of NCWA-II it is provided that the workload and the rate per tub for the piece rated trammers should be fixed at the end level by bipartite negotiation in such a way that the normal earning of the trammers is atleast at the end point of the scale of the time rated trammers. The workload and the rate of tramping should be reviewed periodically as and when change and condition of work occurs. Whenever time rated tramping is prevailing, a system of time cum piece rate for trammers may be introduced. In para 5.5 of NCWA-II it is stated that there will be a daily review of earning of piece rated workers to ensure payment of full back wages, which will be inclusive of lead and hit but not tub pushing allowance. The full back wage is payable in case piece rated workers fail to fulfil the work norms on account of factors for which they are not responsible and that no full back wage is payable if the workers fail to fulfil the work norms due to his own fault. Ex. W-1 is a settlement between the management and the representative of the workmen which shows that the parties came to the following terms of settlement. (1) There will be seven trammers in each shift (2) The work load will be underground 8.5 tubs and 11.33 tubs on the surface (3) The basic rate per tub will be Rs. 1.52 paise underground and Rs. 1.14 paise per tub on the surface. The said agreement came into effect from 1-3-79. It appears, therefore, that the workmen in a bipartite agreement had fixed the number of trammers, work load and the rate of tramping with effect from 1-3-79 and as such the said agreement is binding on them and they cannot now say that they are entitled to increase in the tramping rate from 1-1-79. It is for this reason that the concerned workmen have given up their claim for increase of tramping rate from 1-1-79 to 1-8-81 as originally claimed. Ex. W-2 is a memorandum of settlement arrived at between the management and the representative of the workmen. It will appear from this bipartite settlement that since from November, 1982 eleven seam development was started in 7/10 incline in place of panel B which exhausted another tigger haulage was maintained for taking out tubs from 11 seam development district and thus there was a drastic change in mining condition and rate of underground trammers required revision. On the representation of the workmen of 7/10 incline for revision of rate the matter was settled. It was agreed that (1) There will be eight trammers underground (2) The workload of the underground trammers will be 5.625 tubs per head per shift (3). The basic rate per tub was fixed @ Rs. 3.35 P. and the said agreement was effective from November, 1982. It will appear therefore that since November, 1982 the tramping rate of the concerned workmen was increased to Rs. 3.35 P. and that their number was also increased to eight trammers in the underground. As there was a settlement the concerned workmen are not claiming any revision or increase in the tramping rate from November, 1982 and

the claim is now confined for increase in the tramming rate from 1-2-81 to 31-10-82.

It will appear from the evidence of MW-1 Shri Ashutosh Kulkarni who is working as a manager that there were two panels in 7/10 incline since 1978 only one of the panel in the said incline was being worked and for that four trammers were working in each shift in the said one panel since 1-7-8. He has stated that in February, 1981 another panel was opened and since then two panels were working in No. 7/10 incline and for that eight trammers were put on the job per shift in the two panels. He has stated that towards the close of 1982 the panel which was existing since prior to 1981 was stopped and a development panel was started and then one more tugger haulage was added over and above two permanent haulage already existing in the said incline. He has stated that the rate of tramming was increased from November, 1982 after installation of tugger haulage. This evidence of MW-1 and support from the admitted document Ext. W-2 from which it will appear that from the month of November, 1982 11 seam development was started in 7/10 incline in place of panel B which was exhausted and another tugger haulage was being installed for taking out tubs from 11 seam development district and as there was a drastic change in mining condition and an agreement was arrived at regarding the number of trammers, the workload and basic rate per ton. MW-1 Ragu Singh is one of the concerned trammers. He has stated that in February, 1981 the panel in which they were working was stopped and two separate panels were started underground and thereafter the number of trammers working underground was increased per shift whereas the number of hauler loaders remained the same. From the above evidence of MW-1 it will appear that the panel in which they were working in 7/10 incline was stopped in February, 1981 and that thereafter two support panels were started underground. The said witness examined on behalf of the workmen does not state that a development district had been started in 7/10 incline from November, 1982 and according to him the present seam were working since 1-2-81 but Ext. W-2 clearly shows that one development panel was started in November, 1982 in 7/10 incline after panel B was exhausted. Thus it will appear that the two panels which were working was the development panel started in November, 1982 and another panel which was started in 1981 as stated by MW-1. Had there been the existence of the development panel since February, 1981 the workmen could not have agreed in the settlement Ext. W-2 to get their basic tub rate and the work load fixed w.e.f. November, 1982 but would have insisted on settlement regarding the workload and basic tub rate from 1-2-81. It will further appear from the evidence of MW-1 that from 1-2-81 another panel was started along with the panel which was already existing since before 1981 and as such then four more trammers were employed raising their number to eight. In para 6 of the W.S. filed on behalf of the management it is stated that in 7/10 incline there were two panels out of which one was working in 1979 and that in the year 1981 another panel was started as a result the total out put of both the panels four more trammers were included per shift in the gang of underground trammers as some of the road ways are common for both the panels all the eight trammers of both the panels were grouped together for the purpose of calculation of wages. It is further stated that there was no change in the condition of service and there was no increase or decrease in the rate of tramming. It has been submitted that the workmen had called for the wagesheet from the management by a petition dated 13-5-83 to show the decrease in the earning of the underground trammers since 1-2-81 but the management did not file the same and as such an adverse inference may be drawn against them. Under the rules the wagesheet are maintained for a period of three years and thereafter they are destroyed. It is submitted on behalf of the management that the wagesheet of the required period is now not available and the workmen themselves could produce the copy of the Wagesheet which is admittedly given to them for each month wages. MW-1 has also admitted that they are getting wage slips but he has not filed the same. The concerned workman could have filed the copy of their wage slip in order to show the actual amount of their wages received by them from February, 1981. Had really there been a decrease in the wages, they would have certainly produced the copy of their wage slip which was with them. Moreover the concerned workman cannot get less than the minimum fall back wage and the case of the concerned workmen that their wages were reduced to half since February, 1981 cannot be believed.

From the facts and the evidence in the case it will appear that as there was no change in the working condition of the trammers since 1-2-81 no settlement was required for fixing the tramming rate and that when a new development panel was started in November, 1982 there was a change in the working condition of the trammers necessitating increase in the tramming rate and through bipartite agreement the parties came to a settlement vide Ext. W-2. The new tugger haulage was introduced after the start of the development panel and previously there were two haulages in which eight trammers were working in each shift. There was no change in the working condition of the underground trammers when the two haulages were in operation and that the change in their working condition only took place after the introduction of the tugger haulage with the starting of the development panel and as such there was no need of fresh settlement prior to November, 1982. In my opinion the demand for a revision of tramming rate from 1-2-82 to 31-10-82 does not appear to be justified.

In the result, I hold that the demand of the underground piece rated trammers of 7/10 incline Bhowra North Colliery of M/s. B.C.C. Ltd. for upward revision in the rates of their wages is not justified and they are entitled to no relief.

This is my Award.

I. N. SINHA, Presiding Officer
[No. L-20012/104/82-D.III (A)]

A. V. S. SARMA, Desk Officer

New Delhi, the 19th November, 1984

S.O. 4298.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India, Gorakhpur Branch, Varanasi Region and their workmen, which was received by the Central Government on the 14-11-1984.

BEFORE SRI R. B. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL—
CUM-LABOUR COURT, KANPUR

I. D. No. 14/81

In the matter of disputes between :

Shri Banarasi, Sweeper,
C/o Shri D. R. Saxena,
189, Talabganji, Shukla Mandal House,
Lucknow.

AND

The Chief Regional Manager,
State Bank of India,
Regional Manager's Secretariat,
Varanasi.

PRESENT :

Shri D. R. Saxena—for the workman.

Shri Mahesh Chandra—for the Management.

AWARD

The Central Government vide its Order No. L-12012(192)/79-D-II (A) dated 3-2-1981 referred the following industrial dispute for adjudication :—

"Whether the action of the management of State Bank of India, Gorakhpur Branch of Varanasi Region, in terminating the services of Shri Banarasi, Ex-Sweeper-cum-Farash w.e.f. 1-8-1976 is justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?"

It is common ground that the workman was employed in the State Bank of India, Cantt. Board, Sadar, Lucknow w.e.f. 2-9-69 and was later transferred to State Bank of India, Gorakhpur where he worked upto 30-6-1976. According to workman he fell ill thereafter and proceeded on medical leave w.e.f. 1-7-1976 to 31-7-1976 and submitted Medical Certificate in support thereof when on 1-8-1976, he went to join duty and asked Manager, Gorakhpur did not allow him to join duty and asked him to go to Lucknow Cantt. Branch and join duty there. On return to Lucknow he was not given duty there in Cantt. Branch of State Bank of India.

Since then he went to Gorakhpur several times, but he was neither given duty at Gorakhpur nor at State Bank of India, Cantt. Branch, Lucknow. Ultimately on 24-1-1977 he approached the authorities complaining the high handedness of the two Branches. On 7-2-1977 he was at Gorakhpur Branch that his matter related to Lucknow office and he should contact there. He went to Lucknow office but he was not allowed to join there. On 13-8-1977 the workman got a letter from Gorakhpur Branch informing the workman that his services has been treated as voluntarily vacated w.e.f. 1-8-1976 and in this way his services has been terminated which is illegal. It is also asserted that he was not run down for misconduct and the termination amounting to illegal retrenchment as retrenchment compensation has not been paid to him. In the end pay of May, June and July, 1976 too has been claimed.

According to the Bank management the workman himself abandoned his job and deemed to have resigned by his continuous absence without permission or proper justification. If being not a case of termination of service under Sec. 2A of J. D. Act is not attracted and order of reference is invalid.

It is admitted that the workman while serving in Cantt. Branch, Lucknow had made a report of alleged withdrawal of Rs. 150 from his Saving Bank Account by Shri Talwar a Clerk of that Branch by forging his signature which on investigation, was found false. He was thereafter transferred to Gorakhpur on administrative grounds. It is further averred that after joining his duties at Gorakhpur Branch started absents himself frequently. It is admittedly that after 10 days of commencement of leave his medical leave from 1-7-1976 to 31-7-1976 was allowed. The workman did not join duty on 1-8-1976 and continued to remain absent. The Branch Manager, Gorakhpur then sent him a registered notice dated 17-11-1976 asking him to join duty within 15 days of its service failing which it will be deemed that he was not interested in his job and had vacated his appointment in Bank.

It is admitted by the management that workmen who was appointed on 2-9-1969 as Sweeper-cum-Farash at Lucknow was transferred to Gorakhpur Branch where he joined and was on the work till 31-7-1976 thereafter mostly he was on leave. He was informed by letter dated 13-8-1977 as follows :—

"In view of the fact that you are neither resuming your duties at the Branch nor submitting any explanation regarding your unauthorised absence despite repeated reminders by Registered A.C. Post, it has been decided to treat you as having voluntarily vacated your post in the Bank with effect from 1st August, 1976."

Alongwith his statement of claim he has filed annexures Act B Annexure A is dated 24-1-1977 which the workman had sent to State Bank of India, Central Office, Bombay that he likely to loose his service accusing him of sleeping over the matter.

The workman has averred that on 1-8-1976 he went to join his duty at Gorakhpur but he was not allowed to join and was asked to go back to Lucknow. At Lucknow too he was not allowed to join. In cross-examination he stated that Branch Manager Gorakhpur told him that his transfer was illegal and hence they would neither pay him his dues nor give him any order to go back to Lucknow. He further stated that he worked for full five months at Gorakhpur but was not asked for sign attendance register during that period. In the end he stated that it was wrong to say that I left duty of my own accord and despite notice did not join.

The Management representative Shri S. Dutta deposed that workman's name was struck off when he was absent for a time without leave or information and no notice pay or retrenchment compensation was given, and his name was struck off the rolls.

The representative of the workman referred me the ruling:

L. Robert D'Souza V. Cox Engine Southern Railway 1982 Sec. Cases (L + S) 124.

Wherein it was held :

"If the name of the workman is struck off the rolls that itself would constitute retrenchment. Therefore, the termination of service for unauthorised absence from duty in this case would be retrenchment within the meaning of Section 2(oo) and so the pre-condition to a valid retrenchment set out in Sec. 25-F must be satisfied."

Once the case does not fall in any of the excepted categories the termination of service even if it be according to automatic discharge from service retrenchment would never the less be retrenchment within the meaning of expression in Sec. 2(oo). It must as a corollary follow that if the name of the workman is struck off the rolls that itself would constitute retrenchment.

Under Para 521(6)(a) of the Shastri Award absence without leave or overstaying sanctioned leave without sufficient ground constituted misconduct for which maximum punishment in stoppage of increment for six months could be given.

On the basis of De Souza's case referred above in ruling. Mohd. Abdul Kadar V. A. P. Saule Road Transport 1984 Lab. I.C. page 90.

Termination of service of employee for overstay or expiry of leave by management.

It amounts to retrenchment failure to comply with requirements of Sec. 25-F by management—No enquiry held to justify action of termination on ground of misconduct—Order terminating service is liable to be quashed.

In G. T. Lad and others Vs. Chenuchal and Fibres of India 1979 S.C. (1+5) Page 76

It was held :

"To constitute abandonment of service, there must be total or complete giving up of duties so as to indicate an intention not to resume the same. Abandonment or relinquishment of service is always a question of intention and normally such an intention cannot be attributed to an employee without adequate evidence in that behalf. It is a question of fact to be determined in the light of the surrounding circumstances of each case. Temporary absence is not ordinarily sufficient constitute an abandonment of office."

Management representative Shri S. Dutta in his affidavit stated that workman did not mark his attendance since 1st July, 1976. It may be mentioned that attendance register of July 1976 has not been filed. It was on 17th November, 1976, the Branch Manager wrote to the workman complaining of his continued absence and asking him to join within 15 days failing which it will be presumed that he was not interested in his job and had voluntarily vacated his appointment in the Bank. The workman did not appear within 15 days of the receipt of letter. Rather on 8-12-76 wrote to the Branch Manager Gorakhpur that he was sweeper at Cantt Branch, Lucknow and thus his money in Sundry Deposit that he sent to him. He did not write anything about his absence. He sent another letter asking the Branch Manager Gorakhpur to send his money as he was in grant of financial difficulty. In this he gave his designation as sweeper, State Bank, Gorakhpur. The Branch Manager, Gorakhpur sent another notice dated 24-1-77 to workman complaining of his continued absence from 1-8-76 and asking him to resume duty within 7 days. A third notice dated 26-2-77 was given to workman to join duty within 7 days. The workman after a long interval sent an application on 8-11-77 admitting that after 31-7-76 he could not resume duty due to illness of wife and children applied for further leave of one month i.e. 1-11-77 to 30-11-77. He was intimated by the Bank vide letter dated 28-12-77 that the Bank has treated him as having voluntarily vacated his appointment in the Bank, the question of granting leave does not arise.

On this the workman served notice Annexure B dated 12-7-78 on which he was asked by the Bank to refer the matter to Head Office, Kanpur.

From the above discussion and law referred, two courses were open to the management.

1. To charge the workman for misconduct of remaining on leave without prior sanction and punish him after proof thereof.
2. Treat the service as abandonment thereby producing fact of termination of service and paying retrenchment compensation as required under Sec. 25-F. This having not been done, the termination (so-called) brought about from 1-8-76 availing him as having abandoned the service without paying retrenchment compensation under section 25-F is illegal.

Under the circumstances the termination order dated 13-8-77 is illegal. The result is that the workman has to be reinstated. Question arises if workman should be reinstated with full back wages or less. Admitted by he did not work from 1-8-76, though from his letters it appears that he was in grant financial hardship due to illness of his wife and children under the circumstances a order his reinstatement with 1/2 back wages from 1-8-77 to the date of joining the service.

On issue No. 2 from the circumstances and documents and evidence it emerges that though he did not resume duty after 1-8-77 there is nothing to suggest that he deliberately intended to give up his employment issue is decided accordingly, would be proper.

In view of the findings above I give my award in the affirmative alternative holding their action of the State Bank of India, Gorakhpur Branch of Varanasi Region in terminating the service of Shri Banarasi treating his long absence as abandonment of service w.e.f. 1-8-76 is not justified.

The workman shall be reinstated to his post and shall get 1/2 of the pay from 1-8-76 to the date of joining.

The award is made in the terms aforesaid.

Further ordered that the requisite number of copies may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer
[No. L-12012/192/79-D-II (A)]

New Delhi, the 22nd November, 1984

S.O. 4299.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Kanpur in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India, Main Branch, Allahabad, and their workmen, which was received by the Central Government on the 14th November, 1984.

BEFORE SRI R. B. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL—
CUM-LABOUR COURT, KANPUR

I.D. No. 170/84 (New No.)

56/83 (Old No.)

In the matter of disputes between

Sri Mehdi Hussain S/o Sri Abdul Hamid,
R/o 231, Sultanpur Bhawan,
Allahabad.

AND

The Regional Manager, State Bank of India, Allahabad
Main Branch, Allahabad.

PRESENT :

Sri O. P. Nigam—for the workman.

Sri Vijai Man Singh—for the management.

AWARD

The Central Government vide its order No. L-12012(2854)/81-D. II(A) dated 28th May, 1982 referred the following industrial dispute for adjudication :

"Whether the action of the management of State Bank of India, Main Branch, Allahabad in terminating

the services of Sri Mehdi Hussain, Armed Guard with effect from 5th February, 1972 is justified? If not, to what relief the said workman is entitled?"

It is common case that the workman Sri Mehdi Hussain after discharge from Army in the year 1969 sought recruitment in the management Bank as Armed Guard. He could claim exemption in age limit being discharged army employee, but he was required to give a certificate of school leaving showing his date of birth & educational qualification of non-matriculate. The workman submitted a school leaving certificate showing that he had passed VII class & date of birth as 17th June, 1929 allegedly issued by Principal R. R. K. Higher Secondary School, Dalippur Pratapgarh dated 2nd January, 1971. Consequently on 9th July, 1971 the workman was appointed as Branch Armed Guard & joined duty.

On enquiry regarding genuineness of the school leaving certificate submitted by the workman, it was found that the said certificate was forged and was never issued by the Principal said R. R. K. Higher Secondary School, Dalippur, Pratapgarh. The workman was asked to explain and meanwhile probation was extended. The workman explained the circumstances in which he obtained the certified and assured that he never knew that it was a forged one. It was further revealed that from 1953 there was no institution in the vicinity where the workman could have read upto 8th class. The Bank authority being satisfied that the workman had submitted the false certificate with knowledge that it was in order to support his false claim that he has read upto 8th class which was a condition for appointment as a bank guard, his services were terminated with effect from 5th February, 1972 on the ground of loss of confidence.

It is further averred by the management that even otherwise employment secured by the workman by using a forged certificate to support a false declaration was void ab-initio.

Workman was appointed temporary bank guard on 9th July, 1971 and his services were terminated on 5th February, 1972. The industrial dispute was raised six years later and the reference order was issued ten years later on 28th May, 1982. It is common ground that after termination, the workman was handed over for forgery in a criminal case which he was acquitted on 27th March, 1978 and it is then that he raised the industrial dispute. Thus the plea that the reference is belated is of no avail.

As workman was a probationer, his probation period of six months, having been extended by one month, he was discharged simpliciter in view of para 522(i) of the Shastri Award on giving one month's notice. The workman submitted to it and did not raise any industrial dispute, obviously as he was being prosecuted criminally for forgery.

The judgement of the criminal court is on record. The workman was acquitted as prosecution failed to prove his inus-rea that the document was forged.

A Memo. Ex. D-2 was given to the workman to show cause why his appointment be not terminated having given a forged certificate to obtain appointment, in the bank. Its reply Ex. D-3 the workman informed the bank that the original school leaving certificate was submitted to the defence authorities at the time of recruitment in 1953. In that the workman wrote in what circumstances he got the forged certificate which he submitted in the bank. It was a fact that the workman should have proved by another document or securing the original from the defence authorities that he was educated upto class VIII. For reason best known to the workman he sat idle after giving a plausible explanation in Ex-D. 3. In his certificate of service Ex. D-1 his date of birth is recorded as 17 June, 1929. The workman representative referred me the ruling State Bank of Travancore V/s. Dy. Commissioner, Labour, 1981 I, LLJ page 393 Madras.

If the termination was to be on the ground of reasonable cause, it was incumbent on the part of the employer to disclose the reasonable cause in the order of termination and in the absence of such a disclosure it was not possible for any authority to determine whether the ground put forth by the employer could constitute a reasonable cause and whether the order passed was a bonafide one.

In N. B. Shukla V/s. Bank of Baroda, 1971 I, LLJ 291, the ruling L. Michal V/s. Johnson Pumps Ltd., AIR 1975 SC 661 and Sidhnath Krishnaji Vs. Dadajee Dekjee 1977 Lab. I.C. Page 602 were considered.

In view of the reply Ex. D-3 the management bank had no other option but to take it that school leaving certificate showing workman as non-matriculate was false, as no effort was made to summon the original from the defence authorities and prove contents of the forged certificate as true. Thus loss of confidence was an objective set of facts i.e. non-production of certificate of educational qualification and hence the action of the management in terminating the workman services was bonafide. The workman wanted to obtain employment on false claim. Thus the termination of the services of the petitioner is a discharge simpliciter not amounting to punitive action of dismissal for misconduct and there is no ulterior motive.

In the above circumstances and for the reason discussed I give my award in the affirmative holding that the action of the management of State Bank of India in terminating the services of the workman w.e.f. 5th February, 1972 is justified.

The award is made in the terms aforesaid.

Further ordered that the requisite number of copies may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer
[No. L-12012/285/81-D.II(A)]

S.O. 4300.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Kanpur in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India, Kanpur and their workmen, which was received by the Central Government on the 14th November, 1984.

BEFORE SRI R. B. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-
CUM-LABOUR COURT, KANPUR

I.D. No. 185/84 (New No.)

I.D. No. 182/83 (Old No.)

In the matter of disputes between

Sri Hari Shanker,
C/o Sri O. P. Nigam,
295/387, Deen Dayal Road,
Ashrafabad, Lucknow.

AND

The Regional Manager,
Region No. I, State Bank of India,
Regional Office,
Commercial Exchange Building,
24, Mahatma Gandhi Marg,
Lucknow.

PRESENT:

Sri O. P. Nigam—for the workman.
Sri Vijai Man Singh—for the management.

AWARD

The Central Government vide its order No. L-12012/121/80-D. II(A) dated April, 1983 referred the following industrial dispute for adjudication:

"Whether the action of the management of State Bank of India Kanpur in relation to their Gosaiganj Branch in terminating the services of Sri Hari Shanker, Driver with effect from 1st February, 1975 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

The case of the workman is that he was given an appointment in State Bank of India Lucknow for one month which he joined on 16th April, 1970 and a year later he was transferred to Branch Office Gosaiganj where he joined on 16th April, 1971. The workman was working continuously upto 31st January, 1975 but he was not made permanent though 1146 GI/84—13

he was working on permanent post of Driver. The applicant workman made demands to be made permanent and allowed benefits of a confirmed hand but his services were terminated on 1st February, 1975 without any notice or notice pay and compensation. He later learnt that his services were terminated because he wrongly gave his date of birth as 2nd January, 1949 instead of 20th January, 1939. On getting information he gave an affidavit that he gave his date of birth basing on his false memory because all the records of age were with his previous employer.

The workman has further averred that wrong giving of date of birth amounted to a misconduct and there should have been a proper enquiry and he should have been given a chance to defend himself.

The employer in their written statement averred that reference is belated and that he availed of civil remedy hence remedy under Industrial Act is barred. Accordingly to employer after workman's temporary appointment on 16th April, 1970 his services were terminated w.e.f. 14th December, 1971 as no longer required. The workman accepted the said termination and settled his accounts voluntarily without protest. It is further averred that his last appointment was made at Gosaiganj Branch on 16th December, 1971. At the time of regularisation of the services of workman it was revealed that he gave his date of birth & educational qualification wrongly. It was found that his correct date of birth was 2nd January, 1939 and that he had read upto Vth standard. It was on account of wrong declaration of age and educational qualification the management lost confidence in him and found him not fit to be retained in service. In the end it is averred that appointment being temporary his services could be terminated without notice or notice pay which he could have claimed in later proceedings.

Workman admitted that he got education upto 5th class and his date of birth was noted there. He further admitted that in military service and the service of Geology & Mining Department of U.P. Government was 1939 and not 1949. He denied the management's suggestion that he deliberately gave wrong date of birth with intention to serve longer duration in the bank and wrongly mentioned source of information as parents. He further admitted that on enquiry of the bank if he had served in the Geological Survey of India, he had replied in the negative but did not mention that instead of G.S.I. he had served in U.P. Government Geology & Mining Service. He however gave his correct date of birth later with explanation that in bank's record wrong date was mentioned on parents source of information. It is admitted by the workman that he gave application for correction of his age before 31st January, 1975.

I have heard the learned representatives of the parties at length and considered the law cited by them. From the admitted and proved facts it is clear that the workman would be deemed to have acquired status of a permanent employee having worked for about four years at Gosaiganj Branch even if his one year work at Lucknow Branch is not taken into consideration. The management realised its position and took steps to regularise the services of the workman but during the process of regularisation and finding out details of his previous services and date of birth education etc. it turned out that the date of birth given by the workman at the time of employment with the management bank was ten years more than what he had given out to the earlier two employers i.e. military and U.P. Service of Geologist & Mining and that he had declared himself as illiterate when he had read upto Vth class. The workman desired the management after termination of his services that he had wrongly given the date of birth as told to him by his parents and stuck to that stand even before this Tribunal. It is difficult to believe that a literate man having read upto Vth class would call himself illiterate. Further, if he gave out his age with the management at the behest of his parents, he should have got it corrected to bring it in consonance with the correct age recorded in his school certificate and till one given with his two employers. This having not been done it leads one to one & only one irresistible conclusion that the age ten years younger than the real one was given with the bank management was with intent to serve for ten years

more and thus it was a deliberate lie. Similarly the declaration given with the present management that he was an illiterate was a deliberate lie.

The next question that arises, is if giving false declaration about age and qualification was a misconduct and should have been enquired into giving a fair chance to the workman to contest and prove his innocence or his services could have been terminated after unilateral enquiry and by a discharge simplicitor.

Para 522(i) of the Shastri Award, services of a permanent employee may be terminated by 3 months notice or pay in lieu thereof. The workman representative referred me the ruling N. B. Shukla V/s. Bank of Baroda 1979 1 LLJ page 291, in which the ruling L. Michal V/s M/s. Johnsons Pump Ltd. AIR 1975 SC 661 and Sidhnath Krishanji V/s. Dadaji Dhakji 1977 Labour I.C. 602 were considered. In the instant case it is not only established but admitted that the date of birth given with two earlier employers was ten years more than what has been given in the bank and that he had read in school upto Vth class. Thus the workman guilt is established.

Every contract of employment implies trust and confidence as its indispensable ingredients. Loss of confidence plea can be confined not only to the employer holding confidential posts but also to others. The workman representative further cited Central Bank of India V/s State of Jammu & Kashmir wherein the crucial test laid down is the 'bona fide test'. In the instant case the management acted bona fide and set out to conform and regularise the workman but the workman landed in trouble consequent termination for loss of confidence on account of bona fide proof that he was literate and that he was ten years older than what held out by him with one and only one purpose to retire later.

In Bombay Municipality V/s. P. S. Malvenker 1978 II, LLJ 168 SC wherein it was observed "Now one thing must be borne in mind that there are two distinct and independent powers and as far as possible neither should be construed so as to evacuate the other or to render it ineffective. One is the power to punish an employee for misconduct while the other is the power to terminate simplicitor the service of an employee without any other adverse consequences."

Loss of confidence is a subjective feeling of individual reaction to an objective set of facts and motivations. The court can always examine whether such an action viz. discharging simplicitor is bona fide or not.

In the instant case in view of proved facts that workman had given but false his dates of birth and that he was illiterate the management had a reason for loss of confidence and acted bona fide in discharging the services of the workman.

I accordingly give my award in the affirmative i.e. the action of the management of State Bank of India Kanpur in terminating the services of workman, Hari Shanker with effect from 1st February, 1975 was justified.

The workman shall however have right to realise three months pay from the management in lieu of notice if not realised earlier.

The award is made in the terms aforesaid.

Further ordered that the requisite number of copies may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer
[No. L-12012/121/82-D.II(A)]

S.O. 4301.—In pursuance of section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India, Region-II, Nagpur and their workmen, which was received by the Central Government on the 16th November, 1984.

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY
CAMP : NAGPUR**

PRESENT :

Shri M. A. Deshpande, Presiding Officer.

Reference No. CGIT-2/18 of 1984

PARTIES :

Employers in relation to the management of State Bank of India, Nagpur.

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri G. G. Modak, Advocate.

For the Workmen—Shri S. P. Dharmadhikari, Advocate.

INDUSTRY : Banking

STATE : Maharashtra

Nagpur, dated the 19th October, 1984

AWARD

By their order No. L-12012/244/83-D.II(A) dated 2-7-1984 the following dispute has been referred for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, on the receipt of the failure of conciliation report :—

"Whether the action of the management of State Bank of India, Nagpur in relation to their Itwari Branch Nagpur in dismissing from service Shri A. S. Kulkarni, Cashier with effect from 7-4-1982 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

2. The order of dismissal passed on Shri Kulkarni, who was serving as a Cashier, from 7-4-1982, the question posing for determination is whether the said order is justified. The contention of the Union who is espousing the cause of Shri Kulkarni was perturbed on account of loss of such a big 22-1-1981 when the employee was serving at Itwari Branch of the State Bank of India, by the end of the day found a shortage of Rs. 10,000 at his counter and it is alleged to have been reported to the Branch Manager but since Shri Kulkarni was perturbed on account of loss of such a big sum and since he was engaged in checking and rechecking till 8.30 p.m., no further action was taken. On the next day however it is alleged that the Cashier expressed his suspicion of theft by one of his colleagues. The grievance of the Union is that through Shri Kulkarni had expressed his suspicion and although it was the duty of the Branch Manager immediately to move the Police no such action was taken and the Bank went on writing letters to the employee dated 22-1-1981, 23-1-1981 and 31-1-1981. On 18-2-1981 the employee was placed under suspension. The Union says that had the Bank taken prompt action of lodging complaint to the Police and had it been proved in police investigations that the shortage was result of theft, the Bank could have lodge insurance claim and recovered the money from the Insurance Company and could not have charged the employee of being negligent. Later on an enquiry was ordered and chargesheet dated 22-5-1981 was issued against Shri Kulkarni imputing three charges. It is stated that the charge of negligence was vague and it lacked material particulars and charge Nos. 2 and 3 are not charges at all and therefore the enquiry itself is vitiated from the inception.

3. On the basis of charge-sheet the enquiry was conducted by Shri R. V. Ghavade and Shri A. B. Sharma was the presenting officer on behalf of the Bank, who it is alleged displayed little knowledge of departmental enquiries. The Union complains that the enquiry was conducted contrary to the settled principles of natural justice, before examining any witnesses on behalf of the Bank, the statement of the delinquent employee was recorded and it is alleged that he was tricked into giving admission. It is further alleged that although copy of the report of the preliminary enquiry conducted by Shri N. R. Anegondikar and copy of the complaint to the Police submitted by the Branch Manager were called for during the enquiry on 15-7-1981 copies of these documents were never furnished thus denying opportunity to plead his case. The Union says that but for the procedure

adopted namely recording the statement of Shri Kulkarni before the Bank starting its case, he would have never given any admission and therefore no reliance can be placed thereon. Ultimately on receipt of the report of the Enquiry Officer order by dated 20-3-1982 the cashier was dismissed from service on the ground that the Bank lost confidence in him and in his integrity as an employee working in the Cash Department. When the appeal was preferred against the said order the appeal stood dismissed but with the variation of punishment from dismissal into that of discharge.

4. The case of the workman is that in similar circumstances the Bank never cashiered the Cashier but made arrangement to recoup the loss and this is the first time, according to the Union that an employee was sent home. It is further stated that Shri Kulkarni was ready and willing to repay the entire amount of Rs.10,000/- to the Bank and in fact on 2-11-1981 by pleading the ornaments he had made part payment of Rs. 3000 and that he is still ready and willing to repay the money.

5. By the written statement the Bank has refuted all these contentions and narrated the history as it is alleged to have occurred and has supported the findings of the Enquiry Officer and the order ultimately passed after the enquiry. Regarding the punishment it is alleged that it is open to the Bank to award punishment depending upon the facts of each case and no precedent can be cited by the delinquent employee. Regarding the infirmities during the enquiry the case of the Bank is that no prejudice thereby at any time was caused to the workman and therefore there cannot be any grievance against the same.

6. On the above pleadings the following issues arise for consideration and my findings thereon are :—

ISSUES	FINDINGS
1. Whether there were infirmities during the enquiry as alleged by the Union?	Yes
2. Did those infirmities materially prejudice the case of the workman?	No
3. If not have they any bearing on the facts in issue?	No
4. Was the finding of the Enquiry Officer perverse?	No
5. Whether the punishment awarded of dismissal/discharge harsh and disproportionate?	Yes
6. Whether the workman is entitled to any relief?	As per order

REASONS

7. Now the fact that on 22-1-1981 while Shri Kulkarni was serving as a Cashier at Itwari Branch, a loss of Rs. 10,000 from the cash handled by him stands admitted. Similarly, under the belief that some constituents might have made short payment of Rs. 10,000, although constituents were contacted, no such short payment was detected and therefore while Shri Kulkarni was in possession of the cash on that day, the money must have been removed from his custody. On that day he had received Rs. 1,99,581.14 while he could hand over to the Head Cashier only Rs. 1,89,581.14. Ex facie therefore there was negligence on the part of Shri Kulkarni. What is however urged on his behalf is that though he was complaining that theft had occurred the Bank never moved the Police immediately but considerably afterwards and that the attempt of the Cashier to lodge complaint by the Cashier directly failed because the Police authorities were unwilling to accept the same. When a cognizable offence was reported to the Police Officer concerned on 8-4-1981 a copy of which was submitted to the Police and other authorities, it is impossible to believe that the Police could have declined to register the offence and proceed in the matter insisting upon the complaint by the higher authorities. It is common knowledge that a criminal case by any person having knowledge in the matter can be lodged and since loss had occurred while the cash was being handled by the Cashier, he was the person concerned, who could have the first hand knowledge of the matter. The

grievance therefore that the Bank failed to register the complaint promptly carries no force. It seems that on 13-4-1981 Advocate notice was issued to the Regional Manager insisting upon lodging of complaint but instead of addressing such notice to the Bank, any reasonable person could have addressed it to the Police since despite complaint dated 8-4-1981 according to the Union the Police were reluctant to proceed in the matter.

8. About the actual enquiry the case of the Union is that Charge No. 1 is vague while charges 2 and 3 never amounted any misconduct at all. It is true that debiting the amount to protested bills Account which seems to be the normal practice cannot be an act of misconduct nor can it be a misconduct his failure to make good the deficiency despite letters calling upon him to do so. At best it may prove the inability of the workman to reimburse the money but his inability cannot be a misconduct. This was conceded by the Bank. Then remains the charge ' which says that Shri Kulkarni caused loss of Rs. 10,000 to the Bank by handling the money in a negligent manner and that he failed to make good the short-fall. As already observed the fact that loss of Rs. 10,000 occurred on that day is admitted. Shri Kulkarni has come out with the story that during his short absence from the cabin somebody removed the cash. Now the very fact that he is not charged with misappropriation and/or having committed theft himself but only charge is that act of negligence, shows that it is not the case of the Bank that the money was carried home by the Cashier. What is alleged is the lack of care normally to be taken by the Cashiers while handling cash. So the question is, that has been established or not and there is no substance in the contention that the charge is vague. It so happened that when the Enquiry commenced Shri Kulkarni was asked whether he accepts the charge after the same was read out to him whereupon his reply was that he accepts that there was shortage of Rs. 10,000 and further expressed suspicion about the theft. It is true that immediately the Presenting Officer representing the Bank could not have put questions but should have proceeded to record the evidence of his witnesses. In all probability because the charge was accepted the Presenting Officer certain facts no evidence was necessary and for elucidating he put certain questions to one of which the answer was "I had locked the Cash Drawers but not the cabin door". The grievance of the workman is that this was a procedure uncalled for and that grave injustice has been done by securing an admission from the delinquent. For the said purpose my attention has been drawn to the ruling in Hindusthan Steel Ltd. vs. Their workers reported in 1970 Lab. I.C. 102 (Orissa High Court) where relying on two Supreme Court Judgments reported in 1963 (II), 111 J, 355 and 1964 (I) 111 J, 634 it was held that examination of delinquent about the allegation against him before any evidence in support of the charge was recorded/rendered the enquiry unfair to the workman and could be ignored. In the instant case I have already pointed out that because the charge stood accepted followed by plea of theft the Presiding Officer put certain questions. It is pertinent to note that this had not invoked any protest neither from the employee nor from his representative. It is also no where pointed out as to how this admission was secured unjustly. He was put a question and he had answered it and the record shows that some such thing must have occurred otherwise the cash placed in the Drawer could not have disappeared. It is not anybody's case that the Drawer was closed and the locks were tampered with, or Branch Manager's attention was immediately drawn. It is therefore evident that while Shri Kulkarni was away might be during the lunch time somebody secured access to the cabin where the cash was lying and could part with the bundle of Rs. 10,000. In the light of these circumstances therefore Shri Kulkarni can never complain that he was trickled to give any admission, the said admission does not seem to be improperly obtained, and that since no prejudice was caused particularly when the charge stood accepted on this ground alone the enquiry cannot be said to be vitiated. It seems that when the loss was detected a preliminary enquiry was conducted by Shri N. R. Anegondikar, whose report is dated 2-2-1981 produced at Annexure M-3. This report though a copy was asked was not furnished and the grievance of the workman is that neither the report nor the copy of complaint to Police was also furnished. I have gone through the re-

port of Shri Anegondikar and I do not find anything there whereby non-supply of the copy could cause prejudice to the workman and the same could be said about the Police complaint. Therefore no capital can be made out by the Union for non-supply of these two documents.

9. Having regard to the fact that there was a loss, having regard to the fact that the workman could not find out any circumstances whereby he could have said that he had taken all precaution despite which the money disappeared, the conclusion that he was negligent was held proved and if the Enquiry Officer arrived at such a conclusion no fault can be found with the same. I therefore hold that despite infirmities pointed out no material prejudice was caused and therefore no reliance can be placed thereon. I further hold that in the light of the evidence and other factors already discussed the finding of the Enquiry Officer on charge No. 1 not only was not perverse but was reasonable and proper.

10. The only question then remains is whether the punishment awarded is harsh and disproportionate. It is true that initially there was an order of dismissal which in appeal was converted to discharge. It however seems that in the past in the instances quoted by the Union in Annexure 'A' to the Claim statement the re-action of the Bank was not rigid. The Bank had never disputed those facts. From the letter at Annexure 26 dated 21-12-1981 written by the Regional Manager to the employee it is evident that in case Shri Kulkarni was in a position to clear the liability within a short time the Bank was prepared to be lenient. It was because he was unable to do so the subsequent action followed. Considering therefore the other similar incidents and the action taken by the Bank therein and also considering that no dishonesty is imputed and the only charge is of negligence, at the same time considering the young age of the workman, I hold that the punishment of discharge is also disproportionate and acts harshly on him. If the loss is recouped and for the said purpose sufficient care is taken, I do not think that the extreme punishment of severance of relationship would be called for. Already Shri Kulkarni has deposited a sum Rs. 2000 leaving a balance of Rs. 7000. It is stated that the Bank owes some money to him but without going into the details thereof and without noting whether in fact any such liability is there or not which would be clear from the Bank's record, I think considering the circumstances and other factors particularly that in the past the record of the workman was clean, no order of discharge or dismissal need be passed. At the same time care will have to be taken that the Bank recouped the loss as early as possible and that the employee is suitably punished so that in future he does not commit such wrong. Shri Kulkarni is ordered to be reinstated in service without any back wages. He shall re-pay the balance amount which he owes to the Bank, after deducting any amount which may be payable by the Bank to the employees concerned, with 10 per cent interest from 22-1-81 till the recovery by instalments of Rs. 300 per month commencing from after one month from the date of reinstatement. His three increments shall be permanently stopped. After five years after watching the work of Shri Kulkarni, the Bank at their discretion may release those increments. Till the time full amount is recovered Shri Kulkarni shall not act as Cashier.

Award accordingly.

Dated : 25-10-1984.

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer
Central Govt. Industrial Tribunal.
No. 2, Pambav Camp, Nagpur.
[No. L-12012/244/83.D.II(A)]

S.O. 4302.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay in the Industrial Dispute between the employers in relation to the State Bank of India Nagpur and their workmen, which was received by the Central Government on the 16th November, 1984.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY.

PRESENT :

Shri M. A. Deshpande,—Presiding Officer

Reference No. CGIT-2/24 of 1984

PARTIES :

Employers in relation to the Management of State Bank of India, Nagpur.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employers.—Shri A. A. Khan, Officer-in-Charge Disciplinary Proceedings Cell.

For the Workmen.—Shri S. D. Phadke, President, State Bank of India and Subsidiary Banks' Employees' Union.

Industry : Banking

State : Maharashtra

Bombay, the 22nd October, 1984

AWARD

By their order No. L-12012/47/84-D.II(A) dated 27-7-1984 the following dispute has been referred for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.—

"Whether the action of the management of State Bank of India, Regional Office, Region-II, Nagpur in relation to the Kamptee Branch in terminating the services of Shri R. R. Patrale, Farrash-cum-Messenger with effect from 15-10-82 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

2. The facts giving rise to the present dispute shortly stated are that Shri Patrale who is the workman concerned was initially appointed as a Sweeper on 1-8-1978 on 1/3rd scale of wages since he was a part-time worker he was working for 1/3rd time only. From 1-9-1979 he was required to put in 19 hours per week on 1/2 scale of wages and then from 1-10-1981 the working hours were raised to 29 hours in a week and he was sanctioned 3/4th of the scale of wages. Thus he continued to work till 18-1-1982 when he was appointed as Farrash-cum-Messenger on probation for six months, which period was to end on 17-7-1982. Since his work is alleged to be not satisfactory, the period of probation was extended by three months. However the contention of the Bank is that no improvement was shown by the workman. He used to remain absent without leave or without asking for permission and the Memos. issued did not bring about any change in the conduct as a result of which by order dated 15-10-1982 the Regional Manager terminated his services in exercise of the powers conferred under paragraph 522(1) of the Sastry Award by treating him retrenched by paying compensation of Rs. 1172.40 and three months salary and allowance at the rate of Rs. 586.20 per month.

3. It is this termination which has been challenged by the Union by the claim Statement Ex. 3/W. It is alleged that the Bank never advised the workmen of his short-comings till 17-7-1982 on which day a Memo. was issued and therefore the termination was illegal and unwarranted and uncalled for. It is also alleged that the Branch Manager could not have brought about the termination and that no order of punishment could have been passed, even assuming that there occurred a misconduct.

4. By Ex. 2/M read with Ex. 5/M all these contentions have been refuted, the Banks authority to terminate the services has been asserted and the action is described to be legitimate.

5. At Ex. 4/W we find the Union's rejoinder to the Bank's written statement.

6. On the above pleadings the following issues arise for determination and my findings are:—

ISSUES

FINDINGS

1. What is the date of appointment whether 18-1-1982 or 1-8-1978 1-8-1978

- Whether the period from 1-8-1978 to 18-1-1982 should be counted in service? Yes
- 2A Whether an employee serving as part time Sweeper can subsequently be appointed as probationer while his service was still continuing? If not, what are its effect on order passed? Could be when continued in service. Change in Nature of service is effected when appointed full time
3. If not whether the workman, in view of the payment of retrenchment compensation and three months salary, can challenge the termination? Could have had it been mala fide.
4. Is the termination of the services of the workman illegal and ineffective? No
5. To what relief, if any, he is entitled? Nil
6. What award? As per order.

REASONS

7. The fact that from 1-8-1978 to 17-1-1982 Shri Patrale was working as a Part Time Sweeper initially on 1/3rd scale and then improved to 1/2 scale of wages and then raised to 3/4th scale of wages stands admitted. At that time he was serving as a Sweeper and from 1-8-1982 the record speaks he was appointed as Farrash-cum-Messenger when since it was to bring about change in the nature of service, he was appointed as a probationer for six months which period was extended further by three months but lastly on 15-10-1982 the services were terminated on payment of three months pay and retrenchment compensation considering the entire period from 1-8-1978 as contemplated under Section 25F of the Industrial Disputes Act. The Bank has rightly stated that although during the period from 1-8-1978 to 17-1-1982 he was working as part-time sweeper drawing salary far less than Rs. 586.20, which was the scale in which he was placed as Farrash-cum-Messenger, the entire calculations were made on the basis of last mentioned salary. The Bank has therefore acted generously and thereby considerable monetary advantage was received by the workman. However the question still is whether the Bank could have terminated the services. Under para. 522(1) of the Sastry Award the employment of a permanent employee may be terminated by three months' notice or on payment of three months' pay and allowances in lieu of notice. Here was a peculiar case of a sweeper, who was a confirmed sweeper having served from 1-8-1978, while from 18-1-1982 he was a probationer as Farrash-cum-Messenger. However, when he was a confirmed employee the provisions accordingly were applicable otherwise had the Bank invoked the provisions of latter part of Para. 522(1) and para. 522(4) the services of probationer could have ended and not of a confirmed employees. In that case the workman would have continued to be in service if not as Farrash-cum-Messenger atleast as a sweeper. Having invoked para. 522(1) of Sastry Award this pit-fall has been avoided.

8. The record speaks that even while serving as a Sweeper the workman used to remain absent without obtaining leave or permission. During the earlier period he remained absent for 51 days and even while serving as probationer his habit had not been giving up. The various Memos, from Ex. 7/M to 20/M would reveal that the workman used to remain absent and his period of absence used to be treated without pay after deducting the eligible period and that the Branch Manager found him to be unfit to be confirmed in the Bank's service. Even whether serving as a Sweeper or Farrash-cum-Messenger there were frequent absences and the workman was of no material use to the Bank and when it was found that repeated memos, did not bring about the improvement what is contended by the Bank that they had no other go but terminate the services of the workman carries all the force. Subsequent repentance by Ex. 26/M was of no use. The Bank having decided to terminate the services, the Regional Manager, who was the competent authority issued the order, which was communicated by the Branch Manager. It is not therefore as tried to be represented that the action was

taken by the Branch Manager, as seen from Ex. 30/M dated 12-10-1982, it originated from the Regional Manager and what was left to the Branch Manager was the act of communication.

9. As already stated, the award conferred a right on the Bank to terminate the services of permanent workmen. Now because as Section 2(oo) stands it amounted to retrenchment Section 25F of the Industrial Disputes Act was also attracted and the Bank not only paid three months wages as contemplated under para. 522(1) of the Sastry Award but also complied with the provisions of Section 25F of the Industrial Disputes Act and in this manner followed the procedure laid down by both. When the workman was frequently remaining absent without permission, when repeated chances given to him proved futile and the cautions fell on deaf ears, the Bank had to take action severing the relationship. No doubt that frequent absence was the root cause of falling the axe but it does not mean that it was a punitive action and therefore the plea that without enquiry for misconduct no action could have been taken is no longer available. The Bank decided to bring about a simple termination and the proof of the past history justifies the action, and it is not a defective one.

10. Considering the case therefore from all facets I am convinced that the action is perfectly legitimate, effected legitimately and severed legally the relationship and therefore no relief is permissible.

Award accordingly.

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer
Central Govt. Industrial Tribunal
No. 2, Bombay.
[No. L-12012/47/84-D.II(A)]

S.O. 4303.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India Region-II, Nagpur, and their workmen, which was received by the Central Government on the 16th November, 1984.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2

BOMBAY
CAMP : NAGPUR

PRESENT

Shri M. A. Deshpande, Presiding Officer.
Reference No. CGIT-2/23 of 1984

PARTIES

Employers in relation on to the Management of State Bank of India, Nagpur

AND

Their Workmen

APPEARANCES

For the Employers —Shri G.G.Modak, Advocate
For the Workmen—Shri S. P. Dharmadhikari, Advocate.

INDUSTRY : Banking STATE : Maharashtra
Nagpur, dated the 19th October, 1984

AWARD

By their order No. L-12012/41/84-D.II A dated 27-7-1984 the following dispute has been referred for adjudication under Section 10(1) (d) of the Industrial Disputes Act, 1947 :—

"Whether the action of the management of State Bank of India, Nagpur in terminating the services of Shri M. B. Pawar, Messenger-cum-watchman w. e. f. 29-6-1983 of their Pulgaon Branch is legal and

justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

2. In the statement of claim filed on behalf of the workman the Union contends that Shri Pawar has put in 758 days within a period of two years eight months and 11 days before the date of termination dated 29-6-1983 and that although similarly placed employees were absorbed in service. Shri Pawar was asked to go home that too without following the procedure laid down under Section 25F of the Industrial Disputes Act which renders the action illegal and therefore he must be reinstated in service.

3. By the written Statement the Bank admitted that Shri Pawar was employed as a Badli Watchman from 19-10-1980 at Pulgaon Branch by the Branch Manager and also admitted that he had put in more than 240 days service during the year prior to the date of termination and it is also admitted that the procedure prescribed under Section 25F of the Act has not been complied with. It is contended that subsequently it transpired that though the age limit for appointment as a sub-staff was 18 to 24 years Shri Pawar was over-aged, his birth date being 12-10-149 i. e. at the time of initial appointment having crossed 30 years of age. It is further stated that although a person who has passed matriculation could not have been appointed under the rules of the Bank to the post of member of sub-staff, this information was suppressed, Shri Pawar never revealed that he passed matriculation, but represented that he passed 7th Standard and therefore for this misconduct he should not be reinstated.

4. On the above pleading the following issues arise for determination and my findings are:—

ISSUES	FINDINGS
1. Does the Bank prove that the workman suppressed his having passed the matriculation examination at the time of securing the service?	Yes
2. Does this amount to misconduct?	Yes.
3. Whether the workman could not have been appointed to the post of Messenger-cum-Watchman?	Could not have
3. If the misconduct is proved whether the workman is entitled to any relief on the ground of completion of 240 days before termination?	No

REASONS

5. The Bank has cited Shri A. S. Pande, the then Branch Manager at Pulgaon who had appointed Shri Pawar and also Shri A. E. Kulkarni, Officer-in-Charge Staff Cell, Region-III, Nagpur as witnesses. The contention of Shri Pande is that he made enquiries with the employee when he was given to understand that he passed 7th Standard and because of this representation he came to be employed. Shri Pawar however, when examined denied to have stated so. Now when the Hand-book of the Bank, the extract of which has been furnished on record speaks of educational qualification 8th Standard and not matriculation, I cannot believe Shri Pande would not have made enquiries in this regard. There was absolutely no reason for him to act prejudicially to the interest of the employee and therefore the case of the Bank that there was enquiry and mis-representation seems to be correct.

6. But assuming that there was no such mis-representation at the relevant time, the record speaks that when there was a move for condonation of the over-age Shri Pawar was asked to furnish the proof of educational qualification to which he replied on 2-3-1984 annexure M-2. He furnished School Leaving Certificate of 7th Standard passed although long before that he passed the S.S.C. Examination annexure M-1. When he wanted to furnish the information regarding his educational qualification and not about his age normally he should have produced the S.S.C. certificate but might be because being conscious of the rules of the Bank whereby

no matriculate could have been appointed to the post of sub-staff he forwarded the earlier certificate. In my view this conduct on the part of the workman, disentitles him to the relief of reinstatement, which it is the well settled principle, normally follows when Section 25F stands violated. I therefore hold that on account of mis-representation from the inception and further on the ground that even subsequently when occasion arose for condonation he tried to suppress the real fact in order to secure employment, no relief of reinstatement is passed and that in the first place in the light of these circumstances and in the light of definition of Section 2(oo) of the Industrial Disputes Act it would not be re-trenchment invoking the provisions of Section 25F of the Act and secondly even if it is attracted still no relief of reinstatement would be possible.

Award accordingly.

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer
Central Govt. Industrial Tribunal
No.2, Bombay
Camp: Nagpur
[No. L-12012/4/84-D.II(A)]

S.O. 4304.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal New Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the Reserve Bank of India, Jaipur Branch and their workmen which was received by the Central Government on the 17th November, 1984.

BEFORE SHRI O. P. SINGLA : PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL,
NEW DELHI

I. D. No. 67/79

In the matter of dispute between :

Shri B. L. Meena represented by the Reserve Bank
'Employees' Association, Jaipur

Versus

Reserve Bank of India, Jaipur.

APPEARANCES :

Shri K. T. Anantharaman Adv. for the workman.

Shri V. G. Hegde Principal Legal Advisor for the
Management.

AWARD

Central Government, Ministry of Labour on 15th December, 1979 vide Order No. L-12012/93/79-D.II(A) made reference of the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of the Reserve Bank of India in relation to its Jaipur Branch in terminating the services of Shri B. L. Meena, Clerk with effect from 24-6-76 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

2. Shri B. L. Meena was engaged as a clerk-cum-coin-note examiner Grade II in Reserve Bank of India from January, 75. His services were terminated by Office order No. 13485/M12(7)/75-76 dated 24-6-76, issued by the Local Manager, by order of discharge simpliciter.

3. It is stated in the claim-statement that, by virtue of Administration Circular No. 13 dated 24th June, 1976, Regulations 46 and 47 of Chapter IV had been made applicable in the case of temporary employees who had a service of less than two years, but the workman was denied the advantage of those regulations and his services were terminated, in fact, as a matter of punishment without any enquiry or opportunity to show cause.

4. It was pleaded by the workman that his services were terminated in contravention of principles of natural justice and in violation of Iyer-Award, and the alleged involuntary confession obtained from him was dictated by the Staff Officer, and was not taken in presence of any Trade Union Representative, as envisaged under the Iyer Award.

5. It was further pleaded that his termination was engineered with malice by high-caste persons, because he belonged to scheduled tribes and that he was active member of the Employees' Association.

6. It is also pleaded that his termination violated section 25-F of the I.D. Act, 1947 and its requirements were not complied with. Even if the action was taken on the basis of so called admission letter, that letter was not explained to him and the said admission was not recorded in the course of any enquiry.

7. The Management of Reserve Bank of India contested the claim and asserted that Mr. Meena's services were terminated in accordance with the conditions of service applicable to him, and bona fide.

8. Circumstances leading to termination of services were detailed by the Management and it was explained that the circular extending regulations 46 and 47 of the Banks Staff Regulations to temporary employees having less than two years of service was received in the Jaipur office only on 9th July, 76 and, when the services were terminated, these regulations did not apply to him, and his services were terminated in accordance with his contract of employment.

9. The Management sought leave to justify the termination of service before the Tribunal, if there be any infirmity in the termination of services, made.

10. The matter in issue has been tried and, subject to the right of the workman to urge that Enquiry cannot be had before this tribunal, the evidence of the Management has been recorded in respect of the circumstances in which his services were terminated and Shri P. Srivastav Clerk, Grade I R.B.I. Jaipur and Madan Lal Sharma A.T. retired R.B.I. Jaipur as also N. K. Aggarwal Assistant Head Cashier State Bank of Bikaner and Jaipur have been examined by the Management. The workman did not appear in the witness box.

11. Detailed arguments of the parties have been heard and their written submissions taken on record.

12. The workman's point of view is that his services were terminated by an order of discharge, and there was non-compliance with section 25-F of the I.D. Act, 1947 and he was entitled to reinstatement in service with full back-wages. He repeatedly emphasized that the Management did not take disciplinary action against him under the regulations and the action was taken only under the contractual provision in the order of appointment, which was subject to the over-riding law contained in section 25-F of the I.D. Act, 1947, and the action taken by the Management was void ab initio for non-compliance with applicable section 25-F of the I.D. Act, 1947.

13. It is further urged for the workman that the Tribunal cannot award compensation in lieu of reinstatement on the alleged ground of the Management losing confidence in the workman or on account of the respondent institution being a Reserve Bank. These facts were said to be not covered among those grounds, which the Supreme Court had allowed for allowing compensation in lieu of reinstatement. When the Management held no enquiry whatsoever, it was said to be proof of Management colourable exercise of power.

14. On facts, it is submitted that the Management's argument of bad note being substituted for a good note was incorrect, because the note was a good one, and could have been changed into one-piece note by the Reserve Bank.

15. In respect of the Management's plea that the workman admitted his guilt before two officers, the workman asserts that there was no representative of the trade union then, and that he did not admit his guilt in fact, and that he was virtually forced into making the confession by the bank officers.

16. It is vehemently argued by the workman's Advocate that the Management also had raised the plea again and again that the action was not a disciplinary action, and therefore, no evidence could be led before this Tribunal to justify the action as a disciplinary action, and the necessary consequences of non-compliance with statutory provisions of section 25-F, I.D. Act, 1947 must follow in this case.

17. The present is a peculiar case in which the workman in his statement of claim himself asserted that the action

against him was a punitive action, disguised as a simple order of discharge; alternatively he urged that he could not be discharged from services without compliance of section 25-F of the I.D. Act, 1947.

18. The Management, on its part, in the written statement pleaded that the action was not a disciplinary action, and was action by way of discharge in accordance with contract of employment, but full circumstances leading to the action of discharge were given, and request was made for leading evidence to prove that the workman's termination of service was legal, proper and bona fide.

19. Under the circumstances, it seems that the Management's legal adviser is correct when he states that the court must examine the pleas of the parties as a whole, and determine whether it is a case of estoppel against the Management, or otherwise.

20. When facts are known to both parties, there is no estoppel and, in this particular case, the workman, as well as the Management, both knew why the services of the workman were terminated, and a case of estoppel against the management cannot arise.

21. The bona fides of the Management cannot be doubted, because the circular extending regulations 46 and 47 of Staff Regulation to Employees with less than two years of service were received in Jaipur office only on 9th July, 76, as proved by the Management, and it cannot be said that the Management acted otherwise than bona fide.

22. The action of the Management appears to be just and proper, and the Management has duly proved before this Tribunal the fact of the workman contravening issue department manual by carrying his own cash at the place where bank of Bikaner and Jaipur cash was being counted, and he did show lack of integrity by attempting to put his own note and remove the note of the bank of Bikaner and Jaipur, which facts clearly being the Reserve Bank into disrepute, and lower its image in the eyes of its constituents and general public.

23. The confession made by the workman before the bank officers does not seem to be otherwise than voluntary.

24. It is accepted that the service of Shri B. L. Meena were, in fact, terminated on account of specific misconduct committed by him on 24-6-76 and admitted by him before the two officers of the bank, and the infirmity that the statement was not made before any trade union representative has been cured by the Reserve Bank by leading evidence before this Tribunal to affirm that the workman was guilty as aforesaid, and the confession made by him was neither involuntary nor under coercion.

25. Under the circumstances aforesaid, I am of the clear opinion that action taken against the workman was justified and legal, and disciplinary action did not follow simply because the change in regulations dated 24-6-76 had come to the Jaipur Reserve Bank of India Management notice on 9-7-76 only, and that the action taken against the workman was not an action of mere discharge, but was an action of removal from service, for specific misconduct admitted by the workman before the bank officers voluntarily and clearly proved before this Tribunal in the evidence led by the Management.

26. It is not possible to treat this case as a case of violation of section 25-F of the I.D. Act 1947 and the action by the Management is clearly by way of removal of an employee for specific misconduct, admitted by him voluntarily in these terms :—

"English translation of the statement of Shri B. L. Meena, Clerk, Gr. II/Coim-Note Examiner Grade III(T).

I was given notes, of the SBBJ Sujangarh in the post lunch quota of work today the 24th June 1976. Of these notes, I was given 2000 notes of Rs. 5/- denomination I had with me a personal five rupee note, bearing No. T/16-849169 which was torn into two pieces and was defective. I exchanged this note with a note of the chest. While I was exchanging the note, the representative reported the matter to the Assistant Treasurer. I admit my mistake and beg to be pardoned. I further assure that I will not make similar mistake in future.

This statement has been recorded by me in the presence of Manager and Assistant Currency Officer of my own free Will.

Sd/- B. L. Meena

Coin-Note Examiner Gr. II

N. ES—I

Dated : 24-6-1976

27. Disciplinary proceedings were not started bona fide in the belief that regulations 46 and 47 did not apply to this workman who had less than two years of service to his credit.

28. The removal of B. L. Meena workman from service by the Management does not call for any interference and the action by the Management cannot be said to be otherwise than justified. Award is made accordingly.

O. P. SINGLA, Presiding Officer

Central Government Industrial Tribunal, New Delhi

November 9, 1984

Further it is ordered that the requisite number of copies of this Award may be forwarded to the Central Govt. for necessary action at their end.

O. P. SINGLA, Presiding Officer

Central Govt. Industrial Tribunal, New Delhi

November 9, 1984

[No. L-12012/93/79-D II(A)]

N. K. VERMA, Desk Officer

New Delhi, the 19th November, 1984

S.O. 4305.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur in the industrial dispute between the employers in relation to the Punjab National Bank, Lucknow and their workmen, which was received by the Central Government on the 14th November, 1984.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, KANPUR

I. D. No. 179/84

In the matter of dispute between :

The Vice President,
Punjab National Bank Employees Union,
295/387, Deendayal Road,
Ashrafabad, Lucknow.

AND

The Regional Manager,
Punjab National Bank,
Hazratganj,
Lucknow.

PRESENT :

Sri O. P. Nigam—for the workman.

Sri V. P. Gupta—for the management.

AWARD

The Central Government vide its Order No. L-12012/93/81-D.II (A) dated 2-12-1981 has referred the following industrial dispute for adjudication :—

"Whether the action of the management of Punjab National Bank, Lucknow in not giving Sri Ram Lal Sharma the post of peon-cum-Bill Collector is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

It is common ground that workman Sri Ram Lal Sharma was working as Peon-cum-Armed Guard in one of its branches at Lucknow. As a post of Bill Collector had fallen vacant at Branch Office Rakabganj, Lucknow the workman applied for the same, but his request was turned down on the ground that the policy of the Head Office was that employees carrying the same amount of allowance, their designation will not be changed then shall not be given duties of that post. Thus

armed guards and Bill Collectors both of which carry Rs. 34 as special pay were not to be interchanged. Consequently Regional Manager, Lucknow gave the post of Bill Collector to a junior hand in the branch.

Similar vacancy as one in Lucknow occurred in Fatawa and there are substantial Armed Guard to be posed as Bill Collector and the Regional Manager rejected the same on the ground of the above said policy of the Bank i.e. no change of post when both carry equal allowance of Rs. 34. On protest of the union the Regional Manager, Agra recalled his previous orders given in consequence with Banks Policy allowed Sukh Bari Lal Armed Guard to be posted as Bill Collector, reverting the person working on that post. This action of the management, it is averred is illegal, unjust under present facts and violation of their own policy.

The management in their written statement took the plea that the case of workman Ram Lal Sharma for posting as Bill Collector could not be considered by the bank as he did not have sufficient knowledge for the job of Bill Collector as he was mainly performing the duties of a guard. The management has admitted that request of Sukhbhari Lal guard was first rejected but later accepted because of his seniority and job knowledge.

It is argued that had there been no partiality in the case of Sukhbhari Lal the dispute of Sharma would not have arisen.

Management did not given any oral evidence and simply cross examined the workman witness and stated that management has a right to see working knowledge at the time of officiation and posting.

The management failed to draw out any distinction by adducing evidence that Sukhbhari Lal had working knowledge or was otherwise efficient. Both workmen Sri Sukhbhari Lal and Ram Lal Sharma were working as Armed Guard, both applied to be posted as Peon-cum-Bill Collector, the request of workman was turned down as against Banks policy, but the request of Sukhbhari Lal though first turned down on similar grounds in case of workman was subsequently allowed. There being no proof that Sukhbhari Lal was considered being efficient or having job knowledge the action of the management was highly discriminatory unjust and unfair and shows that it is followed in its breach.

I accordingly give my award that the action of the management of Punjab National Bank, Lucknow in not giving Sri Ram Lal Sharma, post of Peon-cum-Bill Collector was unjustified. He should be given that post forthwith and not from back date as it done not carry burden of extra emoluments.

The award is made in the terms aforesaid.

October , 1984.

Further ordered that the requisite number of copies may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

Dated : October , 1984.

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

[No. L-12012/93/83-D.III(A)/D.IV (A)]

New Delhi the 24th November, 1984

S.O. 4306.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Madras in the industrial dispute between the employers in relation to the Grindlays Bank p.l.c., Cochin and their workmen, which was received by the Central Government on the 14th November, 1984.

BEFORE THIRU K. B. GURUMURTHY, B.A., B.L.
PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL,
TAMIL NADU, MADRAS

(Constituted by the Central Government)

Thursday, the 25th day of October, 1984

Industrial Dispute No. 49 of 1984

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between

the workmen and the Management of Grindlays Bank p.l.c. Wellington Island, Cochin-682003.)

BETWEEN

The workmen represented by The Secretary, Grindlays Bank Employees' Union, Bristow Road, Cochin-682003.

AND

The Manager, Grindlays Bank p.l.c. Wellington Island, Cochin-682003.

REFERENCE:

Order No. L-12011/12/83-D.IV(A), Ministry of Labour and Rehabilitation, Department of Labour, dated 31-5-84 Government of India, New Delhi.

This dispute coming on this day for final hearing upon perusing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Thiru N. P. Pai, President of the Union appearing for the workmen and of Thiru C. Krishnamurthi, Manager Industrial Relations, Authorised Representative appearing for the Management, this Tribunal made the following

AWARD

The Government of India by its order No. L-12011/12/83-D.IV(A), dated 31-5-1984, Ministry of Labour and Rehabilitation has referred the following dispute under Section 7-A and Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication by this Tribunal.

(2) The dispute is:

"Whether the action of the management of Grindlays Bank p.l.c. Cochin in relation to their Wellington Island Branch, Cochin in asking Shri P. G. Jacob Head Clerk for examination of cheques in excess of Rs. 10,000 under the Ultra Violet Lamp is justified? If not to what relief is the workman concerned entitled?"

(3) On receipt of notice from this Tribunal, the Union and the Management have filed claim statement and counter statement respectively.

(4) In the claim statement, the Union has raised the following grounds in support of its claim: The terms and conditions of service of the various employees of the banking companies are governed by the Sastri Award which was subsequently modified and altered by the Settlements between the Management and the Union. The three settlements which came into existence were called the First Bipartite Settlement, Second Bipartite Settlement and the Third Bipartite Settlement. The Union has raised the issue which is covered by the dispute. Chapter VII Part I in Section II(i) of the First Bipartite Settlement regarding non-subordinate staff stipulated certain duties and payment of Special Allowance the Head Clerks for performing all or any of the duties mentioned therein. The approach of the Bank that the Head Clerk must examine cheques in excess of Rs. 10,000 under the Ultra Violet Lamp is unreasonable and unjustified. The action of the Management of Grindlays Bank p.l.c., Cochin should be declared to be not justified.

(5) The Management in its counter statement has stated that its action in asking Thiru P. G. Jacob, Head Clerk, to examine cheques in excess of Rs. 10,000 under Hanovia Lamp is justified, because the Management is entitled to install Hanovia Lamp for the purpose of checking material alterations in the cheques so as to save itself from fraudulent losses. The Bank is entitled to introduce such Hanovia Lamp at its convenience to safeguard its interests. Ordinarily, even a clerk who receives cheques across the paying counter has the duty to see whether the cheques, ex facie, are proper and are in order. He has to check the date, the amount and the signature in the instrument to find out if they are properly filled and whether the cheques are otherwise in order. If there is any alteration, it is his duty to report the matter to the Management and return the cheques to the presenter. The Head Clerk is primarily in the clerical

cadre. The cheques that come to the Head Clerk should be examined by him thoroughly and if alternations are found, the Head Clerk would have to report the same to the Management and that is part of his normal duties. It is for aiding the Head Clerk in his work of detecting such chemical alternations (which cannot be detected by the naked eye) that the Management introduced the Hanovia Lamp. Therefore Thiru P. G. Jacob, the Head Clerk is duty bound to examine the cheques under the Hanovia Lamp as instructed by the Management. The 'examination' of a cheque is different from 'passing' a cheque. The examination merely requires a detailed inspection of the cheque while passing of the cheque indicates passing for payment. What Thiru Jacob was asked to do was only to examine the cheques over Rs. 10,000 and not to pass them for payment. The explanation of Thiru P. G. Jacob that continuous examination of cheques under the Hanovia Lamp may cause injury to his eyes is not tenable. Only a few cheques need be put under the Hanovia Lamp. There are enough safe-guards in the machine itself to protect the health and well being of the employee who uses this Hanovia Lamp. Therefore the claim of the Union is not justified and the Union is not entitled to any relief.

(6) M.W. 1 and W.W. 1 were examined Exs. M-1, M-2 and M-3 series to M-5 series were marked. I have heard the authorised representative appearing for the Management and the authorised representative appearing for the Union.

(7) The point for consideration is whether the assignment of this work of scrutinising the cheques over Rs. 10,000 under Ultra Violet Lamp to the Head Clerk Thiru P. G. Jacob of the Cochin Branch is justified.

(8) In order to ask a particular staff member to do a particular job, the obligation should be couched either in the order of appointment or in the terms and conditions of service. In this case, the order of appointment is not placed before this Tribunal. However the parties agreed that some of the service conditions of the staff members are covered by the Bipartite Settlements. It becomes necessary to scrutinise those Bipartite Settlements to find out whether the duties of the Head Clerk will cover this scrutiny of cheques to the value of Rs. 10,000 under the Ultra Violet Lamp. The representative of the Management drew my attention to Chapter V of the Bipartite Agreement which indicate that the Special Allowances prescribed are paid to compensate a workman for performance or discharge of certain additional duties and functions requiring greater skill or responsibility. This Chapter V contains paragraph 5.7 suggesting that the additional duties and functions involving greater skill or responsibility, which would entitle a workman to a special allowance, are more particularly enumerated, for a category of workmen, in Appendix 'B'. Therefore in this Chapter V, the representative of the Management is not able to refer to any paragraph which would assign the task of scrutinising the cheques over Rs. 10,000 under this Ultra Violet Lamp to the Head Clerk. Now referring to Appendix-3, one would find that the duties of the Head Clerks are enumerated therein. The first paragraph states that passing independently cash, clearing and transfer cheques, vouchers, etc. upto and including Rs. 1,000 is the duty of the Head Clerk. The same paragraph indicates that passing will include verification of signature and scrutiny as to the correctness of endorsements on and other particulars such instruments. Therefore this deals only with passing of cheques by the Head Clerks upto Rs. 1,000. There is no mention that the Head Clerk will have to subject Rs. 10,000 cheques to the examination under Ultra Violet Lamp. There is no mention in this Chapter assigning the special duties of the Head Clerk that the scrutiny of cheques over Rs. 10,000 under the Ultra Violet Lamp will be part of his job.

(9) The learned representative of the Management attempted to rest his argument in support of the Management's stand on the basis of the evidence. M.W. 1 in his evidence has stated that normally when the cheque is tendered across the cash counter, the Clerk who receives the cheques should examine the cheque as to the correctness of the date, the amount in words and figures, the signature of the drawer and should make entry in the ledger. He has also stated

that the cheques received through clearing are checked by other persons. That would suggest that the Clerks concerned are not checking the cheques received through clearing. They merely make postings in the ledger cheques received through clearing. From this particular evidence, the learned representative of the Management would urge that the Head Clerk being primarily a clerk is bound to scrutinise all the cheques received across the cash counter. It is only a sophisticated method that he is asked to adopt by using the Ultra Violet Lamp in the performance of his duties of checking, the correctness of the dates, the amount in words and figures and the signature of drawer before making entry in the ledger, I am afraid that this approach of the learned authorised representative of the Management is not convincing. The scrutiny of a cheque with reference to the correctness of the dates, the amount in words and figures and the signature of the drawer with the naked eyes will not be equivalent to the scrutiny of the cheques with the help of the special contrivance, namely 2, Ultra Violet Lamp. It is because some of the hidden fraudulent intercalations or alterations will not be visible when inspected with the naked eyes that this Ultra Violet Lamp is being used. This is made clear by Ex. W-1 under which the General Manager's Office has given the instructions. That Ex. M-1 states that in view of the growing number of incidents of frauds and forgeries in Banking Industry, the requirement of use of Hanovia Lamp has come to stay. Therefore from this evidence that the duty of the clerk who receives the cheque across the cash counter is to check the figures, the signature and the date of the cheque, it cannot be contended that the checking would include the checking of the cheques by the use of Ultra Violet Lamp.

(10) That apart this M.W. 1 had shown himself to be unsteady. He would admit that in the Madras Main Office there is a Head Clerk. He would admit that there are two Special Assistants. He would admit that cheques upto Rs. 5,000 were put under the Ultra Violet Lamp by the Special Assistants at Cochin Branch. He cannot deny that cheques upto Rs. 5,000 had never been checked under the Ultra Violet Lamp by the Head Clerk of the Cochin Branch. He is very nebulous by admitting that he will not be able to say that Special Assistants also did not examine the cheques under the Ultra Violet Lamp. It is significant that in Cochin Branch there are Special Assistants in the Current Account Section. He admitted that clerks are not checking the cheques under the Ultra Violet Lamp. In the light of these admissions, which completely undermine the stand of the Management that the scrutiny of the cheques under the Ultra Violet Lamp is part of the routine job of the clerk, it is impossible to accept the stand of the learned representative of the Management that the Head Clerk is in duty bound to scrutinise the cheques under the Ultra Violet Lamp.

(11) W.W. 1 in his evidence stated that in the Madras Main Branch of this Bank he had worked as Special Assistant till June, 1984 and he had examined cheques under the Ultra Violet Lamp. There is a Head Clerk in this Main Branch. He is not examining any cheque under the Ultra Violet Lamp. At no time according to W.W. 1 Head Clerk of the Main Branch was asked to examine cheques under the Ultra Violet Lamp. Therefore in branches where there are Head Clerks and Special Assistants according to the evidence, Special Assistants scrutinise the cheques under the Ultra Violet Lamp and the Head Clerks are not asked to do it. In the Cochin Branch, where there are Special Assistants in Current Account Section, these Special Assistants are not assigned this work of scrutinising cheques under the Ultra Violet Lamp, but the Head Clerk had been asked to do it. Therefore, there is no uniformity in the matter of assignment of this work of scrutinising the cheques with the help of this Ultra Violet Lamp in the various branches of this Grindlays Bank. It only shows an arbitrary assignments of the job to Head Clerk at Cochin Branch. In my view, the duty of scrutinising the cheques received across the counter with the naked eyes will not include the scrutiny of the same with the help of the special contrivance namely, Ultra Violet Lamp. Therefore the argument of the authorised representative of the Management that this scrutiny of the cheques under the Ultra Violet Lamp will fall within the

ordinary routine function of the Head Clerk has got to be negated and it is repelled.

(12) For these reasons, I have no hesitations to conclude that the direction of the Assistant Manager under Ex. M-2 to the Head Clerk Thiru P. G. Jacob of the Cochin Branch of this Grindlays Bank that he should examine all cheques in excess of Rs. 10,000 received from clearing under the Ultra Violet Lamp installed at the branch office is not in accordance with the prescribed duties of the Head Clerk. That assignment given to the Head Clerk under Ex. M-2 is unjustified.

(13) There will be an award in the above lines in favour of the Union. There will be no order as to costs.
Dated, this 25th day of October, 1984.

Sd/- K. S. GURUMURTHY, Industrial Tribunal

WITNESS EXAMINED

For workmen

W.W. 1—Thiru R. Sadasivam.

For Management

M.W. 1—Thiru K. P. Ananthanarayanan.

EXHIBITS MARKED

For workmen : Nil.

For Management :

M-1/30-12-83—Letter from the General Manager to all Branches in Southern India.

M-2/22-6-82—Copy of letter from the Management to Thiru P. G. Jacob, Petitioner.

M-3 series—Cheques leaves passed by the Nungambakkam Branch of the Management Bank.

M-4 series—Cheque leaves passed by the Nungambakkam Branch.

M-5 series—Cheque leaves passed by the Madras Main Branch (Madras-1) of the Management—Bank.

Sd/- K. S. GURUMURTHY,

Industrial Tribunal

[No. L-12011/12/83-D.IV-A]

K. J. DYVA, Desk Officer

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1984

का. आ. 4307.—केन्द्रीय सरकार, ठेकाधर्म (नियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 10 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् इससे उपाख्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट संकेतों में जैसे देश के क्रोमाइट, मैगनेसाइट, जिप्सम और भस्मक बालों में ठेका शक्तियों के नियोजन का तात्कालिक प्रभाव से निपेश करती है।

अनुसूची

1. क्रोमाइट खान

- (1) ऊपरि भारतवर्ष उत्खनन और उसे हटाना;
- (2) वेधन और स्फोटन;
- (3) अयस्क निकालन; और
- (4) ऊपरिभार का डम्प तक और अयस्क का स्टैकिंग स्थल तक का परिवहन।

2. मैगनेसाइट खान

- (1) ऊपरिभार हटाना,
- (2) वेधन और स्फोटन; और
- (3) खनिज निकालना।

3. जिप्सम खान

- (1) ऊपरिभार हटाना; और
- (2) खनिज का खनन करना और निकालना।

4. अन्नक बान

- (1) अन्नक निकालना;
- (2) वेधन और स्फोटन;
- (3) बानों का जलरहित करना;
- (4) कार्यवाही कदम हटाना; और
- (5) अन्नक का प्रसंस्करण।

[सं. एस. 16025/22/84-एस. डब्ल्यू.]

पी. बी. महेशी, उप सचिव

New Delhi, the 20th November, 1984

S.O. 4307.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), the Central Government, after consultation with the Central Board, hereby prohibits the employment of contract labour in the works specified in the Schedule annexed hereto, in the Chromite, Magnesite, Gypsum and Mica Mines in the country, with immediate effect.

THE SCHEDULE

1. CHROME MINES

- (i) Over burden excavation and removal;
- (ii) Drilling and Blasting;
- (iii) Raising of Ore; and
- (iv) Transportation of over-burden to dumps and Ore to stocking sites.

2. MAGNESITE MINES

- (i) Over burden removal;
- (ii) Drilling and Blasting; and
- (iii) Raising of Minerals.

3. GYPSUM MINES

- (i) Over burden removal; and
- (ii) Mining/raising of Mineral.

4. MICA MINES

- (i) Raising of Mica;
- (ii) Drilling and Blasting;
- (iii) Dewatering of mines;
- (iv) Muck removal; and
- (v) Processing of mica.

[No. S-16025/22/84-LW]

P. B. MAHISHI, Dy. Secy.

S.O. 4308.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Cantonment Board Ambala and their workmen, which was received by the Central Government on the 8th November, 1984.

BEFORE SHRI I. P. VASISTH, PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL,
CHANDIGARH.

Case No. 139 of 1983 (N. Delhi); 55 of 1983 CHD

PARTIES :

Employers in relation to the management of Cantonment Board Ambala.

AND

Their Workman : Des Raj Sharma

APPEARANCES :

For the Employers : Sh. S. C. Bhatnagar

For the Workman : Sh. V. K. Sharma

Activity : Cantonment Board Ambala State : Haryana

AWARD

Dated the 31st of October, 1984.

The Central Government, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act 1947, hereinafter referred to as the Act, per their Order No. L-13012/6/80-D. II.B, dated the 18th of March, 1981 read with S.O. No. S. 11025(2)/83 dated the 8th of June, 1983 referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the action of the management of Cantonment Board, Ambala Cantt. in transferring the services of the Shri Des Raj Sharma, Ex-Octroi Superintendent to Notified Area Committee and subsequently terminating his services with effect from 23-2-77 without paying him retrenchment compensation according to the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. Brief facts of the case, according to the petitioner/Workman are that he was serving the Respondent Board in various capacities since 1-12-1939 and, on getting normal promotions, was holding the post of Octroi Supdt. in February 1977 when due to excision of certain areas from the territorial jurisdiction of the Board to the erstwhile Notified Area Committee, Ambala (Since upgraded into a regular Municipal Committee) his services were desired to be transferred to the said N.A.C. w.e.f. 5-2-1977. He was informed accordingly and directed that in case of any reluctance on his part, his services with the Board were liable to be terminated. The petitioner resisted the transfer-proposal on the ground that it was prejudicial to his service conditions. However the Board did not find any logic in his representation and, thus, terminated his services w.e.f. 28-2-1977.

3. Feeling aggrieved, the petitioner raised an industrial dispute which defined any amicable settlement despite the intervention of the Conciliation Officer and hence the Reference.

4. Resisting the proceedings, the Respd. Board questioned the validity of the reference on the ground that the petitioner was not a Workman because he was drawing a salary of more than Rs. 500/- p. m. at the relevant time. On facts it was explained that on the excision of certain areas from its jurisdiction, the Central Govt. per their letter Exb. R2 bearing No. 14(3)/73/D(Q&C) dated 5-2-1977 (Ministry of Defence) issued instructions to transfer the entire Octroi department alongwith its personnel to the N.A.C.; and in case of any body's refusal to accept the transfer, to dispenze with his services. Thus the Board had no option but to disengage the petitioner because of his adamant and defiant attitude.

5. The parties were taken to trial on the following issues framed by my Id. predecessor.

1. As in the order of Reference.
2. Whether the claimant is not a Workman?
3. To what relief, if any, he is entitled?

6. In support of his case the petitioner examined himself whereas the Respd. Board produced their Office Supdt. Shri Jagan Nath. Of course both the parties relied on a number of documents also, whose authenticity was not denied from either side. I have carefully scrutinised the entire available data and heard the parties. My issuewise discussion and findings are as follows.

ISSUE NO. 2

7. First of all I would like to deal with the preliminary issue regarding the petitioner's locus standi because on behalf of the Respd. Board it was vehemently argued that he was not a "Workman" within the meaning of Section 2(s) of the Act since on his own admission he was drawing a monthly salary of more than Rs. 500/- at the relevant time. However I am not impressed with the effort to knock him out on the technicalities of Law; after all there is absolutely

no evidence on record to indicate that he had any administrative or disciplinary control over his subordinates. To be precise, in the absence of any material to show that he had the powers to appoint; grant leave, dismiss or in any other manner initiate disciplinary proceedings against his subordinates it could not be inferred that he was holding any managerial, administrative or supervisory post. For my views I draw support from the observations of the Hon. Judges in the cases of Ved Parkash Gupta Vs. M/s. Delton Cable India (P. Ltd.) AIR 1984 S.C. 914 and S. K. Verma Vs. Mahesh Chandra and another AIR 1984 S.C. 1462. Accordingly, on holding the petitioner to be a "Workman" I answer the issue against the Respd. Board.

8. ISSUE NO. 1 & 3

Both these issues are interconnected since they relate to the contentious points of the petitioners proposed transfer and the consequent termination. Therefore, I proceed to deal with them at a stroke for an effective adjudication. At the risk of repetition it may be mentioned that the Respd. Board tried to take cover under the instructions of the Central Government, issued vide their letter Exb. R2, to go ahead with the petitioner's proposed transfer to the N.A.C. as the entire Octroi department was being handed over to latter in view of the excision of certain areas from its jurisdiction. On its behalf it was contended that under the scheme of the Cantonment's Act and the Rules framed thereunder—it was bound to comply with the Government's instructions both in letter and spirit, and being an employee of the Board, the petitioner could not resist the any proposed transfer particularly when he would have been a superfluous entity in the absence of Octroi department.

9. In spite of seeming attraction, the submission raised on behalf of the Board failed to carry conviction with me. For the proper appreciation of the point in issue it would be in the fitness of things to have a sequence wise glance into the facts of the case. To be precise, on the receipt of the letter Exb. R-2 dated 5-12-1977 from the Defence Ministry, the Respd. Board issued the letter Exb. W2 dated 16/2/1977 to the petitioner; perusal thereof would show that it was not a mere proposal, rather a sort of ultimatum that either he should accept the transfer or face termination. The petitioner reacted promptly by sending his representation Exb. W4 dated 18-2-1977; that since he was not assured of the prevalent facilities in the N.A.C., therefore, he was not willing to accept the transfer, he thus prayed for his retention in Board's services but the Board did not respond favourably and terminated his services per Exb. W3 dated 27-2-1977.

10. As a matter of fact there is a twin question involved in the dispute in the sense as to whether the Respd. Board was helpless in pursuing the proposed transfer and as to whether the petitioner was bound to comply with the same? In the totality of the situation, in my considered opinion, the Board must fail on both the counts. The pertinent point is that on the admission of its Office Supt. Sh. Jagan Nath the post of Octroi Supt. was of a non-technical nature and, as such, inter-transferable with the equivalent posts of the Accountant; Tax Supt. and Revenue Supt. He further conceded that at the relevant time the post of the Accountant was lying vacant as the then incumbent Sh. Kirori Mal had gone over to the N.A.C. on transfer. In a manner of speaking the petitioner could be easily adjusted against an equivalent post even if the department of Octroi was proposed to be abolished altogether.

11. Another angle to the problem is that there was no assurance to protect the petitioner's service conditions. Significantly enough, in the written statement itself it was admitted that on to the N.A.C. the petitioner was to be governed by the rules and regulations applicable to the employees of the Municipal Committees. In all fairness to them, at least to this extent, this Respd. Board did not question the petitioner's sworn deposition as WW1 that as an employee of the Cantt. Board he was entitled to pension on his retirement whereas services of the Municipal employees are non-pensionable. Against such back drop one can not possibly resist the inference that since it gravely prejudiced the petitioner's service conditions, therefore, the impugned transfer, being violative of clause (b) to the proviso under Section 25PP of the Act, could not be forced upon him without treating it as a "retrenchment" per ration of the case of the Manage-

ment of Ambala Cantt. Electricity Corporation Vs. Its Workmen AIR 1971 Punjab & Haryana 274; and since there is no denying the fact that the requisite formalities of a "retrenchment" were not followed in the instant case, therefore, the petitioner's disengagement can not be sustained.

12. However, on behalf of the Respd. Board, and without any challenge from the opposite side, it was brought to my notice that despite his disengagement, the petitioner was paid 3 months salary besides the gratuity dues; and was also allowed full pension w.e.f. 1-6-1977; though in the normal course of events he would have retired w.e.f. 31-8-1977. To put in simple words, the termination which preceded superannuation only by six months, cannot be effectively set aside as in the absence of his legal capability to rejoin, no useful purpose would be served by granting him the relief of reinstatement.

13. Regardless of the merits I think the point raised by the Id. Counsel requires to be kept in mind and, hence, to meet the peculiar situation, on answering both the issues in favour of the petitioner Workman, I direct that by way of a legal fiction he be deemed to be in the active service of the Respd. Board till the date of his normal superannuation i.e. 31-8-1977 with all the attendant benefits, with the rider that the various amounts drawn by him during the intervening period, in any shape so ever, shall be fully adjustable.

14. Award returned accordingly.

I. V. VASISHTH, Presiding Officer
Central Govt. Industrial Tribunal,
Chandigarh.

Chadigarh,
Dt. 31-10-1984.

[No. L-13012/6/80-D.III(B)]
HARI SINGH, Desk Officer
New Delhi, the 23rd November, 1984

S.O. 4309.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Sodepur Colliery Messrs Eastern Coalfields Limited, P. O. Sunderchak, District Burdwan and their workmen, which was received by the Central Government on the 17th November, 1984.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA

Reference No. 25 of 1982

PARTIES :

Employers in relation to the management of Sodepur Colliery of M/s. E. C. Ltd., P. O. Sunderchak (Burdwan).

AND

Their Workman.

PRESENT :

Mr. Justice M. P. Singh.—Presiding Officer.

APPEARANCES :

On behalf of Management. Mr. B. N. Lala, Advocate with Mr. P. N. Goswami, Senior Personnel Officer.

On behalf of Workmen.—Mr. S. R. Mitra, Secretary, of the union.

STATE : West Bengal.

INDUSTRY : Coal Mines.

AWARD

By Order No. L-19011(9)/82-D. IV(B) dated 22nd July, 1982, the Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the action of the management of Sodepur Colliery of M/s. Eastern Coalfields Ltd., P. O. Sunderchak, District Burdwan to addressing allowance in the earnings of loaders for the purpose of calculating fall back wages w.e.f. 1-1-75 to 30-6-81 is justified? If not, to what relief the workmen/underground loaders are entitled?"

The case was called for hearing on 5-11-1984, when Mr. S. R. Mitra for the union filed a petition mentioning that the workmen are no longer interested in the instant dispute as the concerned workmen have been getting Fall Back Wages correctly since 1980 onwards; that a 'No dispute' award may be passed. So in my opinion there is no longer any industrial dispute and accordingly I pass a 'No dispute' award in the present case.

This is my Award.

Dated, Calcutta,
6th November, 1984.

M. P. SINGH, Presiding Officer

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL,
CALCUTTA

Reference No. 25 of 1982

PARTIES :

Employers in relation to the management of Sodepur Colliery of M/s. H. C. Ltd., P. O. Sunderchak (Burdwan).

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Mr. Justice M. P. Singh.—Presiding Officer.

APPEARANCES :

On behalf of Management.—Mr. B. N. Lala, Advocate, with Mr. P. N. Goswami, Senior Personnel Officer.

On behalf of Workmen.—Mr. S. R. Mitra, Secretary, of the union.

STATE : West Bengal.

INDUSTRY : Coal Mines.

AWARD

By Order No. L-19011(9)/82-D. IV(B) dated 22nd July, 1982, the Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the action of the management of Sodepur Colliery of M/s. Eastern Coalfields Ltd., P. O. Sunderchak, District Burdwan to addressing allowance in the earnings of loaders for the purpose of calculating fall back wages w.e.f. 1-1-75 to 30-6-81 is justified? If not, to what relief the workmen/underground loaders are entitled?"

The case was called for hearing on 5-11-1984, when Mr. S. R. Mitra for the union filed a petition mentioning that the workmen are no longer interested in the instant dispute as the concerned workmen have been getting Fall Back Wages correctly since 1980 onwards; that a 'No dispute' award may be passed. So in my opinion there is no longer any industrial dispute and accordingly I pass a 'No dispute' award in the present case.

This is my Award.

Dated, Calcutta,
6th November, 1984.

M. P. SINGH, Presiding Officer.

[No. L-19011/9/82-D-IV (B)]

New Delhi, the 23rd November, 1984

S.O. 4310.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government

hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Western Coalfields Limited, Kanhan Area, P. O. Dungaria, Distt. Chhindwara (MP) and their workmen, which was received by the Central Government on the 19th November, 1984.

BEFORE JUSTICE SHRI K. K. DUBE (RETD.) PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC(R)(56) of 1982

PARTIES :

Employers in relation to the management of Western Coalfields Limited, Kanhan Area, Post Office Dungaria, District Chhindwara (M.P.) and their workman, Shri Laxman Sen, Shotfirer, represented through the General Secretary, B.K.K.M. Sangh (BMS), Kanhan Area, Post Office Dungaria, District Chhindwara (M.P.).

APPEARANCES :

For Union—Shri S. B. Singh,

For Management—Shri P. S. Nair, Advocate.

INDUSTRY : Coal Mining DISTRICT : Chhindwara (M.P.)

AWARD

Dated, the 12th November, 1984

The Central Government in exercise of its powers under section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter referred to as the Act), referred the following dispute, for adjudication, vide Notification No. L-22011(11)/82-D.IV (B) dated 15th September, 1982 :—

"Whether the action of the management of Western Coalfields Limited, Kanhan Area in relation to their Ambara Colliery in terminating the services of Shri Laxman Sen, Shotfirer with effect from 16-10-1977 amounts to retrenchment under section 2(OO) of the Industrial Disputes Act, 1947? If so, to what relief is the workman entitled?"

2. The workman Laxman Sen at the relevant time was Shotfirer. He had been appointed on 13-2-1950 and was a permanent workman of Ambara Colliery. Before he reached the age of superannuation, his services were terminated on 18-9-1977.

3. According to the management a Shotfirer is included as a competent person under Coal Mines Regulations 2(7). A Shotfirer has to carry out his duties according to Regulation 45. He is required to pass a Mining Examination under Regulation 12(h). He must possess a Gas Testing Certificate under Regulation 27(g) and has also to obtain a Shotfirer's Certificate under Regulation 24. He must be a physically fit person and therefore he must submit a certificate by a qualified medical practitioner. The Gas Testing Certificate of Laxman Sen expired on 23rd July, 1977 and he was asked to have it renewed. The management by a letter dated 16th October, 1977 informed him that if his Gas Testing Certificate was not renewed and if he failed to produce the first-aid certificate his service will stand terminated with effect from 22-9-1977. In about March 1979 he was also medically examined and it was found he had incurred defect in his eyes and was suffering from Bronchitis. The management contends that they could no longer keep him in service or else they were liable to be prosecuted for violating the mandatory provisions of Mining Regulations. The management, therefore, had no option but to terminate his service.

4. Laxman Sen was having the necessary qualifications to be a Shotfirer and he had served as Shotfirer most of his life. It appears that his Shotfirer licence had expired and it had to be renewed. By a letter dated 22nd July, 1977 the management gave him a notice that his Gas Testing and First Aid Certificates had expired. The certificates had

not been renewed for the last three years. He was asked to renew his Gas Testing and First Aid Certificates within two months of the issue of the letter or his services will stand terminated with effect from 22-9-1977. Then on 12th October, 1977, the workman was given a letter that since his Shotfirer's certificate had expired and it had not been validated he was not competent to work as a Shotfirer. He was, therefore, stopped from working as a Shotfirer. On 16th October, 1977 they again gave a letter that Laxman Sen was not in possession of a Shotfirer's Certificate, a Gas Testing Certificate and First Aid Certificate despite request made on that behalf, they were, therefore, unable to retain him in service and his services would stand terminated with immediate effect. In terms of the Standing Orders 13A(1) he was entitled to one month's notice and therefore he would be paid one month's salary in lieu of notice. He was asked to collect the one month's salary and all other dues. With these formalities the services of Laxman Sen were terminated.

5. According to the workman even if he had not produced the Gas Testing Certificate or other certificates the management ought not to terminate his services without following the procedure prescribed under the Standing Order, but he could be given an alternative job. This was also the practice that they were following. Since he was a permanent servant it was incumbent on the management to give him show cause notice against the disability sought to be established against him before terminating his services. The termination of a permanent employee could only be done for any misconduct or if he were to be retrenched by following the procedure prescribed. Shri Nair learned counsel for the management contends that since he did not produce medical certificate it would be presumed that he was not medically fit and therefore the management could be justified in removing him. Now presumption arises that he was not medically fit if a certificate is not produced. It is a question of fact which has to be established categorically. A presumption attaches to a certificate that he is medically fit but it will not be possible to presume the other way. The contention of Shri Nair, learned counsel for the management, therefore, has no force. I would, therefore, proceed to examine the effect of the non-production of the statutory certificate.

6. If he were to be considered for the job of a Shotfirer, it was necessary that he had the necessary certificate. None the less, he could only be removed from services in accordance with Standing Orders. From the narration of the facts and the contention raised it appears that the services of Laxman Sen could not be dispensed with in the manner it was done. He could not be allowed to continue as a Shotfirer because he had not the requisite certificates which the statute enjoined upon him to produce. He being a permanent servant, he had acquired a right to continue upto the age of superannuation, unless he had been held guilty of any misconduct in accordance with the Standing Orders. It is undisputed that he was not being removed for a misconduct but had incurred a disqualification to continue as a Shotfirer. Now it is not necessary that he was given the work of only a Shotfirer. Till such time he did not possess the shotfirer's certificates and the other statutory required certificates, he was taken out from the Shotfirer's job and was asked to work in other capacities. The order terminating his services was preemptive to the effect that his services shall stand terminated, which shows that he was not given any opportunity to show cause against his termination of services and which was against principles of natural justice. He could show that till such time the certificates were granted, he could be continued on other posts in the establishment.

7. The other aspect of the matter that requires consideration in this case is that unless it was proved as a fact that a disqualification had crept in the performance as a Shotfirer, he could not be removed. He was doing the work of a Shotfirer all his life and the renewal of the certificate at best was a formality and the workman ought to have been given a chance to have the certificate renewed. No attempt has been made to make an enquiry in this regard. Now it is well settled that any termination which was not because of superannuation or because of illness rendering the incumbent incompetent to work or that he was removed on grounds of any misconduct would be retrenchment. Since the mandatory requirements of section 25-F of the Act have not

been complied with, such order of retrenchment would be void ab-initio. The termination order was therefore not justified and the workman was entitled to be retined in service during this period. I have been informed that the workman has now reached the age of superannuation, therefore, he cannot now be employed. It is a fit case where he is directed to be paid compensation by awarding him part of back wages. Since he could not work as a Shotfirer, he would be given a lesser salary of the job he could perform. To avoid all controversies, I would direct that a compensation in the sum of Rs. 15,000 be made to the workman.

AWARD

I render this award, now, finding that the termination of Laxman Sen with effect from 16-10-1977 was not justified. The termination would be retrenchment under section 2(OOO) of the Industrial Disputes Act, 1947 being made in violation of mandatory provisions of section 25-F *ibid*. Laxman Sen be paid Rs. 15,000 (Rupees fifteen thousand) as compensation. He be paid Rs. 100 as costs.

JUSTICE K. K. DUBE, Presiding Officer

[No. L-22011(11)/82-D-IV (B)]

S. S. MEHTA, Desk Officer

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1984

शुद्धि-पत्र

का. आ. 4311—भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. 1117 तारीख 14 मार्च 1984 जो कि भारत के राजपत्र भाग 2 खंड 3 (ii) में पृष्ठ 960, पर प्रकाशित हुई है, की अनुसूची की मद 1 और 8 में "प्रादेशिक भविष्य निधि, आयुक्त, पंजाब" शब्दों के स्थान पर "प्रादेशिक भविष्य निधि, आयुक्त हरियाणा" पढ़ें।

[संख्या एस-35014/4/84-एफ, पी. जी.]

New Delhi, the 24th November, 1984

CORRIGENDUM

S.O. 4311.—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour & Rehabilitation No. S.O. 1117 dated the 14th March, 1984 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) at page 960, in terms 1 and 8 of the Schedule for words 'Regional Provident Fund Commissioner, Punjab' read 'Regional Provident Fund Commissioner, Haryana'.

[No. S-35014/4/84-FPG]

शुद्धिपत्र

का. आ. 4312—भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 914 तारीख 5 मार्च 1984 जो कि भारत के राजपत्र भाग 2 खंड 3 (ii) में पृष्ठ 773 पर प्रकाशित हुई है, की अनुसूची मद 1 और 8 में "प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब" शब्दों के स्थान पर "प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, हरियाणा" पढ़ें।

[संख्या-35014/17/84-एफ.पी.जी.]

CORRIGENDUM

S.O. 4312.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation No. S.O. 914 dated 5th March, 1984 published in the Gazette of India Part II, Section 3 Sub-section (ii) at page 773, in items 1 and 8 of the schedule for the words 'Regional Provident

Fund Commissioner, Punjab' read 'Regional Provident Fund Commissioner, Haryana'.

[No. S-35014/17/84-SS-IV(FPG)]

शुद्धि-पत्र

का. आ. 4313.—भारत सरकार के श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 683 तारीख 15 फरवरी 1984 जो कि भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3 (ii) में पृष्ठ 613-14 पर प्रकाशित हुई है की मद 1 और 8 में "प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पंजाब" शब्दों के स्थान पर "प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त हरियाणा" पढ़ें।

[संख्या एस-35014/34/84-पी. एफ.-2]

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1984

CORRIGENDUM

S.O. 4313.—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation No. S.O. 683 dated the 15th February, 1984 published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (ii) at page 613-14, in items 1 and 8 of the schedule for the words "Regional Provident Fund Commissioner, Punjab" read "Regional Provident Fund Commissioner Haryana".

[No. S-35014/34/84-PF. II]

शुद्धि-पत्र

का. आ. 4314.—भारत सरकार के श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 684 तारीख 15 फरवरी, 1984 जो कि भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3 (ii) में पृष्ठ 615 पर प्रकाशित हुई है, की अनुसूची की मद 1 और 8 में "प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब" शब्दों के स्थान पर "प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, हरियाणा", पढ़ें।

[सं. एस-35014/38/84-पी. एफ.-2]

CORRIGENDUM

S.O. 4314.—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour & Rehabilitation No. S.O. 684 dated the 15th February, 1984 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) at page 615, in items 1 & 8 of the schedule for the words "Regional Provident Fund Commissioner Punjab" read "Regional Provident Fund Commissioner, Haryana".

[No. S-35014/38/84-PF-II]

शुद्धि-पत्र

का. आ. 4315.—भारत सरकार के श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 741 तारीख 24 फरवरी, 1984 जो कि भारत सरकार के राजपत्र भाग 2, खंड 3 (ii) में पृष्ठ 689 पर प्रकाशित हुई है की अनुसूची की मद 1 और 8 में "प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब" शब्दों के स्थान पर प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, हरियाणा" पढ़ें।

[संख्या एस-35014/24/84-पी. एफ.-2]

CORRIGENDUM

S.O. 4315.—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour & Rehabilitation No. S.O. 741 dated the 24th February, 1984 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) at page 689, in items 1 & 8 of the schedule for the words "Regional Provident Fund Commissioner Punjab" read "Regional Provident Fund Commissioner, Haryana".

[No. S-35014/24/84-PF-II]

शुद्धि-पत्र

का. आ. 4316.—भारत सरकार के श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 686 तारीख 15 फरवरी, 1984 जो भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3(ii) में पृष्ठ 618 पर प्रकाशित हुई है की अनुसूची की मद 1 और 8 में "प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब" शब्दों के स्थान पर "प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, हरियाणा", पढ़ें।

[संख्या एस-35014/35/84-पी. एफ.-2]

CORRIGENDUM

S.O. 4316.—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour & Rehabilitation No. S.O. 686. dt. the 15th February, 1984 published in the Gazette of India Part II, Section 3 Sub-section (ii) at page 618, in items 1 & 8 of the schedule for the words "Regional Provident Fund Commissioner, Punjab" read "Regional Provident Fund Commissioner, Haryana".

[No. S-35014/35/84-PF-II]

शुद्धि-पत्र

का. आ. 4317.—भारत सरकार के श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 685 दिनांक 15 फरवरी 1984 जो कि भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3 (ii) में पृष्ठ 616 पर प्रकाशित हुई है की अनुसूची की मद 1 और 8 में "प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब" के शब्दों के स्थान पर "प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, हरियाणा", पढ़ें।

[संख्या एस-35014/33/84-पी. एफ.-2]

CORRIGENDUM

S.O. 4317.—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour & Rehabilitation No. S.O. 685 dated the 15th February, 1984 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) at page 616, in items 1 & 8 of the schedule for the words "Regional Provident Fund Commissioner, Punjab" read "Regional Provident Fund Commissioner, Haryana".

[No. S-35014/33/84-PF-II]

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1984

का. आ. 4318 :—मैसर्स कुमार इन्जीनियरिंग कारपोरेशन मोडल टाऊन, जी. टी. रोड, मंडी गोविन्द गढ़, पंजाब (पी. एन. 14744), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहचर बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुश्रेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपबन्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेंगी और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभागों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जागा, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभागों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों को वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय रकम होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम

का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिगत दशा में, उक्त सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक्दार, नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस. 35014/116/84-एस.एस.-4]

New Delhi, the 2nd November, 1984

S.O. 4318.—Whereas Messrs Kumar Engineering Corporation, Model Town, G. T. Road, Mandi Gobindgarh, Punjab (PN/4744) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are

more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/116/84-SS-IV]

का. अ. 4319.—मैसर्स नवरंग डाइंग प्राइवेट लिमिटेड, 573, गिरगौम रोड, पहली मंजिल, बम्बई-400002, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) की अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहवृद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपावृद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शक्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

1146 GI/84—15

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों को वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुबाब, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत् करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समन्वित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिवत वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिफल के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिगत की दशा में, उन मत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिवत वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त

स्कीम को अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक्कदार, नाम निर्वैधितियों/विभिन्न वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एरु-35014/120/84-एस.एस.-4]

S.O. 4319.—Whereas Messrs Navrang Dyeing Private Limited, 573, Girgaum Road, 1st Floor, Bombay-400002 (MH/8138) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/120/84-SS-IV]

का. आ. 4320.—मैसर्स दोआबा स्टील रोलिंग मिल्स, कमलोह रोड, मंडी गोविन्द गढ़-147301. (पी.एन./3937), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम को अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदाय करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समूचित रूप से वृद्धि की जा मे की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभोग्य हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उक्त सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिथि की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार, नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय

तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/115/84-एस.एस.-4]

New Delhi, the 24th November, 1984

S.O. 4320.—Whereas Messrs Doaba Steel Rolling Mills, Amloh Road, Mandi Gobindgarh (PN/3937) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a rea-

sonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/115/84-SS-IV]

का. आ. 4321.—मैसर्स पैंप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नाभा रोड, पटियाला (पंजाब)-प. न. /386, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पथक अभिव्यय या प्रीमियम का संवाय बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुभोग हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपादक अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों को वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समूहित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभोग हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द हो जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस निरन्तर तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक्दार, नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्पश्चात् से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/129/84-एत.एस.-4]

S.O. 4321.—Whereas Messrs Pepsu Road Transport Corporation Limited, Nabha Road, Patiala (Punjab) (PN/386) (hereinafter referred to as the said establishment) have ap-

plied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of insurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/129/84-SS-IV]

का. श. 4322.—मैसर्स अशोक फाउन्डरी एंड मेटल वर्क्स (पी.) लिमिटेड, 101/103, इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर, (आर. जे./1642) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) वे कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के बर्माहारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संवाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए वे फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपबन्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान को ऐसी दिवरीयों भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मारा की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3-क) के सण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, दिवरीयों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संवाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को अनुसूची की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की

भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदाय करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समूचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों को लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुपलब्ध हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर स्कीम के अधीन संवेद्य रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संचय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिवक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना श्रूका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिगत दशा में, उस मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिवक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक्कदार, नाम निर्देशितियों/विधिवक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एग-35014/117/84-एस.एस.-4]

S.O. 4322.—Whereas Messrs Ashok Foundry and Metal Works Private Limited, 101-103 Industrial Area, Jaipur (RJ/1642) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked

Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/117/84-SS-IV]

का. आ. 4323.—मैसर्स ब्लैकस्मिथ कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, 213-इ., ईस्वरन छेटीयर से-आउट, कोयम्बटूर-641012, (टी. एन./6930), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहृदय बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शक्तों के अधीन होते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभावों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभावों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों को वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस वृत्ति में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उक्त सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस निरत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असमर्थ रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की वृत्ति में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि वह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक्दार, नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/119/84-एस.एस.-4]

S.O. 4323.—Whereas Messrs Blacksmith Construction Company, 213-E, Eswaran Chettiar Layout, Coimbatore-641012 (TN/6930) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establish-

ment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that could be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

का. आ. 4324.—मैसर्स इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ तमिलनाडू लि., एल. एल. ए. बिल्डिंग, 733 अन्ना सलाई, मद्रास, टी. एन./16833 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) के कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होते हुए, उक्त स्थापन को निम्न वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडू को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का उत्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों को वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत् करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिनी को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों का प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार, नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के मातृ दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[मं. एम-35014/118/84-एस.एम.-4]

S.O. 4324.—Whereas Messrs Electronics Corporation of Tamil Nadu Limited, LLA Building, 735, Annasalai Madras-600002 (TN/6633) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund 1146 GI/84—16

Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects."

[No. S-35014/118/84-SS-IV]

का०आ० 4325 केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91क के साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 2957 तारीख 5 अगस्त, 1982 के क्रम में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की, इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट यूनितों के नियोजित कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 अक्टूबर, 1982 से 30 सितम्बर, 1984 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, अवधि के लिये छूट देती है।

उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात् :—

- (1) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान दर्ज किये जायेंगे;
- (2) इस छूट के होते हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रसुविधायें प्राप्त करते रहेंगे, जिनको पाने के लिये वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संदत्त अभिदायों के आधार पर हकदार हो जाते;
- (3) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदेय पहले ही संदत्त किए जा चुके हैं तो वे वापस नहीं किए जाएंगे;
- (4) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी;
- (5) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या इस निमित्त प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी —
 - (i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिये, या
 - (ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिये कि कर्मचारी राज्य (बीमा साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिये रख गये थे या नहीं, या
 - (iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दी गई उन प्रसुविधायों को, जो ऐसी प्रसुविधायें

हैं जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं, या

- (iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं,

निम्नलिखित कार्य करने के लिये सशक्त होगा :—

- (क) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या
- (ख) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के अधिभोग में के कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भारसाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संक्षेप से संबंधित ऐसी लेखा-वहियां और अन्य दस्तावेजों, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या
- (ग) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक की, उसके अधिकर्ता या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाये, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्ति-युक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या
- (घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गये किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल करना या उससे उद्धरण लेना।

अनुसूची

क्र०सं०

यूनिट का नाम

1. विपणन और विक्रय प्रभाग, नई दिल्ली,
2. ट्रान्सफार्मर संयंत्र, झांसी,
3. स्टीम टर्बाइन विनिर्माण यूनिट, हरिद्वार, और
4. उच्च दाब बायलर प्लांट, तिहरी,

[संख्या एस०-38014/44/82-एच० आई०]

स्पष्टीकरण-ज्ञापन

इस मामले में भूतलक्षी प्रभाव से छूट देनी आवश्यक हो गई है, क्योंकि छूट के लिये आवेदन-पत्र देर से प्राप्त हुआ। तथापि, यह प्रमाणित किया जाता है कि भूतलक्षी प्रभाव से छूट देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

S.O. 4325.—In exercise of the powers conferred by section 88 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 2957 dated the 5th August, 1982 the Central Government hereby exempts the regular employees of the units of Bharat Heavy Electricals Limited specified in the Schedule annexed hereto from the operation of the said Act for the period with effect from 1st October, 1982 upto and inclusive of the 30th September, 1984.

The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

- (1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees;
- (2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates :—
- (3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded ;
- (4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 ;
- (5) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—
 - (i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period ; or
 - (ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period ; or
 - (iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification ; or
 - (iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory ;

be empowered to—

- (a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or
- (b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found in charge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

- (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or
- (d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

SCHEDULE

S. No. Name of the Unit

1. Marketing and Sales Division, New Delhi.
2. Transformer Plant, Jhansi.
3. Steam Turbine Manufacturing Unit, Hardwar ; and
4. High Pressure Boiler Plant, Tiruchy.

[No. S-38014/44/82-HI]

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the application for exemption was received late. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

कां०आ० 4326 केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 91क के साथ पठित धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० कां०आ० 1443 तारीख 17 अप्रैल, 1984 के क्रम में (1) भारत गोल्ड, माइन्स प्राइवेट लिमिटेड (सेण्ट्रल वर्कशाप) : डाकघर ऊरगाँव, कोलार गोल्ड फील्ड्स : (2) भारत गोल्ड माइन्स प्राइवेट लिमिटेड, ऊरगाँव डेरे, डाकघर ऊरगाँव, गोला गोल्ड फील्ड्स और (3) भारत गोल्ड माइन्स प्राइवेट लिमिटेड, ऊरगाँव मुद्रणालय, डाकघर ऊरगाँव कोलार गोल्ड फील्ड्स को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 जुलाई, 1983 से 30 जून, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, अवधि के लिए छूट देती है।

2. पूर्वोक्त छूट को शर्त निम्नलिखित है, अर्थात् :—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है), ऐसे विवरणियों, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी :

(2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी—

(1) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणों की विशिष्टियों सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ : या

(2) यह अभिनियमित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा

यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख, उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं; या

- (3) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी नियोजक द्वारा दिए गए उक्त फायदों को, जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है, या नहीं; या

- (4) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि इस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में उक्त अधिनियम के उपबन्ध प्रयुक्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं—

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा:—

- (क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है; या
- (ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिमोक्षाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहियाँ और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दें, या उन्हें ऐसी जानकारी दें जिसे वे आवश्यक समझते हैं; या
- (ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक को, उसके अधिकर्ता या सेवक की, ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि कर्मचारी है, परीक्षा करना;
- (घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना।

[सं० एस-38014/37/81-एच०आई०]

स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस मामले में भूतलक्षी रूप से प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के लिए आवेदन पर कार्रवाई करने में समय लग गया। किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि भूतलक्षी प्रभाव से छूट देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

S.O. 4326.—In exercise of the powers conferred by section 87 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification

of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 1443 dated the 17th April, 1984, the Central Government hereby exempts (1) Bharat Gold Mines Private Limited (Central Workshop), Oorgaum Post, Kolar Gold Fields; (2) Bharat Gold Mines Private Limited (Oorgaum Diary) Oorgaum Post, Kolar Gold Fields and (3) Bharat Gold Mines Private Limited Oorgaum Printing Press, Oorgaum Post, Kolar Gold Fields from the operation of the said Act for a further period from the 1st July, 1983 upto and inclusive of the 30th June, 1984.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

- (1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulation, 1950 ;
- (2) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—
- (i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period ; or
- (ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period ; or
- (iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification ; or
- (iv) ascertaining whether any of the provisions of the said Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory ;

be empowered to—

- (a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or
- (b) enter any factory, establishment office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow, him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary ; or
- (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or
- (d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S-38014/37/81-HI]

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

का०आ० 4327.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91क के माध्यम से अधिनियम 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 1444, तारीख 17 अप्रैल, 1984 के क्रम में, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 अप्रैल, 1983 से 31 मार्च, 1984 तक को जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, अवधि के लिए छूट देती है।

2. पूर्वोक्त छूट को शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात्:—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है), ऐसी विवरणियाँ, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी ;

(2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन निश्चित किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी—

(1) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी को विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ ; या

(2) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख, उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं; या

(3) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को, जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है, या नहीं; या

(4) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में उक्त अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं;

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा:—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों में नियोजन और मजदूरी के संवाद से संबंधित ऐसे लेखा, बहियाँ और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दें, या उन्हें ऐसी जानकारी दें जिसे वे आवश्यक समझते हैं; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक को, उसके अधिकर्ता या सेवक को, ऐसे किसी व्यक्ति को जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि कर्मचारी है, परीक्षा करना;

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना।

[सं० एम 38014/41/S2-एच०आई०]

स्पष्टीकरण

इस मामले में छूट के आवेदन के संबंध में कार्रवाई करने में कुछ समय लग गया था इसलिए छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

S.O. 4327.—In exercise of the powers conferred by section 87 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1444 dated the 17th April, 1984 the Central Government hereby exempts Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from 1st April, 1983 upto and inclusive of the 31st March, 1984.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely:—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulation, 1950;

(2) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act or other official of the Corporation authorised in this behalf shall for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in case and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the said Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory;

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate

employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or

(d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S-38014/41/82-HI]

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

का.आ. 4328.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बंसा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91क के साथ पठित धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1435 तारीख 17 अप्रैल, 1984 के क्रम में, कोल इंडिया लिमिटेड की समस्त कोल इंडिया प्रैस, रांची की उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 जुलाई, 1983 से 30 जून, 1984 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, अवधि के लिए छूट देती है।

2. पूर्वांक छूट का शर्त निम्नलिखित है, अर्थातः—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है), ऐसी विवरणियाँ ऐसे प्रारूप में और ऐसी विनिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बंसा (साधारण) विनियम, 1950 के अर्थन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी ;

(2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अर्थन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारि—

(1) धारा 44 की उपधारा (1) के अर्थन, उक्त अवधि की बाबत वांछित किसी विवरणियों की विनिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ, या

(2) यह अधिनियमित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बंसा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख, उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं ; या

(3) यह अधिनियमित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को, जिसके प्रतिकलस्वरूप इस अधिसूचना के अधिन छूट जा रहा है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है, या नहीं ; या

(4) यह अधिनियमित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान जब उक्त कारखाने के संबंध में उक्त अधिनियम के उपबन्ध प्रवर्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं ;

निम्नलिखित कार्य करने के लिए, मसक्त होगा—

(क) प्रधान या अध्यक्षित नियोजक ने अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे आरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारि आवश्यक समझता है, या

(ख) ऐसे प्रधान या अध्यक्षित नियोजक के अधिभोगार्थन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारों से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरों के संदाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहियों और अन्य दस्तावेज ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारि के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दें, या उन्हें ऐसी जानकारी दें जिसे वे आवश्यक समझते हैं; या

(ग) प्रधान या अध्यक्षित नियोजक को, उसके अधिकारी या सेवक को, ऐसे किसी व्यक्ति को जो ऐसे कारखाने, स्थापन कार्यालय या अन्य परिसर, में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारि के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि कर्मचारी है, परीक्षा करना ;

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखावहों या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना।

[संख्या : एस-38014/4/81-एच.आई.]

स्पष्टीकारक शायन

इस मामले में छूट के आवेदन के सम्बन्ध में कार्यवाई करने में कुछ समय लग गया था इसलिए छूट की भूतलक्ष प्रभाव देना आवश्यक हो गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट का भूतलक्ष प्रभाव देने से किस के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

S.O. 4328.—In exercise of the powers conferred by section 87 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1435 dated the 17th April, 1984, the Central Government hereby exempts the Coal India Press, Ranchi, a subsidiary of the Coal India Limited, from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from 1st July, 1983 upto and inclusive of the 30th June, 1984.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulation, 1950 ;

(2) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act or other official of the Corporation authorised in this behalf shall for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period ; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period ; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification ; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the said Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory ;

be empowered to—

- (a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or
- (b) enter any factory, establishment office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary ; or
- (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or
- (d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S-38014/4/81-HI]

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

का.आ. 4329.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91A के माध पठित धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के अम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1682 तारीख 25 अप्रैल, 1984 के क्रम में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग से संबंधित भूभौतिकीय तथा अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान कर्मशाला (जो अब आई पी ई कर्मशाला के नाम से ज्ञात है) देहरादून को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 जुलाई, 1983 से 30 जून, 1984 तक को जिसमें यह तारीख से सम्मिलित है, अवधि के लिए छूट देती है।

2. पूर्वोक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात्:—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उक्त कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है), ऐसे विवरणियों, ऐसे प्ररूप में और ऐसे विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी, राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधिन उक्त अवधि की बाबत देनी हों :

(2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधिन नियुक्त किया गया कोई निरक्षक या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारि:—

- (1) धारा 44 की उपधारा (1) के अधिन, उक्त अवधि की बाबत दे गई किसे विवरणों की विशिष्टियों को सहायित करने के प्रयोजनार्थ ; या
- (2) यह अभिलिखित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख, उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं ; या
- (3) यह अभिलिखित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को, जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधिन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है, या नहीं ; या
- (4) यह अभिलिखित करने के प्रयोजनार्थ कि उक्त अवधि के दौरान जब उक्त कारखाने के संबंध में उक्त अधिनियम के उपबन्ध

प्रयुक्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं,

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सक्षम होगा:—

- (क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसे जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरक्षक या अन्य पदधारि आवश्यक समझता है ; या
- (ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिसूचना किसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभार से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहियाँ और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरक्षक या अन्य पदधारि के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दें, या उन्हें ऐसे जानकारी दें जिसे वे आवश्यक समझते हैं, या
- (ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक को, उसके अधिकारी या सेवक को ऐसे किसे व्यक्ति को जो कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसे व्यक्ति को, जिसके बारे में उक्त निरक्षक या अन्य पदधारि के पास यह विश्वास करने का युक्तिमत्त कारण है कि कर्मचारी है, परीक्षा करना ;
- (घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए रजिस्टर, लेखाग्रहः या अन्य दस्तावेज के नकल तैयार करना या उसमें उद्घरण लेना।

[संख्या: एम-38014/39/86-एचआई]

स्पष्टीकारक ज्ञापन

इस मामले में छूट के आवेदन के संबंध में कार्यवाही करने में कुछ समय लग गया था इसलिए छूट की भूलक्षता प्रभाव देना आवश्यक हो गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट की भूलक्षता प्रभाव देने से किसे के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

S.O. 4329.—In exercise of the powers conferred by section 87 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) (hereinafter referred to as the said Act) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 1682 dated the 25th April, 1984, the Central Government hereby exempts the Geophysical and Research and Training Institute Workshop (now known as IPE Workshop), Dehradun, belonging to the Oil and Natural Gas Commission from the operation of the said Act for the period from 1st July, 1983 upto and inclusive of the 30th June, 1984.

The above exemption is subject to the following conditions, namely:—

- (1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees;
- (2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates:—
- (3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded ;
- (4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 ;

(5) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

- (i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period ; or
- (ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period ; or
- (iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification ; or
- (iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory ;

be empowered to—

- (a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or
- (b) enter any factory, establishment, office of other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary ; or
- (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or
- (d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S-38014/39/80-HI]

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

का.आ. 4330.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91क के साथ पठित धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1447 तारीख 16 अप्रैल, 1984 के क्रम में, इण्डियन आयल ब्लैंडिंग लिमिटेड, पी-68, सी सी आर डाइवर्जन मार्ग, पहाड़पुर कलकत्ता और इण्डियन आयल ब्लैंडिंग लिमिटेड, पीर पाऊ, ट्राम्बे, बम्बई-74 को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 जुलाई, 1983 से 30 जून, 1984 तक की

जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, अवधि के लिए छूट देती है।

2. पूर्वानुमति छूट की शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात् :—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है), ऐसी विवरणियों, जैसे प्रारूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी;

(2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी :—

(1) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ;

(2) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख, उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं; या

(3) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को, जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है, या नहीं; या

(4) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में उक्त अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं;

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सक्षम होगा :—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है;

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहियां और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दें, या उन्हें ऐसी जानकारी दें जिसे वे आवश्यक समझते हैं; या

- (ग) प्रधान या अन्वयवहित नियोजक को, उसके अधिकारी या सेवक की, ऐसे किसी व्यक्ति को जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर, में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि कर्मचारी है, परीक्षा करना;
- (ख) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उसमें उद्धरण लेना।

[सं० एस-38014/37/82-एच०आई०]

स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस मामले में छूट के आवेदन के संबंध में कार्रवाई करने में कुछ समय लग गया था इसलिए छूट का भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट का भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी के हित पर प्रतिकूल पड़ेगा।

S.O. 4330.—In exercise of the powers conferred by section 87 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1447 dated the 16th April, 1984, the Central Government hereby exempts the Indian Oil Blending Limited, P. 68, C.G.R. Diversion Road, Paharpur, Calcutta and the Indian Oil Blending Limited, Pir Pau, Trombay, Bombay-74 from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from the 1st July, 1984 upto and inclusive of the 30th June, 1984.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely:—

- (1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;
- (2) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—
 - (i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or
 - (ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or
 - (iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or
 - (iii) ascertaining whether the employees continue to be said Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory;

be empowered to—

- (a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

- (b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found in charge thereof to produce to such Inspector or other official and allow, him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or
- (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or
- (d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S-38014/37/82-HI]

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the processing of application for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

का०आ० 4331 केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स लक्ष्मी वेंकटेश्वरा इण्डस्ट्रीज, आर०जी० रोड, गंगवती-583227, डिस्ट्रिक्ट रायचूर, कर्नाटक, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(482)/84/एस०एस०-2]

S.O. 4331.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Lakshmi Venkateshwar Industries, R. G. Road, Gangavati-583227, Distt. Raichur, Karnataka have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No S-35019/482/84-SS. II]

का०आ० 4332 केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मीजरमेंट सिस्टम्स, 739/39, 80 फीट रोड, छाबों बलोक, राजाजीनगर, बंगलूर-560010, कर्नाटका, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं.एस-35019(472)/84-पी.एफ.-2]

S.O. 4332.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Measurement Systems, 739/39, 80 Feet Road, 6th Block, Rajaji Nagar, Bangalore-560010, Karnataka have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(472)/84-PF. II]

कां.आं. 4333.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सुराज इलेक्ट्रीक कॉर्पोरेशन 816 जोशी पथ, करोल बाग, नई दिल्ली नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं.एस-35019(473)/84-पी.एफ.-2]

S.O. 4333.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Suraj Electric Corporation, 816, Joshi Path, Karol Bagh, New Delhi have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(473)/84-PF. II]

कां.आं. 4334.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कोशीज इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, मातज.वी जंकशन, पोस्ट ऑफिस, तीरुवल-689105, केरला स्टेट नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(474)/84-पी.एफ.-2]

S.O. 4334.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Koshi's Electronics Ltd., Manjadi Junction, P.O. Tiruvalla-689105, Kerala State have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No S-35019(474)/84-PF. II]

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1984

कां.आं. 4335.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मिलन थियेट्र, चिकमंगलूर, कर्नाटका, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(477)/84-पी.एफ.-2]

New Delhi, the 26th November, 1984

S.O. 4335.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Milan Theatre Chickmagalur, Karnataka have agreed that the provision of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No S-35019(477)/84-PF. II]

कां. आं. 4336.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स साम पम्पस, मेट्टुपालायम रोड, कोइम्बूर 43, तमिल नाडू, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(480)/84-पी.एफ.-2]

S.O. 4336.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sam Pumps, Mettupalayam Road, Coimbatore, 43, Tamil Nadu have agreed that the provision of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(480)/84-PF-II]

का० आ० 4337.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स गंगाबाई चैरीटीज, नं० 10, राजा अन्ना-मलाई रोड, मद्रास-84, तमिल नाडू, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(479)/84-पी०एफ०-2]

S.O. 4337.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Gangabai Charities, No. 10, Raja Annamalai Road, Madras-84, Tamil Nadu have agreed that the provision of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(479)/84-PF-II]

का० आ० 4338.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स साउथर्न इनवेस्टमेंट प्रापर्टी डेवेलोपमेंट (प्रा.) लिमिटेड, मोन्टीथ कोर्ट, 15, मोन्टीथ रोड, मद्रास-8 और 45/1, पैलेस रोड, बंगलूर स्थित ब्रांच सहित, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(478)/78/पी०एफ०-2]

S.O. 4338.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Southern Investment Property Development (P) Ltd., Montieth Court, 15, Montieth Road, Madras-8 including its branch at 45/1, Palace Road, Bangalore have agreed that the provision of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(478)/84-PF-II]

का० आ० 4339.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सुधारकर फाइनेन्शियर्स "गोरान्तला निलायम" 5, सर थिगराया रोड, टी० नगर, मद्रास-600017, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(476)/84-पी. एफ.-2]

S.O. 4339.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Sudhakar Financiers "Gorantla Nilayam" 5, Sir Theagaraya Road, T. Nagar, Madras-600017 have agreed that the provision of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(476)/84-PF-II]

का० आ० 3440.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इंटगरल अल्फा प्राईवेट लिमिटेड, 703/1/4, उदयमबाग, बेलगाम-8, कर्नाटका, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(475)/84-पी०एफ०-2]

S.O. 4340.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Integral Alpha Pvt. Ltd., 703/1/4, Udyambag, Belgaum-8, Karnataka have agreed that the provision of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(475)/84-PF-III]

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1984

सूक्ति पत्र

का. आ. 4341.—भारत सरकार श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 47, दिनांक 17 दिसम्बर, 1983 के अंग्रेजी रूपान्तर में, जो भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 7 जनवरी, 1984 को प्रकाशित हुआ था, "राज बिल्डिंग" को "ताज बिल्डिंग" पढ़ें।

[सं. एस-35018/55/83-भ.नि.-II]

राम कनूंगा, अवसर सचिव

New Delhi, the 27th November, 1984

CORRIGENDUM

S.O. 4341.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour & Rehabilitation, Department of Labour, No. S.O. 47 dated the 17th December, 1983 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 7th January, 1984, in line 4, for "Raj Building" read "Taj Building".

[No. S-35018/55/83-PF.II]

प्रार्थना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1984

का. आ. 4342.—मैसर्स टी. पी. साव के बीजाय आयरन और माइन्स के प्रबंधन ने सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व यूनाइटेड मिनरल्स वर्कर्स यूनियन (सीटू) करती है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और उक्त नियोजकों और उनके कर्मचारियों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को माध्यस्थ के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त अधिनियम की धारा 10-क की उपधारा (3) के अधीन उक्त माध्यस्थ करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क की उपधारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थ करार को एतद्वारा प्रकाशित करती है।

(करार)

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन) पक्षकारों के नाम

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले मैसर्स टी. पी. साव की बीजाय आयरन और माइन्स, डाकघर बाराजामदा सिधभूम।

कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले जनरल सैक्रेटरी, यूनाइटेड मिनरल्स वर्कर्स यूनियन, डाकघर गुप्ता (सिधभूम)।

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री एस. बी. सिंह, क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद के माध्यस्थ के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है।

विनिर्दिष्ट विवादस्त विषय :-

(i) 1. "क्या बीजाय आयरन और माइन्स नं. 1, पञ्चारीबुध, डाकघर बाराजामदा, जिला सिधभूम (मैसर्स टी. पी. साव, चौबामा) के प्रबंधन की औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25अख के अधीन अपने कर्मचारियों को (सूची संलग्न है)

15-1-1984 से खानों के बन्द होने के फलस्वरूप 3 माह की मजदूरी की दर से छठनी मुआवजा देने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं, तो ये कर्मकार किस अनूतोष के हकदार हैं?"

2. "क्या उपरोक्त प्रबंधन ने 15-1-1984 से खानों के बन्द होने के परिणामस्वरूप उपरिलिखित कर्मचारियों को सभी वेध बकाया राशियों का भुगतान कर दिया है? यदि नहीं, तो ये कर्मकार कितने लाभों के हकदार हैं?"

(ii) विवाद के पक्षकारों का मेसर्स टी. पी. साव की बीजाय विवरण, जिसमें अंतर्भावित आयरन और माइन्स, डाकघर स्थान या उपक्रम का नाम चौबामा (सिधभूम)। और पता भी सम्मिलित है।

(iii) यदि कोई संघ प्रणगत कर्म- जनरल सैक्रेटरी, यूनाइटेड मिनरल्स कारों का प्रतिनिधित्व करता धर्मस यूनियन, डाकघर गुप्ता हो तो उसका नाम (सिधभूम)

(iv) प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या 64

(v) विवाद द्वारा प्रभावित या 50

सम्भाव्यतः प्रभावित होने वाले

कर्मचारियों की प्राक्कलित संख्या

हम यह करार भी करते हैं कि माध्यस्थ का विनिश्चय हम पर बाध्य कर होगा।

माध्यस्थ अपना पंचाट 3 (तीन) मास की कायावधि या दलने और समय की भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाय, देगा। यदि पूर्व वर्णित कायावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यस्थ के लिए निर्देश स्थान: रद्द हो जाएगा और हम नए माध्यस्थ के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे।

पक्षकारों के हस्ताक्षर

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले

कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले

ह. /- (अपठनीय)

ह. /- (एन. गुप्ता)

हुते ठाकुर प्रसाद साव
साकी

जनरल सैक्रेटरी

1. ह. /- (आर. के. नायर)

7-8-1984

2. ह. /- (बी. पी. सिन्हा)

7-8-1984

15-1-1984 के खान के बन्द होने पर मै. टी. पी. साव पी. आ. बाराजामदा, जिला सिधभूम की बीजाय आयरन और माइन्स के छठनी किए गए कर्मचारियों की सूची :-

1. श्री माईकल आईन्ड, सुपुत्र स्वर्गीय श्री विनेश आईन्ड।
2. श्री सुनीला हन्सदा, सुपुत्री गंगा हन्सदा।
3. श्रीमती आशा गोपिन, पत्नी श्री गोपाल गोप।
4. श्री नन्दा शाह, सुपुत्र श्री लाभू शाह।
5. श्री कोनू लोहार, सुपुत्र स्वर्गीय श्री मन्सार लोहार।
6. श्रीमती मंगरी लोहारिन, पत्नी श्री कीनू लोहार।
7. श्री सुनेन्द्र दास, सुपुत्र स्वर्गीय श्री विश्वो दास।
8. श्री कृष्णा बरैक, सुपुत्र हरेकमन बरैक।
9. श्री जमन सबैयन, सुपुत्र स्वर्गीय श्री जरोई सबैयन।
10. श्री हरी चरण दास, सुपुत्र स्वर्गीय श्री निदान दास।

11. श्री माना बांद, सुपुत्र श्री देवा बांद ।
12. श्रीमती तुमरी बांद, पत्नी श्री माना बांद ।
13. श्री गुरु हेम्सा, सुपुत्र स्वर्गीय श्री रघुनाथ हेम्सा ।
14. श्रीमती भगेश भाईन्द, पत्नी श्री माईकल भाईन्द ।
15. श्री बिंदु मुन्दरिन, सुपुत्र स्वर्गीय श्री वैजनाथ मुन्दरी ।
16. श्रीमती गुरुबारी मुन्दरी, पत्नी श्री बिन्दू मुन्दरी ।
17. श्री पटराश बाग्जो, सुपुत्र श्री धर्मश बाग्जो ।
18. श्रीमती सुशारी बाजो, पत्नी श्री पटराश बाजो ।
19. श्री भास्कर दास, सुपुत्र श्री शशिदास दास ।
20. श्री तोबेश होरो, सुपुत्र श्री निवेश होरो ।
21. श्रीमती सरियम होरो, पत्नी श्री तोबेश होरो ।
22. श्री चन्द्र मोहन लोहार, सुपुत्र श्री धानसिंह लोहार ।
23. श्री महेन्द्र दास सुपुत्र स्वर्गीय श्री रत्न दास ।
24. श्री शम्भू दास, सुपुत्र स्वर्गीय श्री रतन दास ।
25. श्री बीबीसन दास, पुत्र श्री रतन दास ।
26. श्री पतराश तैते, सुपुत्र श्री जाल्या तैते ।
27. श्री दाउद कन्दुलना, सुपुत्र स्वर्गीय श्री बसू कन्दुलना ।
28. श्रीमती फुलिष कन्दुलना, पत्नी श्री दाउद कन्दुलना ।
29. श्री गुरु हेम्बरम, सुपुत्र श्री मधू हेम्बरम ।
30. श्री जगमोहन मनकी, सुपुत्र स्वर्गीय श्री मनकी ।
31. श्री जोगहन मनकी, सुपुत्र स्वर्गीय श्री जयमाणी मनकी ।
32. श्रीमती मुन्दरी मनकी, पत्नी श्री जोगहन मनकी ।
33. श्री जोदटो सिन्कू, सुपुत्र श्री बाबुकर सिन्कू ।
34. श्रीमती जैमा सिन्कू, पत्नी श्री जोगो सिन्कू ।
35. श्री सुरेश जोगो, सुपुत्र स्वर्गीय श्री केनुला जोगो ।
36. श्री मोताय जोगो, सुपुत्र श्री जन्तुर जोगो ।
37. श्री याकूब लाकरा, सुपुत्र स्वर्गीय श्री मार्टिन लाकरा ।
38. श्री लखन सुरिन, सुपुत्र स्वर्गीय श्री माधू सुरिन ।
39. श्री पादु सुरिन, सुपुत्र स्वर्गीय श्री माधू सुरिन ।
40. श्री मुनिया चम्पिया, सुपुत्र श्री जोन्दो चम्पिया ।
41. श्री रोया चाटुम्बा, सुपुत्र स्वर्गीय श्री गोमा चाटुम्बा ।
42. श्री अनुमा पुर्ती, सुपुत्र स्वर्गीय श्री गोमा पुर्ती ।
43. श्री नागु चम्पिया, सुपुत्र स्वर्गीय श्री जोगो चम्पिया ।
44. श्रीमती पत्तो चम्पिया, पत्नी श्री नागु चम्पिया ।
45. श्रीमती भोजमोती सुरेन, पत्नी स्वर्गीय श्री कान्हे सुरेन ।
46. श्री मोटे सबायन, सुपुत्र स्वर्गीय श्री जारे सबायन ।
47. श्रीमती विनी हेमा, पत्नी स्वर्गीय श्री सुता हेमा ।
48. श्री ब्रजमोहन सिन्कू, सुपुत्र स्वर्गीय श्री भरत सिन्कू ।
49. श्रीमती संतारी सिन्कू, पत्नी श्री ब्रजमोहन सिन्कू ।
50. श्री समोरा तोप्पो, सुपुत्र श्री शशी तोप्पो ।
51. श्री बोनो क्षेरिया, सुपुत्र श्री यादव क्षेरिया ।
52. श्रीमती नखी मुन्दरी, पत्नी श्री केशव मुन्दरी ।
53. श्री सुखदेव दास, सुपुत्र श्री मेदव दास ।
54. श्री कैलाश चन्द्र दास, सुपुत्र स्वर्गीय श्री प्रसिया दास ।
55. श्रीमती सरानी टोप्पो, पत्नी श्री प्रानन्द टोप्पो ।
56. श्रीमती जोगा सुरेन, पत्नी श्री बुधराम सुरेन ।
57. श्रीमती साम्बरी गोपिन, पत्नी श्री शमिया गोपि ।
58. श्री अकलू बायक, सुपुत्र स्वर्गीय श्री प्रधिराम बायक ।
59. श्री सुखराम सुरेन, सुपुत्र स्वर्गीय श्री माधू सुरेन ।

[संख्या एन. 26013/1/84-डी-III-(बी)]

नन्द लाल, प्रथम सचिव

ORDER

New Delhi, the 24th November, 1984

S.O. 4342.—Whereas an industrial dispute exists between the management of Bijoy Iron Ore Mines of Messrs T. P. Sao and their workmen represented by United Minerals Workers Union (CITU).

And whereas, the said employers and their workmen have by a written agreement under sub-section (1) of Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the said dispute to Arbitration and have forwarded to the Central Government under sub-section (3) of Section 10A of the said Act, a copy of the said arbitration agreement.

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of Section 10A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said agreement.

AGREEMENT

(Under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947)
BETWEEN

NAME OF THE PARTIES

Representing Employers—Bijoy Iron Ore Mine of Messrs T. P. Sao, P.O. Barajamada Singhbhum.

Representing Workmen—General Secretary, United Minerals Workers Union P.O. Gua (Singhbhum).

It is hereby agreed between the parties to refer the following industrial dispute to the arbitration of Shri S. B. Singh, Regional Labour Commissioner (Central) Dhanbad.

SPECIFIC MATTERS IN DISPUTE :

(i) (1) "Whether the management of Bijoy Iron Ore Mines No. 1 at Pachariburu, P.O. Barajamada, District Singhbhum (M/s. T.P. Sao, Chaibasa) were justified in making ~~the~~ payment to their workmen (List enclosed) of retrenchment compensation at the rate of 3 months wages under section 25-FFF of I. D. Act, 1947, as a result of closure of the mines w.e.f. 15-1-1984? If not what relief these workmen are entitled to?"

(2) "Whether the said management have paid all the legal dues to the aforesaid workmen as a result of closure of mines with effect from 15-1-1984? If not what benefits these workmen are entitled to?"

(ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved.

Bijoy Iron Ore Mines of M/s. T. P. Sao, P.O. Chaibasa (Singhbhum).

(iii) Name of the Union, if any, representing the workmen in question—

General Secretary,

United Minerals Workers Union,

P.O. Gua (Singhbhum).

(iv) Total number of workmen employed in the undertaking affected : 64.

(v) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute : 59.

We further agree that the decision of the arbitrator shall be binding on us.

The arbitrator shall make his award within a period of 3 (Three) months or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the period aforementioned the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Representing Employer :

Signature of the parties.

Sd/-

(Illegible)

For Thakur Prasad Sao

Representing Workmen :

Sd/-

(N. Guha)

General Secretary

WITNESSES :

Sd/-
(R. K. Nair)
7-8-1984.

Sd/-
(B. P. Sinha)
7-8-1984.

LIST OF THE RETRENCHED WORKMEN OF BIJOY
IRON ORE MINES OF M/S. T. P. SAO, P.O. BARAJA-
MADA, DISTRICT SINGHBHUM ON CLOSURE OF
MINES WITH EFFECT FROM 15-1-1984

1. Sri Michal Aind, Son of Late Dinesh Aind.
2. Smt. Sunika Hansda daughter of Ganga Hansda.
3. Smt. Ashu Gopin, wife of Gopal Gope.
4. Sri Nandu Jharu, Son of Late Ladhu Jharu.
5. Sri Kinoo Lohar Son of Late Mallar Lohar.
6. Smt. Mangri Loharin, wife of Kinu Lohar.
7. Sri Surendra Das, Son of Late Kristo Das.
8. Sri Krishna Baraik, Son of Harokman Baraik.
9. Sri Chamru Sawaiyan, Son of Late Jaroi Sawaiyan.
10. Sri Hari Charan Das, Son of Late Sidan Das.
11. Sri Mana Band, Son of Debra Band.
12. Smt. Tulshi Band, wife of Mana Band.
13. Sri Gura Hessa, Son of Late Reghunath Hessa.
14. Smt. Aganesh Aind, wife of Michel Aind.
15. Sri Bidu Mundarin Son of Late Baijnath Mundari.
16. Smt. Gurubari Mundarin, wife of Bidu Mundari.
17. Sri Patrash Braje, Son of Amush Braje.
18. Smt. Sushari Braje, wife of Patrash Braje.
19. Sri Bhashker Das, Son of Ghasia Das.
20. Sri Tobeyash Harro, Son of Nirdosh Horro.
21. Smt. Marium Horro, wife of Tobeyash Horro.
22. Sri Chandramohan Lohar, Son of Dhansingh Lohar.
23. Sri Mahendra Das, Son of Late Ratti Das.
24. Sri Shambhu Das, Son of Late Rattan Das.
25. Sri Bibison Das, Son of Rattan Das.
26. Sri Patrash Tete, Son of Jotaya Tete.
27. Sri Daud Kandulna, Son of Late Budhu Kandulna.
28. Smt. Phulith Kandulna, wife of Daud Kandulna.
29. Sri Gura Hembrum, Son of Madhu Hembrum.
30. Sri Jagmohan Manki, Son of Late Manki.
31. Shri Johan Manki, Son of Late Jaimashi Manki.
32. Smt. Sundri Manki, wife of Johan Manki.
33. Sri Jotto Sinku Son of Barkuwar Sinku.
34. Smt. Jema Sinku wife of Jotte Sinku.
35. Sri Suresh Jojo, Son of Late Kongula Jojo.
36. Sri Motai Jojo, Son of Jantur Jojo.
37. Sri Yakub Lakra, Son of Late Martin Lakra.
38. Sri Lakhan Surin, Son of Late Machu Surin.
39. Sri Padu Surin, Son of Late Machu Surin.
40. Sri Suniya Champia, Son of Jondo Champia.
41. Sri Roya Chatumba, Son of Late Goma Chatumba.
42. Sri Atua Purty, Son of Late Goma Purty.
43. Sri Nagu Champia, Son of Late Joggo Champia.
44. Smt. Pallo Champia, wife of Nagu Champia.
45. Smt. Bhojmoti Suren, wife of Late Kandey Suren.
46. Sri Motay Sawaiyan, Son of Late Jaray Sawaiyan.
47. Smt. Sini Hessa, wife of Late Suna Sawaiyan.
48. Sri Brajmohan Sinku, Son of Late Bharat Sinku.
49. Smt. Mantari Sinku, wife of Brajmohan Sinku.
50. Sri Somara Toppo, Son of Shahi Toppo.
51. Sri Ghono Jerai, Son of Yadav Jerai.
52. Smt. Nandi Sundi, wife of Keshav Sundi.
53. Sri Sukhdeo Das, Son of Sedam Das.
54. Sri Kailash Chandra Das, Son of Late Ghasia Das.
55. Smt. Sarani Toppo, wife of Anand Toppo.
56. Smt. Jonga Suren, wife of Budhram Suren.
57. Smt. Sombari Gopin, wife of Ghasia Gope.
58. Sri Akalu Braik, Son of Late Abhiram Braik.
59. Sri Sukharam Suren, Son of Late Machu Suren.

[No. L-26013/1/84-D.III (B)]

आदेश

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर, 1984

का.आ. 4343.—द्रावनकोर टिटैनियम प्रोडक्ट्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम के प्रबंधन से संबंधित नियोजकों और उनके कर्मचारों, जिनका प्रतिनिधित्व टिटैनियम जनरल लेबरर्स यूनियन और टिटैनियम प्रोडक्ट्स लेबर यूनियन करती है, ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (2) के अधीन अपने बीच विद्यमान एक औद्योगिक विवाद का न्यायनिर्णयन के लिए औद्योगिक अधिकरण को भेजने का केन्द्रीय सरकार को आवेदन किया है जो उक्त प्रार्थना पत्र में लिखित तथा इस से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में है ;

और केन्द्रीय सरकार प्रत्येक पार्टी के आवेदन करने वाले व्यक्तियों के बहुमत से संतुष्ट है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तमिलनाडू राज्य सरकार द्वारा गठित औद्योगिक अधिकरण, मद्रास को विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए भेजती है। उक्त औद्योगिक अधिकरण उपर्युक्त अधिनियम की धारा 10(2-क) के अधीन उक्त औद्योगिक विवाद में अपना पचाट चार माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा।

अनुसूची

“क्या टिटैनियम जनरल लेबरर्स यूनियन तथा टिटैनियम प्रोडक्ट्स लेबर यूनियन आदि द्रावनकोर टिटैनियम प्रोडक्ट्स लि. के इाइवर, सर्वश्री एस. के. कोशी, ए. के. कोपीनाथन, परमेश्वरन नायर की इाइवर श्री ए. बी. गोविन्दन के वेतन के बराबर वेतन वृद्धि करने की मांग न्यायोचित है ? यदि हाँ, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है ?”

[सं. एल-29025/5/84-डी-3(बी)]

नन्द लाल, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 29th September, 1984

S.O. 4343.—Whereas, the employers in relation to the management of Travancore Titanium Products Limited, Trivandrum and their workmen represented by Titanium General Labourers Union and Titanium Products Labour Union have jointly applied to the Central Government under sub-section (2) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the reference of an industrial dispute that exists between them to an Industrial Tribunal in respect of the matters set forth in the said application and reproduced in the Schedule hereto annexed:

And whereas, the Central Government is satisfied that the persons applying represent the majority of each party;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 10 of the said Act, the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Madras constituted by the State

Government of Tamil Nadu. The said Industrial Tribunal shall give its award in the said industrial dispute within a period of four months under section 10(2A) of the aforesaid Act.

SCHEDULE

"Whether Titanium General Labourers Union and Titanium Products Labour Union are justified in demanding stopping up of pay of Sarvashri S. K. Koshy, A. K. Gopinathan, Parameswaran Nair, Drivers of Travancore Titanium Products Ltd. to the level of pay of Sri A. P. Govindan, Driver? If so, to what relief are the workmen concerned entitled?"

[No. L-29023(5)/84-D.III.B]

NAND LAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1984

का. आ. 4344.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ड़) के उपखण्ड (vi) के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय श्रम विभाग की अधिसूचना संख्या का. आ. 1767 दिनांक 17 मई, 1984 द्वारा लौह अयस्क खनन उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 9 जून, 1984 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था।

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ड़) के उपखण्ड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 9 दिसम्बर, 1984 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[का. संख्या एस-11017/8/81-डी-1(ए)]

म. स. टांगरी, अवर सचिव

New Delhi, the 27th November, 1984

S.O. 4344.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provision of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation, Department of Labour S.O. No. 1767 dated the 17th May, 1984 the iron ore mining industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months, from the 9th June, 1984;

And, whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a further period of six months from the 9th December, 1984.

[No. S-11017/8/81-D.I(A)]

M. S. TANGRY, Under Secy.

